PLUTUS IAS

UPSC / PCS

PLUTUS IAS

मासिक करेंट अफेयर्स

अगस्त 2025

Phone: +91 8448440231
Email: info@plutusias.com
Web: www.plutusias.com

मुख्य आकर्षण :

प्रारंभिक परीक्षा - 2026 के लिए भारतीय इतिहास , कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न पत्र की विस्तृत व्याख्या
डॉ. अखिलेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर - लेखन की सर्वश्रेष्ठ रणनीति पर विस्तृत चर्चा

PLUTUS IAS

Where there is a will there is way

Offline/Online/Hybrid Batches
Admission Open at Karol Bagh/Mukherjee Nagar/Chandigarh

Experienced Renowned Faculties

Personalized Mentorship Programme

Notes Making & Answer Writing

Live Session with Backup

Important Courses Offered by PLUTUS IAS

- GS Foundation Course
- NCERT Base
- Pre Cum Mains (GS)
- Prelims Test Series (65 Tests)
- Mains Test Series (24 Tests)

Foreword

Dear Aspirants,

This magazine by the Plutus IAS team is designed in such a fashion that it holistically covers all the relevant and important topics for the Civil Services Exam to make aspirants exam-ready. Plutus IAS Current Affairs Magazine is a secondary source of information; the newspaper will remain the primary source for the preparation of Current Affairs.

Now, Current Affairs are no longer merely current; they are Contemporary Affairs. Questions asked in both Prelims as well as the Mains assess the conceptual clarity of an aspirant. This magazine is prepared with the aim of helping you understand the interlinkages of both Static and Dynamic news events and internalize the concepts required to crack this examination.

The Plutus IAS team wishes you all the best. Prepare for the UPSC Civil Services Examination with a calm, composed, or serene mind and some patience to crack this examination in one go.

Team
Plutus IAS

Sources:
The Hindu | The Indian Express | The Economic Times | Press Information Bureau | PRS Legislative Research | IDSA: Institute for Defense Studies and Analysis | Yojana and Kurukshetra | Lok Sabha and Rajya Sabha Debates.

OUR TOP RANKERS

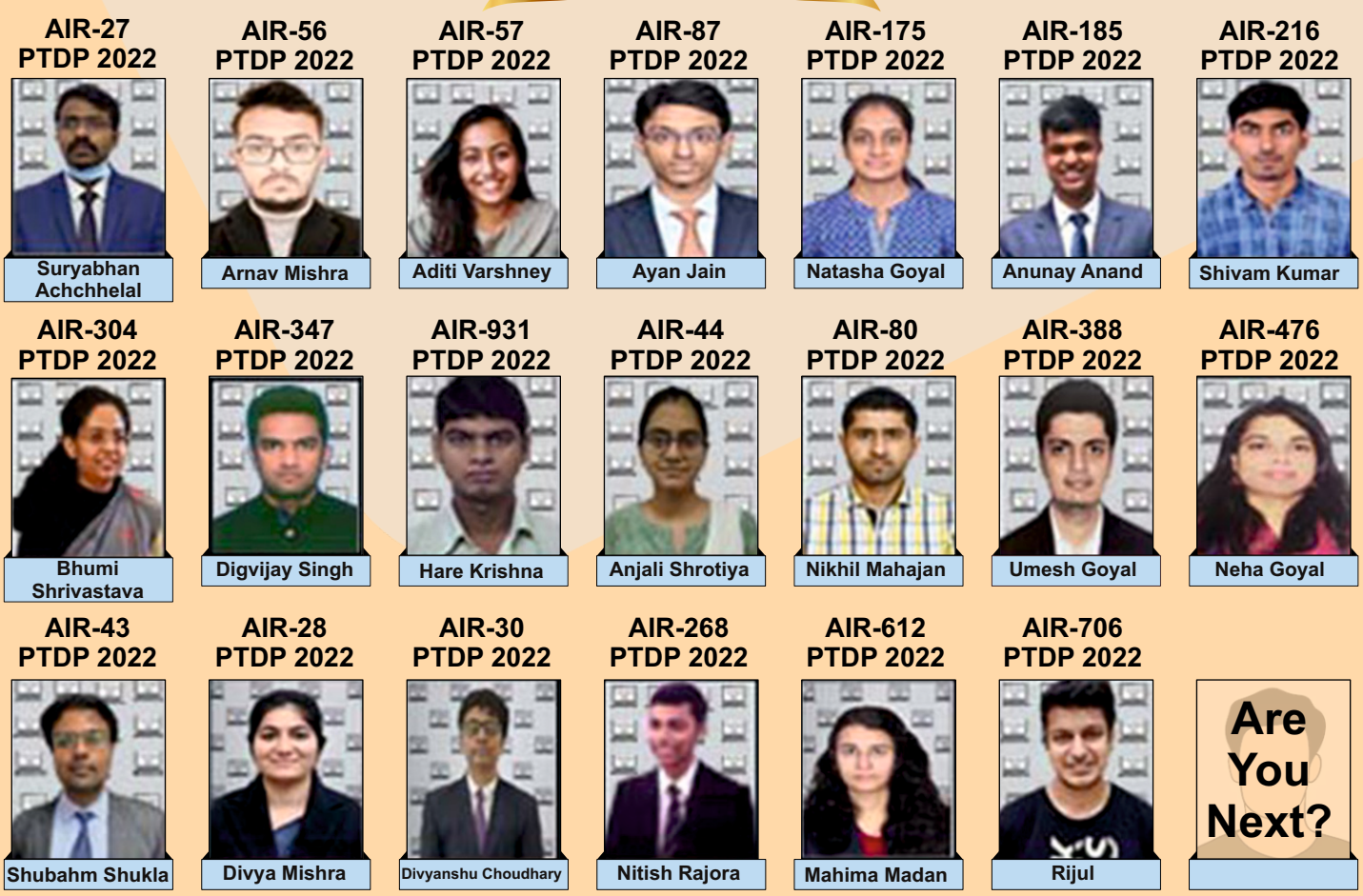

Copyright © by Plutus IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Plutus IAS.

अगस्त 2025
करेंट अफेयर्स

अनुक्रमणिका

भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था (Indian Politics and Governance) :

- भारत में उच्च शिक्षा का अति-राजनीतिकरण : मुख्य चुनौतियाँ और भविष्य.....1
- मतदान से परे आवाजें : दबाव समूहों का लोकतांत्रिक प्रभाव.....4
- रेगिस्तान और लोकतंत्र : भारत – यूएई रणनीतिक संबंधों की नई दिशा 7

विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology):

- पूर्वी सीमा से पश्चिमी मोर्चे तक : अपाचे AH-64E के साथ भारतीय वायुसेना के नए युग का आगाज 11
- भारत बनाम वैश्विक बाज़ार : ग्लोबल मंदी की चपेट में भारत का हीरा उद्योग 14
- क्वांटम प्रकाश से युक्त सिलिकॉन चिप : स्केलेबिलिटी की ओर बढ़ता एक कदम 18
- विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट (WIFEX) : वैज्ञानिक नवाचार और नीतिगत प्रभाव का एक दशक.....21

अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International relations):

- एससीओ (SCO) में भारत : शांति और क्षेत्रीय स्थिरता की एक सुनियोजित कोशिश.....25
- वैश्विक खाद्य मानकों में भारत की भूमिका : कोडेक्स समिति में FSSAI की भागीदारी 29
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता युद्ध और ऊर्जा की आवश्यकता : भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक चेतावनी 31
- भारत-सऊदी अरब उर्वरक समझौता : दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग का एक आधार स्तंभ 34

भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian economy):

- आरबीआई का आर्थिक पूर्वानुमान : भारत की विकास दर और इसका वैश्विक प्रभाव 39
- स्वास्थ्य बनाम राजस्व : तम्बाकू नियंत्रण से जीएसटी पर पड़ने वाला आर्थिक प्रभाव 43
- भारत के कृषि-निर्यात का भविष्य दांव पर : व्यापार वार्ता में जीएम आयात का प्रभाव 45
- यूपीआई : भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति और रीयल-टाइम लेनदेन में वैश्विक नेतृत्व 49
- सीमाओं की सुरक्षा और शिखरों की निगरानी : सीमाई और आंतरिक खतरों से निपटने के लिए अरुणाचल की नई बटालियन.....52

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment and Ecology):

- विश्व ज़ूनोसिस दिवस 2025 56
- भारत के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय विस्थापन : मुद्दे, प्रभाव और नीतिगत अनिवार्यता 58
- भारत –अर्जेंटीना कृषि साझेदारी : नवाचार और स्थिरता के लिए एक रणनीतिक कूटनीति 61
- भारत का स्वच्छ ऊर्जा विरोधाभास : क्षमता और कुल उत्पादन के बीच का अंतर 65
- पीएम ई –ड्राइव 2024–26 : भारत में इलेक्ट्रिक ट्रकिंग के लिए एक क्रांतिकारी पहल 67

भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति (INDIAN HISTORY, ART AND CULTURE) :

- भारत में भक्ति आंदोलन और संत कबीर दास.....71
- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और बाल गंगाधर तिलक.....74

मुख्य आकर्षण : संघ लोक सेवा आयोग के CSE के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में उत्तर - लेखन के दौरान अपनाए जाने वाला दृष्टिकोण

- प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र - 1 (2025 - 2026) डॉ. अखिलेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों का सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उत्तर की विस्तृत व्याख्या।.....77
- प्रारंभिक परीक्षा - सह - मुख्य परीक्षा में उत्तर - लेखन शैली पर केन्द्रित सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र (टीम PLUTUS IAS द्वारा संकलित एवं डॉ. अखिलेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों का सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उत्तर की विस्तृत व्याख्या एवं मुख्य परीक्षा में उत्तर - लेखन के दौरान अपनाए जाने वाली सर्वश्रेष्ठ उत्तर - लेखन रणनीति।).....108

भारत में उच्च शिक्षा का अति-राजनीतिकरण : मुख्य चुनौतियाँ और भविष्य

ख़बरों में क्यों?

- भारतीय उच्च शिक्षा के अत्यधिक राजनीतिकरण की चर्चा आज कल ख़बरों में इसलिए है क्योंकि यह शैक्षिक जीवन और संस्थानों की स्वायत्तता पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। इसकी जड़ें भारतीय शिक्षा के इतिहास में गहराई से जुड़ा हुआ या समाहित हैं और हालिया वर्षों में इसकी तीव्रता में वृद्धि हुई है।
- वर्तमान समय में भारत में अकादमिक स्वतंत्रता और बौद्धिक विमर्श में बाधाएं आ रही हैं, जिसके कारण भारत में शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों की मांग भी एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर कर सामने आई है।

भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति :

- भारत में, उच्च शिक्षा का अर्थ है 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद प्राप्त की जाने वाली तृतीयक स्तर की शिक्षा। यहाँ, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली है, जिसमें 58,000 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थान शामिल हैं।
- वर्तमान में, भारत में 43.3 मिलियन छात्र उच्च शिक्षा के लिए नामांकित हैं। इनमें से लगभग 79% छात्र स्नातक पाठ्यक्रमों में, 12% छात्र स्नातकोत्तर (मास्टर डिग्री) पाठ्यक्रमों में, और केवल 0.5% छात्र PhD पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं। शेष अधिकांश छात्र उप-डिग्री (Sub-Degree) डिप्लोमा कार्यक्रमों में अध्ययनरत हैं।
- स्नातक स्तर पर, कला (34%) सबसे लोकप्रिय विषय क्षेत्र है, इसके बाद विज्ञान (15%), वाणिज्य (13%), और इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी (12%) हैं। स्नातकोत्तर स्तर पर, सामाजिक विज्ञान (21%) शीर्ष विषय क्षेत्र है, उसके बाद विज्ञान (15%) और प्रबंधन (14%) हैं। PhD स्तर पर, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी (25%) में सबसे अधिक छात्र नामांकित हैं, उसके बाद विज्ञान (21%) का स्थान आता है।
- उच्च शिक्षा भागीदारी दर (GER) बढ़कर 28.4% हो गई है, जो पिछले वर्ष 2020-21 से 1.1% अधिक है। उच्चतम GER वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, और तेलंगाना हैं।
- वर्ष 2021-22 में, भारतीय संस्थानों में विदेशी छात्रों की कुल संख्या लगभग 46,000 थी।

भारत में उच्च शिक्षा के अत्यधिक राजनीतिकरण के परिणाम :

भारत में उच्च शिक्षा के अत्यधिक राजनीतिकरण के निम्नलिखित परिणाम हुए हैं -

- **शैक्षणिक स्वतंत्रता में कमी :** राजनीतिक प्रभाव के कारण शैक्षणिक स्वतंत्रता पर असर पड़ा है, जिससे संकाय और छात्रों पर विशेष राजनीतिक विचारधारा को अपनाने का दबाव बढ़ा है।
- **वैश्विक स्तर पर भारतीय शिक्षण संस्थानों की प्रतिष्ठा पर प्रभाव :** उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिकरण होने से भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की वैश्विक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है या हो सकती है,

जिससे प्रतिभाशाली छात्र और शिक्षक इन संस्थानों से दूर हो सकते हैं।

- **विचारों की विविधता में कमी :** भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक एजेंडा के चलते अकादमिक चर्चाओं में विविधता कम हो गई है, जिससे खुली बहस और वैकल्पिक दृष्टिकोणों की खोज में बाधा आई है।
- **छात्र का शोध के प्रति सक्रियता का कम होना :** उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिकरण के बढ़ने से छात्र सक्रियता में वृद्धि हुई है, जो कभी-कभी शैक्षणिक जीवन को बाधित कर शोध के प्रति छात्रों की सक्रियता का कम कर सकती है।
- **शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक विश्वास का ह्रास :** भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक प्रपंचों का विश्वविद्यालयों के स्तर पर इस्तेमाल से शैक्षिक शोध की निष्पक्षता और मूल्य में जनता का विश्वास निरंतर कम हुआ है।
- **शोध के होने वाले वित्तपोषण में कमी होना :** भारत में उच्च शिक्षा में राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक एजेंडा को चलने या बढ़ाने के कारण दीर्घकालिक शोध परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण में कमी आई है, जिससे नवाचार और वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने की भारत के छात्रों की क्षमता भी प्रभावित हुई है।
- **रोजगार प्राप्ति में कमी होना :** भारत में उच्च शिक्षा के अति-राजनीतिक शिक्षा ने स्नातकों को आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान और अनुकूलनशीलता जैसे महत्वपूर्ण कौशलों के विकास में बाधा पहुंचाई है, जिससे उनकी रोजगार सृजन करने और रोजगार प्राप्त करने की क्षमता भी प्रभावित हुई है।

राजनीति का भारतीय उच्च शिक्षा पर प्रभाव :

- **राजनीतिक प्रेरणा :** भारतीय उच्च शिक्षा के संस्थान अक्सर राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित होते हैं, जहाँ राजनेता अपने राजनीतिक करियर को बढ़ाने के लिए कॉलेजों की स्थापना करते रहे हैं।
- **मतदाता आधारित निर्माण :** सामाजिक-सांस्कृतिक मांगों के अनुरूप कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई है, जो भारतीय समाज की विविधता को प्रतिबिंबित करते हैं।
- **स्थानीयकरण :** शैक्षणिक संस्थानों को राजनीतिक रूप से लाभकारी स्थानों पर स्थापित किया गया है, जो अक्सर सामाजिक-सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करते हैं।
- **नामकरण और पुनर्नामकरण :** भारत में विश्वविद्यालयों के नामकरण और पुनर्नामकरण अक्सर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं, जैसे कि UPTU, लखनऊ का नाम परिवर्तन करना।
- **नियुक्तियाँ और पदोन्नतियाँ :** भारत के विश्वविद्यालयों में होनेवाली शैक्षणिक नियुक्तियाँ और पदोन्नतियाँ कभी-कभी योग्यता के बजाय राजनीतिक विचारों से प्रभावित होने के कारण ही होती हैं।
- **शैक्षणिक स्वतंत्रता प्रदान करना :** भारत के विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में खासकर सामाजिक विज्ञान और मानविकी के विषयों में अक्सर शैक्षणिक स्वतंत्रता के मानदंडों का सख्ती से पालन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जहां सेल्फ-सेंसरशिप प्रचलित है और अक्सर वहां विवादास्पद सामग्री के प्रकाशन से हानिकारक परिणाम हो सकते हैं।

वर्तमान समय में भारत में उच्च शिक्षा के लिए नियामक ढाँचा :

भारत में उच्च शिक्षा के लिए नियामक ढाँचा विभिन्न वैधानिक निकायों द्वारा संचालित होता है, जिनका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों को सुनिश्चित करना है। इसके मुख्य निकायों में निम्नलिखित संस्था शामिल हैं -

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) : सन 1956 में स्थापित, यह निकाय विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों को समन्वयित और बनाए रखने के साथ-साथ अनुदान जारी करने का कार्य करता है। इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय बंगलूरू, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में हैं।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) : सन 1945 में स्थापित, यह निकाय तकनीकी शिक्षा के मानदंड और मानक निर्धारित करता है तथा यह भारत में नए संस्थानों और पाठ्यक्रमों को अनुमोदित करता है, और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। वर्ष 1987 में इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यह नए तकनीकी संस्थानों, पाठ्यक्रमों और प्रवेश क्षमता को अनुमोदित करता है

तथा डिप्लोमा स्तर के संस्थानों के लिये राज्य सरकारों को कुछ विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करता है।

- AICTE का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल, बंगलूरू और हैदराबाद में हैं।
- वास्तुकला परिषद (COA) : सन 1972 में वास्तुविद् अधिनियम के तहत स्थापित, यह निकाय वास्तुकला शिक्षा और व्यवसाय के मानकों को नियंत्रित करता है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुसार, चिकित्सा और विधिक शिक्षा को छोड़कर, सभी प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए एक एकल व्यापक निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) की स्थापना को प्रस्तावित किया गया है।
- भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) में चार स्वतंत्र कार्यक्षेत्र शामिल हैं। जिनमें विनियमन के लिए NHERC, मानक निर्धारण के लिए GEC, वित्तपोषण के लिए HEGC, और मान्यता प्रदान करने के लिए NAC जैसी स्वतंत्र संस्था की व्यवस्था है।
- भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) भारत में प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप के माध्यम से कार्य करेगा और इसके द्वारा तय किए गए मानदंडों एवं मानकों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों को दंडित करने का इसे अधिकार प्राप्त है। सार्वजनिक और निजी, दोनों प्रकार के उच्च शिक्षण संस्थान समान विनियमन, मान्यता एवं शैक्षणिक मानकों के अधीन होंगे।

समाधान / आगे की राह :

भारत में उच्च शिक्षा की संस्थागत स्वायत्तता को मजबूत करने और राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

1. **संस्थागत स्वायत्तता को मजबूत करना :** भारत में उच्च शिक्षा की संस्थागत स्वायत्तता को मजबूत करने और राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए तथा अनुचित प्रभावों का विरोध करने के लिए विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए, वित्तपोषण के विविध स्रोतों की तलाश करने और सरकारी निधियों पर निर्भरता कम करने के उपाय किए जा सकते हैं।
2. **शैक्षिक स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करना :** भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक स्वतंत्रता को एक अटूट सिद्धांत के रूप में बनाए रखना और स्वतंत्र विचार-विमर्श तथा अनुसंधान को सुनिश्चित करना आवश्यक है।
3. **स्वायत्त विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना करना :** भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शोध गुणवत्ता को बढ़ावा देने और राजनीतिक प्रभाव से संवेदनशील विषयों की रक्षा के लिए स्वायत्त विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना की जा सकती है।
4. **भारत में शिक्षण संस्थानों को स्वायत्त दर्जा प्राप्त करने का प्रयास करना :** उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों से तुलना करने के लिए भारत के प्रयासों के अनुरूप, संस्थानों को स्वायत्त दर्जा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
5. **राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन करना :** शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में संस्थानों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए NKC और यशपाल समिति की सिफारिशों को लागू करना अनिवार्य होना चाहिए।
6. **शासी निकायों का राजनीतिकरण कम करना :** शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर कुलपति और अन्य प्रमुख पदों के चयन के लिए एक स्वतंत्र चयन प्रक्रिया को अपनाना चाहिए।
7. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों का पालन सुनिश्चित करना :** भारत के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में NEP 2020 में दी गई सिफारिशों के अनुसार, स्वतंत्र और पारदर्शी भर्ती, पाठ्यक्रम डिजाइन की स्वतंत्रता, और संकाय की प्रेरणा और क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना अत्यंत आवश्यक है।
8. **असहमति और आलोचनात्मक जाँच की रक्षा के लिए स्पष्ट नीतियाँ और सुरक्षा उपाय लागू करना :** भारत में शोध, अनुसंधान और छात्रों द्वारा अपने विचार को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के संकाय के अधिकारों की रक्षा के लिए स्पष्ट नीतियाँ और सुरक्षा उपाय लागू करना अत्यंत आवश्यक है।
9. **छात्र संघ की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना :** भारत के विश्वविद्यालयों में छात्र संघों को स्वायत्त निकाय के रूप में बनाए रखना और उनके चुनाव या कार्यप्रणाली में राजनीतिक दलों या प्राधिकारियों का हस्तक्षेप नहीं होने देना चाहिए।
10. **सशक्त लोकपाल की स्थापना करना :** भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप, शैक्षणिक स्वतंत्रता के उल्लंघन, या किसी भी हितधारक से राजनीतिक रूप से प्रेरित उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच और समाधान के लिए एक स्वतंत्र लोकपाल तंत्र की स्थापना करना अत्यंत जरूरी है।

इन कदमों को उठाकर, भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम किया जा सकता है और शैक्षिक स्वतंत्रता और उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया जा सकता है।

स्रोत - पी. आई. बी एवं द हिंदू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत में शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस प्रावधान पर आधारित है? (UPSC - 2019)

1. भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची में।
2. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा।
3. भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में ।
4. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा।
5. भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

A. केवल 1, 2 और 5 B. 1, 2, 3, 4 और 5 सभी।

C. केवल 1, 3 और 4 D. केवल 1 , 3, 4 और 5

उत्तर- B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत में उच्च शिक्षा के राजनीतिकरण को रेखांकित करते हुए इसके परिणामों का विश्लेषण तथा शैक्षणिक संस्थाओं की संस्थागत स्वायत्तता, अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के समाधानों पर तर्कसंगत चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

मतदान से परे आवाजें : दबाव समूहों का लोकतांत्रिक प्रभाव

ख़बरों में क्यों?

- दबाव समूह संगठित निकाय हैं जिनका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने की आकांक्षा के बिना सरकारी निर्णयों को प्रभावित करना है। चुनावी प्रणाली के बाहर काम करते हुए, ये समूह नागरिकों और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वजनिक नीति को आकार देने में मदद करते हैं।

दबाव समूह क्या है?

- दबाव समूह व्यक्तियों का एक समूह है जो नीति निर्धारण को आकार देने के लिए एक समान हित या उद्देश्य के साथ एक साथ आते हैं। राजनीतिक दलों के विपरीत, उनका प्राथमिक लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि नीतियाँ उनकी चिंताओं और मांगों को प्रतिबिंबित करें।

मुख्य विशेषताएं :

1. **मुद्दा-विशिष्ट अभिविन्यास :** वे श्रमिकों के अधिकार, पर्यावरण संबंधी मुद्दे या क्षेत्रीय सुधार जैसे विशेष मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
2. **गैर-चुनावी भागीदारी :** उनका दृष्टिकोण प्रभावित करना है, शासन करना नहीं।
3. **विषम सदस्यता :** विभिन्न क्षेत्रों के लोग प्रायः एक साझा उद्देश्य के तहत एकजुट होते हैं।
4. **गैर-लाभकारी उद्देश्य :** उनकी गतिविधियों का उद्देश्य आमतौर पर वित्तीय लाभ के बजाय किसी उद्देश्य को बढ़ावा देना होता है।
5. **संगठित कार्रवाई :** कुछ औपचारिक रूप से संरचित हैं, जबकि अन्य शिथिल रूप से समन्वित हैं।

दबाव समूहों का वर्गीकरण :

वर्ग	प्रमुख विशेषताएँ	उदाहरण
रुचि-आधारित समूह	विशेष सामाजिक या आर्थिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करें	एटक (श्रमिक), बीकेयू (किसान), फिक्की
कारण-उन्मुख समूह	मूल्यों या सार्वजनिक उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए काम करना	ग्रीनपीस (पर्यावरण), एमनेस्टी (अधिकार)
संस्थागत समूह	आधिकारिक निकाय या पेशेवर शामिल हों	भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए)
एसोसिएशनल समूह	सदस्यता के साथ औपचारिक रूप से गठित निकाय	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)
गैर-सहयोगी समूह	अनौपचारिक, शिथिल रूप से जुड़े समूह	भूमि कानूनों का विरोध कर रहे नागरिक
एनोमिक समूह	अनियोजित, स्वतःस्फूर्त क्रियाएं अक्सर विशिष्ट घटनाओं से प्रेरित होती हैं	छात्रों या गुस्साई भीड़ द्वारा अचानक हड़ताल

मुख्य कार्य :

1. **नीति वकालत :** वे जनता की चिंताओं को विधि निर्माताओं और प्रशासकों तक पहुंचाने के लिए माध्यम के रूप में कार्य करते हैं।
2. **सामाजिक प्रतिनिधित्व :** वे हाशिए पर पड़े लोगों सहित विशिष्ट जनसंख्या वर्गों की आवश्यकताओं और विचारों को आवाज देते हैं।
3. **सूचना प्रसार :** अभियानों, आयोजनों और रिपोर्टों के माध्यम से वे जनता और अधिकारियों दोनों को शिक्षित करते हैं।
4. **लॉबिंग :** वे नीतिगत सुधारों या हस्तक्षेपों पर जोर देने के लिए नीति निर्माताओं से सीधे मिलते हैं।
5. **जवाबदेही तंत्र :** वे शासन की निगरानी करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि नेता अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हों।
6. **विभिन्न विरोधी हितधारकों के बीच मतभेदों को सुलझाने का कार्य करना :** कुछ समूह परस्पर विरोधी हितधारकों के बीच मतभेदों को सुलझाने में सहायता करते हैं।

रणनीतियाँ और उपकरण :

1. **लॉबिंग प्रयास :** अनुकूल नियमों के लिए दबाव बनाने हेतु सरकारी अधिकारियों या विधायकों के साथ सीधा संपर्क (उदाहरणार्थ, आर्थिक नीति पर फिक्की)।
2. **जन-आंदोलन :** जागरूकता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान, रैलियां और विज्ञापन (जैसे, ग्रीनपीस के पर्यावरण अभियान)।
3. **कानूनी कार्रवाई :** कानूनी जांच शुरू करने के लिए अदालती मामलों या जनहित याचिकाओं का उपयोग करना (उदाहरण के लिए, पर्यावरण जनहित याचिकाएं)।
4. **विरोध आंदोलन :** दबाव बनाने के लिए मार्च, धरना और हड़ताल का आयोजन करना (जैसे, हाल ही में हुए किसान आंदोलन)।
5. **मीडिया सहभागिता :** जनमत निर्माण के लिए पारंपरिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना।

लोकतंत्र में दबाव समूहों का महत्व :

1. **लोकतांत्रिक भागीदारी को गहरा करना :** दबाव समूह चुनावों से परे शासन में जनता की निरंतर भागीदारी को सुगम बनाते हैं, जिससे लोकतांत्रिक ताना-बाना समृद्ध होता है।
2. **समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करना :** वे समाज के विभिन्न वर्गों - श्रमिकों, किसानों, व्यापारियों, अल्पसंख्यकों - का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा नीतिगत चर्चाओं में समावेशिता सुनिश्चित करते हैं।
3. **सरकार और नागरिकों के बीच सेतु के रूप में कार्य करना :** दबाव समूह मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, जनता की चिंताओं को प्राधिकारियों तक पहुंचाते हैं तथा सरकार की ओर से प्राप्त फीडबैक को लोगों तक पहुंचाते हैं।
4. **नीति निर्माण में योगदान देना :** परामर्श, अनुसंधान और वकालत में संलग्न होकर ये समूह साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में योगदान देते हैं।
5. **जवाबदेही तंत्र :** वे सरकार के प्रदर्शन की निगरानी करते हैं, अनियमितताओं को उजागर करते हैं और पारदर्शिता की मांग करते हैं, जिससे सुशासन को बढ़ावा मिलता है।
6. **जन जागरूकता सृजन :** अभियान और मीडिया पहुंच के माध्यम से दबाव समूह नागरिकों को महत्वपूर्ण मुद्दों और अधिकारों के बारे में शिक्षित करते हैं।
7. **दबाव समूहों से संबंधित सुधारों को प्रोत्साहित करना :** भारत और विश्व स्तर पर कई सामाजिक, पर्यावरणीय और श्रम सुधार दबाव समूहों के निरंतर प्रयासों से उभरे हैं।
8. **हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाना :** जनजातीय अधिकारों, महिला सशक्तिकरण या पर्यावरण न्याय की वकालत करने वाले समूह उन लोगों की आवाज को बुलंद करते हैं उन्हें मुख्यधारा की राजनीति द्वारा अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

दबाव समूहों की आलोचनाएँ और सीमाएँ :

1. **असमान प्रभाव :** धनी और संगठित समूहों की अक्सर नीति निर्माताओं तक अधिक पहुंच होती है, जिससे कम प्रतिनिधित्व वाले या कमजोर वर्ग दरकिनार हो जाते हैं।
2. **पारदर्शिता का अभाव :** कई दबाव समूह अपने वित्तपोषण स्रोतों या लॉबिंग प्रथाओं का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं करते हैं, जिससे छिपे हुए एजेंडे की चिंता पैदा होती है।
3. **सीमित दायरा :** उनका मुद्दा-विशिष्ट दृष्टिकोण संकीर्ण दृष्टि को जन्म दे सकता है, तथा व्यापक राष्ट्रीय या संवैधानिक हितों की अनदेखी कर सकता है।
4. **विघटनकारी गतिविधियाँ :** हड़तालें, सड़क अवरोध और लंबे समय तक चलने वाले विरोध प्रदर्शन दैनिक जीवन में बाधा डाल सकते हैं, आर्थिक गतिविधियों को बाधित कर सकते हैं और आवश्यक सेवाओं को प्रभावित कर सकते हैं।
5. **अभिजात्यवाद और पूर्वाग्रह से ग्रसित होना :** कुछ समूह केवल अभिजात्य या शहरी हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा ग्रामीण या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उपेक्षा करते हैं।
6. **निर्वाचित संस्थाओं को कमजोर करना :** अनिर्वाचित समूहों के अत्यधिक प्रभाव से निर्वाचित निकायों और अधिकारियों का अधिकार और जवाबदेही कमजोर हो सकती है।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

7. **नीतिगत पक्षाघात :** आक्रामक लॉबिंग और दबाव की रणनीति के कारण नीति निर्माण में देरी हो सकती है या लोकलुभावन समझौते हो सकते हैं।

8. **राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर असर पड़ने की संभावना :** कुछ समूह विदेशी वित्तपोषण या राजनीतिक हितों से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर असर पड़ सकता है।

यह राजनीतिक दलों से किस प्रकार भिन्न है :

पहलू	दबाव समूह	राजनीतिक दल
लक्ष्य	प्रभाव नीति	चुनावों के माध्यम से सत्ता हासिल करें
चुनावों में भागीदारी	चुनाव न लड़ें	चुनावों में भाग लें
सार्वजनिक जवाबदेही	मतदाताओं के प्रति जवाबदेह नहीं	मतदाताओं को जवाब देना होगा
एजेंडा का दायरा	विशिष्ट मुद्दे या कारण	व्यापक नीति मंच

निष्कर्ष :

दबाव समूह किसी भी लोकतांत्रिक समाज में अपरिहार्य अभिनेता हैं। विभिन्न हितों के लिए आवाज़ बनकर वे नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं, जाँच और संतुलन बनाते हैं, और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। हालाँकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज के सभी वर्गों को उनके कार्यों से लाभ मिले, अधिक पारदर्शिता और संतुलित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाए बिना उनके प्रभाव को नियंत्रित करने से लोकतांत्रिक शासन को और मज़बूती मिल सकती है।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत में दबाव समूहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. दबाव समूहों का लक्ष्य चुनावों के माध्यम से राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करना है।
2. वे केवल राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं, स्थानीय स्तर पर नहीं।
3. दबाव समूह सरकार का हिस्सा बने बिना भी सार्वजनिक नीति को प्रभावित कर सकते हैं।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2 B. केवल 3

C. केवल 1 और 3 D. केवल 2 और 3

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. दबाव समूह सरकार और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, जो भागीदारी पूर्ण लोकतंत्र को बढ़ाते हैं, लेकिन पारदर्शिता और समानता के बारे में चिंताएँ भी बढ़ाते हैं। भारत में दबाव समूहों की भूमिका, प्रकार, तकनीक और चुनौतियों पर चर्चा करें।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

रेगिस्तान और लोकतंत्र : भारत - यूएई रणनीतिक संबंधों की नई दिशा

ख़बरों में क्यों?

- हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) अपने परंपरागत साझेदारी के दायरे से आगे बढ़ते हुए अब सहयोग के नए और रणनीतिक क्षेत्रों में कदम रख रहे हैं। दोनों देश अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहकर, परमाणु ऊर्जा, अत्याधुनिक तकनीक, डिजिटल वित्त और रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग को विस्तार देने की दिशा में अग्रसर हैं।
- वर्तमान में हुए यह प्रगति न केवल आर्थिक स्थिरता और सतत विकास की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि क्षेत्रीय संपर्क को भी नई ऊर्जा प्रदान करती है।

भारत-यूएई आर्थिक सहयोग : साझेदारी के नए आयाम

1. **व्यापारिक साझेदारी में ऐतिहासिक छलांग :** भारत और यूएई के बीच व्यापारिक संबंधों ने अभूतपूर्व गति पकड़ी है। 2027 का लक्ष्य निर्धारित करने के बावजूद, दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब के आंकड़े को पाँच वर्ष पहले ही पार कर गया है, जिससे यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है।
2. **सीईपीए : द्विपक्षीय व्यापार में क्रांतिकारी परिवर्तन :** वर्ष 2022 में हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) व्यापार में बाधाओं, टैरिफ और दस्तावेज़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाकर व्यापार प्रवाह को सुगम बना रहा है। यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक सेतु का कार्य कर रहा है।
3. **डिजिटल व्यापार गलियारा : व्यापार प्रक्रिया में नवाचार :** सीईपीए के अंतर्गत "वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर" की स्थापना से सीमा शुल्क प्रक्रिया में तेजी आई है और व्यापारिक पारदर्शिता बढ़ी है। यह पहल भारत-मध्यपूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर (IMEEC) की व्यापक रणनीति को मजबूती देती है।
4. **निवेश का विस्तार :** भरोसे की बुनियाद : यूएई का भारत में कुल एफडीआई $23 अरब तक पहुँच चुका है, जो स्थिर निवेश परिवेश में उसके विश्वास को दर्शाता है।
5. **द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) 2023:** संरक्षित निवेश का आधार : वर्ष 2023 में हुई द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) ने यूएई के निवेशकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की है, जिससे पूंजी प्रवाह और दीर्घकालिक परियोजनाओं में रुचि बढ़ी है।
6. **विविधता में ताकत :** भारत-यूएई व्यापार अब केवल ऊर्जा या वस्त्र तक सीमित नहीं, बल्कि खाद्य प्रसंस्करण, हरित ऊर्जा, आईटी, और पेट्रोकेमिकल जैसे विविध क्षेत्रों तक फैल चुका है — जिससे यह संबंध अधिक रणनीतिक और समग्र बन चुका है।

वित्तीय समावेशन और मुद्रा सहयोग का विस्तार

1. **मुद्रा लेन-देन में बदलाव : रुपये-दिरहम का प्रयोग :** अब द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 10% भारतीय रुपये और यूएई दिरहम में तय हो रहा है, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम हो रही है और लेन-देन अधिक लचीला बन रहा है।
2. **जयवान कार्ड :** एक साझा फिनटेक पहल : यूएई ने भारतीय "रुपे" प्लेटफॉर्म पर आधारित जयवान कार्ड लॉन्च किया है, जो दोनों देशों के बीच डिजिटल भुगतान सहयोग की दिशा में एक नया अध्याय है।
3. **यूपीआई-आनी एकीकरण :** भारत का UPI और यूएई का आनी प्लेटफ़ॉर्म नवंबर 2025 तक जुड़ जाएंगे, जिससे सीमाओं के पार त्वरित और सस्ते डिजिटल भुगतान संभव होंगे।
4. **सीबीडीसी सहयोग :** केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (CBDC) की आपसी संगतता सुनिश्चित करने को लेकर विचार-विमर्श जारी है, जिससे वित्तीय सुरक्षा और स्थायित्व को बल मिलेगा।
5. **स्विफ्ट विकल्प की तलाश :** भारत और यूएई बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक वैकल्पिक और सुरक्षित संदेश प्रणाली विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, जिससे डेटा संप्रभुता सुनिश्चित हो सके।
6. **वैश्विक दक्षिण के लिए फिनटेक मॉडल :** यह साझेदारी डिजिटल फिनटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर में सहयोग का एक आदर्श मॉडल बन रही

है, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण देशों के लिए जो संप्रभु भुगतान प्रणालियों की ओर अग्रसर हैं।

7. **एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए बढ़त :** फिनटेक कनेक्टिविटी छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को सशक्त बना रही है, जिससे लेन-देन की लागत कम हो रही है और वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच आसान हो रही है।

प्रौद्योगिकी और शिक्षा : नवाचार की साझा यात्रा

1. **वाइब्रेंट गुजरात 2024 :** तकनीकी सहयोग पर केंद्रित : गुजरात शिखर सम्मेलन 2024 में एआई, अंतरिक्ष, बायोटेक और स्वच्छ ऊर्जा तकनीक में भारत-यूएई साझेदारी को प्रमुखता दी गई।

2. **ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम :** दोनों राष्ट्र नवाचार, अनुसंधान और डिजिटल बदलाव के माध्यम से अपने शिक्षा व आर्थिक मॉडल को ज्ञान-केंद्रित बनाना चाहते हैं।

3. **आईआईटी अबू धाबी: अनुसंधान का नया केंद्र :** यूएई में आईआईटी अबू धाबी का शुभारंभ उच्च शिक्षा में सहयोग को नई दिशा देता है, विशेषकर अनुसंधान और पीएचडी कार्यक्रमों के माध्यम से।

4. **आईआईएम अहमदाबाद दुबई कैंपस :** दुबई में आईआईएम की उपस्थिति खाड़ी क्षेत्र में भारतीय प्रबंधन शिक्षा की बढ़ती मांग को रेखांकित करती है।

5. **आईआईएफटी का विस्तार :** भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) ने दुबई में परिसर स्थापित कर व्यापार और रणनीतिक शिक्षा को सीईपीए समझौते के अनुरूप सुदृढ़ किया है।

6. **मानव संसाधन गतिशीलता और कौशल उन्नयन पर बल देना :** शिक्षा व उद्योग की आपसी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, दोनों देशों ने मानव संसाधन गतिशीलता और कौशल उन्नयन पर बल दिया है।

7. **तकनीकी और शैक्षणिक संगम :** भारत-यूएई साझेदारी शिक्षा और तकनीक को एकीकृत कर नवाचार गलियारा बना रही है, जो दक्षिण एशिया और अरब क्षेत्र के बीच सहयोग को नई ऊँचाई तक ले जा रही है।

भारत-यूएई रक्षा और रणनीतिक सहयोग : साझेदारी की नई परिभाषा

1. **रणनीतिक संवाद में नई ऊँचाई :** दोनों देशों के बीच रक्षा वार्ता अब सचिव स्तर तक पहुँच गई है, जो संयुक्त सुरक्षा ढांचे की दिशा में बढ़ते संस्थागत विश्वास और सहयोग को दर्शाती है।

2. **समन्वित सैन्य अभ्यास :** डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट फ्लैग, और भारत-फ्रांस-यूएई त्रिपक्षीय अभ्यास जैसे संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से दोनों सेनाएँ आपसी तालमेल, परिचालन दक्षता और युद्ध-सिद्धता को मज़बूत कर रही हैं।

3. **समुद्री और क्षेत्रीय सुरक्षा में साझेदारी :** इन अभ्यासों का फोकस हिंद महासागर क्षेत्र और पश्चिम एशिया में आतंकवाद-रोधी उपायों, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और व्यापक क्षेत्रीय स्थिरता पर है — जो साझा रणनीतिक चिंताओं का प्रमाण है।

4. **रक्षा विनिर्माण और औद्योगिक सहयोग :** भारतीय रक्षा कंपनियाँ IDEX, दुबई एयरशो जैसे वैश्विक मंचों पर अपनी स्वदेशी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रही हैं, जिससे रक्षा प्रौद्योगिकी में साझेदारी को गति मिल रही है।

5. **तेजस परियोजना में अमीराती भागीदारी :** यूएई की कंपनियाँ तेजस हल्के लड़ाकू विमान के निर्माण में सक्रिय सहयोग कर रही हैं, जो रक्षा तकनीकी सहयोग में विश्वास और पारदर्शिता की मिसाल है।

6. **ड्रोन और एंटी-ड्रोन समाधान :** युद्धक्षेत्र की आधुनिक चुनौतियों को देखते हुए, दोनों देश मानव रहित विमान प्रणालियों और उनके प्रतिरोधी समाधानों के संयुक्त अनुसंधान और निर्माण पर काम कर रहे हैं।

7. **रक्षा कूटनीति का विस्तार :** DefExpo और Gulf Defence Exhibition जैसी प्रदर्शनों में पारस्परिक भागीदारी, भारत और यूएई के बीच रक्षा-संबंधी कूटनीतिक संवाद को निरंतर प्रगाढ़ कर रही है।

स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य की दिशा में परमाणु ऊर्जा सहयोग :

1. **वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य :** यूएई अपनी कुल विद्युत आवश्यकताओं का लगभग 25% परमाणु स्रोतों से पूरा करता है, जिसकी कुल क्षमता 5.6 गीगावाट है।

2. **भविष्य का रोडमैप (2030 तक) :** यूएई 2030 तक अपनी परमाणु क्षमता को दोगुना करने की योजना पर कार्य कर रहा है, जो ऊर्जा विविधीकरण की दिशा में एक रणनीतिक प्रयास है।

3. **PACE सहयोग: वैश्विक भागीदारी :** भारत और यूएई, PACE (Partnership for Accelerating Clean Energy) पहल के तहत अमेरिका और फ्रांस के साथ मिलकर स्वच्छ परमाणु ऊर्जा के प्रसार में सहयोग कर रहे हैं।

4. **नेट-ज़ीरो लक्ष्य के लिए सहयोग :** परमाणु ऊर्जा एक कार्बन-मुक्त और भरोसेमंद आधारभूत ऊर्जा स्रोत के रूप में दोनों देशों के जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को सशक्त करता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

5. **बराक परियोजना में भागीदारी :** भारत की तकनीकी भागीदारी बराक परमाणु संयंत्र में है — जो अरब क्षेत्र का पहला बहु-इकाई चालू संयंत्र है — यह रणनीतिक सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण है।

6. **प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान :** भारतीय और अमीराती परमाणु एजेंसियों के बीच सुरक्षा मानकों, प्रशिक्षण और नियामक ढाँचे के क्षेत्र में निरंतर संवाद चल रहा है।

7. **ऊर्जा सुरक्षा का साझा दृष्टिकोण :** यह सहयोग भारत और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा को एक नई मजबूती देता है और व्यापक रणनीतिक साझेदारी का आधार बनता है।

रणनीतिक संसाधन, अंतरिक्ष और अवसंरचना सहयोग :

1. **महत्वपूर्ण खनिजों पर साझेदारी :** वर्ष 2024 में हस्ताक्षरित खनिज सहयोग समझौता का उद्देश्य लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसी हरित प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को पूरा करना है।

2. **अंतरिक्ष अनुसंधान में भागीदारी :** दोनों देश उपग्रह विकास, नेविगेशन और ध्रुवीय मिशनों में साझा अनुसंधान कर रहे हैं, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग की नींव रखता है।

3. **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEC) – एकीकृत कनेक्टिविटी की परिकल्पना :** भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEC) वस्तुओं, ऊर्जा और डेटा को जोड़ने वाली एक आधुनिक, बहु-स्तरीय अवसंरचना दृष्टि प्रस्तुत करता है।

4. **सब-सी केबल्स और डिजिटल नेटवर्किंग :** गलियारे में प्रस्तावित समुद्र तलीय केबल्स, एशिया, खाड़ी और यूरोप के बीच तेज़, सुरक्षित और संप्रभु डेटा ट्रांसफर को सुनिश्चित करेंगे।

5. **सीमा पार ऊर्जा ग्रिड :** तीनों क्षेत्रों के बीच ऊर्जा साझा करने के लिए विद्युत ग्रिड इंटरकनेक्शन की योजना, ऊर्जा क्षेत्र में गहराई से जुड़ाव का संकेत देती है।

6. **लॉजिस्टिक हब और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क :** भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEC) के तहत मल्टी-मॉडल परिवहन व्यवस्था से व्यापारिक वस्तुओं की आवाजाही अधिक तेज़, सस्ती और कुशल हो जाएगी।

7. **संयुक्त निवेश प्रयास :** यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स IMEEC में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण में भागीदार बन सकते हैं, जिससे परियोजनाओं को पूंजी और रणनीतिक सहयोग दोनों मिलेगा।

नवाचार आधारित सहयोग और सतत विकास की दिशा में I2U2 पहल :

1. **क्षेत्रीय चौकड़ी का उदय :** I2U2 (भारत, इज़राइल, यूएई, अमेरिका) को "पश्चिम एशिया का क्वाड" कहा जा सकता है। यह मंच आर्थिक साझेदारी, तकनीकी नवाचार और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक सहयोग तंत्र के रूप में उभरा है।

2. **खाद्य सुरक्षा में निवेश :** यूएई के वित्तीय सहयोग से गुजरात में दो आधुनिक फूड पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करना और उत्पादन चक्र में खाद्य अपव्यय को न्यूनतम करना है।

3. **हरित ऊर्जा की ओर कदम :** I2U2 के माध्यम से 2030 तक गुजरात और राजस्थान में 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को बल मिलेगा।

4. **स्वच्छ तकनीकी साझेदारी :** यह मंच सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और स्मार्ट ग्रिड जैसी आधुनिक तकनीकों में सहयोग के लिए कार्य कर रहा है, जो सतत भविष्य की आधारशिला बनेगा।

5. **निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी :** I2U2 सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल को प्रोत्साहित करता है, जिसके अंतर्गत चारों देशों की प्रमुख कंपनियाँ साझा परियोजनाओं में निवेश और तकनीकी सहयोग कर रही हैं।

6. **कृषि तकनीक में नवाचार :** AI-सक्षम खेती, जल संरक्षण, और नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी समाधानों के माध्यम से खाद्य उत्पादन को टिकाऊ और जलवायु-संवेदनशील बनाने पर विशेष ज़ोर दिया गया है।

7. **वैश्विक दक्षिण के लिए उदाहरण :** I2U2 एक ऐसा कार्यशील मॉडल है, जो विशेष रूप से संयुक्त आर्थिक परियोजनाओं और विकास साझेदारी के संदर्भ में दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए नई दिशा और संभावनाएँ प्रस्तुत करता है।

वैश्विक मंचों पर भागीदारी और अफ्रीकी क्षेत्र में विस्तार :

1. **ब्रिक्स में यूएई की भूमिका :** यूएई के हालिया ब्रिक्स में प्रवेश से उसकी भू-राजनीतिक स्थिति और मजबूत हुई है, जिससे वह एशिया-अफ्रीका के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है।

2. **भारत-अफ्रीका समन्वय :** भारत, यूएई को एक रणनीतिक सेतु मानते हुए अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार, अवसंरचना और विकास सहयोग को नई गति देने की दिशा में कार्य कर रहा है।

3. **सीईपीए नेटवर्क का रणनीतिक लाभ :** भारत, यूएई के साथ-साथ उसके 25 से अधिक सीईपीए समझौतों का लाभ उठाकर अमीरात को वैश्विक आपूर्ति केंद्र के रूप में उपयोग कर सकता है।

4. **ऊर्जा-गहन औद्योगिक आकर्षण :** यूएई की कम लागत वाली ऊर्जा और स्थिर नियामक ढांचा रसायन, उर्वरक और धातु जैसे क्षेत्रों में भारतीय निवेश के लिए आदर्श अवसर प्रदान करता है।

5. **लॉजिस्टिक हब के रूप में यूएई :** यूएई, भारतीय व्यापार के लिए पश्चिम एशिया और अफ्रीका का प्रवेश द्वार बनता जा रहा है, जो ट्रांसशिपमेंट, निवेश और निर्यात के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

6. **बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग :** भारत और यूएई, G20, ब्रिक्स और IORA जैसे वैश्विक मंचों पर साझा हितों को आगे बढ़ाते हुए नीति समन्वय को सुदृढ़ कर रहे हैं।

7. **निवेश और कानूनी स्थिरता :** यूएई का मजबूत मध्यस्थता ढांचा और निवेशक-अनुकूल कानून भारतीय कंपनियों को सुरक्षा और भरोसे का वातावरण प्रदान करता है।

परंपरा और साझेदारी का संगम सांस्कृतिक कूटनीति :

1. **अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर :** सांस्कृतिक प्रतीक : अबू धाबी में उद्घाटित बीएपीएस हिंदू मंदिर अरब जगत का पहला पारंपरिक मंदिर है, जो सांस्कृतिक संवाद और सहिष्णुता का प्रतीक है।

2. **धार्मिक सह-अस्तित्व का आदर्श :** यह मंदिर यूएई में अंतर धार्मिक सौहार्द और विविधता को सम्मान देने की परंपरा को दर्शाता है, जिसे वहाँ की नेतृत्वकर्ता नीति समर्थन देती है।

3. **प्रवासी भावनाओं का जुड़ाव :** यूएई में रह रहे 3.5 मिलियन भारतीय प्रवासी इस पहल को भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव के रूप में देख रहे हैं, जिससे 'पीपल-टू-पीपल' संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं।

4. **सॉफ्ट पावर की प्रस्तुति :** भारत, इस सांस्कृतिक सहयोग का उपयोग बहुलवाद, समावेशिता और शांति के वैश्विक संदेश को प्रसारित करने हेतु करता है।

5. **सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रम :** शैक्षणिक, कलात्मक और विरासत आधारित कार्यक्रम दोनों समाजों की आपसी समझ और सामंजस्य को प्रोत्साहित करते हैं।

6. **धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा :** इस मंदिर के माध्यम से भारत, आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में सक्रिय है, जिससे आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों लाभ अपेक्षित हैं।

7. **द्विपक्षीय सौहार्द का प्रतीक :** यूएई सरकार द्वारा इस मंदिर को समर्थन, आपसी विश्वास और साझा मूल्यों का प्रमाण है, जो दोनों देशों के दीर्घकालिक सांस्कृतिक सहयोग को परिभाषित करता है।

निष्कर्ष :

- भारत और यूएई के संबंध अब सिर्फ व्यापारिक सहयोग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्होंने रक्षा, ऊर्जा, वित्तीय नवाचार, शिक्षा, अवसंरचना, और सांस्कृतिक संवाद तक अपने संबंधों को व्यापक विस्तार दिया है।
- सीईपीए, स्थानीय मुद्रा व्यापार और I2U2 जैसी पहलें आर्थिक एकीकरण को गति देती हैं।
- वहीं I2U2, IMEEC और ब्रिक्स में यूएई की सक्रियता भारत की वैश्विक रणनीतिक पहुँच को और गहरा बनाती है।
- यह साझेदारी, 21वीं सदी के लिए स्थायित्व, विकास और बहुपक्षीय समन्वय का एक आदर्श मॉडल बनकर उभर रही है।
- भारत और यूएई के संबंध अब एक बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ रही है।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. हाल के भारत-यूएई संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र अरब जगत का पहला बहु-इकाई परमाणु संयंत्र है, जिसमें भारत की भागीदारी है।
2. यूएई में लॉन्च किया गया जयवान कार्ड भारत की रुपे टेक्नोलॉजी स्टैक पर आधारित है।
3. I2U2 समूह में भारत, यूएई, यूके और यूएसए शामिल हैं।
4. भारत और यूएई के बीच सीईपीए 2023 में लागू होगा।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 4

C. केवल 1, 2 और 3 D. केवल 1, 2 और 4

उत्तर - (a)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार से परे स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल वित्त, रक्षा और बहुपक्षीय सहयोग जैसे क्षेत्रों में बढ़ती रणनीतिक साझेदारी किस प्रकार भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक भूमिका को प्रभावित कर रही है? इस साझेदारी के व्यापक महत्व पर चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

पूर्वी सीमा से पश्चिमी मोर्चे तक : अपाचे AH-64E के साथ भारतीय वायुसेना के नए युग का आगाज

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2020 में किए गए 600 मिलियन डॉलर के समझौते के तहत छह अत्याधुनिक अपाचे लड़ाकू हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। प्रारंभिक योजना के अनुसार इनकी डिलीवरी मई से जून 2024 के मध्य अपेक्षित थी।
- मीडिया सूत्रों के अनुसार, अब पहले तीन हेलिकॉप्टर आगामी कुछ सप्ताहों में सेना के विमानन कोर को सौंपे जाने की संभावना है, जबकि शेष तीन इकाइयों की आपूर्ति वर्ष के अंत तक होने की उम्मीद है। यह हेलिकॉप्टर विशेष रूप से पश्चिमी सीमा क्षेत्र में तैनात किए जाएंगे, जिससे ऑपरेशन 'सिंदूर' के पश्चात भारतीय सेना की युद्ध क्षमता और रणनीतिक तैनाती को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

रणनीतिक आयाम :

1. **उन्नत हवाई हमला क्षमता :** अपाचे एएच-64ई हेलीकॉप्टरों के शामिल होने से भारतीय सेना की आक्रामक वायु शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, विशेष रूप से पाकिस्तान की सीमा से लगे पश्चिमी मोर्चे जैसे उच्च खतरे वाले क्षेत्रों में।
2. **मजबूत निरोध :** ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के बाद, अपाचे ने सीमा पार के खतरों और विषम युद्ध रणनीति के खिलाफ भारत की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत किया है।
3. **सेना की स्वतंत्र लड़ाकू वायु शक्ति :** यह एक बदलाव है, जहां भारतीय सेना के पास अब अपने स्वयं के समर्पित हमलावर हेलीकॉप्टर हैं, जिससे नजदीकी हवाई सहायता के लिए भारतीय वायु सेना पर निर्भरता कम हो गई है।
4. **एकीकृत युद्ध समूहों (आईबीजी) में बल गुणन :** आईबीजी में अपाचे की तैनाती भारत की तीव्र हमला क्षमता को बढ़ाती है और आधुनिक संयुक्त हथियार युद्ध सिद्धांत के साथ तालमेल बिठाती है।
5. **शत्रुतापूर्ण सीमाओं के निकट रणनीतिक तैनाती :** जोधपुर में इन हेलीकॉप्टरों को तैनात करने से पश्चिमी सीमा पर त्वरित लामबंदी संभव होगी, जिससे सामरिक गहराई और प्रतिक्रिया समय में सुधार होगा।
6. **क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता को संतुलित करना :** अपाचे, प्रतिद्वंद्वियों पर गुणात्मक बढ़त प्रदान करते हैं, तथा क्षेत्रीय सैन्य संतुलन में योगदान देते हैं, विशेष रूप से पाकिस्तान की पुरानी रोटरी परिसंपत्तियों के संदर्भ में।
7. **दोहरे मोर्चे के परिदृश्यों के लिए तैयारी :** यद्यपि शुरू में इन्हें पश्चिमी सीमा के लिए बनाया गया था, लेकिन अपाचे दो मोर्चों पर संघर्ष बढ़ने की स्थिति में उत्तरी सीमा (एलएसी) जैसे अन्य रणनीतिक स्थानों पर पुनः तैनात किए जाने के लिए लचीलापन और गतिशीलता प्रदान करते हैं।

रक्षा खरीद एवं नीति आयाम :

1. **प्रमुख विदेशी रक्षा सौदा :** 2020 में हस्ताक्षरित 600 मिलियन डॉलर के सौदे के तहत छह अपाचे एएच-64ई हेलीकॉप्टरों की खरीद, वैश्विक साझेदारों से उच्च-स्तरीय, युद्ध-सिद्ध प्लेटफार्मों में भारत के निरंतर निवेश को दर्शाती है।
2. **भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों को मजबूत करना :** यह समझौता भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, विशेष रूप से COMCASA और BECA जैसे समझौतों के ढांचे के तहत, गहरी होती रणनीतिक और सैन्य साझेदारी को रेखांकित करता है।
3. **रक्षा स्रोतों का विविधीकरण :** यह खरीद रूस जैसे पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं से परे रक्षा अधिग्रहणों में विविधता लाने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका लक्ष्य एक संतुलित वैश्विक रक्षा पोर्टफोलियो बनाना है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

4. **विदेशी ओईएम पर निर्भरता :** अमेरिका में आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्याओं के कारण डिलीवरी में देरी से भारत की विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) पर निर्भरता और बाहरी व्यवधानों के प्रति संवेदनशीलता उजागर होती है।

5. **खरीद सुधार की आवश्यकता :** लंबे समय से हो रही देरी भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) के तहत अनुबंध प्रवर्तन, आपूर्ति गारंटी में सुधार और खरीद समय सीमा में लचीलापन लाने के महत्व को उजागर करती है।

6. **ऑफसेट अवसर और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण :** इस तरह के विदेशी रक्षा सौदे भी ऑफसेट क्लॉज और स्थानीय विनिर्माण या रखरखाव की संभावना प्रदान करते हैं - हालांकि इस मामले में, मेक इन इंडिया के किसी महत्वपूर्ण घटक पर प्रकाश नहीं डाला गया है।

7. **स्वदेशी विकल्पों के लिए नीतिगत प्रयास :** इस तरह की देरी एचएएल के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (एलसीएच) प्रचंड जैसे स्वदेशी विकल्पों को बढ़ाने के मामले को मजबूत करती है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है।

8. **बजटीय और रणनीतिक समझौता :** अपाचे बेड़े जैसे उच्च लागत वाले आयातों का घरेलू अनुसंधान एवं विकास तथा पारिस्थितिकी तंत्र विकास में निवेश की तुलना में दीर्घकालिक रणनीतिक मूल्य के लिए सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

एमआरआईटी तालिका : अपाचे एएच-64ई अटैक हेलीकॉप्टर

आयाम	विवरण
आधुनिकीकरण	अत्याधुनिक हमलावर हेलीकॉप्टर अपाचे एएच-64ई के शामिल होने से भारतीय सशस्त्र बलों की आक्रामक हवाई क्षमताओं में वृद्धि होगी।
भूमिका	इसका उपयोग मुख्य रूप से सटीक हमलों, नजदीकी हवाई सहायता, कवच-रोधी मिशनों और विविध युद्ध क्षेत्रों में रात्रिकालीन अभियानों के लिए किया जाता है।
प्रभाव	भारत के हवाई युद्ध पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है, खासकर पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में। ध्रुव, रुद्र और यूएवी जैसे प्लेटफार्मों को पूरक बनाता है, जिससे बहुआयामी युद्ध को सक्षम बनाया जा सकता है।
तकनीकी	उन्नत रडार, हेलफायर मिसाइल, 30 मिमी चेन गन और लंबी दूरी की लक्ष्यीकरण प्रणालियों से लैस। नेटवर्क-केंद्रित युद्ध और दिन-रात संचालन में सक्षम।

संगठनात्मक / संस्थागत आयाम :

1. **सेना विमानन कोर की भूमिका विस्तार :** अपाचे के शामिल होने से सेना विमानन कोर को सहायता-आधारित भूमिका (रसद, निगरानी) से अग्रिम पंक्ति आक्रामक लड़ाकू भूमिका में परिवर्तित कर दिया गया है।

2. **अंतर-सेवा क्षमता अंतराल को पाटना :** समर्पित हमलावर हेलीकॉप्टरों के साथ, सेना सामरिक परिदृश्यों में नजदीकी हवाई सहायता के लिए भारतीय वायु सेना पर परिचालन निर्भरता कम कर देती है।

3. **बेहतर सामरिक लचीलापन :** सेना को एकीकृत हवाई-ज़मीनी अभियानों की योजना बनाने और उन्हें अधिक तेजी से क्रियान्वित करने की स्वायत्तता प्राप्त होती है, जिससे प्रतिक्रिया दक्षता में वृद्धि होती है।

4. **नई कमान संरचनाएं और सिद्धांत :** अपाचे को एकीकृत करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी), कमांड पदानुक्रम और सेना के नेतृत्व वाले हवाई हमलों के लिए तैयार युद्ध सिद्धांतों को अद्यतन करने की आवश्यकता है।

5. **प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र विकास :** अपाचे के प्रभावी उपयोग के लिए पायलट और ग्राउंड क्रू प्रशिक्षण के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है, जिसमें सिम्युलेटर और उन्नत वायु युद्ध स्कूल शामिल हों।

6. **रखरखाव और तकनीकी इकाइयों का विस्तार :** सेना को ऐसे उन्नत प्लेटफार्मों को दीर्घकाल तक स्वतंत्र रूप से बनाए रखने के लिए विशेष तकनीकी और सहायता इकाइयां गठित करनी होंगी।

7. **संयुक्त ऑपरेशन के लिए संस्थागत समन्वय :** इस बदलाव के लिए वायु सेना के साथ समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से संयुक्त मिशनों, हवाई क्षेत्र प्रबंधन, तथा अतिरेक से बचने के लिए परिसंपत्ति विवाद निवारण में।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

भू-राजनीतिक आयाम :

1. **सीमा-केन्द्रित रणनीतिक रुख :** पश्चिमी सीमा के निकट अपाचे की तैनाती पाकिस्तान से सीमा पार शत्रुता को रोकने और सीमा गतिशीलता पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत की तत्परता को दर्शाती है।

2. **भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग में वृद्धि :** यह समझौता भारत और अमेरिका के बीच आपसी विश्वास और रक्षा-औद्योगिक संरेखण को दर्शाता है, जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल हैं।

3. **सैन्य आधुनिकीकरण का प्रक्षेपण :** अपाचे को वायुसेना में शामिल करना भारत के अपने सैन्य बलों को आधुनिक बनाने तथा पश्चिमी सहयोगियों के साथ अंतर-संचालन क्षमता बढ़ाने के व्यापक प्रयासों का प्रतीक है।

4. **क्षेत्रीय शत्रुओं का रणनीतिक प्रतिकार :** भारत द्वारा उन्नत लड़ाकू प्लेटफार्मों का अधिग्रहण चीन की पीएलए आर्मी एविएशन और पाकिस्तान की रोटरी-विंग क्षमताओं के प्रतिकार के रूप में कार्य करता है।

5. **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का संकेत :** यद्यपि यह खरीद भूमि सीमाओं पर केंद्रित है, तथापि यह व्यापक हिंद-प्रशांत सुरक्षा ढांचे में प्रभाव स्थापित करने की भारत की क्षमता को मजबूत करती है।

6. **रणनीतिक संतुलन को प्रोत्साहन :** अन्य क्षेत्रीय शक्तियां भारत की बढ़ती सामरिक वायु शक्ति के आधार पर अपनी स्थिति और नीतियों में समायोजन कर सकती हैं - जिससे क्षेत्र में पुनः समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

7. **वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला सहभागिता :** अमेरिकी रक्षा ठेकेदारों के साथ भारत का जुड़ाव उसे वैश्विक रक्षा उत्पादन और लॉजिस्टिक पारिस्थितिकी तंत्र में और अधिक एकीकृत करता है, तथा रणनीतिक सहयोगियों के साथ संरेखित करता है।

रसद और रखरखाव आयाम :

1. **आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियां उजागर :** अमेरिकी आपूर्ति व्यवधानों के कारण 15 महीने की देरी से भारत के उच्च स्तरीय रक्षा आयातों में बाह्य आपूर्ति झटकों के प्रति जोखिम उजागर होता है।

2. **स्पेयर्स के लिए OEM पर निर्भरता :** अपाचे का निरंतर रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स की विश्वसनीय डिलीवरी और अमेरिकी-आधारित ओईएम (बोइंग) से तकनीकी सहायता पर निर्भर करता है।

3. **एएमसी (एयर मेंटेनेंस कमांड) की तत्परता की आवश्यकता :** भारत के लॉजिस्टिक्स विंग और एएमसी को अपाचे जैसी सेंसर-समृद्ध, उच्च-परिशुद्धता मशीनों के रखरखाव की जटिलता को संभालने के लिए उन्नत किया जाना चाहिए।

4. **स्वदेशी एमआरओ (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल) क्षमता :** समय के साथ, भारत को अपाचे बेड़े के लागत प्रभावी और तीव्र बदलाव को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय एमआरओ सुविधाएं विकसित करनी चाहिए।

5. **तकनीकी स्टाफ और इंजीनियरों का प्रशिक्षण :** सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए पायलट प्रशिक्षण के साथ-साथ अच्छी तरह से प्रशिक्षित ग्राउंड इंजीनियर और सहायक कर्मचारी भी महत्वपूर्ण हैं।

6. **अतिरिक्त भंडार का निर्माण :** भारत को संकट के दौरान डाउनटाइम को रोकने के लिए महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियार मॉड्यूल का बफर इन्वेंटरी बनाए रखने की आवश्यकता है।

7. **दीर्घकालिक सतत अवसंरचना :** बेड़े के पूर्ण जीवन चक्र समर्थन को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित बुनियादी ढांचे - हैंगर, हथियार भंडारण, सिम्युलेटर और ईंधन भरने की प्रणाली - की स्थापना महत्वपूर्ण है।

आगे की राह :

1. **समय पर डिलीवरी और बेड़े का विस्तार :** क्षमता अंतराल से बचने के लिए खरीद कार्यक्रम का पालन सुनिश्चित करें। खतरे की गतिशीलता के आधार पर अपाचे की तैनाती को उत्तरी मोर्चे (LAC) तक विस्तारित करने पर विचार करें।

2. **स्वदेशी विकास और आत्मनिर्भरता :** आत्मनिर्भर भारत के तहत LCH प्रचंड जैसे स्वदेशी प्लेटफार्मों को गति दें। विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए अनुसंधान एवं विकास और सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा दें।

3. **एकीकृत संचालन एवं संयुक्त कमान :** सेना, वायुसेना और जमीनी इकाइयों के बीच समन्वय को बढ़ाना। त्वरित प्रतिक्रिया के लिए अपाचे को आईबीजी और थिएटर कमांड में एकीकृत करना।

4. **प्रशिक्षण, रखरखाव और बुनियादी ढांचा :** समर्पित प्रशिक्षण सुविधाएं और सिमुलेटर स्थापित करें। रखरखाव के बुनियादी ढांचे को मजबूत करें और स्पेयर सप्लाई चेन को सुरक्षित करें।

5. **रणनीतिक तैनाती :** राजस्थान और पंजाब जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अपाचे तैनात करें। संयुक्त मिशनों में ISR, नजदीकी हवाई सहायता और एंटी-आर्मर भूमिकाओं के लिए उपयोग करें।

निष्कर्ष :

भारतीय सेना में अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों का शामिल होना भारत की हवाई युद्ध क्षमता में एक महत्वपूर्ण छलांग है, खासकर पश्चिमी क्षेत्र में। देरी के बावजूद, उनके आने से सामरिक युद्ध के मैदान में मारक क्षमता, गति और सटीकता बढ़ेगी। हालाँकि, यह प्रकरण आत्मनिर्भरता, सुव्यवस्थित खरीद और भविष्य के लिए भारत की रक्षा रणनीति के महत्व को भी रेखांकित करता है। दीर्घकालिक रक्षा आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

विदेशी अधिग्रहण और स्वदेशी प्लेटफार्मों के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अपाचे AH-64E एचएएल द्वारा विकसित एक स्वदेशी हमलावर हेलीकॉप्टर है।
2. भारतीय सेना ने 2020 में अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
3. अपाचे हेलीकॉप्टर हेलफायर मिसाइलों और उन्नत लक्ष्यीकरण प्रणालियों से लैस हैं।
4. इन हेलीकॉप्टरों को शुरुआत में भारत की पूर्वी सीमा पर तैनात किया जाएगा।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 4 B. केवल 2 और 3

C. केवल 1, 2 और 3 D. केवल 2, 3 और 4

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारतीय सेना में अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों को शामिल करने का सामरिक और परिचालन महत्व क्या है, और इसमें देरी से होने वाली आपूर्ति एवं विदेशी निर्भरता को देखते हुए भारत के रक्षा आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण प्रयासों को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत बनाम वैश्विक बाज़ार : ग्लोबल मंदी की चपेट में भारत का हीरा उद्योग

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत का हीरा उद्योग चर्चाओं में है, जिसकी मुख्य वजह वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निर्यात में आई 17% की तीव्र गिरावट है। यह आंकड़ा अब घटकर 13.3 अरब डॉलर पर पहुँच गया है। इस गिरावट की प्रमुख वजह अमेरिका द्वारा भारतीय हीरों पर आयात शुल्क को 10% से बढ़ाकर 27% तक कर देना है, जिसने वैश्विक व्यापार को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
- इसके साथ ही, वैश्विक स्तर पर महंगाई की मार और प्रयोगशाला में तैयार किए जा रहे सस्ते हीरों की बढ़ती स्वीकार्यता ने प्राकृतिक हीरों की मांग को कमज़ोर किया है। इन बाधाओं के बावजूद, भारत – खासकर सूरत – आज भी हीरों की कटिंग और पॉलिशिंग में विश्व का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।
- भारत के हीरा उद्योग की वर्तमान स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, भारत सरकार ने उद्योग के पुनरुत्थान के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें लैब-ग्रोन डायमंड (प्रयोगशाला-निर्मित हीरों) के उत्पादन को प्रोत्साहन और स्थायित्व के उपायों को बढ़ावा देना शामिल है। सरकार की यह रणनीति उद्योग को न केवल मौजूदा संकट से उबारने, बल्कि भविष्य के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक प्रयास है।

भारत की चमकदार विरासत हीरा उद्योग की ऐतिहासिकता की पृष्ठभूमि :

- भारत और हीरों का संबंध सदियों पुराना है। प्राचीन काल में जब विश्व में हीरे के सीमित स्रोत थे, तब दक्षिण भारत की गोलकुंडा की खदानें विश्व भर में बेशकीमती हीरों का प्रमुख स्रोत थीं। उस समय भारत न केवल हीरों का खनन करता था, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा केंद्र भी था। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में हीरे की नई खदानों की खोज से पहले, भारत ही इस बहुमूल्य रत्न का प्रमुख आपूर्तिकर्ता माना जाता था।
- वर्तमान भारतीय हीरा उद्योग की नींव 20वीं शताब्दी के मध्य में मजबूत हुई, विशेषकर 1950 के दशक के बाद, जब उदारीकृत व्यापार नीतियाँ और गुजरात के व्यापारिक समुदायों की दूरदर्शी सोच ने इस क्षेत्र को गति दी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया, जब म्यांमार (तत्कालीन बर्मा) के हीरा शिल्पकार भारत आए और अपने साथ परिष्कृत कारीगरी और कौशल लाए। इससे भारत में हीरा तराशने और पॉलिशिंग की पारंपरिक क्षमताओं को एक नई दिशा मिली।
- समय के साथ, विशेष रूप से गुजरात में, इस उद्योग ने विकेंद्रीकृत कारीगरी इकाइयों का एक मजबूत तंत्र खड़ा किया, जिसने भारत को वैश्विक हीरा प्रसंस्करण में अग्रणी बना दिया है।

भारत के प्रमुख हीरा केंद्र :

1. **सूरत** – विश्व के लगभग 80% हीरों की कटाई और पॉलिशिंग यहीं होती है। आधुनिक तकनीकों और कुशल श्रमिकों की बदौलत यह शहर उद्योग की रीढ़ बना हुआ है।

2. **मुंबई** – भारत डायमंड बोर्स (BDB) के माध्यम से यह शहर एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निर्यात केंद्र की भूमिका निभाता है।

3. **भावनगर व नवसारी** – गुजरात के ये शहर सहायक इकाइयों के रूप में सूरत के उत्पादन तंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं।

4. **जयपुर** – रंगीन रत्नों और परंपरागत आभूषण शिल्प के लिए प्रसिद्ध, यह शहर निर्यात की विविधता में योगदान देता है।

भारत में हीरा उद्योग का आर्थिक महत्व :

1. **प्रमुख जीडीपी योगदानकर्ता के रूप में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देना :** भारत में हीरा उद्योग, रत्न एवं आभूषण क्षेत्र का एक प्रमुख स्तंभ है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 7% का योगदान देता है। यह न केवल मूल्य वर्धित उत्पादन में सहायक है, बल्कि भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

2. **विदेशी मुद्रा अर्जन का प्रमुख स्रोत :** हीरा निर्यात भारत के कुल व्यापारिक निर्यात का 10% से अधिक हिस्सा बनाता है। पेट्रोलियम उत्पादों के बाद, यह उद्योग दूसरे सबसे बड़े विदेशी मुद्रा अर्जक के रूप में स्थापित है, जिससे भारत की व्यापार संतुलन रणनीति को मजबूती मिलती है।

3. **रोजगार सृजन का विशाल आधार :** यह क्षेत्र प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 50 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है, जिनमें से अधिकांश कटाई, पॉलिशिंग और पैकेजिंग जैसे कार्यों में संलग्न हैं। खासकर, MSME इकाइयों की भूमिका इस रोजगार सृजन में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

4. **लघु एवं मध्यम उद्यम (SMEs) का आधार स्तंभ :** हीरा उद्योग में कार्यरत हज़ारों लघु एवं मध्यम उद्यम (SMEs) मूल्य श्रृंखला की रीढ़ हैं। ये इकाइयाँ समावेशी विकास को बढ़ावा देती हैं, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करती हैं और स्थानीय उद्यमिता को सशक्त करती हैं।

5. **शहरी औद्योगिक विकास का उत्प्रेरक :** सूरत, मुंबई, जयपुर जैसे शहरी केंद्रों में हीरा उद्योग ने औद्योगिक गतिविधियों, बुनियादी ढांचे और सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा दिया है, जिससे शहरी अर्थव्यवस्था का तीव्र विस्तार हुआ है।

6. **सहायक क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना :** हीरा उद्योग ने परिशुद्धता उपकरण, डिज़ाइन, लॉजिस्टिक्स, प्रमाणन और प्रशिक्षण जैसे अनेक सहायक उद्योगों को बढ़ावा दिया है, जिससे औद्योगिक उत्पादकता और नवाचार की समग्र क्षमता में वृद्धि हुई है।

7. **लचीलापन और निर्यात अनुकूलनशीलता :** वैश्विक स्तर पर आर्थिक अस्थिरताओं के बावजूद, भारत का हीरा उद्योग प्रयोगशाला-निर्मित हीरों (LGD) की ओर रुख कर रहा है और नए निर्यात बाजारों की तलाश में नवाचार और अनुकूलनशीलता का प्रदर्शन कर रहा है।

भारत के हीरा उद्योग में प्रौद्योगिकी और नवाचार :

1. **स्वचालन और मशीन-आधारित उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार होना :** भारत के हीरा उद्योग में मैनुअल प्रक्रियाओं की जगह अब लेजर कटिंग, सीएनसी मशीनें और रोबोटिक्स ले रहे हैं, जिससे गुणवत्ता, सटीकता और उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार आया है।

2. **कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण तकनीकों का उपयोग करना :** AI और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग कच्चे हीरों की पहचान, ग्रेडिंग और गुणवत्ता नियंत्रण में हो रहा है, जिससे उपज अनुकूलन संभव हुआ है।

3. **फेनिक्स जैसी उन्नत रोबोटिक प्रणालियों का उपयोग करना :** फेनिक्स जैसी उन्नत रोबोटिक प्रणालियाँ, बड़े पैमाने पर कटिंग कार्य को स्वचालित कर रही हैं, जिससे मानव-त्रुटि में कमी और तेज़ उत्पादन संभव हो पाया है।

4. **डिजिटल एकीकरण और ट्रैकिंग में आधुनिक प्रणालियों को शामिल करना :** इस उद्योग में अब डिजिटल वर्कफ़्लो, इन्वेंट्री प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला पर निगरानी के लिए आधुनिक प्रणालियाँ अपनाई जा रही हैं।

5. **ब्लॉकचेन के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करना :** हीरों की स्रोत-ट्रेसेबिलिटी और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे उपभोक्ता विश्वास को बल मिलता है।

6. **सटीक मूल्यांकन और दोष पहचान की प्रक्रियाओं का उपयोग करना :** कंप्यूटर विज़न और मशीन लर्निंग तकनीकों के उपयोग से सटीक मूल्यांकन और दोष पहचान की प्रक्रियाएं सशक्त हुई हैं।

7. **अनुसंधान में बढ़ता निवेश :** हीरा कंपनियाँ अब इन-हाउस रिसर्च लैब्स और अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों में निवेश कर रही हैं, ताकि उत्पादन को अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

प्रयोगशाला में विकसित हीरे (LGD) का भविष्य :

1. **भारत का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बनकर उभरना :** भारत LGD का सबसे बड़ा निर्यातक और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है। यह क्षेत्र भारत की नई व्यापार रणनीति का प्रमुख घटक बनता जा रहा है।

2. **भारत की वैश्विक हीरा आपूर्ति में तेज़ी से बढ़ती हिस्सेदारी :** प्रयोगशाला में विकसित हीरे (LGD) का भारत की वैश्विक हीरा आपूर्ति में 16% योगदान है, और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. **लागत और उपभोक्ता-हित में अत्यंत आकर्षक विकल्प बनना :** प्राकृतिक हीरों की तुलना में 30–40% कम कीमत वाले ये हीरे मूल्य-संवेदनशील बाजारों के लिए अत्यंत आकर्षक विकल्प बनते जा रहे हैं।

4. **सतत विकास के लिए हरित उपभोग की ओर बढ़ता कदम :** सतत विकास और नैतिक सोर्सिंग की वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप, LGD को एक पर्यावरण-मित्रवत विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

5. **अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती मांग :** पर्यावरणीय कारणों और सामर्थ्य की वजह से अमेरिका और यूरोप जैसे बाजारों में LGD की मांग तेजी से बढ़ रही है।

6. **सरकारी समर्थन और ढांचागत विकास :** PLI योजनाओं, अनुसंधान अनुदानों और नीति समर्थन के माध्यम से भारत सरकार LGD उद्योग को रणनीतिक प्रोत्साहन दे रही है।

7. **निर्यात विविधीकरण और प्रतिस्पर्धी लाभ के संबंध में भविष्य की संभावना :** भारत के हीरा उद्योग के संबंध में एक अनुमान यह है कि 2030 तक LGD वैश्विक हीरा बिक्री का 25% हिस्सा ले सकते हैं, जिससे भारत को निर्यात विविधीकरण और प्रतिस्पर्धी लाभ मिल सकता है।

भारत का हीरा निर्यात : वर्तमान रुझान और प्रमुख चुनौतियाँ :

1. **निर्यात मूल्य में गिरावट :** वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का हीरा निर्यात 13.3 बिलियन डॉलर तक सिमट गया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में करीब 17% की गिरावट को दर्शाता है। यह मंदी वैश्विक मांग में ठहराव और आपूर्ति श्रृंखला में चुनौतियों का परिणाम है।

2. **वैश्विक बाजार में कीमत प्रतिस्पर्धा को कमजोर होना :** 10% से लेकर 27% तक के अमेरिकी आयात शुल्कों ने भारतीय हीरों की वैश्विक बाजार में कीमत प्रतिस्पर्धा को कमजोर किया है, जिससे निर्यातकों के लाभ पर सीधा प्रभाव पड़ा है।

3. **भू-राजनीतिक संकट से आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होना :** रूसी हीरों पर यूरोपीय संघ और G7 देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने आपूर्ति स्रोतों में बड़ी कटौती की है। रूस, जो भारत का प्रमुख कच्चा हीरा आपूर्तिकर्ता था, अब अप्रत्याशित संकट का केंद्र बन चुका है।

4. **मुद्रास्फीति के कारण वैश्विक उपभोक्ता बाजारों में हीरे की मांग का प्रभावित होना :** मुद्रास्फीति, बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताएँ और आर्थिक अनिश्चितताओं ने अमेरिका और यूरोप जैसे प्रमुख बाजारों में हीरे की मांग को प्रभावित किया है। यह गिरावट मांग-आपूर्ति संतुलन को अस्थिर कर रही है।

5. **भविष्य की आशंकाएँ :** ICRA के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 तक भारत के हीरा निर्यात में और 7-10% की गिरावट की संभावना है, जो वैश्विक स्तर पर अनुकूल वातावरण की कमी का संकेत देती है।

6. **प्राकृतिक बनाम प्रयोगशाला में बने हीरों के बीच मूल्य दबाव का होना :** एलजीडी (Laboratory-Grown Diamonds) के बढ़ते बाजार ने पारंपरिक हीरा उद्योग पर मूल्य दबाव बना दिया है। उपभोक्ताओं की पसंद में हो रहे बदलाव से प्राकृतिक हीरों की मांग कम हो रही है।

7. **मुद्रा उतार-चढ़ाव और बढ़ती रसद लागत :** रुपये में अस्थिरता और लाल सागर जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में तनावपूर्ण स्थिति ने शिपिंग लागत को बढ़ाया है, जिससे निर्यात मार्जिन पर और दबाव पड़ा है।

सुधार और नवाचार की दिशा में आगे की राह :

1. **एलजीडी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की जरूरत :** देश में प्रयोगशाला में बने हीरों के उत्पादन को सशक्त करने हेतु अनुसंधान एवं विकास में निवेश आवश्यक है। आयातित बीजों पर निर्भरता घटाकर स्वदेशी तकनीक को प्राथमिकता देना चाहिए।

2. **ब्रांड की नैतिक और हरित पहचान का निर्माण करने की आवश्यकता :** जिम्मेदार स्रोतों से प्राप्त हीरे, पर्यावरणीय प्रमाणन और ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसेब्लिटी के माध्यम से भारत को वैश्विक उपभोक्ताओं के बीच भरोसेमंद और टिकाऊ ब्रांड के रूप में स्थापित करना होगा।

3. **व्यापारिक बाधाओं को दूर करने हेतु सक्रिय वार्ता करने और बाजार विस्तार करने की आवश्यकता :** भारत को अमेरिका, यूरोपीय संघ, G7 और खाड़ी देशों के साथ टैरिफ में छूट और व्यापारिक बाधाओं को दूर करने हेतु सक्रिय वार्ता करनी चाहिए, जिससे नए बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।

4. **घरेलू खपत को प्रोत्साहन देना :** भारतीय उपभोक्ताओं के बीच आभूषणों की मांग को सशक्त करने के लिए वित्तीय योजनाएं (जैसे EMI) और जागरूकता अभियान शहरों और टियर-2 क्षेत्रों में चलाए जाने चाहिए।

5. **डिजाइन और निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करने की आवश्यकता :** "प्लग एंड प्ले" ज्वेलरी पार्क, डिज़ाइन इनक्यूबेशन सेंटर और निर्यात-आधारित क्लस्टर स्थापित कर मूल्य श्रृंखला को संपूर्ण रूप में विकसित किया जा सकता है।

6. **कौशल निर्माण और समावेशिता पर ज़ोर देने की आवश्यकता :** पॉलिशिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और रिटेल जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देते हुए, IDI जैसे संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार जरूरी है।

7. **कार्बन-तटस्थ तकनीक तथा हरित और वृत्ताकार उत्पादन मॉडल को अपनाने की आवश्यकता :** कार्बन-तटस्थ तकनीकों, नवीकरणीय ऊर्जा और हीरे के अपशिष्ट के पुनर्चक्रण को बढ़ावा

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

देकर भारत को एक पर्यावरण-अनुकूल हीरा उत्पादक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

निष्कर्ष : भारत का हीरा उद्योग एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर

- भारत का हीरा उद्योग आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ परंपरा और नवाचार के बीच संतुलन साधना अनिवार्य हो गया है। युगों से चली आ रही इसकी शिल्प-परंपरा और वैश्विक प्रतिष्ठा अब तकनीकी उन्नयन, नैतिक व्यापार और पर्यावरणीय संवेदनशीलता के साथ कदम मिलाने को बाध्य है।
- वर्तमान वैश्विक परिदृश्य, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला की अस्थिरता, उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव और भू-राजनीतिक तनाव जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं—एक ओर जहाँ जोखिम प्रस्तुत करता है, वहीं दूसरी ओर भारत के लिए नेतृत्व स्थापित करने का एक अभूतपूर्व अवसर भी है।
- वैश्विक स्तर पर विशेषकर, प्रयोगशाला-निर्मित हीरों की ओर बढ़ते रुझान और पारदर्शी व सतत प्रक्रियाओं की माँग को देखते हुए भारत के पास अपनी भूमिका को फिर से परिभाषित करने का समय है।
- यदि नीति- निर्माता, उद्योग जगत और निवेशक समन्वय पूर्वक कार्य करें, तो भारत इस क्षेत्र में न केवल प्रतिस्पर्धी बना रह सकता है, बल्कि वैश्विक रत्न एवं आभूषण उद्योग को नैतिकता, गुणवत्ता और नवाचार के नए मानकों की ओर भी ले जा सकता है।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत में हीरा उद्योग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. सूरत भारत में हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है।
2. भारत प्रयोगशाला में विकसित हीरों (एलजीडी) का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है।
3. हीरा उद्योग में ट्रेसेबिलिटी और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3

उत्तर - (c)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. वैश्विक उथल-पुथल और प्रयोगशाला में विकसित हीरों के बढ़ते प्रचलन के बीच, भारत का हीरा उद्योग किन प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहा है ? इसके साथ ही चर्चा कीजिए कि इस उद्योग में स्थिरता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए कौन-कौन से आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

क्वांटम प्रकाश से युक्त सिलिकॉन चिप : स्केलेबिलिटी की ओर बढ़ता एक कदम

खबरों में क्यों?

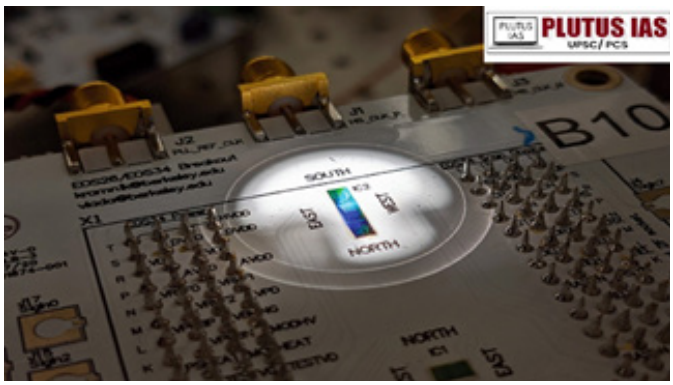

- हाल ही में नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी, बोस्टन यूनिवर्सिटी और यूसी बर्कले के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी पहली सिलिकॉन चिप का निर्माण किया है जो क्वांटम फोटोनिक प्रकाश स्रोतों को पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण सर्किटों के साथ संयोजित करती है। केवल 1x1 मिलीमीटर की यह सूक्ष्म चिप स्वतः ही क्वांटम फोटॉन की युग्मित किरणों का निर्माण और स्थिरीकरण कर सकती है।
- यह उपलब्धि क्वांटम संचार, संवेदन और कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के लिए आवश्यक प्रकाश स्रोतों के भरोसेमंद और बड़े पैमाने पर उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करती है। उल्लेखनीय है कि इस चिप को सामान्य 45-नैनोमीटर CMOS तकनीक से तैयार किया गया है, जिससे इसे औद्योगिक स्तर पर उत्पादित करना संभव हो सकेगा।
- यह नवाचार चिप-आधारित क्वांटम तकनीकों को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।

क्वांटम प्रकाश और फोटोनिक प्रौद्योगिकी से संबंधित मुख्य तथ्य :

1. **क्वांटम प्रकाश :** क्वांटम प्रकाश उन व्यक्तिगत फोटॉनों से बना होता है जो पारंपरिक प्रकाश के विपरीत सुपरपोजिशन और एंटैंगलमेंट जैसी विशिष्ट क्वांटम विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। ये गुण उन्हें क्वांटम सूचना के संग्रहण और प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
2. **सह-संयोजित फोटॉन युग्म :** अक्सर 'फोर-वेव मिक्सिंग' जैसी प्रक्रियाओं से उत्पन्न ये फोटॉन जोड़े आपस में गहरे समय या क्वांटम उलझाव से जुड़े होते हैं। यही विशेषताएँ उन्हें क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार और संवेदन के मूल संसाधन बनाती हैं।
3. **क्वांटम संचार में भूमिका :** ऐसे फोटॉन जोड़े क्वांटम कुंजी वितरण (QKD) जैसे उन्नत संचार प्रोटोकॉल को सक्षम करते हैं, जहाँ किसी भी बाहरी हस्तक्षेप या जासूसी को तुरंत पकड़ा जा सकता है क्योंकि वह क्वांटम स्थिति को प्रभावित करता है।
4. **क्वांटम संवेदन के अनुप्रयोग :** एंटैंगल्ड फोटॉनों का उपयोग मापन की सटीकता और संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इससे इन्हें इंटरफेरोमेट्री और जैव-इमेजिंग जैसी उच्च-प्रदर्शन वाली तकनीकों में विशेष महत्व प्राप्त होता है।
5. **फोटोनिक्स की केंद्रीय भूमिका :** फोटोनिक चिप तकनीक सूक्ष्म प्रकाशीय मार्गों के माध्यम से प्रकाश के प्रवाह को नियंत्रित करती है, जिससे भारी-भरकम ऑप्टिकल सेटअप के बिना ही तेज़, कॉम्पैक्ट और ऊर्जा-कुशल क्वांटम प्रणालियाँ संभव हो पाती हैं।
6. **माइक्रोरिंग रेज़ोनेटर का योगदान :** ये अत्यंत सूक्ष्म प्रकाशीय लूप प्रकाश को सीमित रखते हुए उसमें गहन गैर-रेखीय अंतःक्रिया को बढ़ाते हैं, जिससे वे ऑन-चिप स्तर पर फोटॉन जोड़े उत्पन्न करने के लिए आदर्श विकल्प बनते हैं।
7. **तापीय अस्थिरता की चुनौती :** माइक्रो रिंग रिजोनेटर अत्यधिक ताप-संवेदनशील होते हैं। मामूली तापीय परिवर्तन भी उनके अनुनाद व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे फोटॉन निर्माण अस्थिर हो सकता है।
8. **निर्माण संबंधी जटिलताएँ :** फोटोनिक घटकों के निर्माण में आने वाली सूक्ष्म असंगतियाँ उनके प्रदर्शन में अंतर ला सकती हैं। यह अक्सर बाहरी नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता को जन्म देती है, जिससे स्केलेबिलिटी बाधित होती है।

प्रमुख उपलब्धि : चिप पर निर्मित क्वांटम प्रकाश संयंत्र

1. **एकीकृत मिनिएचर डिज़ाइन :** यह सिलिकॉन चिप केवल 1x1 मिमी^{2} आकार की है, लेकिन इसमें क्वांटम प्रकाश उत्पन्न करने वाले माइक्रोरिंग रेज़ोनेटर, फोटोडायोड तथा पारंपरिक नियंत्रण सर्किट सभी सम्मिलित हैं, जिससे एकीकृत क्वांटम प्रकाश प्रबंधन संभव हो जाता है।
2. **प्रत्येक माइक्रोरिंग एक प्रकाश संयंत्र :** चिप पर मौजूद 12 माइक्रोरिंग अनुनादक स्वतंत्र रूप से फोटॉन जोड़े उत्पन्न करते हैं, जिससे वे "क्वांटम लाइट फैक्ट्री" की तरह कार्य करते हैं, जो कई क्वांटम उपयोगों के लिए आवश्यक स्रोत प्रदान करते हैं।
3. **इनबिल्ट फोटोडायोड द्वारा निगरानी :** इन फोटोडायोड्स को रेज़ोनेटर के समीप संयोजित किया गया है ताकि वे आने वाले लेज़र प्रकाश के साथ संरेखण की निगरानी कर सकें, जिससे सिस्टम की सटीकता बनी रहती है।
4. **तुरंत प्रतिक्रिया करने वाली नियंत्रण प्रणाली :** चिप में लगे ऑन-चिप हीटर और नियंत्रण लॉजिक तापमान भिन्नताओं या निर्माण दोषों के प्रभाव को तुरंत संतुलित करते हैं, जिससे हर रेज़ोनेटर को उसकी आदर्श कार्य आवृत्ति पर संचालित किया जा सकता है।
5. **समानांतर और समन्वित फोटॉन उत्पादन :** सभी 12 स्रोत स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए बिना किसी हस्तक्षेप के एकसाथ फोटॉन उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे प्रणाली स्केलेबल और सिंक्रनाइज़ संचालन के योग्य बनती है।

6. **मानक CMOS तकनीक का उपयोग :** यह चिप पारंपरिक 45-नैनोमीटर CMOS तकनीक से बनाई गई है, जो यह दर्शाती है कि क्वांटम फोटोनिक सिस्टम अब व्यावसायिक अर्धचालक तकनीकों के माध्यम से भी उत्पादित किए जा सकते हैं।

7. **स्केलेबिलिटी और दीर्घकालिक स्थिरता :** चिप के भीतर यह गहन एकीकरण क्वांटम प्रणालियों को न केवल ताप-संवेदनशीलता से मुक्त बनाता है, बल्कि उन्हें दोहराने योग्य और औद्योगिक स्तर पर उत्पाद योग्य भी बनाता है, जिससे क्वांटम टेक्नोलॉजी को व्यापक रूप से अपनाना संभव हो सकता है।

प्रमुख तकनीकी नवाचार और डिज़ाइन की विशेषताएं :

1. **फोटोडायोड आधारित सटीक निगरानी :** प्रत्येक माइक्रोरिंग अनुनादक में एकीकृत फोटोडायोड लगे हैं जो लेज़र संकेतों के साथ संरेखण में किसी भी प्रकार के बदलाव को पहचानते हैं। यह प्रणाली चिप के ऑप्टिकल अनुनाद को वास्तविक समय में नियंत्रित और संतुलित बनाए रखने में सहायक होती है।

2. **ऑन-चिप तापीय नियंत्रण प्रणाली :** रेज़ोनेटर के पास लगे सूक्ष्म हीटर उनके तापमान को आवश्यकता अनुसार समायोजित करते हैं, जिससे अनचाहे आवृत्ति विचलनों को रोका जा सके और लगातार फोटॉन उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

3. **रीयल-टाइम फीडबैक और कंट्रोल लूप तंत्र :** चिप में मौजूद नियंत्रण प्रणाली फोटोडायोड से प्राप्त संकेतों को प्रोसेस करके फोटोनिक घटकों की स्थिति को लगातार समायोजित करती है। यह स्वचालित बंद-लूप तंत्र पूरे सिस्टम को स्थिर बनाए रखता है।

4. **CMOS तकनीक के अनुकूल सह-डिज़ाइन :** इस पूरी प्रणाली—चाहे वो क्वांटम प्रकाश स्रोत हों या नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स—को 45-नैनोमीटर CMOS मानकों के भीतर डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य है इसे पारंपरिक अर्धचालक निर्माण प्रक्रियाओं के अनुरूप बनाना।

5. **स्वतंत्र एवं समांतर स्रोत संचालन :** चिप पर मौजूद सभी 12 प्रकाश स्रोत एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से चलते हुए एक साथ काम कर सकते हैं। इससे मल्टी-चैनल क्वांटम डेटा प्रोसेसिंग और संचार के लिए प्लेटफ़ॉर्म की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है।

6. **क्रॉसटॉक-मुक्त कार्यप्रणाली :** इस डिजाइन में निकटवर्ती रेज़ोनेटरों के बीच तापीय हस्तक्षेप जैसी समस्याओं को प्रभावी ढंग से दूर किया गया है, जिससे कॉम्पैक्ट आकार में भी चिप का संचालन स्थिर और कुशल रहता है।

7. **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के साथ क्वांटम का संगम :** यह वही प्लेटफॉर्म है जिसे अयार लैब्स के सहयोग से विकसित किया गया था और जो एआई-संचालित ऑप्टिकल इंटरकनेक्ट्स को सपोर्ट करता है। अब यही बुनियाद क्वांटम और एआई हार्डवेयर को एकीकृत करने की संभावनाओं को भी दर्शा रही है।

प्रभाव और संभावनाएं : उपयोग की दिशा में बढ़ते कदम

1. **विस्तृत स्तर पर क्वांटम हार्डवेयर का निर्माण :** यह चिप इस बात का प्रमाण है कि क्वांटम फोटोनिक तकनीकों को पारंपरिक CMOS फाउंड्रीज के ज़रिए विश्वसनीय और मापनीय रूप से तैयार किया जा सकता है, जिससे क्वांटम सिस्टम को बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है।

2. **क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए आधारभूत अवसंरचना :** यह एकीकृत चिप भविष्य के क्वांटम प्रोसेसरों में एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में कार्य कर सकती है, जिसमें फोटॉन स्रोत स्थिरता के साथ क्यूबिट्स और लॉजिक गेट्स की रचना संभव होगी।

3. **क्वांटम-संरक्षित डेटा संचार :** चिप का प्रयोग क्वांटम कुंजी वितरण (QKD) में किया जा सकता है, जहाँ फोटॉन युग्मों की उलझी हुई अवस्था डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करती है और किसी भी अनधिकृत हस्तक्षेप का तुरंत पता लगाया जा सकता है।

4. **सटीक मापन और संवेदन अनुप्रयोग :** यह तकनीक बायोमेडिकल इमेजिंग, ग्रेविटी मापन और समय तुल्यकालन जैसे क्षेत्रों में उपयोगी हो सकती है, जहाँ अति-संवेदनशीलता और उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता होती है।

5. **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और सुपरकंप्यूटिंग में इंटरकनेक्ट समर्थन :** इस क्वांटम चिप का ऑप्टिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर हाई-स्पीड डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाता है, जो एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टमों के लिए ऊर्जा-दक्षता के साथ बेहतर प्रदर्शन प्रदान करता है।

6. **मॉड्यूलर क्वांटम नेटवर्किंग का मार्ग :** इस चिप की बहु-स्रोत संचालन क्षमता इसे मॉड्यूलर क्वांटम आर्किटेक्चर के लिए उपयुक्त बनाती है, जो कि नेटवर्क-बेस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग की दिशा में एक आवश्यक कदम है।

7. **अनुसंधान से उद्योग तक का सेतु :** यह प्रगति शोध प्रयोगशालाओं और वाणिज्यिक निर्माण के बीच की दूरी को पाटती है। यह न केवल शिक्षा और विज्ञान जगत को सशक्त बनाती है, बल्कि उद्योगों में व्यावहारिक क्वांटम समाधान अपनाने की गति को भी तेज करती है।

बहु-विषयक सहयोग की ताक़त : अनुसंधान से नवाचार तक

1. **विभिन्न क्षेत्रों का समन्वय :** इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषतायह है कि यह विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों—क्वांटम ऑप्टिक्स, फोटोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग—का एक मंच पर समावेश कर आमतौर पर अलग-अलग काम करने वाले इन क्षेत्रों ने मिलकर एक साथ संयुक्त समाधान को प्रस्तुत करता है।

2. **शैक्षणिक संस्थानों की सहभागिता :** नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी, यूसी बर्कले और बोस्टन यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अपनी विशेषज्ञता—चिप डिज़ाइन, मापन प्रणाली और फोटोनिक एकीकरण—को साझा कर तकनीकी समृद्धि में सहयोग दिया।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. **उद्योग जगत से सशक्त सहभागिता :** ग्लोबलफाउंड्रीज़ (CMOS निर्माण), अयार लैब्स (ऑप्टिकल इंटरकनेक्ट) और साइक्वांटम (क्वांटम कंप्यूटिंग) जैसी अग्रणी कंपनियों की भागीदारी ने शोध को प्रयोगशाला से निकाल कर व्यावसायिक धरातल पर स्थापित करने में मदद की।

4. **इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटोनिक्स का सम्मिलित डिज़ाइन :** इस परियोजना की सफलता का आधार था एक ऐसी प्रणाली का विकास जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रकाशीय घटकों को एक साथ जोड़कर, एकीकृत रूप से मानक CMOS तकनीक पर काम कर सके।

5. **उद्योग-स्तर का निर्माण संभव :** अर्धचालक विनिर्माण इकाइयों के सहयोग से इस चिप को व्यावसायिक रूप से स्थापित प्रक्रियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर निर्मित करना संभव हुआ, जो स्केलेबिलिटी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

6. **विशेषज्ञों की विचारशील टिप्पणियाँ :** मिलोस पोपोविच ने मानक फैब्रिकेशन प्लेटफॉर्म पर क्वांटम डिवाइस निर्माण के महत्व पर ज़ोर दिया; अनिरुद्ध रमेश ने ऑन-चिप नियंत्रण को क्रांतिकारी बताया; और प्रेम कुमार ने इस बहु-विषयक सहयोग की सराहना की।

7. **नवाचार के लिए आदर्श मॉडल के रूप में :** यह परियोजना अंतःविषयक अनुसंधान का एक प्रेरक उदाहरण है, जो प्रयोगशाला में सिमटी तकनीक को व्यावहारिक और मापनीय औद्योगिक समाधान में परिवर्तित करने की दिशा में मार्गदर्शक बनती है।

उद्योग प्रभाव और भविष्य की दिशा : एक नई तकनीकी क्रांति का संकेत

1. **छात्रों का उत्कृष्ट कैरियर विकास :** इस परियोजना से जुड़े स्नातकों ने साइक्वांटम, अयार लैब्स, ऑरोरा और गूगल एक्स जैसी अग्रणी कंपनियों में स्थान पाया, और क्वांटम तथा फोटोनिक नवाचारों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

2. **उद्योग को तैयार उन्नत प्रतिभाएँ :** यह पहल ऐसे इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी को तैयार कर रही है जो उन्नत क्वांटम व ऑप्टिकल तकनीकों में दक्ष हैं और अकादमिक-जगत तथा उद्योग के बीच सेतु का कार्य कर रहे हैं।

3. **सिलिकॉन फोटोनिक्स का बढ़ता वर्चस्व :** क्वांटम प्रकाश स्रोतों और एआई-आधारित ऑप्टिकल इंटरकनेक्ट दोनों के लिए सिलिकॉन फोटोनिक्स एक प्रमुख मंच के रूप में उभर रहा है, जो गति, दक्षता और स्केलेबिलिटी तीनों प्रदान करता है।

4. **मल्टी-चिप क्वांटम सिस्टम का भविष्य :** इस चिप की समानांतर संचालन क्षमता उस आने वाले युग का संकेत देती है जहाँ विभिन्न क्वांटम चिप्स मिलकर समन्वित और शक्तिशाली नेटवर्क बनाएंगे।

5. **क्वांटम नेटवर्किंग की नींव :** स्थिर और ऑन-चिप फोटॉन स्रोतों की उपलब्धता क्वांटम नेटवर्क और संभावित 'क्वांटम इंटरनेट' जैसे भविष्य के दृष्टिकोण को व्यवहारिक आकार देने में मदद करती है।

6. **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और क्वांटम का संभावित संगम :** फोटोनिक्स के ज़रिए एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के बीच सहयोग की संभावना उजागर हो रही है, जिससे दोनों तकनीकों की शक्ति को एक साथ जोड़ा जा सकेगा।

7. **क्वांटम तकनीक का व्यवसायीकरण :** इस चिप का स्थिर, दोहराने योग्य और CMOS-संगत डिज़ाइन क्वांटम तकनीक को औद्योगिक पैमाने पर लागू करने की दिशा में एक ठोस आधार प्रदान करता है।

निष्कर्ष : भविष्य के क्वांटम युग की नींव

- क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और क्वांटम फोटोनिक स्रोतों का एक ही CMOS चिप पर सफल एकीकरण एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
- नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी, बोस्टन यूनिवर्सिटी और यूसी बर्कले के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित यह चिप कॉम्पैक्ट, ताप-स्थिर और औद्योगिक रूप से तैयार करने योग्य है।
- यह नवाचार न केवल तकनीकी बाधाओं को पार करता है, बल्कि क्वांटम कंप्यूटिंग, सुरक्षित संचार, संवेदन और एआई जैसी उभरती हुई तकनीकों में वास्तविक अनुप्रयोगों के द्वार भी खोलता है।
- इस परियोजना ने यह भी सिद्ध किया है कि जब विभिन्न विषयों की विशेषज्ञता मिलती है, तो तकनीक प्रयोगशालाओं की सीमाओं को पार कर, औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त करती है।

स्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. क्वांटम प्रौद्योगिकियों में हालिया प्रगति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. क्वांटम प्रकाश स्रोतों और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण परिपथों को एक ही चिप पर एकीकृत करने का कार्य एक मानक 45-नैनोमीटर CMOS प्रक्रिया का उपयोग करके प्राप्त किया गया है।
2. क्वांटम संचार के लिए आवश्यक सहसंबद्ध फोटॉन युग्म उत्पन्न करने के लिए माइक्रोरिंग रिजोनेटर का उपयोग किया जाता है।
3. इन एकीकृत चिप्स को फोटॉन उत्पादन को स्थिर करने के लिए बाहरी ऑप्टिकल प्रणालियों की आवश्यकता होती है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3

उत्तर - (a)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. एकल CMOS चिप पर क्वांटम फोटोनिक प्रकाश स्रोतों को शास्त्रीय इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण परिपथों के साथ एकीकृत करने के महत्व पर चर्चा कीजिए। यह नवाचार क्वांटम संचार, संवेदन और कंप्यूटिंग की चुनौतियों का समाधान कैसे करता है? साथ ही, भविष्य की तकनीकों, जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और चिप-स्केल क्वांटम नेटवर्क, के लिए इसके संभावित निहितार्थों का भी परीक्षण कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट (WiFEX) : वैज्ञानिक नवाचार और नीतिगत प्रभाव का एक दशक

ख़बरों में क्यों?

- हाल ही में वर्ष 2015 में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGIA) से शुरू किया गया विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट (WiFEX) अब दस वर्ष पूरे कर चुका है। यह उत्तर भारत में घने शीतकालीन कोहरे पर आधारित अग्रणी अनुसंधान परियोजना है।
- इसे विश्व की सबसे व्यापक और दीर्घकालिक कोहरा अनुसंधान पहलों में से एक माना जाता है, जो विशेष रूप से इंडो-गैंगेटिक मैदान पर केंद्रित है।
- इस परियोजना ने कोहरे की गतिशीलता, विविधता और सूक्ष्म भौतिकी को समझने में उल्लेखनीय प्रगति की है। इससे प्राप्त ज्ञान ने उच्च-रिज़ॉल्यूशन कोहरा पूर्वानुमान मॉडल के विकास में सहायता की है, जिसका उपयोग अब विमानन और परिवहन के क्षेत्र में किया जा रहा है।

विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट (WiFEX) का परिचय :

- **उद्देश्य :** WiFEX का मुख्य उद्देश्य इंडो-गैंगेटिक मैदान में घने शीतकालीन कोहरे की उत्पत्ति, संरचना और विविधता का अध्ययन करना है।
- **शुरुआत वर्ष :** इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी।
- **स्थान :** पहले इसे दिल्ली के IGI हवाई अड्डे से शुरू किया गया, फिर इसका विस्तार नोएडा के जेवर हवाई अड्डे और हरियाणा के हिसार तक किया गया।
- **नेतृत्व संस्था :** इस परियोजना का नेतृत्व भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे कर रहा है।
- **संलग्न मंत्रालय :** यह परियोजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के अंतर्गत संचालित है।
- **सहयोगी संस्थाएँ :** भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (NCMRWF) इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

WiFEX का मुख्य उद्देश्य :

1. **कोहरे की सूक्ष्म भौतिकी को समझना** – तापमान उलटना (temperature inversion), आर्द्रता और वायुमंडलीय अशांति के स्वरूपों का अध्ययन करना।
2. **कोहरे की विविधता का विश्लेषण करना** – यह जानना कि किस तरह कोहरे के स्वरूप भौगोलिक और समय की दृष्टि से बदलते हैं।
3. **उच्च सटीकता वाले पूर्वानुमान मॉडल विकसित करना** – त्वरित (nowcasting: 0–6 घंटे) और लघुकालिक भविष्यवाणी के लिए मॉडल तैयार करना।
4. **परिवहन सुरक्षा को सुधारना** – दृश्यता की कमी के कारण उड़ानों, ट्रेनों और सड़क परिवहन में होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना।
5. **आपदा तैयारी में सहायता करना** – कोहरे के पूर्वानुमानों को आपदा चेतावनी प्रणालियों में एकीकृत करना।
6. **विज्ञान और नीति के बीच समन्वय स्थापित करना** – हवाई अड्डा प्राधिकरणों, शहरी योजनाकारों और नीति निर्माताओं को वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध कराना।

7. **स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाना** – भारत के लिए क्षेत्र-विशेष पूर्वानुमान मॉडल और आंकड़े तैयार करना।

WiFEX की प्रमुख विशेषताएँ :

1. **उन्नत उपकरणों का प्रयोग** – माइक्रोमौसमीय टावर, सीलोमीटर और LIDAR का प्रयोग कर कोहरे से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाते हैं।
2. **उच्च आवृत्ति पर वास्तविक समय की निगरानी** – तापमान प्रोफाइल, हवा की गति, अशांति और एरोसोल्स का सतत डेटा संग्रहण किया जाता है।
3. **व्यापक डेटा संग्रह** – मृदा ऊष्मा प्रवाह, सापेक्षिक आर्द्रता, दृश्यता और प्रदूषकों की जानकारी एकत्र की जाती है।
4. **रणनीतिक स्थान चयन** – पहले IGI हवाई अड्डे पर आरंभ हुआ और बाद में जेवर व हिसार तक इसे विस्तारित किया गया है।
5. **कोहरे के जीवन चक्र पर ध्यान** – कोहरे के बनने, तीव्र होने, टिकने और समाप्त होने की प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाता है।
6. **पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन** – इसके तहत शहरी ऊष्मा द्वीप, प्रदूषण और भूमि उपयोग परिवर्तन का कोहरे पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है।
7. **परिचालन पूर्वानुमान मॉडल** – 3 किमी रिज़ॉल्यूशन वाला संभाव्य कोहरा पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया गया, जिसकी सटीकता 85% तक है।

WiFEX की प्रमुख उपलब्धियाँ :

उच्च-रिज़ॉल्यूशन पूर्वानुमान मॉडल :

- रिज़ॉल्यूशन: 3 किमी ग्रिड
- सटीकता: 85% से अधिक (घने कोहरे की स्थिति में)
- उपयोग: कोहरे के आरंभ, अवधि और समाप्ति की भविष्यवाणी करता है।

परिचालन लाभ :

- उड़ानों में देरी और डायवर्जन की घटनाएँ कम होती हैं।
- रनवे की सुरक्षा में सुधार होता है।
- हवाई अड्डों और वायु यातायात नियंत्रण के लिए स्थानीय स्तर पर चेतावनी प्रणाली विकसित हुई है।

वैज्ञानिक अंतर्दृष्टियाँ :

- कोहरे के निर्माण में एरोसोल्स और सूक्ष्म कणों की भूमिका स्पष्ट हुई है।
- शहरी ऊष्मा द्वीप को कोहरे की तीव्रता में योगदानकर्ता के रूप में पहचाना गया।
- शहरीकरण और वनों की कटाई जैसे भूमि उपयोग परिवर्तनों के प्रभाव को समझा गया।

WiFEX का व्यापक सामाजिक एवं पर्यावरणीय महत्व :

- **जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम :** जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में उतार-चढ़ाव और उत्सर्जन में वृद्धि से कोहरे की तीव्रता व आवृत्ति बढ़ रही है।
- **शहरीकरण और ऊष्मा द्वीप :** अनियोजित शहरी विकास से तापमान ग्रेडिएंट में बदलाव आता है जिससे कोहरे का स्वरूप प्रभावित होता है।
- **वायु प्रदूषण और धुंध :** WiFEX के अनुसार PM2.5 और PM10 जैसे कणों का कोहरा और स्मॉग बनने में गहरा संबंध है।
- **आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) :** NDMA और IMD की चेतावनी प्रणालियों को WiFEX के आंकड़ों से मजबूती मिली है।
- **परिवहन और बुनियादी ढांचा योजना :** यह विमानन, रेलवे और राजमार्ग क्षेत्र में कोहरा-प्रभावित व्यवधानों से निपटने में सहायक होता है।
- **विज्ञान और नीति का समन्वय :** यह कार्यक्रम वैज्ञानिक अनुसंधान और नीतिगत निर्णयों के बीच सेतु का कार्य करता है।
- **सतत शहरी नियोजन :** WiFEX के निष्कर्ष शहरी डिज़ाइन, हरित संरचना और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को दिशा प्रदान करते हैं।

अनुसंधान परियोजना से जुड़ी मुख्य चुनौतियाँ :

1. ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मौसम संबंधी उपकरणों की सीमित उपलब्धता के कारण वहाँ से संबंधित आंकड़ों का अभाव देखा जाता है, जिससे पूर्वानुमान प्रणाली में अंधे क्षेत्र (blind spots) बनते हैं।
2. तेजी से और अनियोजित ढंग से हो रहे शहरीकरण के कारण स्थानीय सूक्ष्म जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे कोहरे की भविष्यवाणी करना अधिक जटिल होता जा रहा है।
3. आम जनता और परिवहन संचालन से जुड़े व्यक्तियों में कोहरे के पूर्वानुमानों के प्रति जागरूकता की कमी है, जिससे समय पर चेतावनी का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता।
4. विमानन, रेलवे और सड़क परिवहन प्रणालियों में कोहरे से संबंधित चेतावनी तंत्र का समुचित एकीकरण अभी भी नहीं हो पाया है, जिससे इन प्रणालियों की कार्यकुशलता प्रभावित होती है।
5. कोहरे की निगरानी के लिए आवश्यक उच्च तकनीकी उपकरणों की लागत अधिक होती है, और उनके रखरखाव में भी कई तकनीकी और वित्तीय चुनौतियाँ आती हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

6. भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताएँ, भूमि उपयोग और मौसम संबंधी विविधताओं के कारण पूरे देश के लिए एक समान कोहरा पूर्वानुमान मॉडल लागू कर पाना अत्यंत कठिन कार्य है।

7. पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ सीमापार डेटा साझाकरण और संयुक्त अनुसंधान में निरंतरता का अभाव है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर कोहरे के समग्र अध्ययन में बाधा उत्पन्न होती है।

आगे की राह :

- कोहरे के पूर्वानुमान को अधिक सटीक और व्यावहारिक बनाने के लिए, रनवे-विशिष्ट स्थानीय पूर्वानुमान प्रणालियों को और अधिक विस्तारित किया जाना चाहिए ताकि हवाई अड्डों पर विशेष परिस्थितियों के अनुसार चेतावनी दी जा सके।
- मौसम पूर्वानुमान की गुणवत्ता और अनुकूलन क्षमता को बेहतर बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) जैसी आधुनिक तकनीकों को WiFEX मॉडल में शामिल किया जाना आवश्यक है।
- WiFEX की पहुंच को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे पूर्वी भारत, उत्तर-पूर्वी राज्यों और हिमालयी तलहटी जैसे कोहरा-प्रवण क्षेत्रों तक विस्तार देना चाहिए।
- क्षेत्रीय और वैश्विक पूर्वानुमान क्षमता को मजबूत करने के लिए WiFEX को अंतरराष्ट्रीय मौसम एजेंसियों के साथ डेटा साझा करने और संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं में सहयोग करना चाहिए।
- कोहरे से उत्पन्न यातायात व्यवधानों को कम करने के उद्देश्य से, WiFEX आधारित पूर्वानुमान प्रणाली को भारत की राष्ट्रीय परिवहन योजना में एकीकृत किया जाना चाहिए।
- कोहरे की निगरानी और विश्लेषण की दक्षता को बढ़ाने के लिए नवीनतम मौसम निगरानी उपकरणों की स्थापना की जानी चाहिए तथा डेटा संग्रह नेटवर्क को और अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए।
- कोहरे से जुड़ी चेतावनियों को आम नागरिकों और परिवहन से जुड़े ऑपरेटरों तक प्रभावी रूप से पहुँचाने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन, डैशबोर्ड और SMS अलर्ट जैसी सहज जन-संचार प्रणालियाँ विकसित की जानी चाहिए।

निष्कर्ष :

1. विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट (WiFEX) भारत में वायुमंडलीय विज्ञान, मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक पहल के रूप में उभरा है।

2. इस परियोजना ने उत्तर भारत में शीत ऋतु के दौरान होने वाले घने कोहरे जैसे अनिश्चित और जटिल प्राकृतिक घटनाक्रम को वैज्ञानिक रूप से समझने योग्य और पूर्वानुमान योग्य तत्त्व में परिवर्तित कर दिया है।

3. WiFEX की सफलता का आधार उन्नत तकनीकी उपकरणों का प्रयोग, गहन वैज्ञानिक अनुसंधान, और नीति-निर्माताओं के साथ सशक्त समन्वय में निहित है।

4. इस पहल के माध्यम से अब कोहरे के गठन, तीव्रता, अवधि और लोप होने की प्रक्रिया को अधिक गहराई से समझा जा सका है, जिससे समयबद्ध चेतावनियाँ और परिवहन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकी है।

5. जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और अनियोजित शहरीकरण के बढ़ते प्रभावों के बीच, WiFEX एक ऐसा डेटा-संपन्न और नीति-संवेदनशील मॉडल प्रस्तुत करता है, जिसे न केवल भारत के अन्य क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है, बल्कि वैश्विक संदर्भों में भी अपनाया जा सकता है।

6. यह पहल वैज्ञानिक शोध और जनहित आधारित नीति निर्माण के बीच एक सफल सेतु के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसके साथ ही बदलते जलवायु, प्रदूषण और शहरी विस्तार के दौर में, WiFEX एक प्रमाण आधारित समाधान प्रदान करता है।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट (WiFEX) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?

1. इसका समन्वय भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा किया जाता है।
2. इसका प्रमुख फोकस इंडो-गैंगेटिक मैदान में ग्रीष्मकालीन धूल भरी आँधियों के पूर्वानुमान पर है।
3. इसने 3 किमी रिज़ॉल्यूशन वाला कोहरा पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया है।
4. इसके निष्कर्ष केवल विमानन पूर्वानुमानों के लिए प्रयुक्त होते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए:

A. केवल 1 और 3 B. केवल 1, 2 और 4

C. केवल 2 और 3 D. केवल 1, 3 और 4

उत्तर - A

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट (WiFEX) क्या है? भारत में मौसम पूर्वानुमान, आपदा तैयारी और जनसुरक्षा के क्षेत्र में इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इस परियोजना से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों और उसके समाधान के प्रमुख उपायों से संबंधित सुझाव दीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

एससीओ (SCO) में भारत : शांति और क्षेत्रीय स्थिरता की एक सुनियोजित कोशिश

ख़बरों में क्यों?

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25-26 जून, 2025 को चीन के क़िंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। यह वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर 2020 के सीमा गतिरोध के बाद से चीन की पहली उच्च स्तरीय भारतीय मंत्रिस्तरीय यात्रा है। यह यात्रा भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद हो रही है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया था। सम्मेलन के दौरान, सिंह वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट प्रयासों का आह्वान करेंगे। उनकी उपस्थिति SCO ढांचे के भीतर बहुपक्षवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग के लिए भारत की रणनीतिक प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) क्या है?

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देशों सहित प्रमुख यूरेशियाई शक्तियाँ शामिल हैं। भारत 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बन गया। एससीओ आतंकवाद, उग्रवाद का मुकाबला करने और क्षेत्रीय संपर्क और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह भारत के लिए मध्य एशिया के साथ जुड़ने और क्षेत्रीय प्रभावों को संतुलित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है।

एससीओ में भारत का मुख्य संदेश :

1. संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान: भारत ने इस बात पर जोर दिया कि सभी क्षेत्रीय पहलों में सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखा जाना चाहिए।
2. आतंकवाद का दृढ़ विरोध:भारत ने सीमापार आतंकवाद और आतंकवाद के वित्तपोषण सहित सभी प्रकार के आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहनशीलता की नीति दोहराई।
3. बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता: भारत ने एससीओ ढांचे के भीतर एक सहयोगी, समावेशी और नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था की वकालत की।
4. पारस्परिक सम्मान और समानता को बढ़ावा देना:आपसी समझ, समानता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के आधार पर निर्णय लेने का आह्वान किया गया।
5. क्षेत्रीय शांति के लिए रचनात्मक भागीदारी:भारत ने दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संवाद, विश्वास निर्माण और सहयोग के महत्व पर बल दिया।

एससीओ बैठक में भारत के प्रमुख उद्देश्य :

1. **आतंकवाद विरोधी सहयोग :** भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति की वकालत करता है, एससीओ-आरएटीएस के माध्यम से मजबूत समन्वय पर जोर देता है, तथा आतंकवाद के वित्तपोषण और कट्टरपंथ को लक्षित करता है।
2. **संप्रभुता आधारित कनेक्टिविटी :** चीन की BRI का विरोध करते हुए चाबहार और INSTC जैसी पारदर्शी परियोजनाओं का समर्थन किया गया; व्यापार सुविधा और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं का आह्वान किया गया।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. **ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा :** तेल, गैस, स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ कृषि में सहयोग की मांग, तथा जी-20 पहलों के अनुरूप मोटे अनाजों को बढ़ावा देना।

4. **सांस्कृतिक एवं जन संपर्क :** एससीओ फिल्म महोत्सव और मिलेट फूड महोत्सव जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन और युवा सहभागिता को बढ़ावा देता है।

5. **संतुलित बहुपक्षवाद :** लोकतांत्रिक निर्णय लेने और समान भागीदारी का आह्वान, किसी भी एक सदस्य राज्य के प्रभुत्व का विरोध।

6. **जलवायु कार्रवाई :** एससीओ ढांचे के अंतर्गत LiFE, ISA, तथा स्वच्छ ऊर्जा सहयोग जैसी हरित पहलों को बढ़ावा देना।

7. **चीन और पाकिस्तान को रणनीतिक संकेत :** आतंकवाद, पीओके और सीपीईसी पर चिंताओं को कूटनीतिक रूप से व्यक्त करने के लिए एससीओ का उपयोग करना तथा साथ ही साथ सहभागिता बनाए रखना।

8. **डिजिटल और तकनीकी सहयोग :** इंडिया स्टैक जैसे डिजिटल उपकरण प्रदान करता है, और एआई, फिनटेक और साइबर सुरक्षा में संयुक्त कार्य को बढ़ावा देता है।

9. **मध्य एशिया और यूरेशियन आउटरीच :** एससीओ को ऊर्जा, सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास पर मध्य एशिया के साथ गहरे संबंधों के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है।

एससीओ में भारत का मुख्य संदेश :

1. **आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता :** भारत ने आतंकवाद, विशेषकर सीमापार खतरों, कट्टरपंथ और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ एकजुट और लगातार कार्रवाई का आह्वान किया।

2. **संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान :** भारत ने इस बात पर जोर दिया कि संपर्क और सहयोग में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।

3. **क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता :** भारत ने आरएटीएस सहित एससीओ की सुरक्षा संरचनाओं के माध्यम से क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका की पुष्टि की।

4. **संतुलित बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना :** भारत ने एससीओ के भीतर लोकतांत्रिक, समावेशी निर्णय लेने की वकालत की तथा व्यक्तिगत देशों के किसी भी प्रकार के वर्चस्व का विरोध किया।

5. **शांतिपूर्ण वार्ता और कूटनीति :** भारत ने इस मंच का उपयोग चीन और पाकिस्तान सहित सभी सदस्यों के साथ कूटनीतिक रूप से बातचीत करने के लिए किया, तथा अपने राष्ट्रीय हितों पर दृढ़ता से जोर दिया।

6. **आर्थिक और ऊर्जा संबंधों को मजबूत करना :** भारत ने पारदर्शी व्यापार, ऊर्जा सहयोग और खाद्य सुरक्षा सहयोग को प्रोत्साहित किया तथा आईएनएसटीसी और बाजरा कूटनीति जैसी पहलों को बढ़ावा दिया।

7. **हरित विकास और तकनीकी सहयोग :** भारत ने स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई (LiFE और ISA के माध्यम से) तथा डिजिटल प्रौद्योगिकियों और साइबर सुरक्षा में सहयोग पर संयुक्त प्रयास करने का आग्रह किया।

एससीओ में भारत की यात्रा का महत्व :

1. **2020 के गतिरोध के बाद चीन की पहली उच्च स्तरीय यात्रा :** लद्दाख सीमा गतिरोध के बाद किसी भारतीय केंद्रीय मंत्री की यह पहली चीन यात्रा है, जो सतर्क कूटनीतिक पुनः संपर्क का संकेत है।

2. **आतंकवाद का सामूहिक रूप से मुकाबला करने के लिए मंच :** भारत के मजबूत आतंकवाद विरोधी रुख को मजबूत करता है और एससीओ तंत्र के माध्यम से सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई पर जोर देता है।

3. **संप्रभुता और रणनीतिक चिंताएं :** भारत ने इस मंच का उपयोग संप्रभुता पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया तथा सीपीईसी जैसी परियोजनाओं का विरोध किया, जो इसकी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती हैं।

4. **बहुपक्षीय प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि :** एससीओ ढांचे के भीतर बहुपक्षवाद, क्षेत्रीय सहयोग और न्यायसंगत भागीदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया।

5. **क्षेत्रीय शक्तियों के साथ जुड़ाव :** चीन और रूस जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के साथ रणनीतिक वार्ता को सुविधाजनक बनाया, क्षेत्र में रक्षा और कूटनीतिक समन्वय को बढ़ाया।

6. **यूरेशियन आउटरीच का विस्तार करने का अवसर :** ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और मादक पदार्थ निरोधक सहयोग के लिए मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करता है।

7. **भारत के वैश्विक विजन को प्रदर्शित करने के लिए मंच :** भारत को वैश्विक शांति, सुरक्षा, सतत विकास और डिजिटल सहयोग के लिए अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कूटनीति :

क्र.सं.	पहलू	स्पष्टीकरण
1	द्विपक्षीय बैठकों की योजना बनाई गई	भारत ने चीन और रूस सहित प्रमुख समकक्षों के साथ वार्ता निर्धारित की है।
2	मेजबान चीन के साथ सहभागिता	2020 के एलएसी गतिरोध के बाद पहली भारतीय मंत्रिस्तरीय चीन यात्रा, पुनः संपर्क का संकेत।
3	भारत-रूस संबंधों को मजबूत करना	द्विपक्षीय रक्षा वार्ता ने पारंपरिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया।
4	एनएसए अजीत डोभाल की समानांतर कूटनीति	डोभाल की एससीओ यात्रा ने भारत की बहु-चैनल कूटनीतिक पहुंच को मजबूत किया।
5	सामरिक वार्ता के साधन के रूप में रक्षा कूटनीति	रक्षा बैठकें द्विपक्षीय रूपरेखा के बिना बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।
6	मुद्दा-आधारित समन्वय के लिए बहुपक्षीय मंच	एससीओ भारत को बहुपक्षीय मंच पर आतंकवाद जैसी क्षेत्रीय चिंताओं को उठाने की अनुमति देता है।
7	रणनीतिक सावधानी के साथ सहभागिता को संतुलित करना	भारत एससीओ और पश्चिमी गठबंधनों दोनों के साथ जुड़ते हुए रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखता है।
8	वार्ता के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता को आगे बढ़ाना	द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कूटनीति शांति, स्थिरता और संघर्ष समाधान का समर्थन करती है।

भारत के लिए एससीओ की भूमिका और प्रासंगिकता :

1. **मध्य एशिया का प्रवेश द्वार :** एससीओ भारत को मध्य एशियाई देशों तक संस्थागत पहुंच प्रदान करता है, जिससे संपर्क, व्यापार और रणनीतिक भागीदारी बढ़ती है।
2. **आतंकवाद विरोधी सहयोग :** एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी ढांचे (आरएटीएस) के माध्यम से भारत आतंकवाद, विशेषकर सीमा-पार खतरों के विरुद्ध मजबूत संयुक्त कार्रवाई पर जोर देता है।
3. **चीन के क्षेत्रीय प्रभाव को संतुलित करना :** भारत अपनी उपस्थिति को पुष्ट करने तथा यूरेशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए एससीओ की सदस्यता का उपयोग करता है।
4. **क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना :** एससीओ सुरक्षा, सीमा मुद्दों और साइबर अपराध एवं मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गैर-पारंपरिक खतरों पर बातचीत के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
5. **बहुपक्षवाद और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए समर्थन :** एससीओ भारत के बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के दृष्टिकोण के अनुरूप है और उसे स्वतंत्र विदेश नीति विकल्प चुनने में मदद करता है।
6. **ऊर्जा एवं कनेक्टिविटी साझेदारी:** भारत क्षेत्रीय व्यापार और ऊर्जा सहयोग को बेहतर बनाने के लिए एससीओ के भीतर चाबहार बंदरगाह और आईएनएसटीसी जैसे विकल्पों को बढ़ावा देता है।
7. **लोगों से लोगों के बीच संपर्क और सांस्कृतिक कूटनीति :** भारत सांस्कृतिक संबंधों, शैक्षिक आदान-प्रदान और त्योहारों एवं विरासत संवर्धन के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एससीओ का लाभ उठाता है।
8. **प्रतिद्वंद्वियों के साथ कूटनीतिक जुड़ाव :** एससीओ भारत को प्रत्यक्ष द्विपक्षीय तंत्र के बिना प्रमुख मुद्दों पर चीन और पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए एक तटस्थ मंच प्रदान करता है।

भारत की व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक रणनीति :

1. **'एक्ट ईस्ट' नीति के साथ तालमेल :** एससीओ में भारत की भागीदारी रणनीतिक पहुंच के माध्यम से दक्षिण एशिया को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जोड़कर इसकी एक्ट ईस्ट नीति का पूरक है।
2. **'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति के साथ एकीकरण :** एससीओ इस क्षेत्रीय नीति ढांचे के तहत ऊर्जा, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देकर मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के जुड़ाव को मजबूत करता है।
3. **सामरिक स्वायत्तता की खोज :** भारत राष्ट्रीय हित पर आधारित स्वतंत्र विदेश नीति को कायम रखते हुए पूर्वी और पश्चिमी दोनों ब्लॉकों के साथ संबंध रखता है।
4. **मुद्दा आधारित वैश्विक संरेखण :** भारत आतंकवाद-निरोध, जलवायु परिवर्तन या प्रौद्योगिकी जैसे विशिष्ट मुद्दों पर चुनिंदा

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

वैश्विक शक्तियों (जैसे अमेरिका या रूस) के साथ गठबंधन करता है।

5. **बहुपक्षीय मंचों में भूमिका का विस्तार :** एससीओ के माध्यम से भारत जी-20, ब्रिक्स, क्वाड और यूएनएससी मंचों के साथ-साथ बहुपक्षवाद में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को मजबूत करता है।
6. **चीन के यूरेशियाई प्रभुत्व को संतुलित करना :** भारत की सक्रिय भागीदारी चीन की एकतरफा पहल (जैसे, बी.आर. आई.) का मुकाबला करती है, तथा अधिक समावेशी और नियम-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देती है।
7. **नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देना :** भारत निरंतर संप्रभुता, पारदर्शिता और अहस्तक्षेप की वकालत करता है - ये सिद्धांत स्थिर क्षेत्रीय शासन के लिए आवश्यक हैं।
8. **क्षेत्रीय शांति और संपर्क पहल :** भारत शांति, संपर्क (जैसे, आईएनएसटीसी, चाबहार) और विकास को बढ़ावा देने के लिए एससीओ का उपयोग करता है, जिससे व्यापक यूरेशियाई क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़ता है।

चुनौतियाँ और सीमाएँ :

1. **भारत-चीन सीमा तनाव :** वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर जारी गतिरोध एससीओ के भीतर विश्वास को प्रभावित करता है और रणनीतिक सहयोग को सीमित करता है।
2. **एससीओ में पाकिस्तान की उपस्थिति :** पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय तनाव, विशेष रूप से आतंकवाद और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर आम सहमति बनाने को जटिल बनाता है।
3. **आतंकवाद की भिन्न परिभाषाएँ :** एससीओ सदस्य इस बात पर भिन्न-भिन्न हैं कि आतंकवाद क्या है, जिससे संयुक्त आतंकवाद-रोधी प्रयास प्रभावित होते हैं - भारत चयनात्मक दृष्टिकोण का विरोध करता है।
4. **एससीओ एजेंडे में चीन का प्रभुत्व :** चीन की आर्थिक और रणनीतिक ताकत अक्सर एससीओ की प्राथमिकताओं को आकार देती है, तथा भारत की चिंताओं को दरकिनार कर देती है (उदाहरण के लिए, सीपीईसी का पीओके से होकर गुजरना)।
5. **कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर सीमित प्रभाव :** भारत बी.आर. आई. का विरोध करता है, जबकि अधिकांश एस.सी.ओ. सदस्य इसका समर्थन करते हैं, जिसके कारण क्षेत्रीय अवसंरचना पहलों पर टकराव पैदा हो रहा है।
6. **बाध्यकारी प्रवर्तन तंत्र का अभाव :** एससीओ के निर्णय गैर-बाध्यकारी हैं, जिससे सुरक्षा या आतंकवाद पर संयुक्त घोषणाओं और प्रस्तावों की प्रभावशीलता कम हो जाती है।
7. **वैचारिक और रणनीतिक मतभेद :** एससीओ में लोकतंत्र (भारत) और सत्तावादी राज्य (चीन, रूस, मध्य एशियाई गणराज्य) शामिल हैं, जो सामंजस्य और एकता को प्रभावित करते हैं।
8. **भाषा और प्रक्रियागत बाधाएँ :** कामकाजी भाषा चीनी और रूसी होने के कारण, भारत के प्रस्तावों को औपचारिक वार्ता में संचार संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

निष्कर्ष :

एससीओ में भारत की भागीदारी कूटनीति के प्रति परिपक्व और व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और बहुपक्षीय सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अंतर्निहित तनावों के बावजूद, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के साथ, भारत रचनात्मक रूप से जुड़ना जारी रखता है, अपने रणनीतिक हितों को मुखर करने और नियम-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था की वकालत करने के लिए मंच का लाभ उठाता है। एससीओ भारत की व्यापक विदेश नीति के उद्देश्यों के साथ संवाद, आतंकवाद विरोधी समन्वय और क्षेत्रीय संपर्क के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करता है।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत 2001 में एससीओ का संस्थापक सदस्य बना।
2. क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस) एससीओ के तहत एक पहल है।
3. एससीओ की आधिकारिक कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और रूसी हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2

C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. क्षेत्रीय सुरक्षा, द्विपक्षीय कूटनीति और भारत की व्यापक यूरेशियाई पहुंच के संदर्भ में चीन में 2025 में होने वाली एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की भागीदारी के रणनीतिक महत्व पर चर्चा करें। एससीओ ढांचे के भीतर भारत के सामने कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

वैश्विक खाद्य मानकों में भारत की भूमिका : कोडेक्स समिति में FSSAI की भागीदारी

खबरों में क्यों ?

- भारत ने हाल ही में कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन (Codex Alimentarius Commission - CAC) की कार्यकारी समिति के बैठक में भाग लिया है।
- इस सत्र में भारत ने मसालों के मानकों की गुणवत्ता मानकों जैसे कि छोटी इलायची, वेनिला और हल्दी के मानकों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- इन मसालों के महत्वपूर्ण उत्पादक और निर्यातक के रूप में, भारत की भागीदारी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण है।
- भारत ने नामित वनस्पति तेलों के मानकों के प्रगति को समर्थन दिया है, जिसके तहत शिगा टॉक्सिन-उत्पादक एशेरिकिया कोलाइ को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देशिकाएँ और खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण में पानी के सुरक्षित उपयोग और पुनः प्रयोग के मानकों के लिए भी समर्थन और सहमति व्यक्त किया है।

कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC) :

- कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC) एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है।
- इस निकाय का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना और खाद्य व्यापार में उचित प्रथाओं की सुनिश्चितता को तय करना है।
- इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मई 1963 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organisation - FAO) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था।
- इसके तहत विभिन्न खाद्य मानक, दिशा-निर्देश, और अभ्यास संहिताएं तैयार की जाती हैं।
- इसके तहत तय किए गए मानकों और संहिताएं आमतौर पर स्वच्छता अभ्यास, लेबलिंग, संदूषक, योजक, निरीक्षण, प्रमाणन, पोषण, और पशु चिकित्सा दवाओं और कीटनाशकों के अवशेषों से निपटने के लिए लागू होती हैं।
- वर्तमान में CAC में कुल 189 सदस्य हैं, जिसमें 188 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
- भारत सन 1964 में CAC का सदस्य बना था।
- कोडेक्स के तहत कमोडिटी मानक विशिष्ट उत्पादों को संदर्भित करते हैं, जबकि क्षेत्रीय मानक संबंधित क्षेत्रों पर लागू होते हैं।

CAC की कार्यकारी समिति (CCEXEC) का वर्तमान सत्र :

- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के CEO के नेतृत्व में भारत ने रोम स्थित FAO मुख्यालय में आयोजित कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की कार्यकारी समिति (CCEXEC) के वर्तमान बैठक में सक्रिय रूप से भागीदारी की।
- CCEXEC का प्रमुख कार्य नए कार्य प्रस्तावों की समीक्षा और मानक विकास की प्रगति की निगरानी करना है।
- कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की कार्यकारी समिति (CCEXEC) के 86वें सत्र के दौरान, भारत ने छोटी इलायची, हल्दी और वेनिला सहित विभिन्न मसालों के मानकों के विकास के लिए जोरदार समर्थन किया।
- यह पहल भारत के लिए विशेष महत्त्व रखती है, क्योंकि भारत इन मसालों का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है। अतः इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आसानी होगी।
- इसके अलावा, भारत ने वनस्पति तेलों के लिए मानकों की प्रगति, शिगा टॉक्सिन उत्पादन करने वाले एस्चेरिचिया कोलाई (Shiga Toxin-Producing Escherichia Coli) के नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देशों, और खाद्य उत्पादन एवं प्रसंस्करण में पानी के सुरक्षित उपयोग और पुनः उपयोग का समर्थन किया।
- भारत ने खाद्य पैकेजिंग में पुनर्नवीनीकृत सामग्रियों के उपयोग से संबंधित खाद्य सुरक्षा विचारों पर कोडेक्स द्वारा एक मार्गदर्शन विकसित करने के प्रस्ताव का भी समर्थन किया।
- यह पहल जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- अंततः, भारत ने खाद्य संपर्क अनुप्रयोगों के लिए पोस्ट उपभोक्ता PET (पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट) के पुनर्चक्रण पर FSSAI द्वारा विकसित दिशा-निर्देशों के साथ अपने अनुभव साझा किए।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) :

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है।

- भारत में इसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित किया गया है।
- यह निकाय भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है।
- यह भारत में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को विनियमित तथा पर्यवेक्षण करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और संवर्द्धन के लिए एक जिम्मेदार निकाय है।
- FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन और चेन्नई में स्थित है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का कार्य करता है।
- FSSAI मानव उपभोग के लिये पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य करता है।
- इसके अलावा यह देश के सभी राज्यों, ज़िला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के निर्धारित मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है।
- यह समय-समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य-पदार्थों की गुणवत्ता की भी जाँच करता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित मानकों का निर्माण करना है और खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को नियंत्रित करने के माध्यम से मानव-उपभोग के लिए सुरक्षित और संपूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित करना है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य सुरक्षा से संबंधित शुरू की गई महत्वपूर्ण पहल :

राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक :

- FSSAI ने खाद्य सुरक्षा के पाँच मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI) को विकसित किया है।

ईट राइट अवार्ड्स :

- FSSAI ने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन विकल्प चुनने तथा खाद्यान्न कंपनियों तथा व्यक्तियों के योगदान को मान्यता देने हेतु 'ईट राइट अवार्ड्स' की स्थापना की है, जो नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण में मदद करेगा।

ईट राइट मेला :

- FSSAI द्वारा आयोजित यह मेला नागरिकों को सही खान-पान हेतु प्रेरित करने के लिए एक आउटरीच गतिविधि है।

ईट राइट इंडिया (Eat Right India) :

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा शुरू किए गए इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत में भोजन की गुणवत्ता और पोषण स्तर को सुधारना है। इसके तहत स्वस्थ खाने की आदतें, सुरक्षित भोजन और टिकाऊ खाद्य प्रणाली जैसे विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया जाता है।

ईट राइट स्टेशन (Eat Right Station) :

- FSSAI द्वारा शुरू किया गया यह पहल रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत रेलवे स्टेशनों पर खाद्य विक्रेताओं को FSSAI के मानकों के अनुसार प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाता है। इस पहल के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि यात्रीगण स्वच्छ और सुरक्षित भोजन प्राप्त हो।

RUCO (Reused Cooking Oil) :

- RUCO (Reused Cooking Oil) एक पहल है जिसका उद्देश्य प्रयुक्त खाद्य तेल का पुन: उपयोग करना और उसे बायो-डीजल में परिवर्तित करना है। इस पहल के तहत प्रयुक्त तेल को संग्रहित करके बायो-डीजल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है और ऊर्जा के स्थायी स्रोत को बढ़ावा दिया जा सकता है।

खाद्य सुरक्षा मित्र (Food Safety Mitra) :

- FSSAI द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित पेशेवरों को विभिन्न खाद्य व्यवसायों में खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन के लिए नियुक्त किया जाता है। ये मित्र खाद्य व्यवसायों को सही तरीके से संचालन करने में मदद करते हैं और उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन प्राप्त करने में सहायता करते हैं।

100 फूड्स (100 Foods) :

- भारत में FSSAI द्वारा शुरू किए गए 100 फूड्स कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय खानपान की विविधता और पोषण मूल्य को प्रदर्शित करना है। इसमें 100 प्रमुख भारतीय खाद्य पदार्थों को शामिल किया गया है, जो विभिन्न पोषण गुणों से भरपूर हैं। इस पहल का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ और संतुलित आहार के प्रति जागरूक करना है।

- इन तमाम पहलों का उद्देश्य समग्र रूप से भारतीय खाद्य प्रणाली को सुधारना और स्वस्थ व सुरक्षित भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

स्रोत - पी. आई. बी एवं इकॉनोमिक टाइम्स।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के उपयोग से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए WTO किसके साथ सहयोग करता है? (UPSC - 2018)

A. खाद्य सुरक्षा मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन।

B. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स यूजर्स।

C. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण।

D. कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन।

उत्तर - D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की मुख्य चुनौतियाँ क्या है और भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की मुख्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपनाई गई मुख्य नीतियों का विस्तारपूर्वक एवं तर्कसंगत व्याख्या कीजिए।

(UPSC CSE - 2019 शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता युद्ध और ऊर्जा की आवश्यकता : भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक चेतावनी

खबरों में क्यों?

- हाल ही में चीन ने एक बार फिर वैश्विक सुरक्षा मंच पर हलचल मचा दी है। डीपसीक मॉडल की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू होने से पहले ही उसने अपने सैन्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) कार्यक्रम को तेज़ी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है।
- "कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित युद्ध" की अवधारणा के अंतर्गत पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) युद्ध संचालन में एआई तकनीकों का सक्रिय एकीकरण कर रही है। इसमें ऐसी प्रणालियाँ शामिल हैं जो उच्च सटीकता के साथ तेज़ी से फायरिंग करती हैं, और ऐसे जनरेटिव एआई-सक्षम ड्रोन भी हैं जो दुश्मन के रडार पर स्वतः हमला करने की क्षमता रखते हैं। डीपसीक तकनीक की प्रगति से इन क्षमताओं को और बल मिलने की संभावना है।
- रक्षा क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से चीन की यह बढ़त न केवल तकनीकी दृष्टि से उल्लेखनीय है, बल्कि वैश्विक रक्षा विशेषज्ञों के लिए एक नई चिंता का कारण भी बनती जा रही है।

वैश्विक रक्षा परिदृश्य में सैन्य एआई का उभरता प्रभाव :

1. **चीन का "स्मार्ट युद्ध" दृष्टिकोण :** पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) अपने सैन्य अभियानों में एआई को रणनीतिक रूप से एकीकृत कर रही है। इसमें तेज़ी, सटीकता और स्वायत्त निर्णय क्षमताओं को बढ़ाने हेतु आर्टिलरी सिस्टम, ड्रोन तकनीक और युद्धक्षेत्र की वास्तविक समय में विश्लेषण प्रणाली को शामिल किया गया है।
2. **जनरेटिव एआई-सक्षम चीनी ड्रोन :** चीन ऐसे ड्रोन विकसित कर रहा है जो जनरेटिव एआई द्वारा संचालित होकर स्वचालित रूप से शत्रु की रडार प्रणालियों की पहचान और हमले कर सकें। यह तकनीक मानवीय हस्तक्षेप और प्रतिक्रिया समय को न्यूनतम कर देती है।
3. **डीपसीक तकनीक द्वारा सैन्य क्षमताओं में उन्नयन :** डीपसीक मॉडल चीन के निगरानी, लक्ष्य निर्धारण और स्वायत्त लड़ाकू प्रणालियों को तकनीकी मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
4. **यूक्रेन का एआई-आधारित सामरिक प्रयोग :** रूस-यूक्रेन संघर्ष में, यूक्रेन ने एआई-आधारित ड्रोन और उपग्रह डेटा की सहायता से हमले और निगरानी को अधिक प्रभावी बनाया है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि एआई तकनीक युद्ध शक्ति में संतुलन ला सकती है।

5. **इज़राइल का "लैवेंडर" एआई सिस्टम :** गाजा संघर्ष के दौरान इज़राइल ने कथित रूप से "लैवेंडर" नामक एआई प्रणाली का उपयोग कर 37,000 से अधिक लक्ष्यों की पहचान की, जिससे यह संघर्ष एआई-आधारित लक्ष्यीकरण से संचालित युद्धों में शामिल हो गया।

6. **अमेरिका की एआई आधारित वॉरगेमिंग में प्रगति :** अमेरिकी सेना पूर्वानुमानित युद्ध अभ्यास, खतरे का मॉडलिंग, रसद योजना और डिजिटल ट्विन सिमुलेशन जैसी प्रक्रियाओं में एआई का इस्तेमाल कर युद्ध की तैयारियों को सशक्त बना रही है।

7. **नाटो का बहु-डोमेन एआई समावेशन :** नाटो विभिन्न क्षेत्रों – ज़मीन, आकाश, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस – में एआई का समन्वित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी निवेश कर रहा है। संगठन सुरक्षित, नैतिक और इंटर ऑपरेबल एआई समाधानों पर भी जोर दे रहा है।

8. **नागरिक-सैन्य प्रौद्योगिकी का समन्वय :** अमेरिका बनाम चीन : चीन और अमेरिका दोनों ही नागरिक क्षेत्रों से प्राप्त नवाचारों — जैसे क्लाउड एआई, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग — को रक्षा प्रणालियों में समाहित कर रहे हैं, जिससे उनके सैन्य-तकनीकी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है।

चीन-पाकिस्तान का एआई रक्षा गठबंधन : भारत के लिए चुनौतीपूर्ण संकेत

1. **रणनीतिक तकनीक का हस्तांतरण :** चीन ने 2020 में स्थापित पाकिस्तान के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग सेंटर (CAIC) को महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान की है, जिससे उसकी सैन्य एआई क्षमताएं सुदृढ़ हो रही हैं।

2. **संज्ञानात्मक और इलेक्ट्रॉनिक प्रभुत्व केंद्रित क्षेत्र :** इस सहयोग का उद्देश्य संज्ञानात्मक युद्ध, रियल-टाइम निर्णय प्रणाली और एआई-सक्षम साइबर संचालन को मज़बूत करना है, जो आधुनिक युद्ध की नई परिभाषाएं हैं।

3. **ऑपरेशन सिंदूर में एआई की संभावित भूमिका :** रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, पाकिस्तान ने संभवतः "ऑपरेशन सिंदूर" में एआई उपकरणों का उपयोग किया था, जिसमें चीनी उपग्रह डेटा और विश्लेषण प्रणाली ने सहायता की थी।

4. **दोहरे-उपयोग वाली तकनीक से उत्पन्न जोखिम :** इस गठबंधन से भारत के समक्ष एक नया सुरक्षा परिदृश्य उभरता है, जहाँ नागरिक तकनीकों — जैसे इमेज रिकग्निशन, एनएलपी और ड्रोन स्वार्म — का सैन्य हथियारों में रूपांतरण संभव है।

5. **क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने भारत की रणनीतिक चिंताएं :** भारत को इस दो तरफा एआई-सक्षम खतरे के संदर्भ में अपनी निगरानी, साइबर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं में आत्मनिर्भरता विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखा जा सके।

भारत की सैन्य एआई क्षमता : संभावनाएँ, चुनौतियाँ और रणनीतिक दिशा

1. **भारत की धीमी लेकिन महत्वाकांक्षी शुरुआत :** भारत ने सैन्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दिशा में कदम 1986 में डीआरडीओ के अधीन "कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स केंद्र (CAIR)" की स्थापना से उठाया। इस पहल का फोकस स्वायत्त प्रणालियों, स्मार्ट हथियार प्रणालियों और रोबोटिक्स पर रहा, लेकिन प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही है।

2. **प्राथमिक विकास क्षेत्र :** वर्तमान में भारत स्वायत्त जमीनी वाहनों, निगरानी तंत्र, रसद प्रबंधन, लक्ष्य पहचान और निर्णय सहायता प्रणालियों के क्षेत्र में एआई तकनीकों का विकास कर रहा है। इन प्रयासों का नेतृत्व CAIR और DRDO जैसे संस्थान कर रहे हैं।

3. **सीमित पैमाने पर तैनाती :** वर्तमान समय में भले ही पायलट प्रोजेक्ट और प्रोटोटाइप तैयार किए गए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर सैन्य एआई की तैनाती अभी दूर की बात है। असंगठित अनुसंधान, धीली संस्थागत प्रक्रिया और सामंजस्य की कमी इसकी प्रमुख बाधाएँ हैं।

4. **निजी क्षेत्र की भूमिका सीमित :** भारत के रक्षा तकनीकी तंत्र में एआई स्टार्टअप्स, निजी कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी तुलनात्मक रूप से कम है, जबकि चीन और अमेरिका इस क्षेत्र में नागरिक-सैन्य समन्वय को काफी हद तक सुदृढ़ कर चुके हैं।

5. **रणनीतिक अंतराल और कार्रवाई की आवश्यकता :** चीन-पाकिस्तान के एआई गठबंधन के मद्देनज़र भारत को अपने घरेलू एआई नवाचार, साइबर-लचीलापन और डेटा-आधारित रक्षा संरचनाओं को सशक्त करने की सख्त आवश्यकता है।

C4ISR का महत्व और बहु-डोमेन युद्ध :

1. **C4ISR का परिचय :** C4ISR – अर्थात् कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस – आधुनिक सैन्य अभियानों की रीढ़ है। यह संकल्पना युद्ध के हर चरण में निर्णय क्षमता और गति प्रदान करती है।

2. **युद्धक्षेत्र में बहु-डोमेन समन्वय :** C4ISR प्रणाली थल, जल, नभ, अंतरिक्ष और साइबरस्पेस में एकीकृत कार्रवाई को संभव बनाती है, जिससे तत्काल और समन्वित सैन्य प्रतिक्रिया दी जा सके।

3. **कृत्रिम बुद्धिमत्ता से समृद्ध C4ISR :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से C4ISR प्रणाली को भविष्यसूचक विश्लेषण, रीयल-टाइम सेंसर फ्यूजन और स्वायत्त प्रतिक्रिया जैसी क्षमताएँ मिलती हैं, जिससे युद्ध की संभावनाओं का पूर्वानुमान और कार्रवाई संभव होती है।

4. **भारत के रक्षा तंत्र में एकीकरण की चुनौतियाँ :** भारत के रक्षा तंत्र में अभी तक एआई-आधारित C4ISR प्रणालियों का व्यापक समावेशन नहीं हो पाया है, जिससे ISR विश्लेषण और निर्णय प्रक्रिया में सीमाएँ बनी हुई हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

5. **चीन की बढ़त और भारत के लिए चेतावनी :** चीन ने न केवल अत्याधुनिक C4ISR क्षमताओं का विकास किया है, बल्कि साइबर और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम प्रभुत्व में भी बढ़त बना ली है, जिससे भारत की सुरक्षा रणनीति को पुनर्संरचित करने की आवश्यकता पैदा हो गई है।

6. **भारत में C4ISR पारिस्थितिकी क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता :** भारत को चाहिए कि वह निजी टेक उद्योग, अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसियों और रक्षा अनुसंधान निकायों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे, ताकि C4ISR पारिस्थितिकी को आधुनिक बनाया जा सके।

7. **रणनीतिक संतुलन हेतु मजबूत प्रणाली अनिवार्य :** AI-सक्षम और बहु-डोमेन प्रतिक्रियाओं में दक्ष C4ISR प्रणाली के बिना भारत भविष्य के समन्वित युद्धों में रणनीतिक संतुलन बनाए रखने में पिछड़ सकता है।

ऊर्जा अवसंरचना : एआई आधारित युद्ध की अदृश्य रीढ़ :

1. **ऊर्जा-संवेदनशील एआई प्रौद्योगिकियाँ :** AI आधारित प्रणालियाँ – जैसे मशीन लर्निंग, ड्रोन स्वार्म, एनएलपी और निगरानी प्रणालियाँ – लगातार उच्च ऊर्जा इनपुट की मांग करती हैं, जो पारंपरिक ऊर्जा तंत्र से पूरा करना कठिन होता जा रहा है।

2. **ऊर्जा के नए किले के रूप में डेटा केंद्र :** एआई-आधारित सैन्य प्रणालियाँ युद्धक्षेत्र की सूचनाओं को रीयल-टाइम में संसाधित करने के लिए ऊर्जा-गहन डेटा केंद्रों पर निर्भर हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अवसंरचना का नया आधार बनते जा रहे हैं।

3. **वैश्विक ऊर्जा-सैन्य समीकरण में बदलाव :** अब देश अपने रक्षा ऊर्जा ढांचे को फिर से डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि एआई-समर्थित बहु-डोमेन युद्ध संचालन को निर्बाध रूप से समर्थन मिल सके।

4. **एक रणनीतिक विकल्प के रूप में परमाणु ऊर्जा :** अनिश्चित नवीकरणीय स्रोतों की तुलना में परमाणु ऊर्जा AI के लिए आवश्यक स्थिरता और स्केलेबिलिटी प्रदान करती है, जो आधुनिक सैन्य ऊर्जा रणनीतियों का केंद्र बनती जा रही है।

5. **ग्रिड स्थिरता की सैन्य अनिवार्यता :** बिजली में अस्थिरता से एआई आधारित सैन्य प्रणालियों की प्रभावशीलता बाधित होती है। इसलिए, रक्षा संरचनाओं को स्थायी और निर्बाध रूप से चलने के लिए ऊर्जा आपूर्ति की आवश्यकता होती है।

6. **सह-स्थान रणनीति और SMR का उभरता रोल :** AI हब्स के पास छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) की तैनाती, सुरक्षित और लचीले डेटा प्रोसेसिंग के लिए एक व्यावहारिक रणनीति बनकर उभरी है।

7. **ऊर्जा एक रणनीतिक परिसंपत्ति के रूप में :** ऊर्जा अब केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा योजना का अभिन्न हिस्सा है – विशेष रूप से एआई-सक्षम सैन्य अभियानों में इसकी भूमिका निर्णायक होती जा रही है।

भारत की परमाणु ऊर्जा की कमी :

1. **वर्तमान क्षमता घाटा :** भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता मात्र 7.5 गीगावाट है, जो दक्षिण कोरिया (~24 गीगावाट) जैसे रणनीतिक समकक्षों से काफी पीछे है।

2. **रक्षा एआई तत्परता पर प्रभाव :** कम परमाणु उत्पादन 24/7 सैन्य तत्परता के लिए आवश्यक बड़े पैमाने पर एआई प्रणालियों के संचालन को सीमित करता है।

3. **नवीकरणीय निर्भरता से अस्थिर ग्रिड :** पर्याप्त भंडारण के बिना सौर/पवन ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भरता ने भारत के ग्रिड को संवेदनशील प्रणालियों के लिए अविश्वसनीय बना दिया है।

4. **तापीय निवेश का पुनरुद्धार :** बिजली की कमी के कारण, भारत स्वच्छ कोयला और हाइब्रिड तापीय स्रोतों में निजी क्षेत्र के निवेश पर पुनर्विचार कर रहा है।

5. **छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) खेल-परिवर्तक के रूप में :** एआई केंद्रों के लिए स्थानीयकृत, उच्च दक्षता वाली बिजली सुनिश्चित करने के लिए एसएमआर को डेटा हब के पास तैनात किया जा सकता है।

6. **ऊर्जा और रक्षा नीति का एकीकरण :** भारत को सतत तकनीकी परिचालन के लिए अपनी परमाणु ऊर्जा योजना को रक्षा आधुनिकीकरण योजनाओं के साथ जोड़ने की आवश्यकता है।

7. **रणनीतिक ऊर्जा योजना की तात्कालिकता :** ऊर्जा सुधार के बिना, भारत को एआई-सक्षम लड़ाकू क्षमताओं और डिजिटल युद्धक्षेत्र श्रेष्ठता में पिछड़ने का खतरा है।

भारत के लिए रणनीतिक सिफारिशें :

1. **स्वदेशी एआई अनुसंधान एवं विकास में तेजी लाना :** सैन्य-स्तर के एआई उपकरण बनाने के लिए डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, एआई स्टार्टअप्स और प्रमुख संस्थानों (आईआईटी, आईआईएससी) में निवेश बढ़ाएं।

2. **रक्षा-केंद्रित एसएमआर विकसित करना :** ऊर्जा लचीलेपन के लिए सैन्य एआई प्रतिष्ठानों के निकट लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) की तैनाती में तेजी लाना।

3. **एआई नैतिकता और साइबर सुरक्षा को संस्थागत बनाना :** स्वायत्त हथियार प्रणालियों और युद्धक्षेत्र निर्णयों को नियंत्रित करने के लिए मजबूत एआई नैतिकता और साइबर सुरक्षा ढांचे का निर्माण करना।

4. **रक्षा-अकादमिक-उद्योग को त्रिकोणीय बनाने की जरूरत :** दोहरे उपयोग वाली एआई प्रौद्योगिकियों में तेजी लाने के लिए समर्पित नागरिक-सैन्य-निजी नवाचार गलियारे शुरू करें।

5. **एआई के लिए रक्षा खरीद को सुव्यवस्थित करना :** बलों में एआई प्लेटफार्मों के तेजी से संचालन, स्केलिंग और प्रेरण की अनुमति देने के लिए अधिग्रहण प्रक्रियाओं में सुधार।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

6. **ISR और मल्टी-डोमेन C4I नेटवर्क को बढ़ावा देना :** विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी, लक्ष्यीकरण और प्रतिक्रिया दक्षता में सुधार के लिए AI का उपयोग करके एकीकृत C4ISR सिस्टम का निर्माण करना।

7. **रणनीतिक ऊर्जा-तकनीक संलयन योजना :** ऊर्जा नीति को एआई युद्ध की आवश्यकताओं को विशेष रूप से डेटा सेंटर, रक्षा क्लाउड और क्वांटम नेटवर्क के साथ समन्वयित करें।

निष्कर्ष :

1. आधुनिक युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है, जहाँ निर्णय अब इंसानी प्रवृत्ति नहीं, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा वास्तविक समय डेटा, स्वायत्त नियंत्रण और अति-सटीकता के सहारे संचालित होते हैं, लेकिन एआई की प्रभावशीलता केवल कोड या एल्गोरिद्म पर नहीं टिकी होती; इसके पीछे ऊर्जा अवसंरचना, साइबर लचीलापन और एकीकृत प्रणालियों की ठोस नींव आवश्यक है।

2. भारत अभी भी इन मूलभूत स्तंभों में उल्लेखनीय कमियों से जूझ रहा है, विशेषकर जब इसकी तुलना चीन की तेज़ गति से विकसित हो रही एआई-सक्षम सैन्य रणनीतियों और ऊर्जा-समर्थ डिजिटल क्षमताओं से की जाती है।

3. यदि भारत को अगली पीढ़ी के युद्ध परिदृश्यों में प्रासंगिक और सक्षम बने रहना है, तो उसे एआई अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाना होगा, नागरिक और सैन्य क्षेत्रों के बीच गहरा समन्वय स्थापित करना होगा, और ऊर्जा योजना—विशेषतः छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) जैसे समाधानों—को रक्षा रणनीति के केंद्र में लाना होगा।

4. आज के बहु-डोमेन युद्ध परिदृश्य में, जहां हर सेकंड निर्णायक हो सकता है, वहाँ एआई युद्ध का "मस्तिष्क" बन गया है, और ऊर्जा उसकी "रीढ़"।

5. वर्तमान भारत के लिए यह अनिवार्य है कि वह इन दोनों को न केवल विकसित करे, बल्कि इन्हें रणनीतिक रूप से जोड़कर एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा संरचना का निर्माण करे।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. चीन द्वारा अपनाया गया शब्द "कृत्रिम बुद्धिमत्ता युद्ध" किसको संदर्भित करता है?

A. मानव बुद्धि के साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध।

B. कमांडरों द्वारा निर्देशित पारंपरिक सैन्य रणनीति।

C. बहु-डोमेन परिचालनों में एआई और स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग।

D. स्वायत्त हथियार के उपयोग पर नैतिक प्रतिबंध।

उत्तर - C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. आधुनिक युद्ध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और ऊर्जा अवसंरचना की क्या रणनीतिक भूमिका है, और भारत एआई-सक्षम रक्षा तत्परता प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमतागत अंतरालों को कैसे पाट सकता है?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत-सऊदी अरब उर्वरक समझौता : दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग का एक आधार स्तंभ

खबरों में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन एवं उर्वरक मामलों के प्रभारी जेपी नड्डा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 11 से 13 जुलाई, 2025 के बीच सऊदी अरब के दम्मम और रियाद का दौरा किया।

- इस यात्रा का उद्देश्य भारत और सऊदी अरब के बीच रसायन, उर्वरक, स्वास्थ्य सेवाओं और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करना था।

हस्ताक्षरित महत्वपूर्ण समझौतों की रूपरेखा :

1. **साझेदार संस्थाएँ :** सऊदी अरब की अग्रणी खनन एवं उर्वरक कंपनी मादेन और भारत की तीन प्रमुख सार्वजनिक व सहकारी संस्थाएँ—इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल), कृभको और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)—के बीच बहुवर्षीय उर्वरक आपूर्ति अनुबंधों पर सहमति बनी है।

2. **डीएपी पर विशेष जोर :** इन समझौतों का केंद्रबिंदु डायम्मोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की आपूर्ति है, जो भारतीय कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक उर्वरक है।

3. **आपूर्ति की मात्रा :** अनुबंध के अंतर्गत सऊदी अरब भारत को वित्त वर्ष 2025-26 से प्रतिवर्ष 3.1 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) डीएपी उपलब्ध कराएगा।

4. **समझौते की समयावधि :** ये आपूर्ति अनुबंध प्रारंभ में पाँच वर्षों तक प्रभावी रहेंगे, जिससे भारत को मध्यम अवधि में उर्वरक आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित होगी।

5. **विस्तार की संभावनाएँ :** अनुबंधों में पारस्परिक सहमति से पाँच वर्ष तक विस्तार का प्रावधान भी शामिल है, जो दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत करता है।

6. **मात्रा की रणनीतिक भूमिका :** 3.1 एमएमटी की वार्षिक आपूर्ति प्रतिबद्धता सऊदी अरब से भारत के डीएपी आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाती है, जिससे उर्वरक आपूर्ति में पूर्वानुमान शीलता और सुरक्षा में सुधार होगा।

7. **पिछले आँकड़ों से तुलना :** भारत ने 2023-24 में 1.6 एमएमटी और 2024-25 में 1.9 एमएमटी डीएपी का आयात सऊदी अरब से किया, जो 17% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। नई आपूर्ति व्यवस्था 63% की उल्लेखनीय बढ़त को दर्शाती है, जो सऊदी अरब को भारत का एक प्रमुख दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्तिकर्ता बना देती है।

भारत के लिए रणनीतिक और सामरिक महत्व :

1. **आपूर्ति सुरक्षा की गारंटी :** ये दीर्घकालिक अनुबंध देश को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उर्वरकों की निरंतर और स्थिर आपूर्ति प्रदान करेंगे।

2. **वैश्विक अस्थिरता से सुरक्षा :** सऊदी अरब जैसे विश्वसनीय स्रोत से आपूर्ति मिलने से भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता और मूल्य झटकों से संरक्षण मिलेगा।

3. **भू-राजनीतिक जोखिमों से बचाव :** चीन या यूरोपीय आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता घटाकर यह व्यवस्था आपूर्ति श्रृंखला की लचीलापन को मज़बूत करती है।

4. **कृषि क्षेत्र को संबल :** डीएपी की खासकर बुआई के मौसम में समय पर उपलब्धता से किसानों को फसल की उपज बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

5. **'आत्मनिर्भर भारत' को बल :** यह पहल वैश्विक साझेदारी के माध्यम से रणनीतिक स्रोतों तक पहुंच को सुरक्षित करती है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ठोस कदम है।

6. **किसान हितों की रक्षा :** स्थिर आपूर्ति से मूल्य नियंत्रण संभव होता है, जिससे सीमांत और छोटे किसानों को किफायती दरों पर उर्वरक मिल सकेंगे।

7. **भारत की वैश्विक भूमिका में वृद्धि :** इतने बड़े स्तर पर दीर्घकालिक रणनीतिक समझौते करने की भारत की क्षमता, एक निर्णायक वैश्विक कृषि शक्ति के रूप में उसकी स्थिति को सशक्त बनाती है।

उर्वरक क्षेत्र में सहयोग : एक व्यापक रणनीतिक विस्तार

1. **डीएपी से आगे – उर्वरकों की विविधता की ओर :** दोनों देशों ने डायमोनियम फॉस्फेट (DAP) के अलावा यूरिया और अन्य प्रमुख उर्वरकों के आयात-निर्यात और साझा उत्पादन में सहयोग की संभावनाओं पर सहमति जताई, जिससे भारत की आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाई जा सके।

2. **रणनीतिक निवेश संवाद :** चर्चा में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा सऊदी अरब की खनिज और उर्वरक अधोसंरचना में लंबी अवधि के निवेश की संभावना पर विचार हुआ, जिससे संसाधन समृद्ध परियोजनाओं का लाभ उठाया जा सके।

3. **भारत में सऊदी निवेश की संभावनाएँ :** सऊदी पक्ष को भारत की कृषि इनपुट आपूर्ति श्रृंखला—जैसे उर्वरक विनिर्माण, वितरण और भंडारण—में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया।

4. **द्विपक्षीय समन्वय तंत्र का गठन :** साझेदारी को सशक्त समन्वय देने हेतु भारत के सचिव (उर्वरक) और सऊदी अरब के उप मंत्री (खनन) के नेतृत्व में एक संयुक्त कार्यबल का गठन किया गया।

5. **अनुसंधान एवं नवाचार पर बल :** यह संयुक्त टीम भारत की कृषि जरूरतों के अनुसार अनुकूलित उर्वरकों पर अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देगी, जिससे उत्पादकता में वृद्धि और पर्यावरणीय प्रभाव में कमी आएगी।

6. **सहयोग का दीर्घकालिक दृष्टिकोण :** सहयोग का दायरा पारंपरिक खरीद-बिक्री तक सीमित न रहकर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त निवेश और सतत विकास के मॉडल की दिशा में बढ़ रहा है।

7. **हरित लक्ष्यों में भागीदारी :** पर्यावरण-सम्मत उर्वरकों के विकास और सतत कृषि को प्रोत्साहित करने वाले संयुक्त प्रयास, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक प्रतिबद्धताओं में दोनों देशों की सहभागिता को दर्शाते हैं।

स्वास्थ्य एवं औषधि क्षेत्र : सहयोग की नई दिशा

1. **द्विपक्षीय स्वास्थ्य संवाद :** केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सऊदी उप मंत्री अब्दुलअजीज अल-रुमैह के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा तैयार की।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

2. **डिजिटल स्वास्थ्य तकनीक में भागीदारी :** दोनों देशों ने टेलीमेडिसिन, ई-हेल्थ प्लेटफ़ॉर्म और स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में अनुभवों का साझा करने पर चर्चा की।

3. **औषधीय अनुसंधान में सहभागिता :** जेनेरिक दवाओं, बायोसिमिलर्स और नैदानिक अनुसंधान में द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं को बल मिला, जिससे दोनों देश फार्मा नवाचार में संयुक्त रूप से योगदान दे सकें।

4. **स्वास्थ्य सेवाओं का आपसी आदान-प्रदान :** चिकित्सा प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन, और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति में सर्वोत्तम अभ्यासों के आदान-प्रदान को लेकर सहमति बनी।

5. **स्वास्थ्य एमओयू की प्रभावशीलता :** प्रधानमंत्री मोदी की हाल की यात्रा के दौरान हुए स्वास्थ्य समझौता ज्ञापन को कार्यान्वित करने और उसके माध्यम से स्थायी सहयोग ढांचे को मजबूत करने पर बल दिया गया।

6. **भारतीय फार्मा को नए अवसर :** नियामक समन्वय और मान्यता समझौतों के माध्यम से भारत की फार्मा कंपनियों को सऊदी बाजार तक बेहतर पहुँच मिलने की संभावना खुली है।

7. **आपदा प्रबंधन में समन्वय :** महामारी की तैयारी, स्वास्थ्य आपातकाल प्रतिक्रिया और संकट प्रबंधन में जानकारी और तकनीकी संसाधनों के साझा उपयोग के लिए संयुक्त रणनीति पर विचार हुआ।

रणनीतिक संबंधों को सशक्त आधार

1. **उच्च - स्तरीय नेतृत्व के साथ संवाद :** जेपी नड्डा ने सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान अल सऊद से भेंट कर रणनीतिक साझेदारी परिषद के ढांचे को आगे बढ़ाने पर चर्चा की।

2. **रणनीतिक साझेदारी परिषद (SPC) की सुदृढ़ता :** यह बैठक आर्थिक एवं निवेश समिति के कार्यों को मजबूती प्रदान करती है, जो SPC के अंतर्गत एक प्रमुख इकाई है।

3. **ऊर्जा और संसाधन कूटनीति का समन्वय :** उर्वरक, तेल, गैस, नवीकरणीय ऊर्जा और खनन के क्षेत्रों में सहयोग ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति विविधता के साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है।

4. **मल्टी-डोमेन सहयोग :** SPC ढांचा डिजिटल, स्वास्थ्य, रक्षा, अवसंरचना और रणनीतिक निवेश जैसे क्षेत्रों में भी द्विपक्षीय तालमेल को सशक्त करता है।

5. **द्विपक्षीय व्यापार में उछाल :** उर्वरक और स्वास्थ्य क्षेत्रों के नए समझौते 50 अरब डॉलर से अधिक के वार्षिक व्यापार संबंधों में ठोस योगदान करते हैं।

6. **कार्य प्रगति की निगरानी :** ऐसे उच्चस्तरीय दौरे समझौतों के कार्यान्वयन, समीक्षा और मूल्यांकन के लिए संस्थागत ढांचे को सक्रिय करते हैं।

7. **बहुध्रुवीय विश्व में साझा दृष्टिकोण :** यह रणनीतिक सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक एकजुटता और नवोदित बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में भारत-सऊदी साझेदारी को एक नई ऊँचाई पर ले जाता है।

भारत-सऊदी औद्योगिक और तकनीकी सहभागिता : सहयोग के नए आयाम

1. **मादेन की अत्याधुनिक सुविधा का अवलोकन :** केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने रास अल खैर में स्थित मादेन के विश्वस्तरीय फॉस्फेट संयंत्र का दौरा कर सऊदी अरब की उन्नत उत्पादन क्षमताओं और तकनीकी दक्षता का प्रत्यक्ष अवलोकन किया।

2. **प्रौद्योगिकीय साझेदारी की संभावनाएं :** यह यात्रा दाना निर्माण, मिश्रण तकनीक, और प्रक्रिया स्वचालन जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग की संभावनाओं को खोलने में सहायक रही, जिससे उर्वरक निर्माण में आधुनिक तकनीक हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त हुआ।

3. **भारतीय मानव संसाधन का कौशल संवर्धन :** मादेन की औद्योगिक इकाइयों में भारतीय इंजीनियरों और तकनीशियनों को प्रशिक्षण देने की योजनाएँ बनाई जा रही हैं, जिससे भारत की तकनीकी प्रतिभा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्नत किया जा सके।

4. **खनन एवं रसायन उद्योग में संयुक्त संभावनाएं :** उर्वरकों के अतिरिक्त, खनिज संसाधनों, पेट्रोकेमिकल्स और औद्योगिक रसायनों के क्षेत्र में संयुक्त निवेश व परियोजनाओं पर विचार हुआ, जिससे भारत और सऊदी अरब के बीच औद्योगिक सहयोग का विस्तार होगा।

5. **संयुक्त अवसंरचना विकास की दिशा में पहल :** दोनों देशों ने लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स और वेयरहाउसिंग नेटवर्क को उन्नत बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की, जिससे द्विपक्षीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला की कुशलता में वृद्धि हो सके।

6. **मेक इन इंडिया को बाह्य स्रोतों से समर्थन :** फॉस्फेट रॉक, सल्फर और अन्य कच्चे माल की सुरक्षित आपूर्ति के लिए औद्योगिक साझेदारी, भारत में उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को समर्थन दे सकती है।

7. **औद्योगिक सहयोग के लिए एक संस्थागत मंच :** मादेन के साथ संवाद से एक दीर्घकालिक, तकनीकी सहयोग आधारित औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की नींव रखी गई, जो भारत-सऊदी औद्योगिक रिश्तों को टिकाऊ बनाएगा।

भू-राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से साझेदारी का महत्व :

1. **आपूर्ति स्रोतों में विविधता :** चीन और मोरक्को जैसे सीमित आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने हेतु, सऊदी अरब के साथ दीर्घकालिक अनुबंध भारत की रणनीतिक प्राथमिकता के अनुरूप है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

2. **सऊदी अरब की एशिया-केंद्रित नीति :** यह सहयोग सऊदी अरब के 'पूर्व की ओर झुकाव' की नीति का संकेत देता है, जिसमें भारत को एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्वीकार किया गया है।

3. **ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा की कूटनीति :** भारत खाद्य उत्पादन के लिए आवश्यक इनपुट्स की सुरक्षा हेतु, उसी प्रकार कूटनीतिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है जैसे वह ऊर्जा क्षेत्र में करता रहा है।

4. **राजनीतिक विश्वास और रणनीतिक एकता :** बहु-आयामी समझौतों से राजनयिक भरोसा गहराता है और भारत को विजन 2030 जैसे सऊदी विकास लक्ष्यों से रणनीतिक रूप से जोड़ता है।

5. **स्थिर आपूर्ति मार्गों का निर्माण :** लाल सागर और यूरोप में जारी भू-राजनीतिक तनावों के बीच, यह साझेदारी स्थिर, सुलभ और सुरक्षित आपूर्ति मार्ग सुनिश्चित करने में सहायक होगी।

6. **आर्थिक पूरकता का लाभ :** भारत की उर्वरक मांग और सऊदी अरब की कच्चे माल की समृद्धता एक-दूसरे के पूरक हैं, जिससे दोनों देशों को पारस्परिक लाभ होगा।

7. **दक्षिण-दक्षिण सहयोग का आदर्श :** यह सहयोग वैश्विक दक्षिण में रणनीतिक और आर्थिक एकता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं की सशक्त आवाज़ बनता जा रहा है।

प्रमुख चुनौतियाँ और आगे की राह :

1. **लॉजिस्टिक्स अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण :** 3.1 एमएमटी डीएपी के वार्षिक प्रबंधन के लिए भारत को अपने बंदरगाहों और अंतर्देशीय लॉजिस्टिक्स ढांचे में संरचनात्मक सुधार करने होंगे।

2. **समयबद्ध आपूर्ति प्रणाली :** बुवाई के महत्वपूर्ण मौसमों को ध्यान में रखते हुए, समय पर शिपमेंट और क्लीयरेंस प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

3. **मूल्य स्थिरता हेतु रणनीतिक मूल्य निर्धारण :** भारत को वैश्विक बाजारों में फॉस्फेट एवं गैस मूल्यों में अस्थिरता से बचने के लिए दीर्घकालिक मूल्य निर्धारण अनुबंधों पर बातचीत करनी होगी।

4. **स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अनुसंधान :** फसल-विशिष्ट एवं जलवायु-अनुकूल उर्वरकों के विकास हेतु, भारत-सऊदी संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की आवश्यकता है।

5. **अनुबंधों की पारदर्शी निगरानी :** प्रगति की समीक्षा, समयबद्ध निष्पादन और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु मजबूत संस्थागत निगरानी प्रणाली का निर्माण जरूरी है।

6. **स्वदेशी उत्पादन बनाम आयात संतुलन :** नीति निर्धारण में भारत को घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन और आयात की निर्भरता को संतुलित रखने की रणनीति अपनानी होगी।

7. **नियामक प्रक्रियाओं में समरूपता :** सीमा शुल्क और नियामक प्रक्रियाओं के सरलीकरण से द्विपक्षीय औद्योगिक सहयोग अधिक सुचारु और लागत प्रभावी बनेगा।

निष्कर्ष :

- केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा की जुलाई 2025 में सऊदी अरब यात्रा ने भारत-सऊदी संबंधों को विशेषकर उर्वरक, रसायन, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने की दिशा में एक नई रणनीतिक ऊँचाई प्रदान किया है।
- 3.1 मिलियन मीट्रिक टन DAP की वार्षिक आपूर्ति हेतु हुए दीर्घकालिक समझौतों ने कृषि इनपुट की सुनिश्चित, स्थिर और पूर्वानुमान योग्य आपूर्ति की दिशा में भारत के दृष्टिकोण को अधिक सुदृढ़ और विविध बनाया है।
- यह साझेदारी न केवल भारत की खाद्य सुरक्षा और उर्वरक आत्मनिर्भरता को मजबूत करती है, बल्कि ऊर्जा और संसाधन कूटनीति के क्षेत्र में भी भारत की रणनीतिक परिपक्वता को दर्शाती है।
- यह बहु-क्षेत्रीय सहयोग, भारत की 'आत्मनिर्भर भारत' नीति के अनुरूप, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में स्थायित्व, लचीलापन और साझा समृद्धि की दिशा में एक निर्णायक कदम है।
- इसके माध्यम से भारत और सऊदी अरब एक दीर्घकालिक, समानता-आधारित और रणनीतिक साझेदारी की ओर अग्रसर हैं, जो आने वाले वर्षों में और अधिक विस्तार और गहराई प्राप्त करेगी।

स्त्रोत - डी.डी न्यूज।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित भारत-सऊदी अरब उर्वरक सहयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस समझौते के तहत पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष 3.1 मिलियन मीट्रिक टन डायम्मोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
2. इस सौदे में एक प्रावधान शामिल है जो अतिरिक्त पांच वर्षों के लिए पारस्परिक विस्तार की अनुमति देता है।
3. 2024-25 में सऊदी अरब से भारत का कुल डीएपी आयात पहले से ही 3 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक था।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3

उत्तर - A

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत की खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा-संसाधन कूटनीति और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के संदर्भ में इस समझौते के महत्व पर चर्चा करें।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

आरबीआई का आर्थिक पूर्वानुमान : भारत की विकास दर और इसका वैश्विक प्रभाव

पाठ्यक्रम - सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 3 - भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास - RBI का आर्थिक पूर्वानुमान: भारत की विकास गति और वैश्विक प्रभाव।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु :

वस्तु एवं सेवा कर, अप्रत्यक्ष कर, डिजिटल अर्थव्यवस्था, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, जनसांख्यिकीय लाभांश, आत्मनिर्भर भारत अभियान, मेक इन इंडिया पहल

मुख्य परीक्षा हेतु :

तीव्र विकास के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था किन चुनौतियों का सामना कर रही है? हाल के वर्षों में भारत के आर्थिक विकास के प्रमुख कारक क्या हैं?

खबरों में क्यों?

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक विकास के प्रमुख चालक के रूप में उजागर किया।
- अपने नवीनतम पूर्वानुमान में, RBI ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत के मजबूत जीडीपी प्रदर्शन, व्यापक आर्थिक स्थिरता और लचीलेपन पर जोर दिया। मजबूत घरेलू मांग, बढ़ते निवेश और निर्यात के विस्तार के साथ, भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है।
- RBI ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और डिजिटल नवाचार में भारत की बढ़ती भूमिका की ओर भी इशारा किया। यह मान्यता महामारी के बाद वैश्विक आर्थिक सुधार को आकार देने में भारत के उभरते नेतृत्व को पुष्ट करती है।

वैश्विक संदर्भ में भारत का आर्थिक प्रदर्शन :

1. **सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था :** वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की विकास दर लगभग 7.2% रहने की उम्मीद है, जो चीन, अमेरिका और यूरोजोन से बेहतर प्रदर्शन करेगी।
2. **वैश्विक मंदी का विरोधाभास :** भले ही विश्व की कई उन्नत अर्थव्यवस्थाएं गतिरोध का सामना कर रही हैं, वहीं भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक लचीली और बढ़ती हुई शक्ति बना हुआ है।
3. **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ती हिस्सेदारी :** भारत अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी के संदर्भ में) में इसका योगदान 7% से अधिक है।
4. **वैश्विक मांग को बढ़ावा :** बढ़ता मध्यम वर्ग और उपभोग आधारित विकास भारत को वैश्विक मांग में प्रमुख योगदानकर्ता बनाता है।
5. **सेवा व्यापार का पावर हाउस :** भारत आईटी और डिजिटल सेवाओं का अग्रणी निर्यातक है, जो वैश्विक तकनीक-संचालित विकास में सहायता कर रहा है।
6. **एफडीआई प्रवाह :** स्थिर नीतियों और मजबूत बुनियादी बातों ने रिकॉर्ड एफडीआई प्रवाह को आकर्षित किया, जिससे वैश्विक निवेशकों का विश्वास बढ़ा।
7. **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भूमिका :** पीएलआई, एफटीए और मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत वैश्विक विनिर्माण श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय कड़ी बन रहा है।

घरेलू विकास के चालक :

1. **पूंजीगत व्यय को बढ़ावा :** सरकार का बढ़ता पूंजीगत व्यय, विशेष रूप से सड़क, रेलवे और लॉजिस्टिक्स में, निजी निवेश को आकर्षित कर रहा है और रोजगार को बढ़ावा दे रहा है।
2. **बुनियादी ढांचे का विस्तार :** पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) जैसी प्रमुख पहल कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स दक्षता और व्यापार करने में आसानी को बढ़ा रही हैं।

3. **निजी क्षेत्र का पुनरुद्धार :** कॉर्पोरेट ऋण शोधन, पीएलआई प्रोत्साहन और बेहतर कारोबारी विश्वास के कारण सभी क्षेत्रों में निजी निवेश का चक्र नए सिरे से चल रहा है।

4. **तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था :** यूपीआई, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) और फिनटेक नवाचार को तेजी से अपनाने से सेवा वितरण में बदलाव आ रहा है और औपचारिक अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है।

5. **मध्यम वर्ग का विस्तार :** बढ़ती आय और शहरीकरण घरेलू खपत को बढ़ावा दे रहे हैं, विशेष रूप से आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और खुदरा क्षेत्र में।

6. **वित्तीय समावेशन और ऋण वृद्धि :** जेएएम ट्रिनिटी, डीबीटी और जन धन खातों ने वित्तीय पहुंच को बढ़ाया है, जबकि खुदरा ऋण और एमएसएमई ऋण लगातार बढ़ रहे हैं।

7. **ग्रामीण विकास पर केंद्रित :** प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएमजीएसवाई और मनरेगा जैसी योजनाएं ग्रामीण बुनियादी ढांचे, मांग और आजीविका में सुधार कर रही हैं।

8. **जनसांख्यिकीय लाभांश और कौशल विकास पर केंद्रित :** भारत की युवा आबादी और स्किल इंडिया जैसी पहल उत्पादकता और कार्यबल भागीदारी को बढ़ा रही हैं।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका :

1. **चीन+1 रणनीति :** भू-राजनीतिक और आपूर्ति संबंधी व्यवधानों के कारण वैश्विक निर्माता चीन से अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। भारत अपनी स्थिर नीतियों और युवा कार्यबल के कारण चीन+1 रणनीति के तहत एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहा है।

2. **मेक इन इंडिया पहल :** मेक इन इंडिया मिशन मानदंडों को आसान बनाकर, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देकर और स्थानीय मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करके इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, ऑटोमोटिव और वस्त्र उद्योग में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है।

3. **आत्मनिर्भर भारत अभियान :** भारत का लक्ष्य घरेलू क्षमता निर्माण और रणनीतिक नीति समर्थन के माध्यम से रक्षा, अर्धचालक और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता कम करना है।

4. **विनिर्माण के लिए पीएलआई योजनाएं :** इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर पीवी, फार्मा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं निवेश आकर्षित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है।

5. **रसद और बुनियादी ढांचे में सुधार :** पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के तहत परियोजनाएं उद्योग के लिए टर्नअराउंड समय को कम कर रही हैं और अंतिम-मील कनेक्टिविटी को बढ़ा रही हैं।

6. **निर्यातोन्मुख विकास :** भारत नीति और वैश्विक गठजोड़ के माध्यम से मोबाइल फोन, जेनेरिक दवाओं और सटीक इंजीनियरिंग वस्तुओं के प्रमुख निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बना रहा है।

7. **जी.वी.सी. में सेवाओं का एकीकरण :** भारत की आईटी, डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास, तथा बीपीएम सेवाएं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का अभिन्न अंग बन रही हैं, तथा वैश्विक उत्पादन में उच्च-मूल्य, कौशल-आधारित इनपुट जोड़ रही हैं।

8. **आपूर्ति श्रृंखलाओं में एमएसएमई की भागीदारी :** सरकारी योजनाएं एमएसएमई को वित्त तक पहुंच, परिचालन को डिजिटल बनाने और वैश्विक ओईएम के लिए आपूर्तिकर्ता बनने में सक्षम बना रही हैं।

बाह्य क्षेत्र लचीलापन :

1. **मजबूत निर्यात प्रदर्शन :** वैश्विक व्यापार संबंधी चुनौतियों के बावजूद भारत का वस्तुओं (जैसे इंजीनियरिंग, वस्त्र, फार्मा) और सेवाओं (आईटी, परामर्श) का निर्यात मजबूत बना हुआ है।

2. **स्थिर चालू खाता प्रबंधन :** सेवा व्यापार अधिशेष और प्रवासी भारतीयों से आने वाली मजबूत धन-प्रेषण राशि के कारण चालू खाता घाटा प्रबंधकीय बना हुआ है।

3. **उच्च विदेशी मुद्रा भंडार :** भारत के पास 600 बिलियन डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो समष्टि आर्थिक स्थिरता को मजबूत करता है तथा मुद्रा अस्थिरता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।

4. **निरंतर एफडीआई प्रवाह :** वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद, निवेशकों के विश्वास और सुधारों के कारण भारत डिजिटल तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एफडीआई आकर्षित कर रहा है।

5. **विविध व्यापार साझेदार :** भारत का निर्यात अमेरिका, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात और आसियान जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अच्छी तरह से वितरित है, जिससे किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो जाती है।

6. **रणनीतिक व्यापार समझौते :** संयुक्त अरब अमीरात के साथ सीईपीए तथा यूके, ईयू और ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्ता का उद्देश्य व्यापार बाधाओं को कम करना तथा भारतीय उत्पादों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना है।

7. **भारतीय रुपया व्यापार को बढ़ावा देना :** भारत रूस, संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका जैसे देशों के साथ भारतीय रुपये में व्यापार निपटान की अनुमति देकर रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर जोर दे रहा है।

8. **सहायक बाह्य क्षेत्र नीतियां :** आरओडीटीईपी, एसईजेड सुधार और लॉजिस्टिक्स समर्थन जैसी निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं भारत की बाह्य क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करती हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

संरचनात्मक और नीतिगत सुधार :

1. **अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए जीएसटी :** वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन में सुधार किया है तथा एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन किया है।

2. **दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) और वित्तीय अनुशासन :** दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) ने ऋण समाधान में सुधार किया है और एनपीए को कम किया है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति मजबूत हुई है।

3. **डीबीटी और जेएएम त्रिमूर्ति :** जन धन, आधार और मोबाइल (जेएएम) त्रिमूर्ति के ज़रिए दी जाने वाली सीधी लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना से सब्सिडी का सीधा लाभ सही लोगों तक पहुँचता है, जिससे भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग में कमी आती है।

4. **लचीलेपन के लिए श्रम सुधार :** चारों श्रम संहिताओं का उद्देश्य श्रमिक संरक्षण और व्यावसायिक लचीलेपन के बीच संतुलन स्थापित करना, तथा नियुक्ति में आसानी और औपचारिकता को बढ़ाना है।

5. **वित्तीय समावेशन को बढ़ावा :** 50 करोड़ से अधिक जन धन खातों, डिजिटल बैंकिंग विस्तार और माइक्रो फाइनेंस पहुंच से ऋण और बचत तक पहुंच में सुधार हुआ है।

6. **अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण :** यूपीआई, ई-श्रम, जीएसटीआईएन और डिजिटल भुगतान ने औपचारिक अर्थव्यवस्था का विस्तार किया है और कर राजस्व में सुधार किया है।

7. **व्यापार करने में आसानी संबंधी सुधार :** भारत ने एकल खिड़की मंजूरी, ऑनलाइन पोर्टल और सरलीकृत अनुपालन के माध्यम से लालफीताशाही को समाप्त कर दिया है, तथा विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित किया है।

8. **हरित संक्रमण नीतियां :** भारत नेट-जीरो 2070 रोडमैप के तहत सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, ईवी और कार्बन बाजारों को समर्थन देकर एक स्वच्छ अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है।

बहुपक्षीय मंचों पर भारत का नेतृत्व :

1. **G-20 प्रेसीडेंसी के रूप में योगदान :** भारत ने अपनी जी-20 अध्यक्षता का उपयोग डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जलवायु वित्त और वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को उजागर करने के लिए किया, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सर्वसम्मति वाले परिणाम सामने आए।

2. **वैश्विक दक्षिण के लिए वकालत :** भारत ब्रिक्स, जी-20 और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर विकासशील देशों की आवश्यकताओं को उठा रहा है तथा अधिक न्यायसंगत वैश्विक नियमों और संसाधनों के बंटवारे की मांग कर रहा है।

3. **डिजिटल गवर्नेंस में नेतृत्व :** भारत समावेशी तकनीकी विनियमन के मॉडल के रूप में नैतिक एआई, ओपन-सोर्स डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं और डेटा संप्रभुता की वकालत करता है।

4. **क्वाड, आईपीईएफ में भागीदारी :** भारत आर्थिक सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और क्षेत्रीय सहयोग को आकार देने वाले हिंद-प्रशांत मंच का एक प्रमुख सदस्य है।

5. **जलवायु कूटनीति नेतृत्व :** आईएसए, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन और एलआईएफई जैसी पहलें वैश्विक जलवायु लचीलेपन की कहानी को आकार दे रही हैं।

6. **स्वास्थ्य और वैक्सीन कूटनीति :** वैक्सीन मैत्री के माध्यम से भारत ने 90 से अधिक देशों को कोविड-19 टीके की आपूर्ति की, जिससे सॉफ्ट पावर और मानवीय नेतृत्व को मजबूती मिली।

7. **ब्रिक्स और SCO सहयोग :** भारत ब्रिक्स, एससीओ और एनएएम में सक्रिय भूमिका के माध्यम से बहुध्रुवीयता और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देता है।

8. **संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना एवं सहायता :** भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में योगदान देने वाले शीर्ष देशों में से एक है तथा एशिया और अफ्रीका में आपदा राहत सहायता प्रदान करता है।

मुख्य चुनौतियाँ और खतरे :

1. **वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितता :** रूस-यूक्रेन जैसे संघर्ष और पश्चिम एशिया में तनाव के कारण व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला और तेल की कीमतें बाधित होती हैं, जिससे भारत के लिए बाह्य झटके उत्पन्न होते हैं।

2. **तेल और ऊर्जा निर्भरता :** भारत का 85% से अधिक कच्चा तेल आयात किया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था मूल्य वृद्धि और मुद्रा दबाव के प्रति संवेदनशील हो जाती है।

3. **जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता :** भारत में गर्म लहरों, बाढ़ और अनियमित मानसून का अत्यधिक प्रभाव रहता है, जिससे कृषि, जल सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रभावित होता है।

4. **रोजगार सृजन अंतराल :** उच्च सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के बावजूद रोजगार सृजन, विशेषकर विनिर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों में, एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है।

5. **कौशल और शिक्षा में अंतर :** युवाओं के एक बड़े वर्ग में उद्योग-संबंधित कौशल का अभाव है, जिससे शिक्षा-रोजगार के बीच अंतर को पाटने की आवश्यकता उजागर होती है।

6. **शहरी बुनियादी ढांचे की कमी :** तीव्र शहरीकरण के कारण प्रमुख शहरों में आवास, जल, अपशिष्ट प्रबंधन और परिवहन प्रणालियों पर दबाव पड़ रहा है।

7. **क्षेत्रीय और सामाजिक असमानता :** क्षेत्रीय और सामाजिक असमानता के बीच आर्थिक और मानव विकास असमानताओं को दूर करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

8. **राजकोषीय दबाव और ऋण :** उच्च सार्वजनिक ऋण और सब्सिडी का बोझ सरकार के पूंजीगत और सामाजिक व्यय के लिए राजकोषीय स्थान को सीमित कर देता है।

समाधान / आगे की राह :

1. **मानव संसाधन में निवेश करने की आवश्यकता :** दीर्घकालिक विकास और समावेशन के लिए स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण को मजबूत करना आवश्यक है।

2. **नवाचार और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना :** सार्वजनिक और निजी अनुसंधान एवं विकास व्यय में वृद्धि करना, गहन तकनीक स्टार्टअप्स को समर्थन देना, तथा शिक्षा जगत और उद्योग के बीच संबंध बनाना।

3. **वित्तीय बाज़ारों को गहरा करना :** बुनियादी ढांचे और स्टार्टअप के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड, बीमा और दीर्घकालिक पूंजी तक पहुंच को व्यापक बनाएं।

4. **हरित विकास में तेजी लाने की जरूरत :** नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दें, हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा दें, तथा जलवायु-अनुकूल कृषि और बुनियादी ढांचे को समर्थन दें।

5. **शहरी सुधार और स्मार्ट शहर :** शहरी शासन, किफायती आवास, मेट्रो नेटवर्क और टिकाऊ शहरी गतिशीलता को बढ़ाएं।

6. **कृषि परिवर्तन :** उत्पादकता में सुधार, फसल विविधीकरण, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना तथा किसानों को ई-बाजारों से जोड़ना।

7. **संघवाद को मजबूत करना :** प्रतिस्पर्धी विकास को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय संसाधनों, नीतिगत लचीलेपन और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों के साथ राज्यों को सशक्त बनाएं।

8. **नीति निरंतरता और शासन सुनिश्चित करना :** नीतिगत स्थिरता बनाए रखें, न्यायिक दक्षता में सुधार करें, परियोजना मंजूरी में देरी को कम करें और संस्थागत क्षमता का निर्माण करें।

निष्कर्ष :

वैश्विक विकास के एक प्रमुख इंजन के रूप में भारत का उभरना मजबूत घरेलू बुनियादी बातों, लक्षित नीति सुधारों और रणनीतिक वैश्विक जुड़ाव के संयोजन को दर्शाता है। वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच, भारत की लचीलापन - मजबूत निवेश, डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार और बढ़ते मध्यम वर्ग द्वारा संचालित - इसे स्थिरता और अवसर के एक प्रकाशस्तंभ के रूप में स्थापित करता है। RBI की मान्यता वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को आकार देने, समावेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक दक्षिण के हितों की वकालत करने में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है।

स्त्रोत - पी. आई . बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. आरबीआई के हालिया आकलन के अनुसार, निम्नलिखित में से किन कारकों ने भारत को वैश्विक विकास के प्रमुख इंजन के रूप में उभरने में योगदान दिया है?

1. बढ़ता सार्वजनिक पूंजीगत व्यय
2. डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का विस्तार
3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट
4. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकरण बढ़ाना

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1, 2 और 4

(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1, 3 और 4

उत्तर - (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. "भारत की आर्थिक प्रगति वैश्विक सुधार और वृद्धि के लिए तेजी से केंद्रीय होती जा रही है।" इस संदर्भ में, भारत के आर्थिक प्रदर्शन के प्रमुख घरेलू और बाहरी चालकों तथा इस गति को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

स्वास्थ्य बनाम राजस्व : तम्बाकू नियंत्रण से जीएसटी पर पड़ने वाला आर्थिक प्रभाव

खबरों में क्यों?

- हाल ही में 1 जुलाई, 2025 को भारत ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली की आठवीं वर्षगांठ मनाई है। इस अवसर पर जहां जीएसटी की उपलब्धियों की चर्चा हुई, वहीं इसकी अधूरी पहलुओं पर भी बहस ने फिर से जोर पकड़ा है। खासतौर पर तंबाकू उत्पादों पर कर दरों को लेकर चिंता जताई जा रही है।
- भारत में जीएसटी के लागू होने के बाद भले ही राजस्व संग्रह में वृद्धि और आर्थिक गतिविधियों के औपचारिकीकरण जैसे सकारात्मक परिणाम सामने आए हों, लेकिन तंबाकू जैसे हानिकारक पदार्थों पर कर दरों में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं हुई है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानकों के अनुरूप कार्य करने के लिए अब जीएसटी और उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी की आवश्यकता है।
- वर्तमान में जीएसटी परिषद द्वारा दरों के पुनरीक्षण और सरलीकरण की प्रक्रिया चल रही है, जिसे तंबाकू कर नीति में सुधार के लिए एक उपयुक्त अवसर के रूप में देखा जा रहा है।

जीएसटी : राजकोषीय मजबूती से लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य तक

आर्थिक परिदृश्य में जीएसटी का योगदान :

- **राजस्व में निरंतर वृद्धि :** वित्त वर्ष 2024–25 में जीएसटी से कुल कर संग्रह ₹22.08 लाख करोड़ पर पहुँच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.4% अधिक है। यह वृद्धि सिर्फ आर्थिक सुधार का संकेत नहीं है, बल्कि यह बेहतर अनुपालन प्रणाली और व्यापक कर आधार की सफलता को भी रेखांकित करती है।

प्रणालीगत दक्षता और व्यापार सुगमता में सुधार :

1. **लागत में कटौती :** इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के माध्यम से बहुस्तरीय कर ढांचे को तर्कसंगत बनाते हुए उत्पादन की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है।
2. **डिजिटल पारदर्शिता :** ई-इनवॉइस और ई-वे बिल जैसे उपकरणों ने टैक्स चोरी पर लगाम लगाने और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में सहायता की है।
3. **लॉजिस्टिक के क्षेत्र में तेजी आना :** राज्यों के बीच चेक पोस्ट हटाए जाने के बाद परिवहन समय में लगभग 20% की कमी और आपूर्ति श्रृंखला की प्रभावशीलता में सुधार देखा गया है।

तंबाकू कराधान : जीएसटी के अंतर्गत एक अनसुलझा मुद्दा

- **स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ :** भारत में तंबाकू के सेवन से प्रतिदिन 3,500 से अधिक लोगों की मृत्यु होती है। इससे देश को सालाना ₹2.34 लाख करोड़ का बोझ उठाना पड़ता है — जिसमें उपचार लागत और श्रम उत्पादकता में गिरावट दोनों शामिल हैं। इसके बावजूद, तंबाकू नियंत्रण में कर नीति का पूर्ण उपयोग अब तक नहीं किया गया है।
- **कर नीतियों में स्थिरता :** जीएसटी लागू होने से पहले समय-समय पर कर वृद्धि से तंबाकू की खपत में 17% तक की गिरावट दर्ज की गई थी। परंतु, जीएसटी के बाद प्रभावी कर दरों में कोई विशेष वृद्धि नहीं की गई, जिससे इसका नियंत्रणकारी प्रभाव कमजोर पड़ गया है।
- **अपर्याप्त कर बोझ और वैश्विक मानकों से विचलन :** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की अनुशंसा के अनुसार तंबाकू पर कुल कर बोझ खुदरा मूल्य के न्यूनतम 75% तक होना चाहिए। भारत में यह दरें इससे काफी नीचे हैं:
- बीड़ी – लगभग 22%
- सिगरेट – लगभग 54%
- धूम्र रहित तंबाकू – लगभग 65%
- विशुद्ध मूल्य आधारित कर व्यवस्था सस्ते उत्पादों (जैसे बीड़ी) के लिए अप्रभावी सिद्ध होती है, जिससे व्यापक उपयोग बना रहता है।

कर संरचना में असमानता और उसकी सामाजिक लागत :

- **वित्तीय असमानता का दायरा :** सिगरेट उपभोक्ताओं की संख्या कुल तंबाकू उपयोगकर्ताओं का केवल 15% है, परंतु तंबाकू कर राजस्व में इसका योगदान 80% से अधिक है। दूसरी ओर, बीड़ी जैसे उत्पादों—जो मुख्यतः गरीब, ग्रामीण और आदिवासी समुदायों में उपयोग होते हैं—पर अपेक्षाकृत कम कर लगने से स्वास्थ्य असमानता और वित्तीय अन्याय गहरा होता जा रहा है।

नीतिगत प्रस्ताव :

- **कर दरों में पुनः संरचना और बदलाव की जरूरत :** सभी प्रकार के तंबाकू उत्पादों, विशेषकर बीड़ी को, 40% के उच्चतम कर स्लैब में शामिल किया जाए।
- **विशिष्ट उत्पाद शुल्क की पुनर्स्थापना :** बीड़ी और धूम्र रहित उत्पादों पर स्थिर राशि आधारित करों को पुनः लागू कर उन्हें सशक्त किया जाए।

- **संकर कर मॉडल को अपनाने की आवश्यकता :** संकर कर प्रणाली को अपनाया जाए, जिसमें मूल्य-आधारित और मात्रा-आधारित दोनों घटक हों, ताकि यह कर प्रभावशीलता, पूर्वानुमेयता और स्वास्थ्य प्रभाव सुनिश्चित कर सके।

अवैध व्यापार : प्रचार और वास्तविकता के बीच अंतर :

- **तथ्य बनाम भ्रांतियाँ :** तंबाकू कंपनियों द्वारा अक्सर यह दावा किया जाता है कि अधिक कर दरों के कारण अवैध व्यापार फलता-फूलता है और इसकी हिस्सेदारी 25% तक हो सकती है। परंतु स्वतंत्र अध्ययनों के अनुसार यह आंकड़ा महज 2.7% से 6.6% के बीच है, जो उद्योग के दावों को असत्यापित बनाता है।
- **प्रवर्तन तंत्र की भूमिका :** अवैध व्यापार का मुख्य कारण कर दरें नहीं, बल्कि निम्न स्तर की निगरानी, सीमाओं की सुरक्षा में खामियाँ और नियामक तंत्र की कमजोरियाँ हैं। भारत भले ही WHO के तंबाकू-विरोधी अवैध व्यापार प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता है, लेकिन उसका क्रियान्वयन अब तक सीमित रहा है।
- **नीतिगत निष्कर्ष :** अवैध व्यापार को नियंत्रित करने का उत्तर करों में कटौती नहीं, बल्कि शासन की पारदर्शिता, प्रवर्तन क्षमता और निगरानी में सुदृढ़ता है। अतः स्पष्ट है कि समाधान कर कटौती में नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में है।

विधिक, संस्थागत और वैश्विक उत्तरदायित्व : तंबाकू कराधान के व्यापक आयाम

संवैधानिक और संस्थागत परिप्रेक्ष्य :

- भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 279ए के अंतर्गत स्थापित जीएसटी परिषद के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह परिषद देशभर में कर संरचना की समानता बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाती है।
- हालांकि, तंबाकू पर अब भी क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता है, लेकिन जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद विशिष्ट उत्पाद शुल्क, विशेषकर बीड़ी जैसे उत्पादों पर, लगभग समाप्त हो गया है। इससे कर संरचना में एक महत्वपूर्ण नियामक उपकरण की कमी महसूस की जा रही है, जिसने पहले तंबाकू नियंत्रण में अहम भूमिका निभाई थी।

अंतरराष्ट्रीय संधिबद्ध दायित्व :

- भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के तंबाकू नियंत्रण हेतु फ्रेमवर्क कन्वेंशन (FCTC) पर हस्ताक्षर कर रखे हैं, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सदस्य देशों को तंबाकू की खपत को घटाने के लिए वित्तीय और कराधान संबंधी उपाय अपनाने चाहिएँ।
- हालांकि, वर्तमान में भारत में तंबाकू पर प्रभावी कर दरें इन अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से पीछे हैं, जिससे संधि के अनुपालन पर प्रश्नचिह्न लगता है।

वैश्विक अनुभवों से सीख प्राप्त करना :

- भारत के अतिरिक्त अन्य देशों के अनुभव यह दर्शाते हैं कि उच्च कर और मजबूत नीतियाँ किस तरह जन स्वास्थ्य में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती हैं।
- थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देशों ने तंबाकू और मद्य पर 'पाप कर' (sin tax) लगाकर न केवल उपभोग घटाया है, बल्कि उससे अर्जित राजस्व से अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों का वित्तपोषण भी किया है।
- ऑस्ट्रेलिया ने वार्षिक कर वृद्धि और सादे पैकेजिंग कानूनों के ज़रिए दुनिया की सबसे कम धूम्रपान दरों में से एक हासिल की है।
- भारत भी इन उदाहरणों से प्रेरणा लेकर, विशिष्ट करों को नियमित रूप से बढ़ाने, और उस राजस्व को आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं में निवेश करने की दिशा में ठोस कदम उठा सकता है।

पर्यावरणीय और नैतिक पक्ष :

- तंबाकू की खेती केवल स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
- यह वनों की कटाई, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट, और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग में योगदान देती है।
- यह विशेष रूप से बीड़ी उद्योग, सामाजिक दृष्टिकोण से भी चिंताजनक है, जहाँ अक्सर बाल श्रम, कम मजदूरी और असुरक्षित कार्य स्थितियाँ देखी जाती हैं।
- नैतिक दृष्टिकोण से, एक ऐसा उत्पाद जो जनस्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक हो, उस पर आधारित राजस्व नीति विकास की नैतिक अवधारणा से मेल नहीं खाती। अतः बीड़ी निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को वैकल्पिक एवं सुरक्षित आजीविका की ओर स्थानांतरित करने की दिशा में तत्परता आवश्यक है।

निष्कर्ष :

1. भारत इस समय जीएसटी दरों के पुनर्मूल्यांकन और तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया में है। यह एक नीतिगत अवसर है, जिसमें तंबाकू कराधान को बहुआयामी लक्ष्यों के अनुरूप ढाला जा सकता है। इसके तहत उच्चतम कर स्लैब में तंबाकू उत्पादों को शामिल करना,विशिष्ट उत्पाद शुल्क की पुनर्स्थापना और उसमें वृद्धि और प्रवर्तन प्रणाली को सशक्त बनाना शामिल है।
2. इस तरह के सभी उपाय तंबाकू कर नीति को स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही के साथ संगत बनाएंगे।
3. तंबाकू कराधान को अब केवल राजस्व स्रोत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह संवैधानिक जिम्मेदारी, नैतिक उत्तरदायित्व और जनस्वास्थ्य की प्राथमिकता का संवेदनशील बिंदु है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

4. अतः तंबाकू कराधान अब सिर्फ आर्थिक निर्णय नहीं है, यह संविधान सम्मत जिम्मेदारी, नैतिक अनिवार्यता, और स्वास्थ्य नीति का मूल स्तंभ बन चुका है।

5. एक न्यायपूर्ण और सशक्त कर नीति न केवल लाखों लोगों के जीवन को सुरक्षित कर सकती है, बल्कि दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की आधारशिला भी रख सकती है।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. जीएसटी के तहत भारत में तम्बाकू कराधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सभी तम्बाकू उत्पादों पर वर्तमान में 40% की उच्चतम जीएसटी स्लैब पर कर लगाया जाता है।
2. भारत में तम्बाकू कर राजस्व में बीड़ी का योगदान सबसे अधिक है।
3. भारत तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क कन्वेंशन का एक पक्षकार के रूप में है।
4. जीएसटी कार्यान्वयन के बाद तम्बाकू उत्पादों पर विशिष्ट उत्पाद शुल्क पूरी तरह बरकरार रखा गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 3

C. केवल 1, 3 और 4 D. केवल 2 और 4

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत तंबाकू कराधान की वर्तमान सीमाओं का मूल्यांकन करते हुए चर्चा कीजिए कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को ध्यान में रखते हुए तंबाकू कराधान को अधिक प्रभावी बनाने हेतु कौन-से नीतिगत सुधार आवश्यक है?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत के कृषि-निर्यात का भविष्य दांव पर : व्यापार वार्ता में जीएम आयात का प्रभाव

ख़बरों में क्यों?

- हाल ही में आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने चेतावनी दी है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते - जिसे 9 जुलाई, 2025 से पहले अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है - के भारत के कृषि निर्यात, विशेष रूप से यूरोपीय संघ के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं, यदि यह सोयाबीन भोजन और डीडीजीएस जैसे आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) कृषि उत्पादों के आयात की अनुमति देता है।

जीएम फसल क्या होता है?

आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलें वे पौधे हैं जिनके डीएनए को आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके वांछित गुण प्रदान करने के लिए परिवर्तित किया गया है। इन संशोधनों में फसल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रजातियों (बैक्टीरिया, वायरस, या अन्य पौधों/जंतुओं) के जीनों को सम्मिलित किया जाता है।

जीएम फसलों में शामिल सामान्य लक्षण :

1. **कीट प्रतिरोध :** फसलों को विशिष्ट कीटों के लिए विषैले प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए तैयार किया जाता है।

   उदाहरण : बैसिलस थुरिंजिएंसिस से प्राप्त बीटी जीन पौधों को बॉलवर्म और अन्य कीटों को मारने में मदद करता है।

2. **शाकनाशी सहिष्णुता :** फसलें खरपतवार नाशक के प्रयोग से बच सकती हैं जो खरपतवारों को मारते हैं। इससे हाथ से निराई कम होती है और श्रम लागत बचती है।

3. **रोग प्रतिरोधक क्षमता :**आनुवंशिक गुण फसलों को विषाणु या फफूंद जनित रोगों से बचाते हैं।

4. **बेहतर शेल्फ-लाइफ और पोषण :** भंडारण अवधि बढ़ाने या पोषक तत्व जोड़ने के गुण (उदाहरण के लिए, विटामिन ए युक्त गोल्डन राइस)।

भारत की जीएमओ-मुक्त प्रतिष्ठा और कृषि निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता :

1. **प्रमुख बाजारों में सख्त जीएम विनियम :** भारतीय कृषि उत्पादों का एक प्रमुख आयातक, यूरोपीय संघ (ईयू), जीएम लेबलिंग और ट्रेसेबिलिटी के कड़े मानदंडों को लागू करता है। जीएम सामग्री की थोड़ी सी भी मात्रा शिपमेंट अस्वीकृति या कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकती है।
2. **जीएम उत्पादों के प्रति उपभोक्ताओं की उच्च संवेदनशीलता :** यूरोपीय उपभोक्ता जीएमओ-मुक्त खाद्य पदार्थों को अधिक पसंद करते हैं, विशेष रूप से जैविक उत्पादों, शिशु आहार और प्राकृतिक स्वास्थ्य पूरकों जैसी संवेदनशील श्रेणियों में, जिससे भारतीय कृषि-निर्यात की मांग प्रभावित होती है।
3. **जोखिम में मुख्य निर्यात वस्तुएं :** बासमती चावल, जैविक शहद, चाय, मसाले और आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियाँ जैसे भारतीय निर्यातों को प्राकृतिक और जीएमओ-मुक्त बताकर विपणन किया जाता है। अनजाने में भी जीएम संदूषण इस बाजार की छवि और विश्वसनीयता को खतरे में डाल सकता है।
4. **आपूर्ति श्रृंखलाओं में क्रॉस-संदूषण का जोखिम :** भारत में मज़बूत पृथक्करण और पता लगाने योग्य बुनियादी ढाँचे का अभाव है। सोयाबीन खली या डीडीजीएस जैसे जीएम फ़ीड का आयात स्थानीय कृषि-आपूर्ति श्रृंखलाओं को दूषित कर सकता है, जिससे निर्यात वस्तुओं में अनजाने में जीएम की उपस्थिति हो सकती है।
5. **संभावित शिपमेंट अस्वीकृति और वित्तीय नुकसान :** दूषित माल को विदेशी बंदरगाहों पर अस्वीकार किया जा सकता है, जिससे प्रत्यक्ष नुकसान, ब्रांड का क्षरण, प्रतिष्ठा को नुकसान, तथा भारतीय निर्यातकों के लिए महंगा परीक्षण और अनुपालन बोझ बढ़ सकता है।
6. **जैविक प्रमाणीकरण और विशिष्ट बाज़ार के खतरे :** भारत जैविक उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक है। पशुपालन में जीएम फ़ीड का उपयोग या फसल निर्यात में जीएम अंश जैविक प्रमाणीकरण को ख़तरे में डाल सकते हैं, जिससे प्रीमियम बाज़ार और किसानों की आय प्रभावित हो सकती है।
7. **निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का नुकसान :** पर्याप्त लेबलिंग, निगरानी और नियंत्रण तंत्र के बिना, भारत जीएमओ-संवेदनशील निर्यात बाजारों में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त खो सकता है, जिससे खरीदार श्रीलंका या वियतनाम जैसे वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की ओर रुख कर सकते हैं।

घरेलू बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियां :

1. **खंडित कृषि-लॉजिस्टिक्स:** भारत की कृषि आपूर्ति श्रृंखला विखंडित है, जिसमें छोटे किसान, बिचौलिए और अनियमित बाजार शामिल हैं, जिससे यह प्रणाली संदूषण और अकुशलता के प्रति संवेदनशील हो जाती है।
2. **पृथक्करण तंत्र का अभाव:** कटाई, भंडारण, प्रसंस्करण और परिवहन के दौरान जीएम और गैर-जीएम उत्पादों को अलग करने के लिए कोई मजबूत प्रणाली नहीं है, जिससे गैर-जीएम खेपों में अनजाने में जीएम की उपस्थिति का जोखिम बढ़ जाता है।
3. **अपर्याप्त भंडारण और हैंडलिंग सुविधाएं:** अधिकांश ग्रामीण मंडियां और गोदाम जीएम और गैर-जीएम वस्तुओं को अलग-अलग रखने के लिए सुसज्जित नहीं हैं, जिससे पता लगाने और विनियामक अनुपालन का मुद्दा और जटिल हो जाता है।
4. **क्रॉस-संदूषण का उच्च जोखिम:** सख्त प्रोटोकॉल के बिना, डीडीजीएस या सोयाबीन भोजन जैसे जीएम फ़ीड का आयात करने से घरेलू गैर-जीएम उत्पादों के साथ इसका आकस्मिक मिश्रण हो सकता है, विशेष रूप से पशुपालन या अनाज प्रबंधन कार्यों में।
5. **कमजोर ट्रेसिबिलिटी और निगरानी प्रणाली :** भारत में वर्तमान में कृषि वस्तुओं की उत्पत्ति और हैंडलिंग पर नज़र रखने के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल ट्रेसेबिलिटी प्रणाली का अभाव है, जो अंतर्राष्ट्रीय जीएम मानदंडों के अनुपालन के लिए आवश्यक है।
6. **घरेलू अंतराल के कारण निर्यात जोखिम :** इन बुनियादी ढांचे की कमियों के परिणामस्वरूप भारतीय निर्यात के लिए GMO-मुक्त स्थिति समाप्त हो सकती है, जिससे यूरोपीय संघ जैसे उच्च मूल्य वाले बाजारों में अस्वीकृति हो सकती है, जहां सख्त पृथक्करण और दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होती है।
7. **नियामक तत्परता की तत्काल आवश्यकता :** यदि जीएम आयात की अनुमति दी जाती है, तो भारत को अपने कृषि-निर्यात क्षेत्र की प्रतिष्ठा और आर्थिक क्षति को रोकने के लिए लेबलिंग, प्रमाणन, पृथक्करण और परीक्षण प्रोटोकॉल को तत्काल स्थापित करने की आवश्यकता है।

धार्मिक और नैतिक चिंताएँ :

1. **जीएम फसलों में पशु-मूल जीन का उपयोग :** कुछ जीएम फसलें पशुओं, बैक्टीरिया या वायरस के जीन का उपयोग करके बनाई जाती हैं, जिससे उन समुदायों के लिए गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं जो सख्त शाकाहारी या धार्मिक आहार कानूनों का पालन करते हैं।
2. **शाकाहारी और वीगन उपभोक्ताओं पर प्रभाव :** भले ही अंतिम उत्पाद पादप-आधारित हो, लेकिन पशु-व्युत्पन्न जीन की उपस्थिति के कारण यह नैतिक या धार्मिक आधार पर शाकाहारियों, जैनियों या शाकाहारी लोगों के लिए अस्वीकार्य हो सकता है।
3. **सूचित उपभोक्ता विकल्प का उल्लंघन :** अनिवार्य जी.एम. लेबलिंग के बिना, उपभोक्ता जी.एम. और गैर-जी.एम. उत्पादों में अंतर नहीं कर पाते, जिससे उन्हें व्यक्तिगत या सांस्कृतिक

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

मान्यताओं के आधार पर सूचित आहार विकल्प चुनने के अधिकार से वंचित होना पड़ता है।

4. **खाद्य शुद्धता को खतरा :** ऐसे देश में जहां खाद्य शुद्धता का गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, व्यापक सार्वजनिक परामर्श के बिना जीएम खाद्य पदार्थों को पेश करने से सामाजिक अविश्वास और प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है।
5. **सार्वजनिक खरीद में नैतिक दुविधा :** मध्याह्न भोजन, आईसीडीएस या पीडीएस जैसी सरकारी योजनाएं अनजाने में जीएम-आधारित खाद्य पदार्थों का वितरण कर सकती हैं, जिससे सूचित सहमति के बारे में प्रश्न उठते हैं, विशेष रूप से बच्चों या आदिवासियों जैसी कमजोर आबादी के लिए।
6. **लेबल पारदर्शिता और सार्वजनिक जागरूकता अंतराल :** भारत में वर्तमान में जी.एम. उत्पादों के लिए अनिवार्य, उपयोगकर्ता-अनुकूल लेबलिंग व्यवस्था का अभाव है, जिससे पारदर्शिता संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं और नैतिक उपभोक्ताओं के लिए जी.एम.-संबंधित उत्पादों से बचना कठिन हो रहा है।
7. **सामाजिक और राजनीतिक विरोध का जोखिम :** जीएम खाद्य पदार्थों के आयात से धार्मिक समूहों, नागरिक समाज और राजनीतिक दलों में विरोध उत्पन्न हो सकता है, विशेषकर यदि नीति निर्धारण के दौरान नैतिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं की अनदेखी की जाए।

विनियामक और नीति परिदृश्य :

1. **जीएम अनुमोदन में जीईएसी की केंद्रीय भूमिका :** पर्यावरण मंत्रालय के अधीन जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) भारत में जीएम जीवों के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है।
2. **अनिवार्य जीएम लेबलिंग का अभाव :** यूरोपीय संघ जैसे देशों के विपरीत, भारत में वर्तमान में सभी जीएम-व्युत्पन्न उत्पादों के लिए पैकेट के सामने अनिवार्य लेबलिंग लागू नहीं है। इससे उपभोक्ताओं को जानकारी नहीं मिल पाती और घरेलू तथा निर्यात बाज़ारों में पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
3. **मजबूत प्रमाणन और ट्रेसिबिलिटी मानकों की आवश्यकता :** घरेलू अखंडता और निर्यात अनुपालन दोनों के लिए जीएम और गैर-जीएम उत्पादों में अंतर करने के लिए प्रभावी प्रमाणन तंत्र, आपूर्ति श्रृंखला दस्तावेजीकरण और उत्पाद ट्रैकिंग आवश्यक हैं।
4. **मौजूदा दिशानिर्देशों का कमजोर प्रवर्तन :** हालाँकि कुछ दिशानिर्देश मौजूद हैं, लेकिन राज्यों और हितधारकों के बीच उनका क्रियान्वयन एक जैसा नहीं है। FSSAI, सीमा शुल्क और कृषि नियामकों के बीच खराब समन्वय के कारण कई खाद्य उत्पाद जाँच से बच जाते हैं।
5. **व्यापक जीएम नीति का अभाव :** भारत में जीएम खाद्य पदार्थों पर एक एकीकृत, राष्ट्रीय नीति का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप खंडित विनियमन, अस्पष्ट अनुमोदन प्रक्रियाएँ और तदर्थ निर्णय होते हैं। इससे उत्पादकों, उपभोक्ताओं और निर्यातकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होती है।
6. **अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तुलना :** यूरोपीय संघ, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश सख्त लेबलिंग, सार्वजनिक परामर्श, दीर्घकालिक स्वास्थ्य अध्ययन और ट्रेसेबिलिटी कानून लागू करते हैं। भारत का विकसित हो रहा ढाँचा अभी भी ऐसे वैश्विक मानकों से पीछे है।
7. **व्यापार वार्ता के आलोक में नीतिगत स्पष्टता की तत्काल आवश्यकता :** भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में जी.एम. आयात पर विचार किया जा रहा है, इसलिए वैज्ञानिक प्रगति सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिक चिंताओं और निर्यात हितों की रक्षा के लिए विनियामक स्पष्टता आवश्यक है।

व्यापार वार्ता और रणनीतिक समझौता :

1. **जीएम बाज़ार तक पहुंच के लिए अमेरिकी दबाव :** मक्का और सोया जैसी जीएम फसलों का प्रमुख उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत पर दबाव डाल रहा है कि वह चल रही अंतरिम व्यापार संधि वार्ता के भाग के रूप में सोयाबीन खली और डीडीजीएस जैसी जीएम फसलों के आयात की अनुमति दे।
2. **संभावित कूटनीतिक लाभ :** यद्यपि अमेरिकी मांगों को स्वीकार करने से व्यापार संबंधों में सुधार हो सकता है और व्यापक आर्थिक सहयोग के द्वार खुल सकते हैं, लेकिन इससे खाद्य सुरक्षा और किसान अधिकारों जैसे संवेदनशील घरेलू मुद्दों पर समझौता करने की चिंताएं पैदा होती हैं।
3. **घरेलू सुरक्षा उपायों के साथ व्यापार को संतुलित करने की आवश्यकता :** भारत को एक नाजुक संतुलन बनाना होगा - अपनी नियामक स्वायत्तता, उपभोक्ता संरक्षण या निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को कम किए बिना व्यापार सुविधा को बढ़ावा देना होगा।
4. **दीर्घकालिक रणनीतिक हितों के लिए जोखिम :** यदि भारत की जीएमओ-मुक्त स्थिति से समझौता किया जाता है, तो अल्पकालिक व्यापार लाभ दीर्घकालिक प्रतिष्ठा और आर्थिक क्षति की कीमत पर आ सकते हैं, विशेष रूप से यूरोपीय संघ जैसे प्रीमियम बाजारों में।
5. **भावी व्यापार सौदों के लिए मिसाल :** जी.एम. आयात पर सहमति देने से एक मिसाल कायम हो सकती है, जिससे अन्य व्यापारिक साझेदारों को भविष्य में द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सौदों में पर्यावरण या स्वास्थ्य मानकों में ढील की मांग करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
6. **घरेलू उद्योग और किसान पर प्रभाव :** सस्ते जीएम फ़ीड आयात के लिए रास्ता खुलने से घरेलू फ़ीड उत्पादकों पर असर

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

पड़ सकता है, जबकि गैर-जीएम फसलों का उपयोग करने वाले भारतीय किसानों को जीएमओ-मुक्त प्रमाणीकरण की आवश्यकता वाले निर्यातकों की ओर से कम मांग का सामना करना पड़ सकता है।

7. **पारदर्शी सार्वजनिक परामर्श का आह्वान :** जीएम उत्पादों पर किसी भी व्यापार-संबंधी निर्णय में समावेशी नीति निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए किसानों, निर्यातकों, नागरिक समाज, वैज्ञानिकों और धार्मिक निकायों सहित व्यापक हितधारक परामर्श शामिल होना चाहिए।

व्यापार वार्ता और रणनीतिक समझौता :

1. **जीएम बाज़ार खोलने के लिए अमेरिका का दबाव :** अंतरिम व्यापार समझौते के एक भाग के रूप में, अमेरिका आर्थिक और खाद्य सुरक्षा लाभों का तर्क देते हुए सोयाबीन खली और डीडीजीएस जैसे जीएम उत्पादों के लिए भारत के बाजार तक पहुंच पर जोर दे रहा है।
2. **रणनीतिक व्यापार लाभ बनाम घरेलू संवेदनशीलताएं :** यद्यपि इन मांगों को समायोजित करने से भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में सुधार हो सकता है, लेकिन इससे घरेलू विनियामक मानकों, विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, के कमजोर होने का खतरा है।
3. **अल्पकालिक लाभ और दीर्घकालिक जोखिम के बीच व्यापार-बंद :** इस कदम से तत्काल सीमित आर्थिक लाभ तो हो सकता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप निर्यात बाजारों को नुकसान, जनता की नाराजगी और भारत के कृषि क्षेत्र की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है।
4. **अन्य एफटीए में भारत की स्थिति को कमजोर करना :** यदि भारत दबाव में आकर समझौता स्वीकार कर लेता है, तो इससे अन्य व्यापार समझौतों में उसकी वार्ता संबंधी स्थिति कमजोर हो सकती है, जिससे वह अन्य देशों की इसी प्रकार की मांगों के प्रति संवेदनशील हो जाएगा।
5. **भारत के घरेलू उत्पादकों पर प्रभाव :** सस्ते जी.एम. आयात से घरेलू बाजार विकृत हो सकता है, जिससे पारंपरिक और जैविक फीडस्टॉक के भारतीय उत्पादकों को नुकसान होगा तथा अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा होगी।
6. **व्यापार-नापसंद के रणनीतिक मूल्यांकन की आवश्यकता :** निर्णय समग्र लागत-लाभ विश्लेषण द्वारा निर्देशित होने चाहिए, जिसमें व्यापार, नैतिक, उपभोक्ता और पर्यावरणीय आयाम शामिल होने चाहिए, न कि केवल वाणिज्यिक लाभ।
7. **बाहरी दबाव की तुलना में नियामक तत्परता को प्राथमिकता दें :** बाजार खोलने से पहले, भारत को अपनी संस्थागत तैयारी को मजबूत करना होगा, जिसमें परीक्षण प्रयोगशालाएं, लेबलिंग मानक और सार्वजनिक संचार शामिल हैं।

आगे की राह और मुख्य सिफारिशें :

1. **पृथक्करण, परीक्षण और पता लगाने की क्षमता के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश करें :** जीएम और गैर-जीएम उत्पादों के अलग-अलग प्रबंधन को सक्षम बनाने के लिए भारत की कृषि रसद व्यवस्था को मज़बूत करें। निर्यात विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाएँ और डिजिटल ट्रेसेबिलिटी प्रणालियाँ स्थापित करें।
2. **पारदर्शी राष्ट्रीय जीएम लेबलिंग नीति बनाएं :** उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा, सूचित विकल्पों को बढ़ावा देने, तथा जीएम-संवेदनशील बाजारों में निर्यात मानकों को पूरा करने के लिए जीएम उत्पादों की स्पष्ट और उपभोक्ता-अनुकूल लेबलिंग को अनिवार्य बनाना।
3. **जैव-सुरक्षा विनियमन और किसान जागरूकता को मजबूत करना :** जी.ई.ए.सी. और एफ.एस.एस.ए.आई. की भूमिका और क्षमता को उन्नत करना ताकि कठोर जैव सुरक्षा आकलन सुनिश्चित किया जा सके, साथ ही जी.एम. बीजों से संबंधित जोखिमों, कानूनी पहलुओं और प्रदर्शन संबंधी मुद्दों के बारे में किसानों को शिक्षित किया जा सके।
4. **जीएमओ से संबंधित व्यापार निर्णयों में सार्वजनिक परामर्श सुनिश्चित करें :** व्यापार समझौतों के माध्यम से जीएम आयात पर नीतियां बनाते समय बहु-हितधारक दृष्टिकोण अपनाएं जिसमें नागरिक समाज, उपभोक्ता समूह, किसान, वैज्ञानिक और निर्यातक शामिल हों।
5. **भारत के विशिष्ट जैविक और जीएमओ-मुक्त बाजार खंडों की रक्षा करना :** भारत के आकर्षक जैविक, हर्बल और गैर-जीएमओ निर्यातों की सुरक्षा के लिए सख्त सुरक्षा उपाय बनाए रखें, जो यूरोपीय संघ, जापान और मध्य पूर्व जैसे बाजारों में प्रीमियम मूल्य प्राप्त करते हैं।
6. **अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के विरुद्ध बेंचमार्क :** यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के सफल मॉडलों का अध्ययन करें और उन्हें अपनाएं जो वैज्ञानिक नवाचार को कड़े लेबलिंग, उपभोक्ता सुरक्षा और सार्वजनिक विश्वास के साथ संतुलित करते हैं।
7. **एक व्यापक राष्ट्रीय जीएम नीति ढांचा विकसित करना :** आयात विनियमन, उपभोक्ता अधिकार, किसान कल्याण, वैज्ञानिक अनुसंधान और व्यापार प्रभाव शमन को कवर करने वाली एक सुसंगत राष्ट्रीय जीएमओ नीति को अंतिम रूप देना और लागू करना।

निष्कर्ष :

- जीटीआरआई की चेतावनी नीति निर्माताओं के लिए एक सामयिक और महत्वपूर्ण सूचना है क्योंकि भारत अमेरिका के साथ अपने अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब पहुँच रहा है। यह आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) आयातों

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

के प्रति एक सतर्क और सुव्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देता है, खासकर कृषि, व्यापार और जनभावना पर उनके दूरगामी प्रभावों को देखते हुए। भारत को अपनी निर्यात अखंडता से समझौता नहीं करना चाहिए, खासकर यूरोपीय संघ जैसे जीएम-संवेदनशील बाजारों में, जहाँ कड़े मानक लागू हैं। साथ ही, देश को खाद्य नैतिकता, धार्मिक संवेदनशीलता और किसान हितों की रक्षा करनी चाहिए। जीएम उत्पादों पर कोई भी निर्णय विज्ञान, पारदर्शिता और अल्पकालिक व्यापार लाभों के बजाय दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरित होना चाहिए।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. जीएम फसलों को आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके उनके डीएनए में परिवर्तन करके वांछित गुण उत्पन्न किये जाते हैं।
2. जी.एम. फसलों में प्रयुक्त बीटी जीन एक जीवाणु से आता है और शाकनाशी के प्रति सहनशीलता में मदद करता है।
3. गोल्डन राइस विटामिन ए से समृद्ध जीएम फसल का एक उदाहरण है।
4. भारत वर्तमान में सभी खाद्य उत्पादों पर अनिवार्य जी.एम. लेबलिंग लागू करता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1, 2 और 3

(c) केवल 2 और 4 (d) केवल 1, 3 और 4

उत्तर - (a)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते के तहत आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) कृषि उत्पादों के प्रस्तावित आयात के संबंध में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों और रणनीतिक विचारों पर चर्चा करें। चर्चा कीजिए कि भारत व्यापार सुगमता और घरेलू कृषि एवं नैतिक चिंताओं की सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बना सकता है?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

यूपीआई : भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति और रीयल-टाइम लेनदेन में वैश्विक नेतृत्व

ख़बरों में क्यों?

UNIFIED PAYMENTS INTERFACE

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी एक नोट के अनुसार, भारत तीव्र भुगतान में वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा है।
- बढ़ते खुदरा डिजिटल भुगतान अंतर-संचालनीयता का मूल्य इस बदलाव का मूल आधार एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस है, जिसे यूपीआई के नाम से जाना जाता है।
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा 2016 में लॉन्च किए गए यूपीआई ने देश में लोगों के पैसे भेजने और प्राप्त करने के तरीके को बदल दिया है।

यूपीआई क्या है?

What is UPI?

Unified Payments Interface (UPI) is a real -time payment system that enables in stant money transfers between bank accounts through a mobile application. It is built on the Immediate Payment Service (IMPS) infrastructure. UPI brings multiple bank accounts into a single app and supports various features such as fund transfers, merchant payments, and peer -to-peer payment requests, making digital transactions quick and convenient.

यूपीआई की सफलता की एक झलक (आंकड़ों में) :

- भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का दायरा और प्रभाव असाधारण से कम नहीं है। अकेले जून 2025 में, UPI ने 18.39 अरब लेनदेन के ज़रिए ₹24.03 लाख करोड़ से ज़्यादा का भुगतान किया। यह जून 2024 की तुलना में 32% की वृद्धि दर्शाता है, जब 13.88 अरब लेनदेन हुए थे—जो इस प्लेटफ़ॉर्म की साल-दर-साल तेज़ वृद्धि को दर्शाता है।

यूपीआई अब निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है :

- 491 मिलियन व्यक्ति
- 65 मिलियन व्यापारी
- 675 बैंक एक ही अंतर-संचालनीय मंच पर
- इस व्यापक पहुँच ने UPI को भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ बना दिया है। आज, देश में सभी डिजिटल लेनदेन में UPI का योगदान 85% है, जो इसके प्रभुत्व और विश्वसनीयता को दर्शाता है।
- वैश्विक स्तर पर भी यूपीआई उतना ही प्रभावशाली है - जो विश्व के लगभग 50% वास्तविक समय डिजिटल भुगतानों को संचालित करता है।
- ये आँकड़े सिर्फ़ आँकड़े नहीं हैं; ये भरोसे, सुविधा और दक्षता का प्रतीक हैं। हर गुजरते महीने के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग और व्यवसाय यूपीआई अपना रहे हैं, जिससे भारत कम नकदी वाली, डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है।

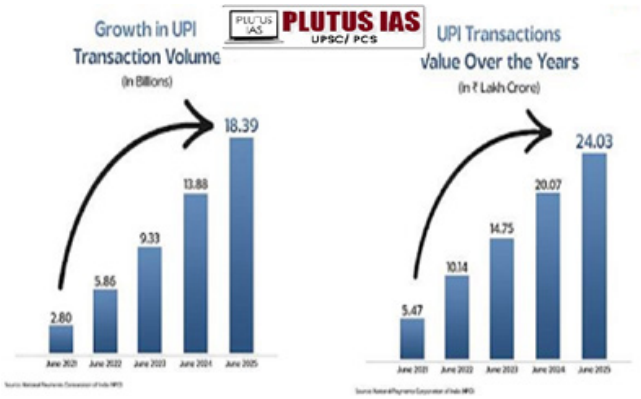

यूपीआई वास्तविक समय भुगतान में दुनिया में अग्रणी है :

- भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) दुनिया की अग्रणी रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली बनकर उभरा है, जिसने वीज़ा जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया है। UPI अब प्रतिदिन 64 करोड़ से ज़्यादा लेनदेन करता है, जो वीज़ा के 63.9 करोड़ लेनदेन से थोड़ा ही आगे है।
- इस उपलब्धि को असाधारण बनाने वाली बात यह है कि 2016 में अपनी शुरुआत के बाद से UPI ने यह उपलब्धि सिर्फ़ नौ सालों में हासिल की है।
- आज, वैश्विक वास्तविक समय डिजिटल लेनदेन में यूपीआई का योगदान लगभग 50% है, जो गति, मापनीयता और समावेशन के लिए निर्मित एक खुली, अंतर-संचालनीय और उपयोगकर्ता-अनुकूल प्रणाली की ताकत को उजागर करता है।

वैश्विक स्तर पर बढ़ता पदचिह्न :

- यूपीआई की सफलता अब केवल भारतीय सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। अब यह सात देशों में भी सक्रिय है।
- इनमें से, फ्रांस में इसकी शुरुआत एक ऐतिहासिक उपलब्धि है—यूपीआई का यूरोप में पहला प्रवेश। यह भारतीय पर्यटकों, छात्रों और प्रवासियों को पारंपरिक विदेशी मुद्रा बाधाओं और लेन-देन में देरी से बचते हुए, विदेशों में निर्बाध डिजिटल भुगतान करने की सुविधा देता है।

ब्रिक्स और उससे आगे का रणनीतिक प्रयास :

- भारत ब्रिक्स समूह में यूपीआई को डिजिटल भुगतान मानक के रूप में अपनाने की भी वकालत कर रहा है, जिसका विस्तार अब छह नए सदस्य देशों को शामिल करने के लिए किया गया है। अगर यह कदम साकार होता है, तो:
- सीमा पार प्रेषण में क्रांतिकारी बदलाव
- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना
- वैश्विक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) में अग्रणी के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना।

इंटरऑपरेबिलिटी और यूपीआई : निर्बाध डिजिटल भुगतान को सशक्त बनाना :

- इंटरऑपरेबिलिटी विभिन्न प्रणालियों की एक साथ कुशलतापूर्वक कार्य करने की क्षमता को संदर्भित करती है।

- डिजिटल भुगतान के संदर्भ में, इसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता बिना किसी प्लेटफ़ॉर्म द्वारा प्रतिबंधित हुए विभिन्न बैंकों या ऐप्स के माध्यम से पैसे भेज और प्राप्त कर सकते हैं।
- यह निर्बाध कार्यप्रणाली समान तकनीकी मानकों, साझा डेटा प्रोटोकॉल और पारिस्थितिकी तंत्र में सभी खिलाड़ियों के बीच स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिकारों और जिम्मेदारियों के माध्यम से संभव हो पाती है।

क्लोज्ड-लूप (बंद लूप) प्रणालियों से खुले नेटवर्क तक :

- यूपीआई के आगमन से पहले, भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में क्लोज्ड-लूप प्रणालियों का बोलबाला था। ये प्रणालियाँ केवल एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर लेनदेन की अनुमति देती थीं। उदाहरण के लिए:
- एक डिजिटल वॉलेट केवल अपने उपयोगकर्ताओं के बीच ही धन का हस्तांतरण कर सकता है।
- यद्यपि IMPS ने अंतर-बैंक स्थानान्तरण को सक्षम किया, लेकिन उपयोगकर्ता तृतीय-पक्ष ऐप्स के माध्यम से इस तक पहुंच नहीं सकते थे।
- इससे प्रयोज्यता और मापनीयता दोनों सीमित हो गयीं।

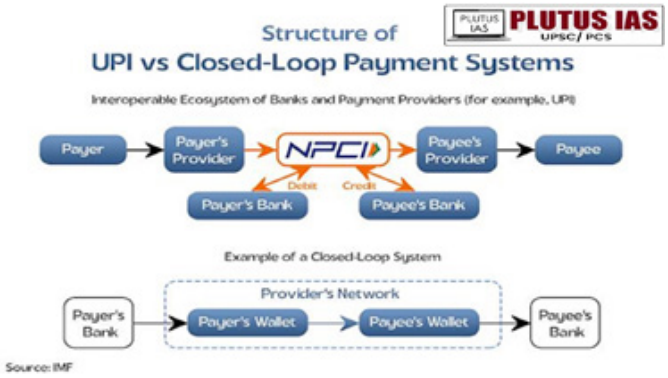

यूपीआई ने भारत में रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल दिया है ?

1. **पैसा कभी भी, कहीं भी :** बैंक या एटीएम जाने की ज़रूरत नहीं। मोबाइल फ़ोन से 24×7 तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा।
2. **सभी खातों के लिए एक ऐप :** उपयोगकर्ता एक ही ऐप में कई बैंक खाते लिंक कर सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म बदले बिना धन प्रबंधन को आसान बनाता है।
3. **सुरक्षित और त्वरित भुगतान :** दो-कारक प्रमाणीकरण सुरक्षित लेनदेन सुनिश्चित करता है। भुगतान कुछ ही सेकंड में पूरा हो जाता है।
4. **गोपनीयता सर्वप्रथम :** बैंक खाता संख्या या IFSC कोड साझा करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक सरल UPI ID गोपनीयता सुनिश्चित करती है और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करती है।
5. **क्यूआर कोड सुविधा :** स्कैन-एंड-पे विकल्प दुकानों, विक्रेताओं और स्थानीय बाज़ारों में लेन-देन को तेज़ बनाता है। नकदी पर निर्भरता कम करता है।
6. **अब कैश-ऑन-डिलीवरी की परेशानी नहीं :** ऑनलाइन खरीदारी का भुगतान UPI के ज़रिए किया जा सकता है। इससे खुले पैसे या नकदी की ज़रूरत खत्म हो जाती है।
7. **हर चीज़ के लिए भुगतान :** उपयोगिता बिल, मोबाइल रिचार्ज, दान और बहुत कुछ सीधे ऐप से किया जा सकता है। यह घर बैठे डिजिटल सेल्फ-सर्विस को प्रोत्साहित करता है।
8. **आसान शिकायत निवारण :** उपयोगकर्ता ऐप के भीतर विफल या विवादित लेनदेन की रिपोर्ट कर सकते हैं। ग्राहक सहायता सुलभ और त्वरित हो जाती है।

यूपीआई के पीछे डिजिटल आधार :

गोलियाँ	पहल	विवरण
वित्तीय समावेशन	प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY)	- बैंकिंग तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 2014 में शुरू किया गया। - ऊपर 55.83 करोड़ जन धन खाते9 जुलाई 2025 तक खोला जाएगा। - प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), बचत, ऋण और बीमा तक पहुंच को सक्षम बनाया गया।
डिजिटल पहचान	आधार	- बायोमेट्रिक्स और जनसांख्यिकी से जुड़ी एक अद्वितीय 12-अंकीय डिजिटल आईडी प्रदान करता है। - 142 करोड़ से अधिक आधार संख्या30 जून 2025 तक जारी किया जाएगा। - बैंक खातों और भुगतान प्रणालियों से जुड़ा हुआ।
कनेक्टि-विटी	किफायती इंटरनेट और 5G रोलआउट	- तेजी से 5G रोलआउट4.74 लाख बेस स्टेशन2025 तक। - मोबाइल उपभोक्ता आधार तक पहुँच गया116 करोड़. - डेटा लागत में कमी₹308/ जीबी (2014) को ₹9.34/जीबी (2022).

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

निष्कर्ष :

- भारत तेज़ भुगतान में वैश्विक अग्रणी बनकर उभरा है और इस उपलब्धि के केंद्र में UPI है। इसने न केवल डिजिटल लेनदेन को तेज़ और सुरक्षित बनाया है, बल्कि सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढाँचे में नवाचार के लिए एक नया वैश्विक मानक भी स्थापित किया है।
- बैंक खातों को मोबाइल ऐप से जोड़ने की एक सरल प्रणाली के रूप में शुरू हुआ यह UPI, डिजिटल-प्रथम अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया है। इसका विकास वित्तीय समावेशन, डिजिटल पहचान और किफायती कनेक्टिविटी की मज़बूत नींव पर टिका है। अन्य देशों में UPI का विस्तार इसकी वैश्विक क्षमता को उजागर करता है।
- जैसे-जैसे अधिक से अधिक अन्य देश इस मॉडल को अपना रहे हैं, भारत का एक सुरक्षित, रीयल-टाइम और खुली भुगतान प्रणाली का दृष्टिकोण डिजिटल वित्त के भविष्य को प्रभावित कर रहा है।

स्रोत: पी.आई.बी. एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यूपीआई मोबाइल उपकरणों के माध्यम से वास्तविक समय में बैंक खातों के बीच धन हस्तांतरण की अनुमति देता है।
2. यूपीआई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित एक बंद-लूप भुगतान प्रणाली है।
3. 2025 तक भारत में सभी डिजिटल भुगतानों में यूपीआई लेनदेन का हिस्सा 80% से अधिक होगा।
4. यूपीआई विभिन्न बैंकों और ऐप्स के बीच अंतर-संचालन का समर्थन करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 1, 3 और 4

C. केवल 2 और 3 D. 1, 2, 3 और 4

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) ने किस प्रकार डिजिटल भुगतान प्रणाली में क्रांति लाकर देश को वास्तविक समय के वित्तीय लेनदेन में वैश्विक अग्रणी बनाया है? इस परिवर्तन को संभव बनाने वाले डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे और नीतिगत पहलों की क्या भूमिका रही है? इसके साथ - ही - साथ , UPI की वैश्विक प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

सीमाओं की सुरक्षा और शिखरों की निगरानी : सीमाई और आंतरिक खतरों से निपटने के लिए अरुणाचल की नई बटालियन

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने एक नई अरुणाचल सशस्त्र पुलिस बटालियन (AAPBN) के गठन को मंज़ूरी दी है।
- इस बटालियन का उद्देश्य राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) पर निर्भरता को कम करना है।
- यह एक इंडिया रिज़र्व बटालियन होगी, जिसे आवश्यकतानुसार गृह मंत्रालय पूरे भारत में तैनात कर सकता है। इस निर्णय से राज्य की पुलिसिंग क्षमता में वृद्धि होगी, सुरक्षा खतरों पर तेज़ प्रतिक्रिया संभव हो पाएगी और दूरदराज़ व संवेदनशील क्षेत्रों में सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
- इसके साथ ही अरुणाचल सशस्त्र पुलिस बटालियन (AAPBN) स्थानीय युवाओं के लिए सुरक्षा क्षेत्र में रोज़गार के अवसर भी पैदा करेगी।

आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता क्यों है?

1. **बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ :** अरुणाचल प्रदेश की चीन, म्यांमार और भूटान से लगभग 1600 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिससे यह राज्य अवैध घुसपैठ, तस्करी और बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील है।
2. **चीनी क्षेत्रीय दावे :** चीन बार-बार अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को "दक्षिण तिब्बत" बताकर दावा करता है, जिससे इस क्षेत्र की रणनीतिक संवेदनशीलता बढ़ जाती है।
3. **विद्रोही गतिविधियों का प्रभाव :** नागालैंड, असम और म्यांमार जैसे पड़ोसी क्षेत्रों से उग्रवादी समूह अरुणाचल में शरण लेने या रास्ता बनाने के लिए प्रवेश करते हैं।
4. **स्थानीय पुलिस व्यवस्था की कमजोरी :** दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित आधारभूत ढांचे के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में पुलिस की उपस्थिति प्रभावी नहीं है।
5. **सीमावर्ती गांवों में सुरक्षा की कमी :** सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त और सुरक्षा तंत्र कमजोर है, जिससे ये इलाके बाहरी प्रभाव और प्रवासन के लिए संवेदनशील हो जाते हैं।
6. **जातीय संघर्ष और असंतोष :** कई जनजातियाँ स्वायत्तता की मांग करती रही हैं, जो समय के साथ सुरक्षा संकट में बदल सकती हैं।
7. **त्वरित प्रतिक्रिया बल की आवश्यकता :** स्थानीय स्तर की सशस्त्र पुलिस बल, दूर स्थित CAPFs की तुलना में तेज़ प्रतिक्रिया दे सकती है।
8. **विकास परियोजनाओं को सुरक्षा देना :** सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास और संपर्क परियोजनाओं के सुचारु संचालन के लिए आंतरिक सुरक्षा का मजबूत होना आवश्यक है।

अरुणाचल सशस्त्र पुलिस बटालियन (AAPBN) की मुख्य भूमिका :

1. **भीड़ नियंत्रण और दंगा प्रबंधन :** यह बटालियन विरोध-प्रदर्शनों, त्योहारों और सामुदायिक तनावों के दौरान व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेगी।
2. **विद्रोह विरोधी अभियान :** इसे जंगलों और ऊँचाई वाले क्षेत्रों में उग्रवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
3. **सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त :** यह बटालियन ऐसे संवेदनशील और विवादास्पद क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करेगी जहाँ नागरिक पुलिस की उपस्थिति कम है।
4. **आपदा राहत और बचाव कार्य :** भूस्खलन, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय यह बटालियन लॉजिस्टिक और सुरक्षा सहयोग प्रदान कर सकेगी।
5. **विशेष सुरक्षा दायित्व :** यह वीवीआईपी, प्रमुख प्रतिष्ठानों और महत्वपूर्ण परियोजनाओं (जैसे हाईवे और जलविद्युत) की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
6. **नागरिक प्रशासन को सहायता :** कानून व्यवस्था में विफलता या आपात स्थिति में यह जिला पुलिस और प्रशासन को मदद प्रदान करेगी।
7. **CAPFs पर निर्भरता में कमी :** इस बटालियन के ज़रिए अरुणाचल आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा सकेगा।
8. **सार्वजनिक विश्वास में वृद्धि :** प्रशिक्षित बलों की दृश्य उपस्थिति आम जनता में सुरक्षा के प्रति विश्वास बढ़ाएगी।

इंडिया रिज़र्व बटालियन (IRB) मॉडल की मुख्य विशेषताएँ :

1. यह बटालियन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होती है और राज्य सरकारें इसे स्थापित करती हैं।
2. इन्हें आवश्यकता अनुसार राज्य के भीतर और भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।
3. इन बटालियनों को BSF और CRPF जैसे CAPFs के समकक्ष प्रशिक्षण दिया जाता है।
4. केंद्र सरकार इनकी बुनियादी ढांचे, हथियारों और वेतन के लिए प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
5. राष्ट्रीय संकट के समय अन्य राज्यों की IR बटालियनों को जम्मू-कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और दंगा प्रभावित स्थानों पर तैनात किया गया है।
6. इनका ढांचा तेज़ गति से संचालन और तैनाती की अनुमति देता है।
7. यह राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मज़बूत करने वाला पूरक बल है।

सार्वजनिक सुरक्षा और प्रशासनिक प्रभाव :

1. AAPBN की स्थापना से दूरस्थ क्षेत्रों में पुलिसिंग करना अत्यंत आसान होगा।
2. यह बटालियन त्वरित प्रतिक्रिया बल के रूप में कार्य करेगी और आपात परिस्थितियों से निपटेगी।
3. यह चुनावों, त्योहारों और सुरक्षा अभियानों के दौरान लॉजिस्टिक और मानव संसाधन सहयोग प्रदान करेगी।
4. सीमाई इलाकों में AAPBN की उपस्थिति से तस्करी, मानव तस्करी और नशीली दवाओं के व्यापार पर रोक लगेगी।
5. शहरी क्षेत्रों में कानून व्यवस्था में सुधार होगा और पारंपरिक पुलिस पर दबाव कम होगा।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

6. यह बटालियन स्थानीय खुफिया तंत्र को मज़बूत बनाएगी और समुदाय से संवाद को बढ़ावा देगी।
7. AAPBN की उपस्थिति पर्यटकों के लिए सुरक्षा का भरोसा बढ़ाएगी, जिससे राज्य में साहसिक और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
8. इससे खासकर आदिवासी और सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराधों की तेज़ जांच और समाधान संभव होगा।

रोजगार और स्थानीय युवाओं का सशक्तिकरण :

1. AAPBN में स्थानीय जनजातियों से युवाओं की भर्ती को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे समावेशिता सुनिश्चित होगी।
2. सुरक्षा क्षेत्र में रोज़गार से स्थायी आय और कौशल विकास संभव होगा।
3. प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं में अनुशासन, संप्रेषण कौशल और आधुनिक पुलिसिंग कौशल विकसित करेंगे।
4. युवाओं की पुलिस सेवा में भागीदारी से विद्रोह की ओर झुकाव कम होगा।
5. रोज़गार प्राप्त युवा अपने परिवारों की सहायता कर सकेंगे, जिससे ग्रामीण विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
6. सफल युवा अधिकारी अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे।
7. महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती से लैंगिक समावेशिता में सुधार होगा।
8. सरकारी सेवा से पेंशन, आवास और शिक्षा जैसी सुविधाएँ मिलेंगी, जिससे दीर्घकालिक कल्याण सुनिश्चित होगा।

भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश की रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्व :

1. चीन के साथ भू-राजनीतिक तनाव और पीएलए की घुसपैठ से यह क्षेत्र सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया है।
2. तवांग क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए AAPBN की उपस्थिति निगरानी को बेहतर बनाएगी।
3. भारत की "फॉरवर्ड पॉलिसी" के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय सुरक्षा को मज़बूत करना आवश्यक है।
4. यह बटालियन चीनी दुष्प्रचार और प्रभाव को सीमित करने में सहायक होगी।
5. फ्रंटियर हाईवे और सीमा विकास परियोजनाओं जैसी रणनीतिक परियोजनाओं को सुरक्षा मिलेगी।
6. प्रशिक्षित राज्य पुलिस सेना के साथ समन्वय में मार्ग-साफ़ करने जैसे कार्यों में सहायता करेगी।
7. उत्तर–पूर्व की सुरक्षा "एक्ट ईस्ट नीति" के तहत दक्षिण-पूर्व एशिया से संपर्क के लिए आवश्यक है।
8. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत विकसित हो रहे **आदर्श गांवों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में AAPBN सहयोग करेगा।

कार्यान्वयन की प्रमुख चुनौतियाँ :

1. बटालियन की स्थापना और संचालन में उच्च वित्तीय व्यय की आवश्यकता होगी।
2. कठिन भूगोल और सड़क नेटवर्क की कमी लॉजिस्टिक्स को प्रभावित कर सकती है।
3. प्रशिक्षकों की कमी विशेषकर ऊँचाई वाले क्षेत्रों, जंगल युद्ध और तकनीक आधारित पुलिसिंग के लिए चुनौती है।
4. दूरस्थ क्षेत्रों के युवा राज्य के बाहर अवसर तलाश सकते हैं, जिससे बल की स्थिरता पर असर होगा।
5. विभिन्न एजेंसियों में समन्वय की आवश्यकता होगी – जैसे सिविल पुलिस, AAPBN, सेना और CAPFs।
6. अत्यधिक सैन्यीकरण से नागरिकों में अविश्वास या मानवाधिकार उल्लंघन की आशंका हो सकती है।
7. सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर कार्रवाई करनी होगी।
8. राजनीतिक इच्छाशक्ति और निरंतर समर्थन बटालियन की दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है।

आगे की राह :

1. **तकनीक का समावेश :** ड्रोन, बॉडीकैम, GPS आधारित गश्त और AI निगरानी से प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है।
2. **विशेष प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना :** उत्तर–पूर्व में विशेष पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की आवश्यकता है।
3. **सामुदायिक पुलिसिंग :** जनजातीय बुजुर्गों, स्थानीय नेताओं और शांति समितियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
4. **महिला भागीदारी को बढ़ावा :** अधिक महिलाओं की भर्ती से समावेशिता और विश्वास बढ़ेगा।
5. **राज्य–केंद्र आपसी समन्वय :** नियमित संयुक्त अभ्यास और सूचना साझा करने की व्यवस्था होनी चाहिए।
6. **प्रदर्शन की नियमित समीक्षा :** स्वतंत्र ऑडिट और जन प्रतिक्रिया से बटालियन की कार्यक्षमता का मूल्यांकन किया जाए।

7. **स्मार्ट पुलिसिंग से एकीकरण :** CCTNS जैसे प्लेटफॉर्म से जोड़कर आधुनिक प्रणाली अपनाई जाए।

8. **विकेन्द्रीकृत सुरक्षा रणनीति :** स्थानीय इकाइयों को सशक्त बनाकर खुफिया आधारित पुलिसिंग को प्राथमिकता दी जाए।

निष्कर्ष :

- अरुणाचल सशस्त्र पुलिस बटालियन (AAPBN) का गठन आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने, केंद्रीय बलों पर निर्भरता घटाने और सीमावर्ती खतरों का समाधान करने की दिशा में एक रणनीतिक पहल है।
- यह बटालियन न केवल स्थानीय पुलिसिंग को मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि युवाओं को सशक्त करेगा और भारत के रणनीतिक हितों को संरक्षित करेगा।
- यदि अरुणाचल सशस्त्र पुलिस बटालियन (AAPBN) का क्रियान्वयन, प्रशिक्षण और सामुदायिक सहभागिता सही तरीके से सुनिश्चित की जाए, तो यह बटालियन उत्तर-पूर्व भारत में जवाबदेह, विकेन्द्रीकृत और प्रभावी सुरक्षा तंत्र का मजबूत स्तंभ बन सकती है।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत रिज़र्व बटालियनों (IRBs) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इन्हें राज्य सरकारों द्वारा गृह मंत्रालय की वित्तीय सहायता से गठित किया जाता है।
2. इन्हें केवल उसी राज्य में तैनात किया जा सकता है जिसने इन्हें गठित किया हो।
3. ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) का हिस्सा होती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही उत्तर है?

A. केवल 1 B. केवल 1 और 2

C. केवल 1 और 3 D. केवल 2 और 3

उत्तर - A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत रिज़र्व बटालियनों की राज्य स्तरीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ये बल आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की भूमिका को कैसे पूरक बनाते हैं?

(250 शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

विश्व ज़ूनोसिस दिवस 2025

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में केन्द्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग ने विश्व ज़ूनोसिस दिवस के उपलक्ष्य में एक इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया है।
- इस सत्र की अध्यक्षता केन्द्रीय पशुपालन तथा डेयरी विभाग के सचिव (AHD) ने की है।

विश्व जूनोसिस दिवस :

- विश्व जूनोसिस दिवस, संपूर्ण विश्व में हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाले जूनोसिस रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
- इस दिन को विशेष रूप से फ्रांसीसी जीवविज्ञानी लुई पाश्चर की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए भी मनाया जाता है, जिन्होंने 1885 में रेबीज का पहला सफल टीका विकसित किया था।
- जूनोसिस रोग वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और परजीवी के कारण फैल सकते हैं, और इनमें रेबीज, एंथ्रेक्स, इन्फ्लूएंजा, निपाह, कोविड-19, ब्रुसेलोसिस और तपेदिक जैसे रोग शामिल हैं।

जूनोटिक और गैर-जूनोटिक रोग :

जूनोटिक रोग :

- ज़ूनोसिस संक्रामक रोग हैं जो जानवरों एवं मनुष्यों के बीच स्थानांतरित हो सकते हैं, जैसे रेबीज़, एंथ्रेक्स, इन्फ्लूएंजा (H1N1 और H5N1), निपाह, कोविड-19, ब्रूसेलोसिस तथा तपेदिक।
- ये रोग विभिन्न रोगजनकों के कारण होते हैं, जिनमें जीवाणु, विषाणु, परजीवी, और कवक शामिल हैं। हालाँकि, सभी पशु रोग जूनोटिक नहीं होते हैं।

गैर-जूनोटिक रोग :

- कई बीमारियाँ मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा किए बिना पशुधन को प्रभावित करती हैं। ये गैर-जूनोटिक रोग प्रजाति-विशिष्ट हैं और मनुष्यों को संक्रमित नहीं कर सकते हैं। उदाहरणों में फुट एंड माउथ डिज़ीज, पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (PPR), लम्पी स्किन डिज़ीज, क्लासिकल स्वाइन फीवर, और रानीखेत रोग शामिल हैं।
- सभी रोगों में से लगभग 60% ज़ूनोटिक हैं और 70% उभरते संक्रमण जानवरों से उत्पन्न होते हैं।
- भारत में वैश्विक पशुधन तथा मुर्गीपालन की संख्या क्रमशः 11% और 18% है। इसके अतिरिक्त, भारत विश्व स्तर पर दूध का सबसे बड़ा उत्पादक और अंडे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

जूनोटिक रोगों का प्रभाव :

जूनोटिक रोगों का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डाल सकता है। जो निम्नलिखित है -

1. **सार्वजनिक स्वास्थ्य :** जूनोटिक रोगों के प्रसार के कारण रुग्णता और मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है। यह महामारी पैदा करने की क्षमता रखता है।
2. **आर्थिक :** जूनोटिक रोगों से जुड़ी लागतें भी हो सकती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल, पशु वध और व्यापार प्रतिबंधों से संबंधित।
3. **सामाजिक :** जूनोटिक रोगों से जुड़ा भय और कलंक भी हो सकता है। इसके अलावा, आजीविका पर भी प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से कृषि और पशुपालन पर।

रोकथाम और नियंत्रण :

ज़ूनोटिक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए जा सकते हैं -

1. टीकाकरण :

- गोजातीय बछड़ों के लिए ब्रुसेल्ला टीकाकरण के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।

- रेबीज टीकाकरण के लिए भी राज्यों को सहायता (ASCAD) के तहत अभियान शुरू किया गया है।

2. स्वच्छता और पशुपालन प्रथाएँ :

- रोगों के प्रसार को रोकने के लिए अच्छी स्वच्छता और उचित पशुपालन प्रथाओं को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

3. वेक्टर नियंत्रण :

- इसके तहत रोग फैलाने वाले वेक्टरों को नियंत्रित करने के उपाय किए जाते हैं और रोग फैलाने वाले वेक्टरों को नियंत्रित करने के उपायों पर ध्यान देना चाहिए।

4. एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण / वन हेल्थ दृष्टिकोण :

- इसके तहत मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के अंतर्संबंध को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ दृष्टिकोण के माध्यम से सहयोगात्मक प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

- इसके तहत पशु चिकित्सकों, चिकित्सा पेशेवरों और पर्यावरण वैज्ञानिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है ताकि जूनोटिक रोगों का व्यापक रूप से समाधान किया जा सके।

5. जनता को शिक्षित और जागरूक करना :

- जूनोटिक और गैर-जूनोटिक रोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने से अनुचित भय को कम किया जा सकता है और पशु स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति अधिक सूचित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

- जूनोसिस रोगों के प्रति जागरूकता और उनके नियंत्रण के लिए सार्वजनिक जागरूकता, स्वास्थ्य शिक्षा और प्रभावी टीकाकरण कार्यक्रम आवश्यक है।

इन उपायों के माध्यम से, जूनोटिक रोगों के जोखिम को कम किया जा सकता है और एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है।

स्रोत - पी.आई.बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. विश्व ज़ूनोसिस दिवस के संबध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. जूनोसिस रोग जानवरों से मनुष्यों में फ़ैलाने वाला रोग है।
2. जूनोसिस रोग के नियंत्रण के सार्वजनिक जागरूकता, स्वास्थ्य शिक्षा और प्रभावी टीकाकरण कार्यक्रम आवश्यक होता है।
3. सभी पशु रोग जूनोटिक रोग नहीं होते हैं।
4. जूनोटिक रोग से महामारी फैल सकता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3 B. केवल 2, 3 और 4
C. इनमें से कोई नहीं। D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. चर्चा कीजिए कि जूनोटिक बीमारियों से जुड़े जोखिमों को कम करने और सभी के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहयोगात्मक प्रयास और वन हेल्थ दृष्टिकोण क्यों आवश्यक हैं?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय विस्थापन : मुद्दे, प्रभाव और नीतिगत अनिवार्यता

खबरों में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के तटीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक उथल-पुथल से गुज़र रहे हैं। बढ़ते समुद्री जलस्तर, अनियंत्रित विकास और प्राकृतिक आवासों के विनाश ने कई समुदायों को विस्थापित कर दिया है, और उन्हें असुरक्षित शहरी रोज़गार बाज़ारों में धकेल दिया है जहाँ उनके पास पर्याप्त सुरक्षा और सहायता प्रणालियों का अभाव है।

पर्यावरणीय आयाम :

1. **समुद्र-स्तर में वृद्धि :** ओडिशा में सतभाया जैसे गांव बढ़ते समुद्र के कारण जलमग्न हो गए हैं, जो आवास पर जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रभाव को दर्शाता है।
2. **तटीय कटाव :** तमिलनाडु, केरल, गुजरात और कर्नाटक में तटरेखाएं तेजी से सिकुड़ रही हैं, जिससे बस्तियों और बुनियादी ढांचे को खतरा पैदा हो रहा है।
3. **मैंग्रोव का नुकसान :** प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करने वाले मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र औद्योगिक और बंदरगाह विकास के कारण नष्ट हो रहे हैं।
4. **आर्द्रभूमि का क्षरण :** अतिक्रमण के कारण तटीय आर्द्रभूमि और नदियाँ सिकुड़ रही हैं, जिससे जैव विविधता और बाढ़ नियंत्रण प्रभावित हो रहा है।
5. **रेत के टीलों का विघटन :** तटीय स्थिरता के लिए आवश्यक प्राकृतिक रेत के टीले निर्माण और पर्यटन अवसंरचना के कारण समतल हो गए हैं।
6. **खारे पानी का घुसपैठ :** समुद्र का जलस्तर बढ़ने से मिट्टी और भूजल में लवणता बढ़ जाती है, जिससे भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है और स्थानीय वनस्पतियों और जीवों को नुकसान पहुंचता है।
7. **जैव विविधता में गिरावट :** आवास की क्षति से समुद्री और तटीय जैव विविधता में कमी आती है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन और मछली पकड़ने से जुड़ी आजीविका प्रभावित होती है।

सामाजिक-आर्थिक आयाम :

1. **आजीविका का नुकसान :** बिगड़ते पारिस्थितिकी तंत्र और संसाधनों की कमी के कारण मछुआरे और किसान अपनी कमाई के पारंपरिक साधन खो रहे हैं।
2. **अलाभकारी कृषि :** बढ़ती लवणता और अप्रत्याशित मौसम के कारण तटीय किसानों के लिए कृषि आर्थिक रूप से अव्यावहारिक हो जाती है।
3. **शहरों की ओर पलायन :** विस्थापित लोग काम की तलाश में चेन्नई, मुंबई और भुवनेश्वर जैसे शहरी केंद्रों की ओर पलायन करते हैं।
4. **शहरी भीड़भाड़ :** जलवायु प्रवासियों के आगमन से शहरी आवास, स्वच्छता और रोजगार प्रणालियों पर दबाव पड़ता है।
5. **अनौपचारिक श्रम प्रवेश :** प्रवासियों को बिना किसी रोजगार सुरक्षा के, निर्माण या घरेलू काम जैसे कम वेतन वाले अनौपचारिक क्षेत्रों में काम पर लगा दिया जाता है।
6. **सामाजिक सुरक्षा का अभाव :**विस्थापित व्यक्तियों को अक्सर सामाजिक कल्याण योजनाओं, पेंशन और राशन तक पहुंच नहीं मिल पाती है।
7. **आर्थिक हाशिए पर जाना:** प्रवासन और नौकरी छूटने से दीर्घकालिक गरीबी चक्र और मुख्यधारा की आर्थिक वृद्धि से बहिष्कार पैदा होता है।

कानूनी और संस्थागत आयाम :

1. **जलवायु प्रवासियों के लिए कोई कानूनी दर्जा नहीं :** धीमी गति से होने वाले जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न विस्थापन को संबोधित करने के लिए कोई मान्यता या नीति नहीं है।
2. **अनुच्छेद 21 की अनदेखी :** विस्थापित व्यक्तियों के लिए अपर्याप्त कानूनी सुरक्षा के कारण अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और सम्मान का अधिकार कमजोर हो गया है।
3. **अप्रभावी श्रम कानून :** बीओसीडब्ल्यू जैसे अधिनियम अनौपचारिक और प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षा जाल से बाहर कर देते हैं।
4. **आपदा कानूनों का खराब कार्यान्वयन :** आपदा प्रबंधन अधिनियम आपातकालीन प्रतिक्रिया पर केंद्रित है, न कि दीर्घकालिक स्थानांतरण या अनुकूलन पर।
5. **पर्यावरण कानूनों का कमजोर प्रवर्तन :** मौजूदा पर्यावरण कानून अनेक परियोजनाओं से होने वाले संचयी पारिस्थितिक क्षरण पर विचार करने में विफल रहते हैं।
6. **सीआरजेड 2019 कमजोर पड़ना :** तटीय विनियमन क्षेत्र के मानदंडों को कमजोर कर दिया गया है, जिससे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में वाणिज्यिक विस्तार की अनुमति मिल गई है।
7. **जलवायु जोखिम आकलन का अभाव :** पर्यावरणीय मंजूरी में अक्सर दीर्घकालिक जलवायु कमजोरियों और सामाजिक प्रभावों की अनदेखी की जाती है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

लिंग और भेद्यता संबंधी आयाम :

1. **महिलाओं पर असमान प्रभाव :** सामाजिक मानदंडों, गतिशीलता की कमी और सीमित रोजगार विकल्पों के कारण महिलाएं अधिक असुरक्षित हैं।
2. **घरेलू शोषण :** कई विस्थापित महिलाएं शहरों में घरेलू कामगार के रूप में काम करने लगती हैं, जहां उन्हें दुर्व्यवहार, वेतन चोरी और अत्यधिक काम का सामना करना पड़ता है।
3. **स्वास्थ्य और पोषण जोखिम :** विस्थापित महिलाओं को कुपोषण, खराब प्रजनन स्वास्थ्य और अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल की समस्या का अधिक खतरा रहता है।
4. **शिक्षा छोड़ने वाले :** विस्थापित परिवारों में लड़कियों के आर्थिक तनाव और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण स्कूल छोड़ने की संभावना अधिक होती है।
5. **तस्करी और बंधुआ मजदूरी :** कमजोर महिलाओं और बच्चों को तस्करी किये जाने या जबरन श्रम में धकेले जाने का अधिक खतरा रहता है।
6. **लिंग-संवेदनशील नीतियों का अभाव :** मौजूदा राहत और पुनर्वास ढांचे में अक्सर महिलाओं और लड़कियों की विशिष्ट आवश्यकताओं की अनदेखी की जाती है।
7. **सीमित प्रतिनिधित्व :** विस्थापित महिलाओं को नियोजन, पुनर्वास या जलवायु अनुकूलन चर्चाओं में शायद ही कभी आवाज मिलती है।

विकास बनाम स्थिरता संबंधी आयाम :

1. **संवेदनशील क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा :** पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में बंदरगाहों और बिजली संयंत्रों जैसी बड़ी परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं।
2. **सागरमाला परियोजनाएँ :** सागरमाला के अंतर्गत तटीय अवसंरचना में अक्सर पारिस्थितिक संतुलन के स्थान पर वाणिज्य को प्राथमिकता दी जाती है।
3. **वाणिज्यिक जलीय कृषि :** बड़े पैमाने पर झींगा पालन से भूमि का क्षरण होता है, जल प्रदूषित होता है, तथा छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले लोग विस्थापित होते हैं।
4. **पर्यटन दबाव :** समुद्र तटीय पर्यटन परियोजनाएं सामुदायिक भूमि पर अतिक्रमण करती हैं तथा टीलों और मैंग्रोव जैसे प्राकृतिक अवरोधकों को नष्ट करती हैं।
5. **जलवायु प्रभाव की अनदेखी :** परियोजना अनुमोदन में अक्सर जलवायु संबंधी संचयी कमजोरियों और दीर्घकालिक स्थिरता की उपेक्षा की जाती है।
6. **अल्पकालिक आर्थिक लक्ष्य :** आर्थिक विकास, समतापूर्ण, जलवायु-अनुकूल आजीविका के बजाय सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि पर केंद्रित है।
7. **कमजोर नियामक निगरानी :** पर्यावरणीय प्रभाव निगरानी का अभाव पारिस्थितिक क्षति और विस्थापन को जारी रहने देता है।

शासन और लोकतांत्रिक मूल्यों से संबंधित आयाम :

1. **शीर्ष-नीचे स्थानांतरण :** समुदायों को उचित परामर्श या भागीदारी के बिना स्थानांतरित किया जाता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन है।
2. **अनियोजित पुनर्वास :** पुनर्वास कॉलोनियों में स्कूल, अस्पताल या पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।
3. **विरोध प्रदर्शन का अपराधीकरण :** पर्यावरण कार्यकर्ताओं और सामुदायिक नेताओं को पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी और निगरानी का सामना करना पड़ता है।
4. **असहमति का दमन :** सेव सतभाया या एन्नोर जैसे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को कानूनी धमकी और गलत सूचना अभियानों का सामना करना पड़ता है।
5. **सहभागी शासन का अभाव :** प्रभावित समुदायों को परियोजना नियोजन या पर्यावरणीय आकलन में शायद ही कभी शामिल किया जाता है।
6. **संस्थाओं में विश्वास का क्षरण :** स्थानीय आवाजों की बार-बार उपेक्षा से लोकतांत्रिक संस्थाओं और न्याय में नागरिकों का विश्वास खत्म हो जाता है।
7. **संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन :** विस्थापित समुदायों को सुनवाई, सम्मानपूर्वक पुनर्वास या कानूनी उपाय पाने के अधिकार से वंचित रखा जाता है।

जमीनी स्तर और नागरिक समाज संबंधी आयाम :

1. **उभरते स्थानीय आंदोलन :** सेव सताया, पट्टवम मैंग्रोव प्रोटेक्शन और एन्नोर विरोध जैसी पहल पारिस्थितिक अन्याय का विरोध करती हैं।
2. **सामुदायिक ज्ञान प्रणालियाँ :** ज्वार-भाटा, मिट्टी और जैव विविधता पर पारंपरिक ज्ञान का उपयोग स्थानीय लोगों द्वारा टिकाऊ मॉडलों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है।
3. **नागरिक समाज वकालत :** गैर सरकारी संगठन और नागरिक समूह जलवायु-प्रेरित विस्थापन पर मुकदमेबाजी, पुनर्वास और जागरूकता का समर्थन करते हैं।
4. **युवा सहभागिता :** तटीय क्षेत्रों के युवा कार्यकर्ता न्याय और स्थिरता के लिए आवाज बनकर उभर रहे हैं।
5. **कानूनी याचिकाएं और जनहित याचिकाएं :** नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा कई जलवायु और विस्थापन संबंधी मुद्दों को अदालतों में उठाया जा रहा है।
6. **सहयोगात्मक अनुसंधान:** शैक्षणिक संस्थान पारिस्थितिक क्षति का दस्तावेजीकरण करने तथा वैकल्पिक नीति प्रस्तावित करने के लिए समुदायों के साथ साझेदारी करते हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

7. **जलवायु न्याय का आह्वान :** जलवायु अनुकूलन योजनाओं के एक भाग के रूप में कमजोर समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने की मांग बढ़ रही है।

नैतिक और मानवाधिकार संबंधी आयाम :

1. **जीवन के अधिकार पर खतरा :** समुद्र का बढ़ता जलस्तर, जबरन विस्थापन और संसाधनों की कमी जीवन और सम्मान के मूल अधिकार के लिए खतरा बन रहे हैं।
2. **पीढ़ी दर पीढ़ी अन्याय :** आज पर्यावरण क्षरण आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों और भविष्य के लिए खतरा बन रहा है।
3. **अनुपातहीन पीड़ा :** गरीब, तटीय और स्वदेशी आबादी को जलवायु परिवर्तन का खामियाजा भुगतना पड़ता है, जिसका कारण वे नहीं हैं।
4. **राज्य की नैतिक जिम्मेदारी :** राज्य को केवल लाभ-संचालित विकास को सुविधाजनक बनाने के बजाय कमजोर लोगों की रक्षा करके नैतिक शासन को बनाए रखना चाहिए।
5. **वैश्विक असमानता स्थानीय स्तर पर परिलक्षित :** भारत में तटीय गरीब लोग वैश्विक उत्सर्जन और घरेलू नीति विफलताओं दोनों के शिकार हैं।
6. **अधिकार-आधारित अनुकूलन की आवश्यकता :** अनुकूलन रणनीतियों को मानव अधिकारों पर केन्द्रित होना चाहिए, न कि केवल भौतिक अवसंरचना पर।
7. **संवैधानिक कर्तव्य के रूप में जलवायु न्याय :** जीवन, पर्यावरण और न्यायसंगत विकास की रक्षा करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के अनुरूप है।

आगे की राह :

1. **जलवायु विस्थापन को कानूनी मान्यता देना :** धीमी गति से जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवास करने वाले प्रवासियों को एक अलग श्रेणी के रूप में मान्यता देने और उनकी सुरक्षा करने के लिए एक व्यापक कानूनी और नीतिगत ढांचा विकसित करना, जिससे आवास, सामाजिक सुरक्षा और आजीविका तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके।
2. **सीआरजेड और पर्यावरण विनियमों में सुधार :** दीर्घकालिक जलवायु जोखिमों, संचयी प्रभावों और सामुदायिक सहमति को नियोजन में एकीकृत करने के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) मानदंडों और पर्यावरण मंजूरी प्रक्रियाओं को मजबूत करना।
3. **अधिकार-आधारित पुनर्वास सुनिश्चित करना :** भागीदारीपूर्ण, अधिकार-आधारित पुनर्वास और पुनर्वास योजनाओं को डिजाइन और कार्यान्वित करना जो विस्थापित समुदायों के लिए बुनियादी सेवाओं, बुनियादी ढांचे, भूमि के स्वामित्व और आजीविका समर्थन की गारंटी देते हैं।
4. **सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार :** विस्थापित अनौपचारिक श्रमिकों को ई.एस.एच.आर.ए.एम., राशन वितरण, स्वास्थ्य बीमा और श्रम सुरक्षा जैसी योजनाओं में शामिल करें, जिसमें महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान हों।
5. **समुदाय-आधारित अनुकूलन को बढ़ावा देना :** स्थानीय पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन का समर्थन करें, जैसे कि मैंग्रोव पुनःरोपण और आर्द्रभूमि संरक्षण, जिसका नेतृत्व पारंपरिक ज्ञान और समावेशी योजना का उपयोग करने वाले समुदायों द्वारा किया जाए।
6. **जलवायु शासन और जवाबदेही को मजबूत करना :** सक्रिय नागरिक समाज और सामुदायिक भागीदारी के साथ जलवायु अनुकूलन योजना, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी और शिकायत निवारण के लिए पारदर्शी तंत्र स्थापित करना।
7. **विकास में मुख्यधारा जलवायु न्याय :** तटीय विकास रणनीतियों (जैसे सागरमाला) को जलवायु न्याय, समानता और अंतर-पीढ़ीगत स्थिरता के सिद्धांतों के साथ संरेखित करना, तथा औद्योगिक विस्तार की तुलना में कमजोर आबादी को प्राथमिकता देना।

निष्कर्ष :

भारत के तटीय क्षेत्र जलवायु संकट की अग्रिम पंक्ति में हैं, जहाँ पर्यावरणीय क्षरण और असंवहनीय विकास समुदायों को विस्थापित कर रहा है, आजीविका को नष्ट कर रहा है और कमज़ोरियों को बढ़ा रहा है। यह न केवल एक पारिस्थितिक आपातकाल है, बल्कि एक गहरी मानवीय और संवैधानिक चुनौती भी है। जलवायु प्रवासियों को कानूनी मान्यता न मिलना, महिलाओं का हाशिए पर होना और सामुदायिक आवाज़ों का दमन मौजूदा शासन ढाँचे में लोकतांत्रिक और नैतिक कमियों को उजागर करता है।

स्रोत - पी. आई. बी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत के तटीय क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. भारत में तटीय कटाव पूर्वी तटरेखा तक ही सीमित है।
2. मैंग्रोव तूफानी लहरों और तटीय बाढ़ के विरुद्ध प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं।
3. तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना 2019 ने तट के साथ पर्यावरण संरक्षण को मजबूत किया।
4. समुद्र-स्तर में वृद्धि के कारण खारे पानी का प्रवेश कृषि और भूजल की गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 3 B. केवल 2 और 4

C. केवल 2, 3 और 4 D. केवल 1, 2 और 4

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत के तटीय समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के बहुआयामी प्रभाव पर चर्चा करें और जलवायु न्याय और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएँ।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत - अर्जेंटीना कृषि साझेदारी : नवाचार और स्थिरता के लिए एक रणनीतिक कूटनीति

खबरों में क्यों?

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- हाल ही में भारत और अर्जेंटीना ने 15 जुलाई को कृषि क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए संयुक्त कार्य समूह (JWG) की दूसरी वर्चुअल बैठक का आयोजन किया।
- इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी और अर्जेंटीना के कृषि, पशुधन एवं मत्स्य पालन सचिव सर्जियो इराटा ने की।
- भारत-अर्जेंटीना कृषि कूटनीति के तहत होने वाला यह संवाद दोनों देशों के बीच कृषि-संबंधी तकनीकी, व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी को नए आयाम देने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।

भारत-अर्जेंटीना कृषि साझेदारी : कूटनीति के एक नए युग की ओर

1. **राजनयिक प्राथमिकता में कृषि का महत्व :** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2025 में अर्जेंटीना यात्रा, जो कि पिछले 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, ने द्विपक्षीय संबंधों में कृषि को एक केंद्रीय विषय के रूप में उभारा और यह संकेत दिया कि भारत अब क्षेत्र-विशिष्ट कूटनीति को प्राथमिकता दे रहा है।
2. **एक सॉफ्ट पावर के रूप में कृषि :** नई दिल्ली में आयोजित 16वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन के दौरान अर्जेंटीना ने स्पष्ट रूप से कहा कि कृषि, भारत-अर्जेंटीना साझेदारी का प्रमुख आधार है, और दोनों देशों ने नवाचार व स्थिरता के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
3. **संयुक्त कार्य समूह (JWG) के द्वारा संस्थागत संवाद को मजबूती प्रदान करना :** द्वितीय संयुक्त कार्य समूह (JWG) की बैठक ने कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रमुख विषयों - जैसे जलवायु - संवेदनशील खेती, अनुसंधान एवं विकास, और कृषि मशीनीकरण पर नियमित और संरचित संवाद की नींव रखी, जिससे नीति-निर्माण में स्थायित्व आया।
4. **पूरक क्षमताओं का सामंजस्य :** भारत जहां डिजिटल तकनीक और लघु जोत कृषि मॉडल में मजबूत है, वहीं अर्जेंटीना उन्नत परिशुद्धता आधारित और मशीनीकृत खेती में दक्षता रखता है। यह पूरकता दोनों देशों के बीच परस्पर लाभकारी सहयोग का मार्ग प्रशस्त करती है।
5. **शोध और नवाचार के लिए राजनयिक मंच :** भारत और अर्जेंटीना ने जैव-प्रौद्योगिकी एवं कृषि-तकनीक के क्षेत्रों में युवा वैज्ञानिकों और स्टार्टअप्स के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, जिससे वैज्ञानिक समुदाय और आम जनता के बीच आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे।
6. **विस्तारित कृषि व्यापार सहयोग :** द्विपक्षीय व्यापारिक वार्ता अब केवल तिलहन तक सीमित नहीं रही, बल्कि दलहन, डेयरी उत्पादों और बागवानी जैसे विविध कृषि क्षेत्रों तक विस्तार पा चुकी है, जिससे यह साझेदारी भारत की खाद्य सुरक्षा नीति के साथ भी जुड़ गई है।

7. **रणनीतिक सहयोग में कृषि की प्रमुख भूमिका :** कृषि अब भारत-अर्जेंटीना रणनीतिक साझेदारी के व्यापक फलक में ऊर्जा, खनिज (विशेष रूप से लिथियम), और रक्षा जैसे क्षेत्रों के साथ समाहित हो चुकी है, जिससे भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका में कृषि की हिस्सेदारी भी सशक्त हुई है।

भू राजनीतिक और क्षेत्रीय संदर्भ में भारत - अर्जेंटीना कृषि सहयोग का महत्व :

1. **लैटिन अमेरिका में भारत की बढ़ती मौजूदगी :** दक्षिण अमेरिका में, विशेषकर कृषि संसाधनों से परिपूर्ण लेकिन पारंपरिक रूप से भारत की कूटनीति में गौण रहे क्षेत्रों में, यह साझेदारी भारत की प्रभावशाली उपस्थिति को मजबूत करती है।

2. **क्षेत्रीय प्रतिसंतुलन में भूमिका :** यह सहयोग विशेष रूप से ब्राजील और अर्जेंटीना में चीन के बढ़ते निवेश और प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में, एक रणनीतिक संतुलन प्रस्तुत करता है और भारत की कूटनीतिक गहराई को बढ़ाता है।

3. **दक्षिण-दक्षिण सहयोग का नेतृत्व :** भारत इस साझेदारी के माध्यम से दक्षिण-दक्षिण सहयोग में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है, जहां कृषि को विकासशील देशों के साथ तकनीकी और व्यावसायिक जुड़ाव के एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

4. **मर्कोसुर तक सीधी पहुंच :** अर्जेंटीना के माध्यम से भारत अब मर्कोसुर व्यापार समूह, जिसमें ब्राजील, पैराग्वे, और उरुग्वे भी शामिल हैं, तक अपनी पहुंच को सुदृढ़ कर रहा है, जिससे कृषि व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग को बल मिलेगा।

5. **त्रिकोणीय सहयोग की संभावना :** भारत और अर्जेंटीना अब अफ्रीकी देशों के साथ कृषि-मशीनीकरण, जलवायु-अनुकूल खेती और बीज तकनीक जैसे क्षेत्रों में त्रिकोणीय साझेदारी की संभावनाएं तलाश रहे हैं, जो विकासशील राष्ट्रों में कृषि नवाचार को गति देगा।

6. **आपूर्ति श्रृंखला का विवेकपूर्ण विविधीकरण :** भारत अपनी कृषि-आयात नीति को विविध बनाकर—विशेषकर तिलहन, दलहन और उर्वरकों के संदर्भ में—आपूर्ति जोखिमों को कम करने और दीर्घकालिक स्थिरता को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है।

7. **वैश्विक मंचों पर संयुक्त प्रभाव :** भारत और अर्जेंटीना के बीच बढ़ती नजदीकी, FAO, G20 (कृषि ट्रैक), और WTO जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कृषि नीति से जुड़ी चर्चाओं में एक संयुक्त दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने की संभावना को सशक्त करती है।

8. **खाद्य-ऊर्जा-जल संरक्षण का समेकन :** कृषि सहयोग को ऊर्जा संसाधनों (जैसे लिथियम, जैव-ईंधन) से जोड़कर भारत क्षेत्रीय सुरक्षा नीतियों में बहुआयामी दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है।

भारत - अर्जेंटीना : कृषि नवाचार और ज्ञान सहयोग में एक प्रगतिशील साझेदारी

कृषि नवाचार और तकनीकी सहयोग :

1. भारत और अर्जेंटीना ने जलवायु-संवेदनशील कृषि प्रणालियों को सशक्त करने हेतु सूखा-प्रतिरोधी फसलों, जल दक्षता तकनीकों और न्यूनतम उत्सर्जन वाले कृषि मॉडल पर संयुक्त रूप से कार्य करने का संकल्प लिया है।

2. दोनों देश उच्च उत्पादकता और रोग-प्रतिरोधक क्षमताओं वाली फसलों के विकास के लिए CRISPR जैसी जीन-संपादन तकनीकों पर साझा अनुसंधान को बढ़ावा दे रहे हैं।

3. छोटे व बड़े किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, दोनों देशों ने किफायती, स्केलेबल और सटीक कृषि उपकरणों के विकास में सहयोग पर सहमति व्यक्त की है।

4. कृषि तकनीक क्षेत्र में भारत और अर्जेंटीना के स्टार्टअप्स के बीच सीमा-पार सहयोग, वित्तीय निवेश और इनक्यूबेशन के माध्यम से नवाचार पारिस्थितिकी को गति देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

5. भारत और अर्जेंटीना मिलकर ऐसे कृषि नवाचार केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, जो सह-विकास आधारित उत्पाद नवाचार को संस्थागत स्वरूप देंगे।

6. तकनीकी हस्तांतरण को द्वि दिशात्मक और व्यावहारिक बनाने के लिए दोनों देशों के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की संस्थागत क्षमताओं को समन्वित किया जा रहा है।

7. भारत की डिजिटल कृषि पहलें—जैसे एग्रीस्टैक और ई-एनएएम—अर्जेंटीना के लिए डिजिटल कृषि क्षेत्र में अनुकरणीय मॉडल बनकर उभर रही हैं।

कृषि शिक्षा, प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास :

1. भारत और अर्जेंटीना पौध संरक्षण, जैव-प्रौद्योगिकी, कृषि मशीनीकरण और खाद्य प्रसंस्करण जैसे विषयों पर संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के आयोजन के लिए सहयोग कर रहे हैं।

2. किसानों के लिए विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों देशों की खेती प्रणालियों—विशेषकर बड़े और छोटे जोत मॉडल—का व्यावहारिक अनुभव साझा किया जा रहा है।

3. कृषि-जैव प्रौद्योगिकी, कीट प्रबंधन और जलवायु विज्ञान जैसे क्षेत्रों में शोधरत विद्यार्थियों को पीएचडी व पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय अनुभव दिया जा रहा है।

4. अर्जेंटीना के राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान (INTA) और भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों के बीच पाठ्यक्रम निर्माण और संयुक्त शोध परियोजनाओं में सहयोग गहराया जा रहा है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

5. द्विभाषी (स्पेनिश-हिंदी/अंग्रेज़ी) कृषि-प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए जा रहे हैं, ताकि संचार की बाधाएं खत्म हों और स्थानीय किसानों को अधिक उपयोगी ज्ञान प्राप्त हो।

6. नवाचार और कौशल विकास को संस्थागत स्वरूप देने हेतु सार्वजनिक-निजी साझेदारी आधारित अनुसंधान प्लेटफार्मों का निर्माण किया जा रहा है।

7. वास्तविक परिस्थितियों में ज्ञान आदान-प्रदान को प्रभावशाली बनाने के लिए दोनों देश संयुक्त अनुसंधान प्रयोगशालाओं और मॉडल फार्मों की स्थापना पर विचार कर रहे हैं।

वैश्विक कृषि चुनौतियों के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व :

1. खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए भारत और अर्जेंटीना ऐसे साझा नीति ढांचे तैयार कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य खाद्य उपलब्धता, पोषण सुधार और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना है।

2. शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों की लॉजिस्टिक्स को सुरक्षित करने हेतु दोनों देश लचीली और ठंडी श्रृंखला से युक्त आपूर्ति प्रणालियों का विकास कर रहे हैं।

3. जलवायु संकटों से निपटने के लिए अनुकूली कृषि तकनीकों पर साझा अनुसंधान और अनुभव-साझा की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

4. खाद्यान्नों के भंडारण और आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में रणनीतिक बफर स्टॉक निर्माण और संकट प्रतिक्रिया प्रणाली पर सहयोग किया जा रहा है।

5. भारत की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और अर्जेंटीना की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के बीच श्रेष्ठ व्यवहारों का आदान-प्रदान किया जा रहा है।

6. कीट प्रकोप, टिड्डी हमलों और मौसम परिवर्तन की भविष्यवाणी के लिए दोनों देशों के बीच कृषि पूर्व-चेतावनी प्रणाली का डेटा साझा किया जा रहा है।

7. वैश्विक खाद्य संकटों के समय निष्पक्ष और संतुलित कृषि व्यापार सुनिश्चित करने के लिए दोनों देश विश्व मंचों पर समन्वित रणनीति अपनाने की दिशा में अग्रसर हैं।

टिकाऊ खेती की ओर पारिस्थितिकी आधारित मशीनीकरण :

1. भारत की जैविक कृषि और अर्जेंटीना की बिना जुताई वाली खेती की सफल कहानियों को संयुक्त रूप से दस्तावेजीकृत कर उन्हें वैश्विक मंचों पर प्रस्तुत करने की तैयारी हो रही है।

2. अर्जेंटीना के उच्च तकनीक युक्त कृषि यंत्रों को भारत के पारंपरिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोणों के साथ मिलाकर स्थायी खेती के लिए एक हाइब्रिड मॉडल विकसित किया जा रहा है।

3. पारंपरिक भारतीय कृषि-पारिस्थितिकी ज्ञान का उपयोग अर्जेंटीना में सतत भूमि प्रबंधन पद्धतियों को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है।

4. दोनों देश जैव उर्वरक, प्राकृतिक कीट नियंत्रण और एकीकृत खेती जैसे कम लागत वाले समाधानों पर संयुक्त ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

5. मिश्रित कृषि तकनीकों को प्रदर्शित करने हेतु संयुक्त मॉडल फार्मों की स्थापना की योजना है, जो नवाचार को जमीन पर उतारने का कार्य करेंगे।

6. किसानों द्वारा विकसित नवाचारों, जैसे पारंपरिक बीज संरक्षण विधियां और फसल चक्र प्रणाली, को साझा मंचों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है।

7. विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों—जैसे अर्ध-शुष्क, वर्षा-आधारित या ऊंचाई वाले क्षेत्रों—के लिए तकनीकों के स्थान-विशिष्ट अनुकूलन हेतु संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।

भारत-अर्जेंटीना कृषि सहयोग समान और सतत विकास की ओर

समावेशी ग्रामीण प्रगति के लिए कृषि को उत्प्रेरक बनाना :

1. भारत और अर्जेंटीना कृषि क्षेत्र को उच्च मूल्य आधारित उत्पादन की ओर पुनः दिशा देने के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं, जहां पारंपरिक अनाज उत्पादन से आगे बढ़कर बागवानी, दलहन, फूलों और मसालों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कृषकों की आमदनी में ठोस सुधार की संभावनाएं बन रही हैं।

2. खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और पैकेजिंग जैसे कृषि से जुड़े उपक्रमों को प्रोत्साहित करते हुए दोनों देश कृषि आधारित लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता को सशक्त बना रहे हैं।

3. मूल्य वर्धित कृषि उत्पादों—जैसे प्रोसेस्ड फूड, जैविक उत्पाद, डेयरी और जैव-इनपुट—के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत और अर्जेंटीना मिलकर वैश्विक बाजारों तक पहुंच के अवसर खोल रहे हैं।

4. पारंपरिक कृषि के साथ-साथ संबद्ध गतिविधियाँ जैसे डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता लाकर गैर-कृषि रोजगार के अवसरों को बढ़ा रही हैं।

5. दोनों देशों में कृषि-पर्यटन को एक नवाचार-आधारित ग्रामीण विकास मॉडल के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें कृषि विरासत, इको-फार्मों और डेमो मॉडल पर आधारित पर्यटन सर्किट विकसित किए जा सकते हैं।

6. भारत और अर्जेंटीना कृषि यंत्र संचालन, कृषि विपणन और स्मार्ट कृषि तकनीकों में ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास हेतु संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने की दिशा में अग्रसर हैं।

7. समावेशी कृषि विकास सुनिश्चित करने हेतु महिला, जनजातीय और सीमांत किसान समुदायों को कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने पर दोनों देश विशेष ध्यान दे रहे हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

हरित और जलवायु-उत्तरदायी कृषि एजेंडा की दिशा में सहयोग :

1. कृषि भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए मृदा परीक्षण, जैविक आदानों और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंधन पर भारत और अर्जेंटीना के बीच संयुक्त कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
2. जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में ड्रिप सिंचाई, वर्षा जल संचयन और माइक्रो-इरिगेशन प्रणाली के माध्यम से जल उपयोग दक्षता बढ़ाने की दिशा में द्विपक्षीय प्रयास किए जा रहे हैं।
3. कार्बन पृथक्करण को बढ़ावा देने हेतु कृषि वानिकी के साथ-साथ जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण आय में विविधता लाने के लिए साझेदारी आधारित पहलें की जा रही हैं।
4. जलवायु लचीली भूमि उपयोग के लिए समोच्च कृषि, भूमि पुनर्स्थापन और स्थानीय स्थलाकृति के अनुरूप टिकाऊ फसल प्रणाली के विकास में दोनों देश सहयोग कर रहे हैं।
5. जैव कीटनाशकों, जैव उर्वरकों और प्राकृतिक खेती तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान, विनियमन और व्यावसायीकरण की प्रक्रिया में साझेदारी की जा रही है।
6. कृषि में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को अपनाते हुए फसल अवशेषों से कम्पोस्ट, जैव ऊर्जा और मल्चिंग जैसे नवाचारों को बढ़ावा देने हेतु द्विपक्षीय परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं।
7. दोनों देश कृषि को जलवायु लक्ष्य (NDCs) और सतत विकास लक्ष्यों (SDG-2: भूख समाप्त करना, SDG-12: टिकाऊ उपभोग, SDG-13: जलवायु कार्रवाई) से जोड़ने के लिए एक समन्वित रणनीति पर कार्य कर रहे हैं।

निष्कर्ष :

- भारत और अर्जेंटीना के बीच कृषि पर द्वितीय संयुक्त कार्य समूह (JWG) की बैठक केवल एक नीतिगत बातचीत नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी बदलाव की शुरुआत है, जहां एक परंपरागत लेन-देन वाली साझेदारी को एक बहुआयामी, रणनीतिक और नवाचार-आधारित सहयोग में रूपांतरित किया जा रहा है।
- यह साझेदारी न केवल तकनीकी और संस्थागत क्षमताओं को साझा करने का एक मंच है, बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन और सतत विकास की व्यापक चुनौतियों से मिलकर निपटने का भी माध्यम है।
- कृषि, ऊर्जा, खनन और रक्षा के साथ जैसे-जैसे भारत की विदेश नीति का एक केंद्रीय स्तंभ बन रही है, वह भारत-अर्जेंटीना सहयोग वैश्विक दक्षिण में समावेशी नवाचार और स्थिरता की नई परिभाषा गढ़ने की दिशा में अग्रसर है।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत-अर्जेंटीना संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत और अर्जेंटीना के बीच कृषि पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) जलवायु-लचीली खेती, मशीनीकरण और कृषि अनुसंधान में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।
2. अर्जेंटीना मर्कोसुर ब्लॉक का सदस्य है, जिसमें बोलीविया और चिली भी शामिल हैं।
3. भारत और अर्जेंटीना ने जीनोम संपादन और डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकियों में सहयोग शुरू किया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर - (c)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. चर्चा कीजिए कि भारत और अर्जेंटीना के बीच विकसित हो रहा कृषि सहयोग भारत की क्षेत्र-विशिष्ट कूटनीति में आए किस प्रकार के बदलाव को दर्शाता है, और इस प्रकार की साझेदारियाँ वैश्विक खाद्य सुरक्षा, नवाचार एवं सतत विकास में किस प्रकार योगदान कर सकती हैं ?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत का स्वच्छ ऊर्जा विरोधाभास : क्षमता और कुल उत्पादन के बीच का अंतर

खबरों में क्यों?

- भारत वर्तमान में ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसका उद्देश्य एक अधिक सतत एवं निम्न-कार्बन उत्सर्जन पर आधारित भविष्य का निर्माण करना है। इस प्रयास के तहत, देश ने कुल स्थापित विद्युत क्षमता का आधा हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों — जैसे सौर, पवन, जल एवं परमाणु ऊर्जा से प्राप्त कर लेने में सफलता प्राप्त की है।
- भारत की यह उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए योगदान (NDC) लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे भारत ने पाँच वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया है।
- इन स्वच्छ स्रोतों से उत्पन्न वास्तविक बिजली उत्पादन अभी भी कुल उत्पादन का 30% से भी कम है, जो चिंता का विषय यह है। यह स्थिति इस बात को दर्शाती है कि स्थापित क्षमता के पूर्ण उपयोग में अभी भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं और उत्पादन क्षमता तथा वास्तविक ऊर्जा उपयोग के बीच एक स्पष्ट अंतर मौजूद है।

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा : प्रगति, उपलब्धियां और चुनौतियाँ

- भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नीतिगत समर्थन, तकनीकी नवाचार और निजी क्षेत्र की भागीदारी के सहारे उल्लेखनीय प्रगति की है। यह बदलाव न केवल ऊर्जा क्षेत्र की दिशा को परिवर्तित कर रहा है, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर अग्रणी हरित ऊर्जा राष्ट्रों की पंक्ति में भी स्थापित कर रहा है।

तेज गति से बढ़ती हरित ऊर्जा क्षमता :

- मार्च 2025 तक भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 220.10 गीगावाट तक पहुँच चुकी है, जो पिछले वित्त वर्ष (2023-24) में 198.75 गीगावाट थी। केवल वित्त वर्ष 2024-25 में ही रिकॉर्ड 29.52 मेगावाट नई हरित क्षमता जोड़ी गई, जो अब तक की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि है।

वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति :

- कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में: विश्व में 4वां स्थान
- पवन ऊर्जा के क्षेत्र में: 4वां स्थान
- सौर ऊर्जा उत्पादन में (REN21 की रिपोर्ट के अनुसार): 5वां स्थान

विभिन्न स्रोतों में प्रगति (2024-25) :

स्रोत	मुख्य विवरण
सौर ऊर्जा	- 23.83 गीगावाट की नई वृद्धि - कुल स्थापित क्षमता: 105.65 गीगावाट - आरई पोर्टफोलियो में ~50% हिस्सेदारी
पवन ऊर्जा	- 4.15 गीगावाट की वृद्धि - कुल क्षमता: 50.04 गीगावाट
जैव ऊर्जा	- कुल क्षमता: 11.58 गीगावाट - इसमें 0.53 गीगावाट अपशिष्ट-से-ऊर्जा और ऑफ-ग्रिड शामिल
लघु जल विद्युत (SHP)	- कुल क्षमता: 5.10 गीगावाट - 0.44 गीगावाट निर्माणाधीन

परियोजनाओं की स्थिति और नवाचार :

- **निर्माणाधीन परियोजनाएं:** 169.40 गीगावाट
- **निविदा जारी परियोजनाएं:** 65.06 गीगावाट
- **नई अवधारणाएं :**
  - हाइब्रिड मॉडल (सौर + पवन)
  - चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति (RTC)
  - पीकिंग पावर संयोजन
  - थर्मल और नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकृत बंडलिंग

नवीकरणीय ऊर्जा विकास की प्रमुख बाधाएँ :

चुनौती	स्पष्टीकरण
1. कम क्षमता उपयोग कारक (CUF)	सौर (~20%) और पवन (~25–30%) ऊर्जा की परिवर्तनशील प्रकृति इन्हें कोयला (~60%) और परमाणु (~80%) की तुलना में कम विश्वसनीय बनाती है।

2. कोयले पर निर्भरता	कोयला अभी भी 75% से अधिक बिजली उत्पादन करता है, जिससे यह नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक बाधा बना हुआ है।
3. ऊर्जा भंडारण और ग्रिड ढाँचे की कमी	बैटरी भंडारण प्रणालियाँ और पारेषण अवसंरचना सीमित हैं, जिससे हरित ऊर्जा का उपयोग बाधित होता है।
4. फ्लैट टैरिफ व्यवस्था	समय आधारित मूल्य निर्धारण की कमी सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग में बाधा बनती है।
5. भूमि अधिग्रहण एवं अनुमोदन में विलंब	परियोजनाओं के लिए भूमि एकत्र करना और आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त करना जटिल और समयसाध्य है।
6. वित्तीय चुनौतियाँ	उच्च पूंजी लागत, पीपीए में विलंब और नीति अस्थिरता निजी निवेश को प्रभावित करती है।
7. डिस्कॉम के साथ समन्वय की कठिनाई	वितरण कंपनियाँ आर्थिक दबाव में हैं और वे अनिश्चित हरित ऊर्जा को अपनाने में हिचकिचाती हैं।

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना क्यों आवश्यक है ?

- भारत जैसे विशाल और ऊर्जा-गहन देश के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का सशक्त उपयोग केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता का मार्ग है। बदलते वैश्विक जलवायु परिदृश्य और घरेलू ऊर्जा मांग को देखते हुए यह परिवर्तन अत्यंत आवश्यक बन जाता है।

नवीकरणीय ऊर्जा के प्रसार की आवश्यकता क्यों है?

1. **ऊर्जा आत्मनिर्भरता और सुरक्षा :** वर्ष 2040 तक ऊर्जा मांग दोगुनी हो सकती है। यदि नवीकरणीय स्रोतों को पर्याप्त रूप से नहीं अपनाया गया, तो भारत को आयातित कोयला और गैस पर अधिक निर्भर रहना पड़ेगा, जिससे वैश्विक मूल्य अस्थिरता और आपूर्ति जोखिम की चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं।

2. **जलवायु प्रतिबद्धताओं की पूर्ति :** भारत ने भले ही कुल स्थापित क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल कर लिया है, परंतु वास्तविक उत्पादन अभी भी 28% के आसपास है। यह पेरिस समझौते के तहत उत्सर्जन में कमी की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को कमजोर कर सकता है।

3. **वायु प्रदूषण में कमी :** कोयला आधारित संयंत्र प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। जबकि दुनिया के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में हैं, ऐसे में नवीकरणीय ऊर्जा का प्रसार आवश्यक है ताकि शहरी स्वास्थ्य और वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके।

4. **आर्थिक लाभ और दक्षता :** कम क्षमता उपयोग दर (CUF) का अर्थ है कि निवेशित पूंजी से अपेक्षित उत्पादन नहीं हो पा रहा। इससे डेवलपर के लाभ, डिस्कॉम की स्थिरता और उपभोक्ताओं की दरें सभी प्रभावित होती हैं।

5. **कठिन क्षेत्रों का डीकार्बोनाइजेशन :** हरित हाइड्रोजन जैसे ईंधनों के माध्यम से स्टील, उर्वरक और परिवहन जैसे क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करना तभी संभव है जब पर्याप्त नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध हो।

6. **जल संरक्षण :** तापीय विद्युत संयंत्रों की तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों में जल की खपत न्यूनतम होती है, जो विशेषकर जल संकट वाले क्षेत्रों के लिए फायदेमंद है।

7. **रोजगार और ग्रामीण सशक्तिकरण :** पीएम-कुसुम जैसी योजनाएँ किसानों को ऊर्जा उत्पादक बना रही हैं। इससे स्थानीय रोजगार सृजन होता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ा जा रहा है।

8. **ग्रिड सुधार और लचीलापन :** नवीकरणीय ऊर्जा के समुचित उपयोग से स्मार्ट ग्रिड, भंडारण, और लचीलापन को बढ़ावा मिलता है, जिससे आपूर्ति अधिक विश्वसनीय और हानि कम होती है।

नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित प्रमुख सरकारी पहलें :

उपाय	लक्ष्य
हरित ऊर्जा गलियारा (GEC)	दूरदराज क्षेत्रों से मांग केंद्रों तक पारेषण व्यवस्था को मज़बूत करना
पीएम-कुसुम योजना	किसानों के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा पहुंच बढ़ाना
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन	हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देकर उद्योगों को डीकार्बोनाइज करना
PLI योजनाएं	घरेलू सौर और बैटरी निर्माण को समर्थन देकर आत्मनिर्भरता बढ़ाना
नवीकरणीय हाइब्रिड नीति	सह-स्थित सौर और पवन संयंत्रों के माध्यम से ऊर्जा की उपलब्धता में सुधार
समय-आधारित टैरिफ सुधार	मांग के अनुसार मूल्य निर्धारण को प्रोत्सा-हित करना
बैटरी स्टोरेज प्रोत्साहन	भंडारण परियोजनाओं को समर्थन देकर ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करना
ग्रीन ओपन एक्सेस नियम	उद्योगों को सीधे हरित ऊर्जा खरीदने की अनुमति देना

समाधान / आगे की राह :

1. **स्मार्ट ग्रिड में निवेश करने की आवश्यकता :** ऊर्जा मांग को सौर-समृद्ध समय की ओर मोड़ने के लिए स्मार्ट ग्रिड और वास्तविक समय लोड प्रबंधन तंत्र को अपनाएं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

2. **भंडारण समाधान का विस्तार करने की जरूरत :** PLI और VGF जैसे प्रोत्साहनों से बैटरी स्टोरेज व पंप-हाइड्रो परियोजनाओं का स्केल-अप करें।

3. **विकेन्द्रीकृत ऊर्जा विकल्प को अपनाने की जरूरत :** ग्रामीण क्षेत्रों में सौर छतें, मिनी-ग्रिड और सौर पंप जैसी स्थानीय समाधान अपनाकर केंद्रीकृत ग्रिड पर बोझ कम करें।

4. **बिजली दरों में सुधार की जरूरत :** पीक और ऑफ-पीक दरों को अलग करके टैरिफ प्रणाली को अधिक व्यावहारिक बनाएं। हरित ऊर्जा एक्सचेंजों को सुदृढ़ करें।

5. **भूमि और पारेषण अवसंरचना सुधार की आवश्यकता :** अनुमोदन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने हेतु केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल विकसित करें और ट्रांसमिशन योजना को RE लक्ष्यों के अनुरूप बनाएं।

6. **नीतिगत और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता :** निजी निवेश आकर्षित करने के लिए दीर्घकालिक, पारदर्शी बिजली खरीद अनुबंध (PPA) की गारंटी सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष :

- भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है, भारत के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास की गति ने वैश्विक मानकों को पीछे छोड़ा है और निर्धारित राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को समय से पहले छू लिया है। फिर भी, स्थापित क्षमता का होना ही पर्याप्त नहीं है; असली उपलब्धि तब होगी जब इसे सतत, विश्वसनीय और चौबीसों घंटे ऊर्जा आपूर्ति में रूपांतरित किया जा सके।

- भारत को अब नवीकरणीय ऊर्जा के निर्माण से आगे बढ़कर इसके प्रभावी उपयोग और वितरण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके लिए स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ, बाजार आधारित सुधार, और विकेन्द्रीकृत समाधान जैसी रणनीतियाँ निर्णायक होंगी।

- वर्ष 2030 और उसके आगे के दशकों में, यदि भारत इन संरचनात्मक व नीतिगत चुनौतियों का समाधान एक समन्वित दृष्टिकोण से करता है, तो वह न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को संतुलित कर पाएगा, बल्कि वैश्विक मंच पर हरित ऊर्जा नेतृत्व की एक मज़बूत पहचान भी स्थापित कर सकेगा।

स्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत में नवीकरणीय ऊर्जा विकास के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत ने 2030 की समय-सीमा से पहले ही कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है।
2. भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा का योगदान आधे से अधिक है।
3. वर्तमान में सभी भारतीय राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा खपत के लिए टाइम-ऑफ-डे (टीओडी) टैरिफ लागू है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, और 3

उत्तर - (a)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत ने अपनी कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त कर लिया है, फिर भी विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का वास्तविक योगदान 30% से कम क्यों है? चर्चा कीजिए कि इस असंतुलन के प्रमुख कारण क्या हैं और देश में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए किन उपायों को अपनाया जा सकता है?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

पीएम ई - ड्राइव 2024–26 : भारत में इलेक्ट्रिक ट्रकिंग के लिए एक क्रांतिकारी पहल

खबरों में क्यों?

- हाल ही में भारत सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना की शुरुआत की है, जो देश में इलेक्ट्रिक ट्रकों को बढ़ावा देने के लिए पहली समर्पित योजना है। इस योजना के लिए कुल ₹500 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है और इसका उद्देश्य 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रकों की खरीद को प्रोत्साहन देना है। इन कुल फंडों में से 20% राशि दिल्ली के पंजीकृत ट्रकों के लिए आरक्षित की गई है।

- यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी और पूर्व की ईएमपीएस-2024 योजना को इसमें समाहित कर दिया गया है। इसके साथ-साथ यह योजना दोपहिया, तिपहिया और कार्गो ई-वाहनों के लिए श्रेणीबद्ध प्रोत्साहनों की भी व्यवस्था करती है।
- इस योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल ई-वाउचर प्रणाली शुरू की गई है। साथ ही, यह योजना सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पर भी बल देती है ताकि रेंज एंग्जायटी जैसी समस्याओं को दूर किया जा सके।

योजना का मुख्य उद्देश्य :

1. **इलेक्ट्रिक ट्रकों को बढ़ावा देना :** पूरे भारत में मालवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रकों के बड़े पैमाने पर उपयोग को प्रोत्साहित करना।
2. **डीजल पर निर्भरता कम करना :** डीजल आधारित परिवहन पर निर्भरता घटाकर ईंधन आयात और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना।
3. **प्रदूषणकारी वाहनों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देना :** पुराने और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों को हटाने के लिए लाभों को स्क्रैपिंग से जोड़ना।
4. **नेट ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करना :** वर्ष 2070 तक भारत के नेट ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने हेतु स्थायी परिवहन को प्रोत्साहित करना।
5. **शहरी वायु गुणवत्ता सुधार लाना :** खासकर दिल्ली जैसे अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना।
6. **प्रोत्साहनों के माध्यम से वहनीयता सुनिश्चित करना :** प्रोत्साहन के जरिये इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यक्तिगत और फ्लीट ऑपरेटरों के लिए किफायती बनाना।
7. **स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देना :** 'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत घरेलू स्तर पर ईवी, मोटर और बैटरी निर्माण को प्रोत्साहित करना।
8. **ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाना :** सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों और डिजिटल ई-वाउचर जैसे सहायक ढांचे का विकास करना।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ :

वित्तीय प्रावधान और योजना की अवधि :

- इस योजना के अंतर्गत ₹500 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है जिससे 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रोत्साहन मिलेगा। योजना की समयावधि 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक है। इसमें से 20% फंड दिल्ली के ट्रकों के लिए आरक्षित हैं।

पात्रता मानदंड :

- बैटरी की वारंटी 5 वर्ष या 5 लाख किलोमीटर (जो पहले हो)।
- वाहन और मोटर की वारंटी 5 वर्ष या 2.5 लाख किलोमीटर।
- प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पुराने डीजल ट्रकों की स्क्रैपिंग अनिवार्य है।

वाहन-वार सब्सिडी संरचना :

- दोपहिया वाहन : पहले वर्ष ₹5,000 प्रति kWh (अधिकतम ₹10,000), दूसरे वर्ष ₹2,500 प्रति kWh (अधिकतम ₹5,000)।
- तिपहिया वाहन : पहले वर्ष ₹25,000, दूसरे वर्ष ₹12,500।
- एल5 कार्गो तिपहिया वाहन : पहले वर्ष ₹50,000, दूसरे वर्ष ₹25,000।

ई-वाउचर प्रणाली :

- एक व्यक्ति एक आधार पर केवल एक वाहन के लिए पात्र होगा।
- वाहन बिक्री के समय ई-वाउचर स्वतः उत्पन्न होगा।
- ओईएम को सरकार से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए यह वाउचर आवश्यक होगा।

चार्जिंग अवसंरचना :

- सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों (EVPCS) को बढ़ावा देना।
- उच्च ईवी उपयोग वाले शहरों और प्रमुख मालवाहक मार्गों पर विशेष ध्यान देना।
- रेंज की चिंता को कम कर ईवी अपनाने के वातावरण को मजबूत बनाना।

अन्य योजनाओं के साथ एकीकरण :

1. **पूर्ववर्ती योजनाओं का विलय :** यह योजना ईएमपीएस-2024 को समाहित करती है जिससे ईवी प्रोत्साहन के प्रयास एकीकृत हो सकें।

2. **फेम योजना के विस्तार :** यह योजना FAME I और II को पूरक बनाते हुए इलेक्ट्रिक ट्रकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिन्हें पहले इसमें शामिल नहीं किया गया था।

3. **एनईएमएमपी के साथ तालमेल :** यह योजना राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (NEMMP) के तहत जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लक्ष्य में सहयोग करती है।

4. **स्क्रैपिंग नीति को मजबूत बनाना :** पुराने डीजल वाहनों की स्क्रैपिंग को अनिवार्य बनाकर स्क्रैपिंग इकोसिस्टम को सशक्त बनाती है।

5. **'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को समर्थन :** देश में ईवी और उसके कलपुर्जों के निर्माण को प्रोत्साहित करती है।

6. **राज्य स्तरीय ईवी नीतियों से समन्वय :** यह योजना केंद्र और राज्यों के प्रयासों को समन्वित करती है।

7. **वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं में योगदान :** यह योजना पेरिस समझौते जैसे वैश्विक जलवायु लक्ष्यों में भारत की भागीदारी को मजबूती प्रदान करती है।

योजना का महत्व :

1. यह मालवाहक परिवहन के लिए पहली इलेक्ट्रिक वाहन योजना है।
2. यह शहरी प्रदूषण को लक्षित रूप से कम करने का प्रयास करती है।
3. यह डीजल से स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण को बढ़ावा देती है।
4. यह घरेलू विनिर्माण और एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाती है।
5. यह ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करती है।
6. यह उपयोगकर्ताओं के लिए वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ाती है।
7. यह भविष्य की ईवी नीतियों का ब्लूप्रिंट तैयार करती है।

योजना से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ और चिंताएँ :

1. ₹500 करोड़ का बजट भारत के विशाल मालवाहक क्षेत्र के लिए अपर्याप्त हो सकता है।
2. सभी वाहन निर्माता 5 वर्ष की वारंटी देने में सक्षम नहीं हो सकते।
3. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी छोटे शहरों और राजमार्गों पर सीमित है।
4. छोटे ऑपरेटरों के लिए प्रारंभिक लागत अधिक बनी रहती है।
5. डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण ई-वाउचर प्रणाली सभी तक नहीं पहुंच सकती है।
6. बैटरी आपूर्ति और कच्चे माल का आयात-निर्भर होना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
7. जमीनी स्तर पर निगरानी, वितरण और राज्य परिवहन विभागों के साथ समन्वय में कठिनाइयाँ हो सकती हैं।

समाधान / आगे की राह :

1. आने वाले केंद्रीय बजट में वित्तीय सहायता में वृद्धि की जानी चाहिए।
2. चार्जिंग स्टेशनों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए।
3. योजना को लंबी दूरी और अंतर-राज्यीय परिवहन तक विस्तारित करना चाहिए।
4. ई-वाउचर प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल और समावेशी बनाना चाहिए।
5. वाहन स्क्रैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना आवश्यक है।
6. स्थानीय बैटरी उत्पादन और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना चाहिए।
7. ओईएम, डीलरों और परिवहन अधिकारियों को प्रशिक्षित करना चाहिए।

निष्कर्ष :

- पीएम ई-ड्राइव योजना भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्रांति में एक निर्णायक और दूरदर्शी पहल के रूप में उभर रही है, जो विशेष रूप से वाणिज्यिक और मालवाहक वाहनों को विद्युतीकरण की ओर ले जाने पर केंद्रित है।
- यह योजना ई-वाउचर प्रणाली, चरणबद्ध प्रोत्साहन और पूर्ववर्ती योजनाओं के एकीकरण के माध्यम से नीतिगत खामियों, लागत संबंधी बाधाओं और अवसंरचना की कमियों को दूर करने का प्रयास करती है।
- इस योजना में यद्यपि सीमित बजट, बैटरी आपूर्ति श्रृंखला की निर्भरता और चार्जिंग नेटवर्क की अपर्याप्तता जैसे व्यावहारिक अवरोध मौजूद हैं, फिर भी यह योजना भारत को नेट ज़ीरो उत्सर्जन, शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार, और ऊर्जा आत्मनिर्भरता जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक मजबूत आधार और दिशा प्रदान करती है।
- सरकार के स्तर पर यदि नीति-स्तर पर निरंतर समर्थन, निजी निवेश और व्यापक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, तो यह योजना भारत के सतत और स्वच्छ परिवहन भविष्य की आधारशिला बन सकती है।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. यह योजना भारत की पहली समर्पित योजना है जो इलेक्ट्रिक ट्रकों को बढ़ावा देती है।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

2. यह ईएमपीएस-2024 योजना को समाहित करती है।

3. केवल भारत में निर्मित वाहनों को ही इस योजना के अंतर्गत पात्रता दी गई है।

4. योजना के अंतर्गत प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए पुराने डीजल ट्रकों की स्क्रैपिंग अनिवार्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए।

A. 1, 2 और 3 B. 1, 2 और 4

C. 2 और 3 D. 1 और 4

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. पीएम ई-ड्राइव योजना की शुरुआत भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नीति में एक परिवर्तन को दर्शाती है। स्वच्छ और सतत मालवाहक परिवहन को प्राप्त करने के संदर्भ में इसके उद्देश्यों, प्रमुख विशेषताओं, महत्व और चुनौतियों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

इतिहास, कला एवं संस्कृति

भारत में भक्ति आंदोलन और संत कबीर दास

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 11 जून, 2025 को मध्यकालीन संत और भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवि कबीर दास की 648वीं जयंती मनाई।
- इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि - " कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज तथा असत्य के खंडन में व्यतीत हुआ है। मानवता की रक्षा, विश्व बंधुत्व और परस्पर प्रेम के लिए कबीर की वाणी एक बड़ा ही सरल माध्यम है।"
- भारत में कबीर दास की जयंती हिंदू चंद्र कैलेंडर (Hindu Lunar Calendar) के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है।

कबीर दास :

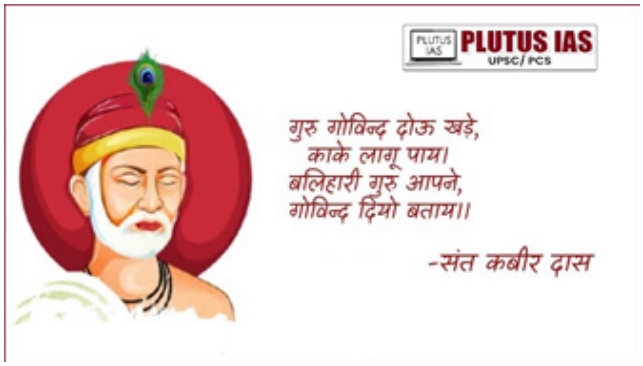

- कबीर दास, 15वीं सदी के मध्यकालीन भारत के रहस्यवादी कवि और संत थे।
- उनका प्रारंभिक जीवन एक मुस्लिम परिवार में बीता, परंतु वे अपने शिक्षक, भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रमुख प्रणेता रामानंद से काफी प्रभावित थे, जो हिन्दू धर्म से संबंधित थे।
- उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था, और उनका पालन-पोषण एक हिंदू बुनकर दंपत्ति ने किया था।
- कबीर दास भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम को जोर दिया।
- उनकी रचनाएँ हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल के निर्गुण शाखा के ज्ञानमार्गी उपशाखा के महानतम काव्यों के रूप में प्रसिद्ध हैं।
- कबीर ने अपने गुरुओं, जैसे कि रामानंद और शेख तकी, से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया और अपने दर्शन को एक अद्वितीय आकार दिया।
- कबीर के दोहे जो उन्होंने अपने छंदों के रूप में लिखे थे, उनकी प्रसिद्धि को दर्शाते हैं।
- उनकी रचनाएँ हिंदी भाषा में लिखी गईं और लोगों को जागरूक करने के लिए वे अपने दोहों का उपयोग करते थे।
- उनकी रचनाओं ने भारतीय साहित्य और हिंदी भाषा के विकास को महत्त्वपूर्ण रूप से समृद्ध किया है।
- उनके द्वारा लिखी गई ब्रजभाषा और अवधी बोलियों में लिखी गई रचनाएँ आज भी प्रसिद्ध हैं।
- कबीर दास के लेखन का भक्ति आंदोलन पर बहुत प्रभाव पड़ा तथा इसमें कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक और सखी ग्रंथ जैसे ग्रंथ शामिल हैं।
- उनके छंद सिख धर्म के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में पाए जाते हैं।
- उनके प्रमुख रचनात्मक कार्यों का संकलन पाँचवें सिख गुरु, गुरु अर्जन देव द्वारा किया गया था।
- उन्होंने अपने दो-पंक्ति के दोहों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की, जिन्हें 'कबीर के दोहे' के नाम से जाना जाता है।

- भाषा : कबीर की कृतियाँ हिंदी भाषा में लिखी गईं, जिन्हें समझना आसान था। लोगों को जागरूक करने के लिए वह अपने लेख दोहों के रूप में लिखते थे।

भारत में भक्ति आंदोलन :

- भारत के संपूर्ण सांस्कृतिक इतिहास में भक्ति आंदोलन मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्यिक घटना या आन्दोलन था, जो मुख्य रूप से 6वीं और 17वीं शताब्दी के बीच भारत में उपजी और अत्यंत तेजी तत्कालीन भारतीय समाज में प्रसारित हुई।
- इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत भगवान या देवता के प्रति उत्कट भक्ति को प्रचार - प्रसार करना था, जो मोक्ष और दिव्य प्राप्ति के साधन के रूप में प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव, प्रेम और भक्ति पर जोर देता था।
- भारत में भक्ति आंदोलन ने जाति, पंथ और धर्म जैसे अनेक सामाजिक असमानताओं को दूर कर लिया था, जिससे पूरे भारत में धार्मिक प्रथाओं, सामाजिक संबंधों, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और दार्शनिक विचारों में गहरा परिवर्तन आया।
- इस आंदोलन की शुरुआत भारत के दक्षिण राज्यों संभवत: तमिल क्षेत्र में हुई, जहां अलवार (विष्णु के भक्त) और नयनार (शिव के भक्त) तथा वैष्णव और शैव कवियों ने कविताओं के माध्यम से भक्ति का प्रचार-प्रसार किया।
- अलवार और नयनार अपने देवताओं की स्तुति में तमिल भाषा में भजन गाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे।
- उनकी रचनाओं में भगवान की महिमा और प्रेम की भावना व्यक्त होती थी।
- भक्ति आंदोलन के द्वारा भक्ति योग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति के तरीके और मार्ग के रूप में स्थापित किया गया।
- इस आंदोलन ने भारत के मध्यकाल के समाज में व्याप्त धार्मिक आडम्बरों, कुरीतियों आदि के स्थान पर एक तार्किक धार्मिक विचारों को एक नई दिशा दी और सांप्रदायिक कट्टरता, आपसी वैमनस्यता और जातिगत भेदभाव की जगह सामाजिक एकता को प्रसारित और समृद्ध किया।
- भक्ति आंदोलन के दौरान भारत में एक तरफ जहाँ सगुण भक्ति परंपराएँ शिव, विष्णु और उनके अवतारों या देवी के विभिन्न रूपों जैसे विशिष्ट देवताओं की पूजा पर केंद्रित थीं, जिन्हें प्रायः मानवशास्त्रीय रूपों में अवधारणाबद्ध किया जाता था। वहीं दूसरी ओर, निर्गुण भक्ति भगवान के एक अमूर्त रूप की पूजा पर आधारित थी।

भक्ति आंदोलन के समय भारत की सामाजिक व्यवस्था :

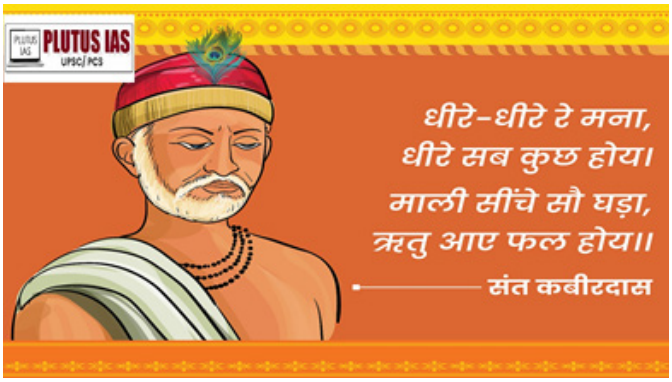

- भक्ति आंदोलन भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू, मुसलमान और सिख समुदायों के बीच एक महत्वपूर्ण आंदोलन था।
- इस काल में सामाजिक-धार्मिक सुधारकों ने भगवान की भक्ति को प्रमुख आधार बनाया।
- भारत में इस आंदोलन में उच्च और निम्न जातियों से आए कवियों ने साहित्य को एक महत्वपूर्ण साधन बनाया, जिसने लोकप्रिय कथाओं को मजबूती से स्थापित किया।
- इन संतों ने समाज में सांप्रदायिक कट्टरता और जातिगत भेदभाव की आलोचना की और वास्तविक मानवीय आकांक्षाओं के क्षेत्र में धर्म की प्रासंगिकता का दावा किया।
- भक्ति आंदोलन के समस्त कवि भारत में सभी लोगों के लिए ईश्वर की भक्ति को ही सच्चे अर्थों में संसार के मायामोह से मुक्ति प्राप्त करने का साधन मानते थे।
- भक्ति आंदोलन के कवियों की भक्ति स्वार्थरहित और अनन्य श्रद्धा पर आधारित थी।
- इस आंदोलन ने तत्कालीन भारतीय समाज की विभाजक और विध्वंसक तत्वों के खिलाफ सार्थक भूमिका अदा की और कर्म योग, ज्ञान योग, और भक्ति योग के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को स्थापित किया।
- भक्तिकालीन कवियों ने ईश्वर के प्रति समर्पण को महत्व दिया और मूर्ति पूजा को उन्मूलन करने का प्रयास किया।

भक्ति आंदोलन में महिलाओं की भूमिका :

- भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाया।
- यह आंदोलन महिलाओं को अपनी आध्यात्मिकता और भक्ति को व्यक्त करने का माध्यम प्रदान करता था, जिससे उन्हें घरेलू भूमिकाओं से बाहर निकलने में मदद मिली।
- महिलाएं धार्मिक सभाओं में सक्रिय रूप से शामिल होती थीं, भक्तिपूर्ण गीत गाती थीं और आध्यात्मिक चर्चाओं में भाग लेती थीं।
- इस आंदोलन में महिला संतों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा दिया और जाति भेद को कम किया।
- इस आंदोलन ने महिलाओं को आध्यात्मिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की और उन्हें समाज में अधिक समानता दिलाई।

अंडाल :

- अंडाल एक महिला अलवार थीं, जिन्होंने खुद को विष्णु की प्रेमिका के रूप में देखा। उनकी रचनाएँ और उमें निहित भक्ति का भाव आज भी प्रमुख हैं।

कराईकल अम्मैयार :

- कराईकल अम्मैयार शिव की भक्त थीं। उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया।
- उनकी रचनाओं को नयनार परंपरा के भीतर संरक्षित किया गया है।

भक्ति आंदोलन के महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व :

कन्नड़ क्षेत्र :

- कन्नड़ क्षेत्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत 12वीं शताब्दी में बसवन्ना (1105-68) द्वारा की गई थी।

महाराष्ट्र :

- महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन 13वीं सदी के अंत में शुरू हुआ। इसके समर्थकों को वारकरी कहा जाता था। इसके सबसे प्रमुख नामों में ज्ञानदेव (1275-96), नामदेव (1270-50), और तुकाराम (1608-50) शामिल हैं।

असम :

- श्रीमंत शंकरदेव एक वैष्णव संत थे जिनका जन्म 1449 ईस्वी में असम के नगांव जिले में हुआ था। उन्होंने नव-वैष्णव आंदोलन को शुरू किया था।

बंगाल :

- चैतन्य बंगाल के एक प्रसिद्ध संत और सुधारक थे, जिन्होंने कृष्ण पंथ को लोकप्रिय बनाया।

उत्तरी भारत :

- इस क्षेत्र में 13वीं से 17वीं शताब्दी तक कई कवि भक्ति आंदोलन से जुड़े रहे।
- कबीर, रविदास, और गुरु नानक ने निराकार भगवान (निर्गुण भक्ति) की महत्ता बताई।
- राजस्थान की मीराबाई (1498-1546) ने कृष्ण की स्तुति में भक्ति छंदों की रचना की और उनका गुणगान किया।
- सूरदास, नरसिंह मेहता, और तुलसीदास ने भी भक्ति साहित्य और भक्ति आंदोलन में अमूल्य योगदान दिया तथा इसकी गौरवशाली विरासत को बढ़ाया।

इस प्रकार भक्ति आंदोलन ने मध्यकालीन भरतीय समाज में जातिगत भेदभाव, धार्मिक आडम्बरों और कट्टरताओं को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत में भक्ति आंदोलन और कबीर दास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. कबीर दास भक्ति आंदोलन के भक्तिकाल के निर्गुण शाखा के ज्ञानमार्गी उपशाखा के व्यक्ति थे।
2. कबीर दास की रचनाओं ने भारतीय साहित्य और हिंदी भाषा के विकास को महत्त्वपूर्ण रूप से समृद्ध किया है।
3. भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू होकर उत्तर भारत में पहुंची थी।
4. भक्ति आंदोलन के कारण महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं से बाहर निकलने में मदद मिली।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3 B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं। D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - D

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत में भक्ति आंदोलन के उद्भव के प्रमुख कारणों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भक्ति आंदोलन ने किस प्रकार भारतीय समाज में सांप्रदायिक कट्टरता, धार्मिक आडम्बर और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और बाल गंगाधर तिलक

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में, 23 जुलाई 2025 को, भारत ने बाल गंगाधर तिलक की 169वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद् के रूप में लोकमान्य की अद्वितीय विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
- लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान :
- लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था।
- पेशे से एक वकील होने के बावजूद, उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता के रूप में जाना जाता है। उनके विचारों और कार्यों ने उन्हें भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है।
- लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान " स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा " जैसे क्रांतिकारी नारे दिए, जो भारतीयों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करते थे।
- उनका निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ।

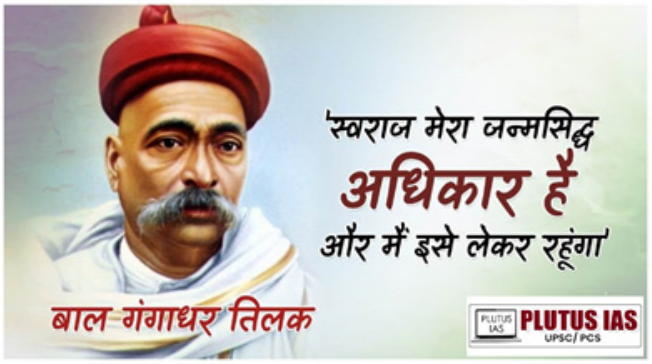

- बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के प्रारंभिक और प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिनका योगदान न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष की दिशा में था, बल्कि उन्होंने तत्कालीन भारत में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

'लाल-बाल-पाल ' की तिकड़ी और ' गरम दल ' का गठन :

- लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर बाल गंगाधर तिलक ने ' लाल-बाल-पाल ' की तिकड़ी का गठन किया।
- यह तिकड़ी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ' गरम दल ' या ' उग्रपंथी दल ' के रूप में जानी गई। गरम दल ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कठोर संघर्ष की आवश्यकता पर जोर दिया और भारतीय जनमानस को आत्मनिर्भरता और स्वाधीनता की दिशा में प्रेरित किया।
- उनकी विचारधारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अधिक सशक्त और आक्रामक दृष्टिकोण की समर्थक थी, जो उस समय की कांग्रेस की नरमपंथी विचारधारा से अलग और भिन्न थी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश :

- सन 1890 में तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) में शामिल होकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी।
- उनकी नेतृत्व क्षमता और विचारशीलता ने कांग्रेस की नीतियों को एक नई दिशा प्रदान की।
- उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की, जिसके तहत उन्होंने भारतीयों को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी वस्त्रों और उत्पादों को अपनाने की अपील की।
- यह आंदोलन भारत में आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ था।

होम रूल लीग की स्थापना :

- अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगाम में अखिल भारतीय होम रूल लीग (All India Home Rule League) की स्थापना की।

- यह लीग भारत के स्वशासन के लिए एक प्रमुख संस्था थी। इसका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र (बॉम्बे को छोड़कर), मध्य प्रांत, कर्नाटक और बरार में था।
- होम रूल लीग के माध्यम से तिलक ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन को संगठित किया और भारतीयों को स्वशासन के महत्व और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

हिंदू-मुस्लिम एकता :

- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास किए।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर लखनऊ पैक्ट (1916) पर हस्ताक्षर किए।
- यह पैक्ट दोनों समुदायों के बीच समझौते और सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जो आगे चलकर भारतीय राजनीति में एकता और सामंजस्य को बढ़ावा देने में सहायक साबित हुआ था।

पत्रकारिता और साहित्य :

- तिलक ने मराठी भाषा में 'केसरी' और अंग्रेजी भाषा में 'मराठा' नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया।
- ये पत्र - पत्रिकाएँ स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को फैलाने और जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम थीं।
- इसके अतिरिक्त, तिलक ने ' गीता रहस्य ' और ' द आर्कटिक होम इन द वेदाज ' जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन किया। 'गीता रहस्य' में उन्होंने भगवद गीता की गहराई से व्याख्या की और उसे भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता के संदर्भ में प्रस्तुत किया।

सामाजिक योगदान :

- लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे, जिसे 1884 में स्थापित किया गया था।
- इस सोसाइटी की स्थापना में गोपाल गणेश अगरकर और अन्य सहयोगी भी शामिल थे।
- इस सोसाइटी का उद्देश्य भारतीय समाज में शिक्षा का प्रसार करना और सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहित करना था।
- लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार को लोकप्रिय बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- उन्होंने इस त्योहार को एक सामूहिक और सांस्कृतिक आयोजन के रूप में स्थापित किया, जिससे यह त्योहार केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में भी स्थापित हुआ।
- तिलक ने सम्राट छत्रपति शिवाजी की जयंती पर शिव जयंती मनाने का प्रस्ताव पेश किया। इस पहल ने शिवाजी के ऐतिहासिक महत्व को पुनर्जीवित किया और उनकी विरासत को नई ऊर्जा दी।
- तिलक ने हिंदू धर्म के अनुयायियों को अत्याचार के खिलाफ खड़ा होने और अपने धर्मग्रंथों का उपयोग करने पर जोर दिया।
- इस दृष्टिकोण ने धार्मिक आत्म-रक्षा की भावना को प्रोत्साहित किया और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

वर्तमान समय में तिलक के विचारों की प्रासंगिकता :

1. **स्वदेशी उत्पादों और स्वदेशी आंदोलन :** तिलक ने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित किया। उन्होंने भारतीय उद्योगों और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई अभियान चलाए। आज के भारत में, जहाँ 'आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना को प्रमुखता दी जा रही है, तिलक के विचारों की प्रासंगिकता अत्यधिक है। उनकी विचारधारा हमें प्रेरित कर सकती है कि हम अपनी स्वदेशी क्षमताओं को पहचानें और उनका पूर्ण उपयोग करें। इस प्रकार, आर्थिक राष्ट्रवाद के पुनरुद्धार में तिलक की दृष्टि को शामिल किया जा सकता है, जिससे भारत न केवल आर्थिक रूप से सशक्त होगा बल्कि देशवासियों की आत्म-निर्भरता भी बढ़ेगा।
2. **मातृभाषा का महत्व :** तिलक ने कांग्रेस की स्थानीय बैठकों में मातृभाषा के उपयोग की वकालत की थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मातृभाषा के माध्यम से आम लोगों तक सन्देश और विचार पहुँचाना अधिक प्रभावी होगा।
3. हाल ही में भारत सरकार ने **' नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति '** (2020) के माध्यम से संस्कृत और स्थानीय और मातृ भाषाओं को अपनाने

पर जोर दिया है। इस नीति के तहत, भारतीय भाषाओं को शिक्षा और प्रशासन में अधिक महत्व दिया जा रहा है। तिलक की यह दृष्टि कि मातृभाषा का प्रयोग लोगों के साथ सच्चा संवाद स्थापित करने के लिए आवश्यक है, आज भी प्रासंगिक है और वर्तमान में भारत सरकार द्वारा ' नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ' (2020) नीति के माध्यम से इसे साकार किया जा रहा है।

4. **जातिवाद और अस्पृश्यता के खिलाफ दृष्टिकोण :** तिलक जातिवाद और अस्पृश्यता के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने समाज में जातियों और संप्रदायों के बीच विभाजन को समाप्त करने के लिए व्यापक आंदोलन चलाया। उनके समय में समाज में जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई ने महत्वपूर्ण सामाजिक बदलावों की नींव रखी। आज भी भारतीय समाज में जातिवाद और सामाजिक असमानताएँ एक चुनौती बनी हुई हैं। तिलक के दृष्टिकोण की इस संदर्भ में प्रासंगिकता है कि हमें समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करने और समानता की दिशा में काम करना चाहिए। उनके विचार हमें यह याद दिलाते हैं कि सामाजिक समरसता और एकता के लिए लगातार प्रयास करना अत्यंत आवश्यक हैं।

निष्कर्ष :

- लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के भारतीय समाज और राजनीति में कई महत्वपूर्ण विचार विशेष रूप से स्वदेशी आंदोलन, मातृभाषा के महत्व और जातिवाद के खिलाफ उनके दृष्टिकोण आज भी हमारे समाज को मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।
- लोकमान्य बालगंगाधर तिलक का जीवन और कार्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनके दृढ़ समर्पण और राष्ट्रीयता की गहरी भावना को दर्शाता है। इस प्रकार, तिलक के विचार आज भी भारतीय समाज और राजनीति में अत्यधिक प्रासंगिक हैं। उनकी दृष्टि हमें यह सिखाती है कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाना, मातृभाषा का सम्मान करना और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष करना, भारतीय समाज की प्रगति और एकता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन विचारों को अपनाकर हम एक समृद्ध और सशक्त भारत की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

स्रोत - पी.आई.बी एवं द इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें :

	अखबार	संबंधित व्यक्तित्व	क्षेत्र
1	केसरी	बालगंगाधर तिलक	महाराष्ट्र
2	कालांतर	लाला लाजपत राय	पंजाब
3	अमृत बाज़ार पत्रिका	शिशिर कुमार घोष	बंगाल
4	स्वराज	महात्मा गाँधी	गुजरात

उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3

C. केवल 3 और 4 D. केवल 1 और 3

उत्तर - D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. " भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर चर्चा करना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के उल्लेख के बिना अधूरी है।" क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र - 1 (2025 - 2026) डॉ. अखिलेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों का सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उत्तर की विस्तृत व्याख्या।

(टेस्ट संख्या - 1 प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। कला एवं संस्कृति, वास्तुकला साहित्य, समसामयिक घटनाक्रम।)

Q1. सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की पहली शहरी सभ्यता थी।
2. सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले लिपि को दाएँ से बाएँ लिखने वाली सभ्यता थी।
3. सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्तिकला के लिए लोहे के बारे में जानते थे।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक B. सिर्फ दो

C. तीनों D. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: B

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** सिंधु घाटी सभ्यता (आईवीसी) को भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्रारंभिक ज्ञात शहरी सभ्यता के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। यह लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक फला-फूला, इसकी परिपक्व अवधि 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक रही। मोहनजो-दारो और हड़प्पा जैसे सुनियोजित शहर, अपनी परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था, अन्न भंडार और मानकीकृत ईंट निर्माण के साथ, उनकी उन्नत शहरी योजना को प्रमाणित करते हैं। यह सभ्यता इस क्षेत्र में अन्य ज्ञात शहरी बस्तियों से भी पहले की है, जो इसे उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु बनाती है। उनके शहरों की संगठित प्रकृति और उनकी आबादी का पैमाना इस कथन को एक पुष्ट तथ्य बनाता है। शहरी नियोजन और विशाल जनसंख्या घनत्व इसे एक प्रमुख विशेषता बनाते हैं।
- **कथन 2 सही है।** सिंधु लिपि, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, के बारे में माना जाता है कि इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। हालांकि लिपि का सटीक अर्थ अज्ञात है, लेकिन मुहरों और मिट्टी के बर्तनों सहित विभिन्न कलाकृतियों में लेखन की दिशा देखी गई है। मुहरों के किनारों पर अक्षरों के ओवरलैपिंग के माध्यम से लिपि की दिशा देखी जाती है। यह दिशात्मक विशेषता सिंधु लिपि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। लिपि के अध्ययन में लेखन की दिशा एक महत्वपूर्ण घटक है।
- **कथन 3 गलत है।** सिंधु घाटी सभ्यता ने अपने औजारों और मूर्तियों के लिए मुख्य रूप से कांस्य, तांबा और टेराकोटा का इस्तेमाल किया। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह युग बहुत बाद में, लगभग 1200 ईसा पूर्व में, चित्रित ग्रे वेयर संस्कृति के साथ शुरू हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य ढलाई में कुशल थे, जैसा कि प्रसिद्ध "डांसिंग गर्ल" मूर्ति से पता चलता है, लेकिन उनके पास लौह धातु विज्ञान नहीं था। पुरातात्विक अभिलेखों में लौह उपकरणों की कमी इसकी पुष्टि करती है। कांस्य युग लौह युग से पहले आया था।

Q2. भारत के प्राचीन इतिहास में, गुआम, रज्जू और सेतु निम्नलिखित में से किस काल के दौरान करों के प्रकार थे?

A. मौर्य साम्राज्य B. सातवाहन साम्राज्य

C. वाकाटक साम्राज्य D. होयसल साम्राज्य

उत्तर: A

व्याख्या:

प्राचीन भारतीय करों और उनके राज्यों की विशेषताओं सहित सूची।

कर	राजवंश/काल	गुण
बाली	वैदिक काल	राजा को स्वैच्छिक उपहार
अयुधीय	मौर्य राजवंश	आपूर्ति कर
भागा	मौर्य राजवंश	कृषि उत्पादन पर कर (कुल उत्पादन का 6%)
द्वारबाहिरिकडेय	मौर्य राजवंश	चुंगी और सड़क कर
गुआम	मौर्य राजवंश	सैन्य अड्डों पर कर
मनप्याजी	मौर्य राजवंश	शाही वस्तुओं की बिक्री पर कर
निष्क्रमय कर	मौर्य राजवंश	निर्यात कर
परिध	मौर्य राजवंश	एकाधिकार कर
पश्मेव	मौर्य राजवंश	उपकर
पिंडकर	मौर्य राजवंश	ग्रामीणों द्वारा देय उत्पाद कर

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

प्रतिकर	मौर्य राजवंश	उत्पाद कर
प्रणय कर	मौर्य राजवंश	आपातकालीन कर
सेनाभक्त	मौर्य राजवंश	सैन्य अभियानों के दौरान एकत्र किया गया कर
औपायनिक	मौर्य राजवंश	विशेष अवसरों पर राजा को दिया जाने वाला उपहार
कोष्ठेय	मौर्य राजवंश	सरकारी जलाशयों से कर एकत्र किया जाता है
परिहीनक	मौर्य राजवंश	सरकारी भूमि पर पशुओं से होने वाली हानि पर कर लगाया जाता है
द्रुवाधिकार	मौर्य राजवंश	भूमि कर संग्राहक
रज्जू	मौर्य राजवंश	भूमि माप के समय लिया जाने वाला कर
सेतु	मौर्य राजवंश	फल कर
हिरण्य	मौर्य राजवंश	कर नकद रूप में देय
धान्या	मौर्य राजवंश	कुछ विशेष फसलों पर कर
उद्रंग	मौर्य राजवंश	स्थायी भूमि निवासियों से कर वसूला जाता है
उपरि	मौर्य राजवंश	अस्थायी भूमि निवासियों से कर वसूला जाता है
उदका भाग	मौर्य राजवंश	सिंचाई कर
कुटक	मौर्य राजवंश	गृहकर
भाग	गुप्त वंश	कृषि उत्पादन पर कर (कुल उत्पादन का 1/6)
भोग	गुप्त वंश	ग्रामीणों द्वारा समय-समय पर देय कर
अधियांग	गुप्त वंश	पुलिस चौकियों के रखरखाव के लिए कर
हिरण्य	गुप्त वंश	कर का भुगतान सोने के सिक्कों में किया जाता है
हलिवर्करा	गुप्त वंश	हल जोतने वाले किसानों से कर वसूला जाता था
शुलका	गुप्त वंश	व्यापारियों द्वारा बंदरगाहों पर लाए गए माल पर सीमा शुल्क
पदिकाबलकुली	चोल राजवंश	सुरक्षा कर
पेशावर	चोल राजवंश	विशेष व्यवसायों पर लगाया जाने वाला कर
पथकर	चोल राजवंश	अंतरराज्यीय कर
मरमञ्जादि	चोल राजवंश	पेड़ों पर कर
कदमई	चोल राजवंश	सुपारी की खेती पर कर
मनिराय	चोल राजवंश	हाउस टैक्स
किडक्कशु	चोल राजवंश	पशुओं पर कर
पडिकावल	चोल राजवंश	ग्राम सुरक्षा कर
वशिलप्रमम्	चोल राजवंश	द्वारका कर
मगनमाई	चोल राजवंश	स्वर्णकार, लोहारों और कुम्हारों पर कर
क्लिष्ट या अप-क्लिष्ट	चोल राजवंश	क्रय-विक्रय कर

उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

A. केवल एक B. सिर्फ दो

C. तीनों D. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: B

व्याख्या:

- **युग्म 1 सही सुमेलित है।** तक्षशिला, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित, भारत, मध्य एशिया और फ़ारसी साम्राज्य को जोड़ने वाले प्राचीन व्यापार मार्गों पर एक महत्वपूर्ण शहर था। यह मौर्य युग से काफी पहले ही शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ था, लेकिन इसकी प्रमुखता मौर्य शासन के तहत भी जारी रही। शहर ने दूर-दराज के देशों से विद्वानों को आकर्षित किया, जो चिकित्सा, दर्शन, कानून और कला सहित विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम पेश करते थे। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार, चाणक्य जैसी प्रसिद्ध हस्तियों ने वहां पढ़ाया या अध्ययन किया था। तक्षशिला की रणनीतिक स्थिति और विविध बौद्धिक वातावरण ने एक अग्रणी शैक्षिक केंद्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा में योगदान दिया। तक्षशिला के खंडहर एक परिष्कृत शहरी लेआउट को दर्शाते हैं, जो शहर के महत्व को दर्शाता है। यह एक ऐसा स्थान था जहां सांस्कृतिक आदान-प्रदान और बौद्धिक विकास शहर का प्रमुख घटक था। मौर्य साम्राज्य, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को एकीकृत किया, ने तक्षशिला के बौद्धिक योगदान का समर्थन किया और उससे लाभ उठाया।

- **युग्म 2 गलत सुमेलित है।** वैशाली, भारत के वर्तमान बिहार का एक प्राचीन शहर, गौतम बुद्ध के समय में एक महत्वपूर्ण गणराज्य था। यह वज्जि संघ की राजधानी थी, जो अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए जाना जाता था। बुद्ध ने कई बार वैशाली का दौरा किया, कई उपदेश दिए और एक मजबूत मठवासी समुदाय की स्थापना की। वैशाली में ही उन्होंने महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति दी, उनकी पालक माँ महापजापति गौतमी पहली महिला भिक्षु बनीं। हालाँकि, उनका अंतिम उपदेश और परिनिर्वाण (अंतिम प्रस्थान) वैशाली में नहीं, बल्कि कुशीनगर में हुआ था। हालाँकि, वैशाली का उनके जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। बुद्ध के परिनिर्वाण के एक सदी बाद वैशाली में दूसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। शहर का समृद्ध इतिहास और बुद्ध के साथ जुड़ाव इसे बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाता है। वैशाली गणराज्य को एक बहुत शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था।

- **युग्म 3 सही सुमेलित है।** भारत के मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर बसा उज्जैन गुप्त काल के दौरान एक प्रमुख शहर था, जो भारतीय संस्कृति और शिक्षा का स्वर्ण युग था। यह एक प्रमुख राजनीतिक और वाणिज्यिक केंद्र था, जो अवंती साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। माना जाता है कि प्रसिद्ध कवि और नाटककार कालिदास इस युग के दौरान उज्जैन में रहते थे और काम करते थे। उनकी रचनाएँ, जैसे "मेघदूत" (बादल दूत) और "अभिज्ञान शाकुंतलम" (शकुंतला की पहचान), शहर की सांस्कृतिक जीवंतता और बौद्धिक परिष्कार को दर्शाती हैं। उज्जैन खगोलीय अध्ययन का भी केंद्र था, और कालिदास के लेखन से खगोलीय अवधारणाओं से उनकी परिचितता का पता चलता है। कालिदास और अन्य विद्वानों के साथ शहर के जुड़ाव ने साहित्यिक और बौद्धिक गतिविधि के केंद्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा में योगदान दिया। गुप्त साम्राज्य, जिसने कला और विज्ञान के लिए एक समृद्ध वातावरण को बढ़ावा दिया, ने उज्जैन के विकास का समर्थन किया। यह शहर भारत में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र बना हुआ है।

Q4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मिताक्षरा विधि विद्यालय उत्तराधिकार संपत्ति अधिकारों से संबंधित है।
2. बौधायन धर्मसूत्र सपिंडों के बीच विवाह पर प्रतिबंध लगाता है।
3. दयाभाग विधि विद्यालय जाति व्यवस्था से संबंधित है।
4. याज्ञवल्क्य स्मृति बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक B. सिर्फ दो

C. केवल तीन D. चारों

उत्तर: B

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** मिताक्षरा हिंदू कानून का एक महत्वपूर्ण स्कूल है, जो मुख्य रूप से विरासत और संपत्ति के अधिकारों से संबंधित है। यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है और भारत के अधिकांश हिस्सों में प्रचलित है। मिताक्षरा की प्रमुख विशेषता यह है कि पुत्र को जन्म से ही पैतृक संपत्ति का अधिकार मिल जाता है। इस विचारधारा का भारत में संपत्ति कानूनों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह परिभाषित करता है कि पैतृक संपत्ति को परिवार के सदस्यों के बीच कैसे विभाजित किया जाता है। मिताक्षरा प्रणाली पारंपरिक हिंदू कानून का एक मुख्य घटक है।

- **कथन 2 सही है।** बौधायन धर्मसूत्र, एक प्राचीन हिंदू कानूनी पाठ, सपिंडों (जो एक निश्चित संख्या में पीढ़ियों के भीतर एक ही पूर्वज साझा करते हैं) के बीच विवाह को संबोधित और प्रतिबंधित करता है। यह निषेध इस विश्वास पर आधारित है कि ऐसे विवाह आनुवंशिक अशुद्धता को जन्म देंगे। इन नियमों का उद्देश्य वंश की पवित्रता को बनाए रखना और घनिष्ठ सजातीय संबंधों को रोकना था। बौधायन पाठ प्रारंभिक हिंदू सामाजिक और कानूनी मानदंडों को समझने का एक प्रमुख स्रोत है। सपिंड विवाह पर प्रतिबंध कई धर्मसूत्रों में एक सुसंगत विशेषता है। यह ग्रंथ विवाह संबंधी प्राचीन नियमों को दर्शाता है।

- **कथन 3 गलत है।** दयाभागा हिंदू कानून का एक और प्रमुख स्कूल है, लेकिन यह मुख्य रूप से विरासत और संपत्ति के अधिकारों से संबंधित है, खासकर बंगाल और असम में। मिताक्षरा के विपरीत, दयाभागा का मानना है कि पुत्र को जन्म से पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता है। इसके बजाय, विरासत पिता की मृत्यु के बाद होती है। दयाभागा स्कूल विशेष रूप से जाति व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। जबकि जाति व्यवस्था सामाजिक संरचना का एक हिस्सा थी, दयाभागा प्रणाली विरासत के समय और विधि से अधिक संबंधित है। दयाभागा प्रणाली संपत्ति के निपटान के लिए पिता के अधिकारों पर केंद्रित है।

- **कथन 4 गलत है।** याज्ञवल्क्य स्मृति हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, विशेष रूप से धर्मशास्त्र परंपरा के भीतर, जो कानून, नैतिकता और धार्मिक कर्तव्यों से संबंधित है। यह धर्म पर प्रमुख ग्रंथों में से एक है और प्राचीन भारतीय कानून का एक आधारभूत ग्रंथ है। इसके मुख्य विषय धर्म, योग और दान के इर्द-गिर्द घूमते हैं। यह ग्रंथ धर्म की बहुलता पर जोर देता है, जिसमें कर्तव्य, दायित्व और नैतिक आचरण शामिल हैं। यह धर्म को तीन भागों में वर्गीकृत करता है: आचार (उचित आचरण), व्यवहार (कानूनी प्रक्रिया), और प्रायश्चित (तपस्या)। इसके अतिरिक्त, यह स्वीकार करता है कि सही इरादे से इच्छाओं को पूरा करना भी धर्म का एक हिस्सा है। याज्ञवल्क्य स्मृति योग और आत्म-बोध (आत्म-दर्शन) को धर्म के सर्वोच्च रूपों के रूप में उभारती है, जिसमें प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा सहित योग के आठ घटकों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ का एक और महत्वपूर्ण पहलू उपहार देने (दान) पर जोर देना है, जिसे धर्म के ढांचे के भीतर एक आवश्यक अभ्यास माना जाता है। कुल मिलाकर, याज्ञवल्क्य स्मृति प्राचीन

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

हिंदू समाज में नैतिक आचरण, कानूनी सिद्धांतों और आध्यात्मिक अनुशासन के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करती है।

Q5. निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ थीं/थीं?

1. धातु मुद्रा का व्यापक उपयोग
2. कमजोर कराधान प्रणाली
3. अधिशेष खाद्य उत्पादन
4. मुख्यतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था / मुख्य रूप से पशुपालन अर्थव्यवस्था
5. यूरोपीय लोगों के साथ व्यापार

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1, 2, 3, और 5 B. केवल 1 और 4

C. केवल 2, 3, और 5 D. केवल 2 और 4

उत्तर: D

व्याख्या:

- **धातु मुद्रा का उपयोग:** ऋग्वैदिक ग्रंथों में निष्क, सुवर्ण और पाद जैसे शब्द पाए जाते हैं, जो धातु की वस्तुओं की उपस्थिति का सुझाव देते हैं, वे आधुनिक अर्थों में मानकीकृत, व्यापक रूप से प्रचलित सिक्कों के रूप में कार्य नहीं करते थे। इन वस्तुओं का उपयोग आभूषण या मूल्यवान वस्तुओं के रूप में और कभी-कभी विशिष्ट लेन-देन में किया जाता था। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वस्तु विनिमय पर आधारित थी, जिसमें मवेशी विनिमय का प्राथमिक माध्यम थे। इन धातु की वस्तुओं का उपयोग सीमित था और वे औपचारिक मौद्रिक प्रणाली का गठन नहीं करते थे। एक संरचित टकसाल प्रणाली की कमी इसकी पुष्टि करती है। इन वस्तुओं को मुद्रा के बजाय अधिक मूल्यवान वस्तुएँ माना जाता था। इस प्रकार, यह वैदिक अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी।

- **कमजोर कराधान प्रणाली:** ऋग्वैदिक काल में औपचारिक, केंद्रीकृत कराधान प्रणाली का अभाव था। योगदान अनिवार्य करों के बजाय स्वैच्छिक श्रद्धांजलि थी। जनजातीय संरचना और एक मजबूत राज्य तंत्र की अनुपस्थिति ने व्यवस्थित कर संग्रह को रोक दिया। अर्थव्यवस्था मुख्यतः परिवार और जनजातीय इकाइयों पर आधारित थी। "बाली" श्रद्धांजलि उपहार की तरह थी। अत: यह वैदिक अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी।

- **खाद्य अधिशेष उत्पादन:** जबकि कृषि का अभ्यास किया जाता था, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्यतः देहाती थी। खाद्य उत्पादन मुख्य रूप से निर्वाह के लिए था, बड़े पैमाने पर अधिशेष के लिए नहीं। पशुपालन पर फोकस था. हालाँकि, नदी घाटियों के किनारे कुछ कृषि गतिविधियाँ थीं, मुख्य रूप से जौ की खेती। कृषि उत्पादन उपलब्ध प्रौद्योगिकी और कुछ ऋग्वैदिक जनजातियों की अर्ध-खानाबदोश जीवन शैली के कारण सीमित था। मुख्य भोजन स्रोत मवेशी से संबंधित था। इस प्रकार, यह वैदिक अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी।

- **मुख्य रूप से पशुपालन अर्थव्यवस्था :** ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में मवेशी पालन केंद्रीय था, जिसमें मवेशी धन और विनिमय का प्राथमिक साधन थे। ऋग्वैदिक लोग अर्ध-खानाबदोश थे, जो अपने झुंड के साथ घूमते थे। ऋग्वेद में कई भजनों में मवेशियों के महत्व पर जोर दिया गया है। कृषि गौण थी। गाय एक पवित्र प्रतीक थी। इसलिए, यह वैदिक अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी।

- **यूरोपीय लोगों के साथ व्यापार :** ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में व्यापार होता था, लेकिन यह मुख्य रूप से आंतरिक या पड़ोसी क्षेत्रों के साथ था। सिंधु घाटी सभ्यता (जो ऋग्वैदिक काल से पहले की है, लेकिन इसके शुरुआती चरणों के साथ ओवरलैप होती है) और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार के पुरातात्विक साक्ष्य हैं। हालाँकि, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद, व्यापार पैटर्न बदल गए। आंतरिक व्यापार में विभिन्न जनजातियों और बस्तियों के बीच वस्तुओं का आदान-प्रदान शामिल था। मवेशियों, वस्त्रों, मिट्टी के बर्तनों और धातु की वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। परिवहन और व्यापार के लिए नदी मार्ग महत्वपूर्ण थे। यूरोप के साथ संगठित लंबी दूरी के व्यापार की अवधारणा अस्तित्व में नहीं थी। वैदिक लोग अपने आस-पास के इलाकों और भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते थे। इस प्रकार, यह वैदिक अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी।

Q6. निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें:

क्रम संख्या	साहित्य	साहित्य का मुख्य विषय	लेखक
1	बृहत संहिता	खगोल	वराहमिहिर
2	देवीचंद्रगुप्तम	गुप्त साम्राज्य	विशाखदत्त
3	राजतरंगिणी	कश्मीर के राजा का इतिहास	बिल्हण
4	विक्रमांकदेव चरित	चालुक्य राजा विक्रमादित्य VI की जीवनी	कल्हण

उपरोक्त पंक्तियों में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही ढंग से मेल खाती है?

A. केवल एक B. सिर्फ दो

C. केवल तीन D. चारों

उत्तर: B

व्याख्या:

- **पंक्ति 1 सही ढंग से सुमेलित है।** बृहत् संहिता - वराहमिहिर : वराहमिहिर की "बृहत् संहिता" गुप्त युग की एक स्मारकीय रचना है, जो महत्वपूर्ण बौद्धिक और वैज्ञानिक प्रगति द्वारा चिह्नित अवधि है। 5वीं-6वीं शताब्दी ई. में रहते हुए, वराहमिहिर ने एक व्यापक विश्वकोश संकलित किया, जिसमें खगोल विज्ञान और ज्योतिष से लेकर भूगोल और वास्तुकला तक के कई विषयों पर गहन चर्चा की गई। इस कार्य का मुख्य विषय ब्रह्मांड की खोज और मानव अस्तित्व पर इसका गहरा प्रभाव है। यह ग्रहों की चाल, ग्रहण और मौसम के पैटर्न की सावधानीपूर्वक जांच करता है, इन घटनाओं को ज्योतिषीय महत्व प्रदान करता है। खगोलीय प्रेक्षणों से परे, यह पाठ वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और यहां तक कि कीमती पत्थरों की विशेषताओं सहित दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी जानकारी देता है। गुप्त साम्राज्य द्वारा कला और विज्ञान के संरक्षण ने वराहमिहिर की विद्वत्तापूर्ण खोज के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की, जिससे "बृहत् संहिता" भारत के उस स्वर्ण युग की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक समझ में एक मूल्यवान खिड़की बन गई। संस्कृत में लिखी गई यह पुस्तक गुप्त काल के उन्नत खगोलीय ज्ञान और उस समय के लोगों द्वारा प्राकृतिक दुनिया के साथ महसूस किए जाने वाले गहरे अंतर्संबंध को दर्शाती है।

- **पंक्ति 2 सही ढंग से सुमेलित है।** देवीचंद्रगुप्तम - विशाखदत्त : विशाखदत्त का "देवीचंद्रगुप्तम" एक खंडित नाटक है जो गुप्त वंश की राजनीतिक साज़िशों की एक झलक प्रदान करता है। माना जाता है कि यह 4वीं और 8वीं शताब्दी ई. के बीच हुआ था, विशाखदत्त ने एक नाटक तैयार किया जो चंद्रगुप्त द्वितीय के इर्द-गिर्द केंद्रित एक कहानी कहता है। अपने खंडित स्वभाव के कारण, नाटक की पूरी कथा को फिर से बनाना मुश्किल है, लेकिन बचे हुए हिस्से राजनीतिक रणनीति और साहस की कहानी बताते हैं। मुख्य विषय एक संकट के इर्द-गिर्द घूमता है जहाँ चंद्रगुप्त के बड़े भाई रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुवदेवी को एक शक राजा को सौंपने के लिए सहमत होते हैं। बहादुरी और राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए चंद्रगुप्त खुद को ध्रुवदेवी के रूप में प्रच्छन्न करते हैं और शक राजा को खत्म कर देते हैं। वीरता और रणनीतिक सोच का यह कार्य गुप्त शासकों द्वारा अपनी सत्ता बनाए रखने में सामना की गई चुनौतियों को उजागर करता है। यह नाटक गुप्त युग की आंतरिक राजनीति और सम्मान और राजनीतिक चालाकी के महत्व पर प्रकाश डालता है। विशाखदत्त, जो अपने नाटक मुद्राराक्षस के लिए भी जाने जाते हैं, गुप्त काल की जटिलताओं में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए, अपने नाटकीय कार्यों के माध्यम से बहुमूल्य ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं।

- **पंक्ति 3 सुमेलित नहीं है।** राजतरंगिणी - कल्हण : कल्हण की "राजतरंगिणी" एक उल्लेखनीय ऐतिहासिक पुस्तक है जो कश्मीर के राजाओं का व्यापक विवरण प्रदान करती है। 12वीं शताब्दी ई. में लिखी गई यह पुस्तक भारत में ऐतिहासिक लेखन के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। इस कृति का मुख्य विषय कश्मीर का इतिहास है, जो पौराणिक काल से लेकर कल्हण के अपने युग तक इसकी उत्पत्ति का पता लगाता है। यह क्षेत्र पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण करता है, जो उनके शासनकाल का कालानुक्रमिक वर्णन प्रदान करता है। मध्यकाल के दौरान कश्मीर के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को समझने के लिए "राजतरंगिणी" एक अमूल्य स्रोत है। विभिन्न स्रोतों का उपयोग करके एक वस्तुनिष्ठ इतिहास लिखने का कल्हण का प्रयास इसे भारतीय इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। संस्कृत पद्य में लिखी गई यह पुस्तक कश्मीर के इतिहास के लिए एक प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करती है, जो क्षेत्र के शासकों और उनके समय के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। कल्हण का कार्य उनकी मातृभूमि के इतिहास को संरक्षित करने के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण है, जो इसे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज बनाता है।

- **पंक्ति 4 सुमेलित नहीं है।** विक्रमांकदेवचरित - बिल्हण : बिल्हण का "विक्रमांकदेव चरित" एक जीवनी महाकाव्य है जो चालुक्य राजा विक्रमादित्य VI के जीवन और उपलब्धियों का जश्न मनाता है। 11वीं शताब्दी ई. में लिखा गया यह कार्य चालुक्य वंश को समझने के लिए एक प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करता है। महाकाव्य का मुख्य विषय विक्रमादित्य VI के जीवन का चित्रण है, जिसमें उनके सैन्य अभियान, प्रशासनिक सुधार और कलाओं का संरक्षण शामिल है। एक दरबारी कवि के रूप में, बिल्हण राजा की उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है, जो उस अवधि के दौरान चालुक्य साम्राज्य के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह कार्य एक मूल्यवान ऐतिहासिक संसाधन है, जो चालुक्य वंश की शक्ति और प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करता है। संस्कृत में लिखा गया, यह ऐतिहासिक महाकाव्यों की शैली का उदाहरण है, जिसमें ऐतिहासिक तथ्यों को काव्यात्मक अलंकरणों के साथ मिलाया गया है। बिल्हण का कार्य चालुक्य युग की साहित्यिक और ऐतिहासिक परंपराओं का प्रमाण है तथा उस समय के अध्ययन के लिए एक प्रमुख संसाधन है।

Q7. निम्नलिखित में से कौन गुप्त साम्राज्य में सबसे छोटी से लेकर सबसे बड़ी तक प्रशासनिक इकाइयों के सही पदानुक्रमित क्रम का प्रतिनिधित्व करता है?

A. वीथी → विषय → भुक्ति

B. विथि → प्रदेश → विषय

C. ग्राम → वीथी → भुक्ति

D. ग्राम → भुक्ति → वीथि

उत्तर: C

व्याख्या:

- **प्रांत (भुक्ति, देश, राज्य) :** गुप्त साम्राज्य प्रशासनिक रूप से प्रांतों में विभाजित था, जिन्हें भुक्ति, देश या राज्य के नाम से जाना जाता था। ये प्रांत क्षेत्रीय प्रशासन का उच्चतम स्तर बनाते थे और इनका

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

शासन उपरीक नामक अधिकारी द्वारा किया जाता था। केंद्र सरकार उपरीक को नियुक्त करती थी, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने, राजस्व संग्रह की देखरेख करने और कुशल शासन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार था। प्रांतीय प्रशासन ने विशाल साम्राज्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इसने केंद्रीय शासकों से स्थानीय अधिकारियों को अधिकार सौंपे।

- **जिले (विषय, प्रदेश, विथि) :** प्रत्येक प्रांत को आगे जिलों में विभाजित किया गया था, जिन्हें विषय या प्रदेश कहा जाता था। भारत के पूर्वी क्षेत्रों में, जिले के भीतर एक छोटी प्रशासनिक इकाई को विथि के नाम से जाना जाता था। विषयपति, या जिला गवर्नर, कर संग्रह, कानून प्रवर्तन और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने सहित जिले के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। शासन में सहायता के लिए, अधिकरण के रूप में जानी जाने वाली प्रतिनिधियों की एक परिषद की स्थापना की गई थी। इस परिषद ने विषयपति को सलाह देने और जिला स्तर पर सुचारू प्रशासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- **गाँव (ग्राम) (ग्राम अध्यक्ष, गणपति) :** जमीनी स्तर पर, गुप्त साम्राज्य में एक सुव्यवस्थित ग्राम प्रशासन था। ग्राम प्रधान, जिसे ग्रामाध्यक्ष या गणपति के रूप में जाना जाता है, स्थानीय शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वह विवादों को सुलझाने, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार था कि करों को कुशलतापूर्वक एकत्र किया जाए। ग्राम प्रशासन काफी हद तक स्वायत्त था, स्थानीय विधानसभाएं और गिल्ड भी निर्णय लेने में भूमिका निभाते थे। गुप्त शासक एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली पर निर्भर थे जहाँ गाँवों का अपने मामलों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण था, जिससे पूरे साम्राज्य में कुशल शासन की अनुमति मिलती थी।

- **इसलिए, सही कालानुक्रमिक क्रम ग्राम → विथी → भुक्ति है। इस प्रकार, यहाँ सही उत्तर विकल्प C है।**

Q8. भारत के सांस्कृतिक इतिहास में टोडी, दरबारी, भोपाली और भीमपलासी आमतौर पर निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं?

A. संगीत B. नृत्य

C. मंदिर वास्तुकला D. भाषा

उत्तर: A

व्याख्या:

- **तोड़ी :** तोड़ी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक मौलिक और प्राचीन राग है। यह अपने आत्मनिरीक्षण, उदासी और गहरे भावनात्मक चरित्र के लिए जाना जाता है। इसे पारंपरिक रूप से देर सुबह बजाया जाता है। तोड़ी हिंदुस्तानी गायन और वाद्य संगीत का एक मुख्य हिस्सा है। तोड़ी के कई रूप हैं, जैसे मियाँ की तोड़ी (मियाँ तानसेन को जिम्मेदार ठहराया गया)। इसकी उत्पत्ति प्राचीन भारतीय संगीत परंपराओं से जुड़ी है और यह एक बहुत पुराना राग है। हालाँकि यह किसी खास राज्य से उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन इसका विकास विभिन्न मध्यकालीन और मुगल-युग के शासकों के दरबार में हुआ, जिसमें तानसेन जैसे प्रमुख संगीतकारों ने इसके परिशोधन में योगदान दिया। यह अपनी जटिल मधुर संरचना के लिए जाना जाता है।

- **दरबारी :** दरबारी कणाद एक राजसी और गंभीर राग है। यह भव्यता और दरबारी माहौल की भावना पैदा करता है, इसलिए इसका नाम "दरबारी" (दरबारी) है। इसे पारंपरिक रूप से देर रात में बजाया जाता है। यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित राग है, जिसे अक्सर अनुभवी गायक और वाद्य वादक बजाते हैं। यह अपनी धीमी, सोची-समझी हरकतों के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति मुगल काल में हुई थी, जो फारसी संगीत परंपराओं से प्रभावित था। यह मुगल दरबारों में फला-फूला, जहाँ सम्राटों और कुलीनों ने इसका संरक्षण किया। यह एक ऐसा राग है जिसे प्रस्तुत करने के लिए बहुत कौशल की आवश्यकता होती है।

- **भोपाली :** भोपाली एक पंचकोणीय (पाँच-स्वर वाला) राग है जो अपनी सरलता और सुखदायक गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। इसे पारंपरिक रूप से रात के शुरुआती समय में बजाया जाता है। यह शांति और स्थिरता की भावना पैदा करता है। यह एक लोकप्रिय राग है, जिसका उपयोग अक्सर भक्ति संगीत और हल्की शास्त्रीय रचनाओं में किया जाता है। इसका नाम भोपाल शहर से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी सटीक उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। हालाँकि इसका नाम इसे भोपाल से जोड़ता है, लेकिन यह पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय हो गया, और इसे विभिन्न क्षेत्रीय दरबारों में संरक्षण मिला। यह एक बहुत ही लोकप्रिय परिचयात्मक राग है।

- **भीमपलासी :** भीमपलासी एक ऐसा राग है जो करुणा और लालसा की भावना व्यक्त करता है। यह अपनी अभिव्यंजक धुनों और भावनात्मक गहराई के लिए जाना जाता है। इसे पारंपरिक रूप से दोपहर के अंत में बजाया जाता है। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में व्यापक रूप से बजाया जाने वाला राग है, जिसे अक्सर गायन और वाद्य दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन भारतीय संगीत परंपराओं में निहित है, और यह सदियों से विकसित हुई है। अन्य रागों की तरह, इसका विकास विभिन्न क्षेत्रीय दरबारों और संगीत परंपराओं से प्रभावित था। यह एक ऐसा राग है जिसे जटिल प्रकृति का माना जाता है। ये राग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की समृद्ध टेपेस्ट्री का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा चरित्र और भावनात्मक प्रतिध्वनि है। इसलिए, यहाँ सही उत्तर विकल्प A है।

Q9. निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सही है/हैं?

1. धर्मपाल ने नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना की।
2. चन्द्रगुप्त-2 ने नालन्दा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. विश्वविद्यालय में शिक्षण का मुख्य फोकस महायान बौद्ध धर्म था।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. 1 और 2 B. केवल 2

C. 1 और 3 D. केवल 3

उत्तर: D

व्याख्या:

- **कथन 1 गलत है।** 8वीं और 9वीं शताब्दी ई. में पाल वंश के एक प्रमुख शासक धर्मपाल को विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जाना जाता है, जो बौद्ध शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण केंद्र है। दूसरी ओर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बहुत पहले, 5वीं शताब्दी ई. में गुप्त काल के दौरान हुई थी। नालंदा की स्थापना का श्रेय धर्मपाल को देना एक ऐतिहासिक गलत धारणा है। पाल वंश बाद की शक्ति थी, और उनका ध्यान विक्रमशिला जैसी संस्थाओं के माध्यम से बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने पर था। संभवतः यह भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि दोनों विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। जबकि धर्मपाल बौद्ध शिक्षा के एक महान संरक्षक थे, वे नालंदा की स्थापना में शामिल नहीं थे। ऐतिहासिक अभिलेख स्पष्ट रूप से नालंदा की उत्पत्ति के लिए गुप्त युग की ओर संकेत करते हैं।
- **कथन 2 गलत है।** चंद्रगुप्त द्वितीय एक शक्तिशाली गुप्त शासक था, वह नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना या महत्वपूर्ण पुनरुद्धार से जुड़ा नहीं था। नालंदा की स्थापना का श्रेय कुमारगुप्त प्रथम को दिया जाता है, जिन्होंने 5वीं शताब्दी ई. में शासन किया था। अपने लंबे इतिहास में, नालंदा ने विकास और गिरावट के दौर का अनुभव किया, जिसमें विभिन्न शासकों और संरक्षकों ने इसके रखरखाव और विस्तार में योगदान दिया। हालांकि, इसकी आधारभूत स्थापना कुमारगुप्त प्रथम से दृढ़ता से जुड़ी हुई है। नालंदा के निरंतर संचालन के दौरान विभिन्न स्तरों पर संरक्षण देखा गया। चन्द्रगुप्त द्वितीय एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन उनका योगदान अन्यत्र था। गुप्त काल महान शिक्षा और विकास का समय था।
- **कथन 3 सही है।** नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र था। विश्वविद्यालय ने तिब्बत, चीन और कोरिया सहित पूरे भारत और उससे बाहर के विद्वानों और छात्रों को आकर्षित किया। पाठ्यक्रम में दर्शनशास्त्र, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा और खगोल विज्ञान सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। हालाँकि, मुख्य ध्यान महायान बौद्ध सिद्धांतों और प्रथाओं पर रहा। नागार्जुन, आर्यदेव और धर्मकीर्ति जैसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नालंदा से जुड़े थे। विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में बौद्ध ग्रंथों का विशाल संग्रह था, जिससे यह ज्ञान का एक महत्वपूर्ण भंडार बन गया। महायान बौद्ध धर्म पर जोर ने नालंदा के बौद्धिक वातावरण को आकार दिया और बौद्ध शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में इसकी स्थायी विरासत में योगदान दिया। नालंदा में प्रदान की गई शिक्षाओं ने महायान बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलाने में मदद की।

Q10. निम्नलिखित में से किस पंक्ति की जानकारी सही ढंग से मेल खाती है?

क्रम संख्या	बंदरगाहों	साम्राज्य/साम्राज्य	तटों
1	घंटाशाला	राष्ट्रकूट साम्राज्य	कोरोमंडल तट
2	कदूरा	मौर्य साम्राज्य	कोंकण तट
3	मुजिरिस	चेर साम्राज्य	मालाबार तट
4	ताम्रलिप्ति	पाल साम्राज्य	पूर्वी तट

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3

C. केवल 3 और 4 D. केवल 1 और 4

उत्तर: C

व्याख्या:

- **पंक्ति 1 गलत है। घंटाशाला :** आधुनिक आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर बसा घंटाशाला एक महत्वपूर्ण समुद्री केंद्र था, जिसने कई राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा। कोरोमंडल तट पर इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु बना दिया, जो भारतीय अंतर्देशीय क्षेत्रों को हिंद महासागर के विशाल विस्तार से जोड़ता था। उल्लेखनीय रूप से, यह सातवाहन और गुप्त साम्राज्यों के तहत फला-फूला, जिसने विभिन्न युगों में इसके स्थायी महत्व को उजागर किया। बंदरगाह ने कई तरह के सामानों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान की, जिससे क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि में योगदान मिला। कभी चहल-पहल वाले इस बंदरगाह के अवशेष इसके अतीत के गौरव के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, जो कोरोमंडल तट के इतिहास को आकार देने वाले समुद्री व्यापार नेटवर्क की एक झलक पेश करते हैं। कृष्णा डेल्टा के पास का वर्तमान क्षेत्र अभी भी अपने ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है, जो अतीत को वर्तमान से जोड़ता है। एक व्यापारिक संबंध के रूप में घंटाशाला की विरासत भारत के पूर्वी तट के समुद्री इतिहास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।
- **पंक्ति 2 गलत है। कदूरा :** वर्तमान महाराष्ट्र में बीहड़ कोंकण तट पर स्थित कदुरा को गुप्त साम्राज्य के दौरान एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में प्रसिद्धि मिली। मौर्य साम्राज्य के साथ शुरुआती जुड़ाव के विपरीत, गुप्तों ने ही कदुर के समुद्री व्यापार के लिए रणनीतिक स्थान को पहचाना और उसका लाभ उठाया। कोंकण तट, अपने प्राकृतिक बंदरगाहों और अरब सागर तक पहुँच के साथ, गुप्तों के व्यापक व्यापार नेटवर्क में कदुर को एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाता था। यह पश्चिमी क्षेत्रों से आने-जाने वाले सामानों के लिए प्रवेश द्वार

के रूप में कार्य करता था, जिससे साम्राज्य की आर्थिक मजबूती में योगदान मिला। गुप्त युग के दौरान कदुर का महत्व साम्राज्य के दूरगामी प्रभाव और विविध तटीय क्षेत्रों की क्षमता का दोहन करने की इसकी क्षमता को दर्शाता है। कोंकण तट पर बंदरगाह की ऐतिहासिक उपस्थिति क्षेत्र की दीर्घकालिक समुद्री परंपराओं को रेखांकित करती है। एक प्रमुख गुप्त बंदरगाह के रूप में, कडूरा ने साम्राज्य की व्यापार गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- **पंक्ति 3 सही है। मुजिरिस :** वर्तमान केरल में सुरम्य मालाबार तट पर स्थित मुजिरिस एक हलचल भरा बंदरगाह था जिसने प्राचीन दुनिया के व्यापार की गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चेरा राजवंश के संरक्षण में, मुजिरिस रोमन साम्राज्य को मसालों, विशेष रूप से काली मिर्च के निर्यात का एक प्रमुख केंद्र बन गया। अपने समृद्ध मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मालाबार तट ने मुजिरिस की समृद्धि के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि प्रदान की। प्राचीन ग्रंथ, जैसे कि पेरिप्लस ऑफ़ द एरिथ्रियन सी, प्राचीन दुनिया में इसके महत्व को उजागर करते हुए बंदरगाह की जीवंत व्यापार गतिविधियों का विशद वर्णन करते हैं। चेरों ने अपने समुद्री कौशल के साथ, दूर-दराज के देशों के साथ आकर्षक व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए मुजिरिस का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया। इस व्यापार से उत्पन्न धन ने चेरा साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज, मालाबार तट मसाला उत्पादन के लिए एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है, जो ऐतिहासिक व्यापार मार्गों की याद दिलाता है जिसने कभी मुजिरिस को वैश्विक व्यापारिक शक्ति बना दिया था।

- **पंक्ति 4 सही है। ताम्रलिप्ति :** ताम्रलिप्ति, जिसे अब पश्चिम बंगाल में तामलुक के नाम से जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण प्राचीन बंदरगाह था जो दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार था। भारत के पूर्वी तट पर रणनीतिक रूप से स्थित, यह पाल साम्राज्य और उससे भी पहले के समय में एक महत्वपूर्ण समुद्री संपर्क के रूप में कार्य करता था। बंदरगाह ने व्यापक व्यापार की सुविधा प्रदान की, जिससे भारत और बंगाल की खाड़ी के पार के राज्यों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिला। बौद्ध धर्म और व्यापार के संरक्षण के लिए जाने जाने वाले पाल साम्राज्य ने दूर के क्षेत्रों से जुड़ने के लिए ताम्रलिप्ति का उपयोग किया। इसके स्थान ने इसे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच यात्रा करने वाले व्यापारियों और विद्वानों के लिए एक प्रमुख पारगमन बिंदु बना दिया। एक व्यापारिक बंदरगाह के रूप में ताम्रलिप्ति का लंबा इतिहास भारत के पूर्वी तट के समुद्री इतिहास में इसके स्थायी महत्व को रेखांकित करता है। एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र के रूप में बंदरगाह की विरासत प्राचीन भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में इसके योगदान को उजागर करती है। अतः, यहाँ सही उत्तर विकल्प C है।

Q11. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: हड़प्पा वासियों द्वारा कांस्य-ढलाई की कला का व्यापक पैमाने पर अभ्यास किया जाता था।

कथन II: कई तांबे के खनन स्थल, जैसे खेतड़ी खदान, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए शुद्ध तांबे के स्रोत थे।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

A. कथन I और कथन II दोनों सही हैं, और कथन II कथन I की सही व्याख्या है।

B. कथन I और कथन II दोनों सही हैं, और कथन II कथन I का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

C. कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

D. कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

उत्तर: A

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** हड़प्पा वासियों द्वारा 'खोई हुई मोम' तकनीक का उपयोग करके कांस्य ढलाई की कला का व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता था। इस प्रक्रिया में एक मोम की मूर्ति बनाना, उस पर मिट्टी का लेप लगाना और उसे सूखने देना शामिल था। फिर मोम को पिघलाया गया और एक छोटे से छेद के माध्यम से निकाला गया, जिससे एक खोखला मिट्टी का साँचा रह गया। इस साँचे में पिघली हुई धातु डाली जाती थी, जिससे मूल आकृति का आकार आ जाता था। एक बार जब धातु ठंडी हो गई, तो मिट्टी का आवरण हटा दिया गया। कांस्य मूर्तियों में मानव और पशु दोनों की आकृतियाँ शामिल थीं, जिनमें प्रसिद्ध 'डांसिंग गर्ल' की मूर्ति और व्यापक सींगों वाली भैंस उल्लेखनीय उदाहरण हैं।

- **कथन 2 सही है।** तांबा और कांस्य सिंधु घाटी सभ्यता में औजारों और औज़ारों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्राथमिक धातुएँ थीं। इनमें सपाट आयताकार कुल्हाड़ियाँ, छेनी, चाकू, भाले, तीर के निशान (संभवतः पड़ोसी शिकार जनजातियों को निर्यात किए गए), छोटी आरी और छुरे शामिल थे। इन वस्तुओं की उत्पादन प्रक्रिया में ढलाई, छेनी और हथौड़ा मारने जैसी सरल तकनीकें शामिल थीं, जो रोजमर्रा के औजारों और हथियारों में इन धातुओं के व्यावहारिक उपयोग को दर्शाती हैं।

- **वर्तमान राजस्थान में खेतड़ी की खदानें तांबे का प्राथमिक स्रोत थीं। अतः, सही उत्तर विकल्प A है।**

Q12. निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

क्रम संख्या	मौर्यकालीन वास्तुकला	विशेषताएँ
1	कुम्हरार स्थान	अकेले चुनार का व्यापक उपयोग।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

2	सारनाथ स्तंभ	मुख्य निर्माण सामग्री के रूप में लकड़ी का उपयोग
3	स्तूप वास्तुकला	स्तूप के मुख्य भाग में सोने और हाथी दांत का उपयोग किया गया था।

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

A. केवल एक B. सिर्फ दो

C. तीनों D. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D

व्याख्या:

- **युग्म 1 गलत सुमेलित है।** भारत में पहला शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य ने पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी स्थापित की, जहाँ कुम्हरार के महलों ने इसकी भव्यता को दर्शाया। चंद्रगुप्त मौर्य का महल ईरान के पर्सेपोलिस में अचमे नीद महलों से विशेष रूप से प्रेरित था, जो सांस्कृतिक प्रभावों के मिश्रण को दर्शाता है। इन महलों के निर्माण में लकड़ी मुख्य निर्माण सामग्री के रूप में काम आई। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने इसकी प्रभावशाली वास्तुशिल्प उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए महल को मानव जाति की सबसे महान कृतियों में से एक बताया।

- **युग्म 2 गलत सुमेलित है।** अशोक के शासनकाल के दौरान, स्तंभ राज्य के महत्वपूर्ण प्रतीक बन गए और अक्सर युद्ध की जीत की याद में खुदे होते थे। अशोक ने इन स्तंभों का उपयोग शाही उपदेशों के प्रचार के लिए भी किया। आमतौर पर लगभग 40 फीट ऊंचे, स्तंभ मुख्य रूप से चुनार बलुआ पत्थर से बने थे और इसमें एक शाफ्ट और एक शीर्ष शामिल था। लंबे शाफ्ट ने आधार बनाया और पत्थर के एक टुकड़े से तैयार किया गया था, जिसे मोनोलिथ के रूप में जाना जाता है। शाफ्ट के ऊपर शीर्ष रखा गया था, जो कमल के आकार का या घंटी के आकार का हो सकता है, बाद वाला ईरानी स्थापत्य शैली से प्रभावित है। स्तंभों में अत्यधिक पॉलिश और चमकदार फिनिश थी, और शीर्ष के ऊपर एक गोलाकार या आयताकार आधार था जिसे अबेकस कहा जाता था, जिस पर एक पशु आकृति रखी गई थी - उदाहरण: चंपारण में लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ, आदि।

- **युग्म 3 गलत सुमेलित है।** स्तूपों का मुख्य भाग कच्ची ईंटों का उपयोग करके बनाया गया था, जबकि बाहरी सतह प्लास्टर की मोटी परत से ढकी पकी हुई ईंटों से बनी थी। स्तूप, जो वैदिक काल से भारत में प्रचलित दफन टीले थे, अंतिम संस्कार क्यूम्यलस के पारंपरिक प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते थे, जिसमें मृतक के अवशेष और राख होते थे। अशोक के शासनकाल के दौरान, स्तूप की कला अपने चरम पर पहुंच गई, लगभग 84,000 स्तूप बनाए गए।

Q13. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा करवाया था।
2. तुगलक वंश ने वास्तुकला की दोहरी गुंबद वाली विशेषता पेश की।
3. लोधी राजवंश ने वास्तुकला की बत्तर शैली की शुरुआत की।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक B. सिर्फ दो

C. तीनों D. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D

व्याख्या:

- **कथन 1 गलत है।** कुतुब मीनार, इंडो-इस्लामिक वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है, यह एक ऊंची पांच मंजिला संरचना है। इसका निर्माण कुतुब-उद-दीन ऐबक ने शुरू किया था, उन्होंने केवल भूतल का निर्माण पूरा किया था। अगली तीन मंजिल उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने जोड़ीं और अंतिम पांचवीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने पूरी की। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित, कुतुब मीनार में जटिल नक्काशी, कुरानिक शिलालेख और सजावटी पट्टियाँ हैं। खनिक का पतला डिजाइन, इसके वैकल्पिक कोणीय और गोलाकार बांसुरी के साथ मिलकर, मेहराब और इस्लामी अलंकरण के उपयोग से चिह्नित आर्कुएट शैली को प्रदर्शित करता है।

- **कथन 2 गलत है।** लोदी राजवंश के तहत, स्थापत्य कला का विकास सीमित था, मुख्य रूप से मकबरे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस अवधि के सबसे उल्लेखनीय नवाचारों में से एक दोहरे गुंबद की शुरुआत थी, जिसमें बाहरी गुंबद के नीचे एक खोखला आंतरिक गुंबद था। इस डिजाइन ने संरचनात्मक मजबूती को जोड़ा और आंतरिक गुंबद की कथित ऊंचाई को कम करने में मदद की, जिससे आंतरिक स्थान अधिक आनुपातिक हो गया। इस युग के मकबरे सरल और सादगीपूर्ण थे, जिनमें विस्तृत सजावट का अभाव था। लगभग 15 मीटर के व्यास के साथ निर्मित अष्टकोणीय आकार, उन्हें ढलान वाले बरामदों द्वारा समर्थित किया गया था। लोदी वास्तुकला के उदाहरणों में लोदी गार्डन में मकबरे और सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना शामिल है।

- **कथन 3 गलत है।** तुगलक राजवंश ने दिल्ली सल्तनत के दौरान वास्तुकला संकट की अवधि को चिह्नित किया, जिसमें अधिक उपयोगितावादी डिजाइनों की ओर बदलाव हुआ। चुनौतियों के बावजूद, निर्माण जारी रहा, और ग्रे बलुआ पत्थर एक प्रमुख निर्माण सामग्री बन गया। इस समय के दौरान वास्तुकला का ध्यान ताकत और स्थायित्व पर था, जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम सजावट के साथ एक सरल सौंदर्यबोध हुआ। प्रमुख नवाचारों में

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

से एक निर्माण की "बैटर" शैली थी, जिसमें संरचनात्मक स्थिरता जोड़ने और बाहरी दबावों का सामना करने के लिए ढलान वाली दीवारें थीं। तुगलकों ने प्रवेश द्वार के डिजाइन के लिए मेहराब और लिंटेल दोनों विधियों को भी जोड़ा, जिससे पारंपरिक और नवीन तकनीकों का मिश्रण बना। तुगलक वास्तुकला के उल्लेखनीय उदाहरणों में तुगलकाबाद और फिरोजाबाद के शहर शामिल हैं, जो सजावटी सुंदरता पर किलेबंदी और लचीलेपन पर राजवंश के जोर का उदाहरण देते हैं।

Q14. बहमनी वास्तुकला के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. बहमनी वास्तुकला उत्तर भारत में विकसित भारत-इस्लामिक वास्तुकला का मिश्रण थी।
2. बहमनी वास्तुकला में बल्बनुमा गुंबदों, जटिल टाइल काम और सुलेख सजावट के साथ वर्गाकार संरचनाएं शामिल हैं।
3. गुलबर्गा किला और रंगीन महल बहमनी वास्तुकला के प्रसिद्ध वास्तुशिल्प चमत्कार हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक B. सिर्फ दो

C. तीनों D. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: B

व्याख्या:

- **कथन 1 गलत है।** बहमनी वास्तुकला, बहमनी सल्तनत के दौरान विकसित हुई, जिसने दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र में 1347 से 1518 तक शासन किया, यह फारसी और हिंदू मंदिर शैलियों से प्रभावित इंडो-इस्लामिक वास्तुकला का एक क्षेत्रीय रूप था। कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाने जाने वाले बहमनी शासकों ने अपनी संरचनाओं को डिजाइन करने के लिए फारस, तुर्की और अरब से वास्तुकारों को आमंत्रित किया।
- **कथन 2 सही है।** बहमनी वास्तुकला की एक प्रमुख विशेषता शासकों की कब्रें हैं, जो बल्ब नुमा गुंबदों के साथ चौकोर आकार की है और जटिल टाइल काम, सुलेख और शिलालेखों से सजी हैं। अहमद शाह वली बहमन का मकबरा अपने आंतरिक भाग के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसे फ़ारसी रूपांकनों से सजाया गया है, जो सांस्कृतिक प्रभावों के मिश्रण को प्रदर्शित करता है।
- **कथन 3 सही है।** बहमनी वास्तुकला के चमत्कार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक नवाचार को दर्शाते हैं। गुलबर्गा किला, अपनी महान मस्जिद के साथ, नक्काशीदार फूलों और लताओं की उत्कृष्ट सजावट पेश करता है, जो उस युग की कलात्मक शक्ति का उदाहरण है। बीदर किला अपने दुर्जेय बुर्जों और मोटी दीवारों के लिए जाना जाता है, जिसमें करेज प्रणाली शामिल है - जल आपूर्ति के लिए एक सरल फ़ारसी नवाचार। रंगीन महल अपनी जीवंत सजावटी टाइलों के लिए प्रसिद्ध है, जो कलात्मक शैलियों और शासकों की सौंदर्यशास्त्र के प्रति प्रशंसा के मिश्रण को दर्शाता है। हम्पी में हाथी अस्तबल, अपने विशिष्ट धनुषाकार उद्घाटन और अवकाश के साथ, उस समय की स्थापत्य भव्यता को उजागर करते हैं। अंत में, सोलह खंभा मस्जिद, जो मूल रूप से एक औपचारिक दर्शक हॉल था, को सोलह स्तंभों वाले स्तंभ हॉल जोड़कर एक मस्जिद में बदल दिया गया था जो इसकी विशाल छत को सुरुचिपूर्ण ढंग से सहारा देते हैं, जो बहमनी वास्तुकला में धर्मनिरपेक्ष और पवित्रता को जोड़ता है।

Q15. निम्नलिखित में से एलोरा और अजंता गुफा वास्तुकला के बीच मुख्य अंतर क्या हैं?

1. एलोरा की गुफाएँ बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, जबकि अजंता की गुफाएँ हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन को समर्पित हैं।
2. दोनों गुफाओं का निर्माण गुप्त वंश के चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था।
3. एलोरा की गुफाओं में प्रकृतिवाद मौजूद है, जबकि अजंता की गुफाओं में विषयों की विविधता मौजूद है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल एक B. सिर्फ दो

C. तीनों D. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D

व्याख्या:

- **अजंता की गुफाएँ:** महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वाघोरा नदी के पास सह्याद्रि पर्वतमाला में स्थित अजंता गुफाएँ, 29 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं की एक श्रृंखला हैं। इनमें से 25 का उपयोग विहार (आवासीय गुफाओं) के रूप में किया जाता था, और 4 का उपयोग चैत्य (प्रार्थना कक्ष) के रूप में किया जाता था, जिन्हें 200 ईसा पूर्व और 650 ईस्वी के बीच विकसित किया गया था। इन गुफाओं को मुख्य रूप से वाकाटक राजाओं, विशेष रूप से राजा हरिषेण के संरक्षण में, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया था। फ्रेस्को तकनीक का उपयोग करके बनाई गई गुफा चित्र, उल्लेखनीय प्रकृतिवाद का प्रदर्शन करते हैं। स्थानीय वनस्पतियों और खनिजों से प्राप्त रंगों को लाल रंग में रेखांकित किया गया था, जिसमें नीला रंग विशेष रूप से अनुपस्थित था। गुफा संख्या 16 अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए मशहूर है।
- **एलोरा की गुफाएँ:** अजंता से लगभग 100 किमी दूर स्थित एलोरा गुफाओं में 34 रॉक-कट गुफाएँ शामिल हैं: 17 ब्राह्मणवादी, 12

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

बौद्ध और 5 जैन। 5वीं और 11वीं शताब्दी ईस्वी के बीच विकसित ये गुफाएं विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के गिल्डों की भागीदारी के कारण स्थापत्य शैली के विविध मिश्रण को दर्शाती हैं। हिंदू और बौद्ध गुफाओं का निर्माण मुख्य रूप से राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा किया गया था, जबकि यादव राजवंश ने जैन गुफाओं का निर्माण किया था। मुख्य आकर्षणों में शामिल हैं कैलाश मंदिर (गुफा 16), जो एक अखंड पत्थर से बना है, और विश्वकर्मा गुफा (गुफा 10), एक बौद्ध चैत्य हॉल है।

पहलू	अजंता की गुफाएँ	एलोरा की गुफाएँ
धार्मिक समर्पण	मुख्य रूप से बौद्ध, कुछ गुफाओं का उपयोग चैत्य के रूप में किया जाता है	हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समर्पित
समय सीमा	200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के बीच विकसित हुआ	5वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी के बीच विकसित हुआ
कलात्मक फोकस	पर्याप्त प्रकृतिवाद के साथ फ्रेस्को पेंटिंग	मूर्तियों और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के साथ विविध विषय
विषय-वस्तु और शैलियाँ	बौद्ध आख्यानों पर ध्यान दें, धार्मिक विषय में कोई विविधता नहीं	विभिन्न राजवंशों के कारण विविध स्थापत्य शैली और धार्मिक विषयों को दर्शाता है
मुख्य संरचनाएँ	विहार (मठ की गुफाएँ) और चैत्य (प्रार्थना कक्ष)	मंदिर, मठ और बड़े मंदिर।

Q16. यह किला महान मुगल सम्राटों में से एक के राजधानी शहर में स्थित है। किले को इसकी चटगाँव शैली और इस किले परिसर की अन्य संरचनाओं, जिनमें मोती मस्जिद, जहाँगीरी महल, शीश महल आदि शामिल हैं, के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऊपर दिया गया विवरण किस किले का है?

A. आगरा का किला B. लाल किला

C. लालबाग किला D. हाजीगंज किला

उत्तर: A

व्याख्या:

- **विकल्प A:** आगरा किला एक महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प चमत्कार है, इसका निर्माण अकबर के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था, हालांकि किले के भीतर की अधिकांश प्रमुख संरचनाएं शाहजहाँ के शासनकाल में पूरी हुईं। उल्लेखनीय इमारतों में मोती मस्जिद, दीवान-ए-आम (सार्वजनिक दर्शकों का हॉल), और दीवान-ए-खास (निजी दर्शकों का हॉल) शामिल हैं, सभी शाहजहाँ द्वारा बनवाए गए थे। किले में जहांगीरी महल और शीश महल (तुर्की स्नानघर) भी हैं, जो उत्कृष्ट मुगल वास्तुकला का प्रदर्शन करते हैं। आगरा किले के भीतर के उद्यान चारबाग शैली में डिज़ाइन किए गए हैं, जो एक क्लासिक मुगल उद्यान लेआउट का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः, विकल्प A सही है।
- **विकल्प B:** लाल किला, जिसे लाल किला के नाम से भी जाना जाता है, भारत के दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक किला है, जो मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था। 12 मई 1639 को सम्राट शाहजहाँ द्वारा बनवाए गए इस किले का निर्माण तब किया गया जब उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। इसके आकर्षक डिजाइन, जिसमें मूल रूप से लाल और सफेद रंग शामिल हैं, का श्रेय वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया जाता है, जिन्होंने ताज महल को भी डिजाइन किया था। लाल किला मुगल वास्तुकला का शिखर है, जो फारसी महल शैलियों और स्वदेशी भारतीय परंपराओं का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्रदर्शित करता है, जो शाहजहाँ के शासनकाल की भव्यता और कलात्मक उपलब्धियों को दर्शाता है। आज, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक है। इस प्रकार, विकल्प B गलत है।
- **विकल्प C:** लालबाग किला, जिसे मूल रूप से किला औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश के ढाका के केंद्र में स्थित है। किले का निर्माण 1678 ई. में सम्राट औरंगजेब के तीसरे बेटे मुगल सूबेदार मोहम्मद आजम शाह के अधीन शुरू हुआ था, उस समय जब नौसैनिक किलों की उपस्थिति के कारण ढाका विद्रोही जमींदारों और समुद्री डाकुओं द्वारा उत्पन्न खतरों से अपेक्षाकृत सुरक्षित था। 15 महीने के बाद, मराठा विद्रोह को दबाने के लिए आजम को बुलाया गया और उनके उत्तराधिकारी सूबेदार शाइस्ता खान ने निर्माण जारी रखा, लेकिन 1684 ई. में अपनी बेटी ईरान दुखत (परी बीबी) की दुखद मौत के बाद इसे अधूरा छोड़ दिया। 1844 में, किले को 'ढाका संरक्षण समिति' नामक एक स्वायत्त संस्था ने अपने कब्जे में ले लिया था और तब से इसे लालबाग किले के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार, विकल्प C गलत है।
- **विकल्प D:** हाजीगंज किला, जिसका निर्माण 1610 ई. के आसपास हुआ था, भारत के पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में स्थित है। बंगाल में मुगल सेनापति मिर्जा नाथन द्वारा 17वीं शताब्दी में लिखे गए इतिहास बहारिस्तान-ए-ग़ैबी के अनुसार, यह किला स्थानीय जमींदारों के गठबंधन बारा भुइयां के खिलाफ़ ऑपरेशन के दौरान मुगल सूबेदार इस्लाम खान के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे के रूप में कार्य करता था। किले ने उस समय की रणनीतिक सैन्य वास्तुकला को दर्शाते हुए, क्षेत्र में मुगल शक्ति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज, हाजीगंज किला एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में खड़ा है, जो बंगाल में मुगल प्रभाव और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी देता है। इस प्रकार, विकल्प D गलत है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

Q17. प्राचीन भारत में वैज्ञानिक विकास के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. गुप्त काल में आचार्य पिंगला औषधि विद्वान थे।
2. माधव मौर्य काल के महान गणितज्ञ थे।
3. आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक B. सिर्फ दो

C. तीनों D. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: D

व्याख्या:

- **कथन 1 गलत है।** आचार्य पिंगला (लगभग तीसरी-दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व) एक प्रभावशाली प्राचीन भारतीय कवि और गणितज्ञ थे जो अपने काम छंद शास्त्र के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें पिंगला-सूत्र भी कहा जाता है। यह ग्रंथ, जिसे संस्कृत छंद शास्त्र पर सबसे पहला ज्ञात कार्य माना जाता है, इसमें स्वर्गीय सूत्र शैली में लिखे गए आठ अध्याय शामिल हैं, जिससे इसे टिप्पणी के बिना समझना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। छंद शास्त्र का समय ईसा पूर्व पिछली कुछ शताब्दियों का बताया गया है और 10वीं शताब्दी ई. में हलायुध ने इस पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखी थी। इस प्रकार, यह कथन गलत है।

- **कथन 2 गलत है।** माधव, जिन्हें माधव-कारा के नाम से भी जाना जाता है, 7वीं या 8वीं शताब्दी की शुरुआत में सक्रिय एक प्रमुख भारतीय आयुर्वेद चिकित्सक थे। उन्हें उनके मौलिक कार्य, रग-विनिश्चय के लिए जाना जाता है, जिसे आमतौर पर माधव निदान के रूप में जाना जाता है। इस आधिकारिक पाठ में 79 अध्याय शामिल हैं जो विभिन्न बीमारियों को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत करते हैं, उनके कारणों, लक्षणों और जटिलताओं का विवरण देते हैं। विशेष रूप से, माधव के काम में चेचक (मसूरिका) पर एक समर्पित अध्याय शामिल है, जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति में इस बीमारी को समझने और निदान करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। माधव निदान ने आयुर्वेदिक चिकित्सा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसे निदान और उपचार के व्यापक दृष्टिकोण के लिए संदर्भित किया जाता है। अतः यह कथन गलत है।

- **कथन 3 गलत है।** आर्यभट्ट (476-550 ई.पू.) प्राचीन भारत के एक प्रभावशाली गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे, जो दोनों क्षेत्रों में अपने मूलभूत योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। उनके मौलिक कार्य, आर्यभटीय को दुनिया में गणित पर पहली पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें बीजगणित, अंकगणित और ज्यामिति में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को शामिल किया गया है। इस पाठ का बाद में 820 ई.पू. के आसपास अल-ख्वारिज्मी द्वारा अरबी में अनुवाद किया गया, जिससे इसका प्रभाव और अधिक फैल गया। खगोल विज्ञान में, आर्यभट्ट ने उल्लेखनीय प्रगति की, जिसमें पाई के मूल्य की गणना करना, सौर और चंद्र ग्रहण के कारणों को स्पष्ट करना और पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का वर्णन करना शामिल है। उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि सौर वर्ष की लंबाई 365 दिन, 6 घंटे, 12 मिनट और 30 सेकंड होगी। विशेष रूप से, आर्यभट्ट शून्य को एक संख्या के रूप में उपयोग करने वाले और दशमलव अंक प्रणाली बनाने वाले पहले लोगों में से एक थे, जिसने गणित और खगोल विज्ञान के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। अतः यह कथन गलत है।

लेखक	किताब	विषय	अनुमानित समय
पिंगला	चण्डशास्त्र	गणित (छंद विद्या)	तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व
चरक	चरक संहिता	दवा	दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व
सुश्रुत	सुश्रुत संहिता	शल्य चिकित्सा	छठी शताब्दी ईसा पूर्व
माधव	माधव निदान	विकृति विज्ञान	14 वीं शताब्दी ई.पू
वराहमिहिर	पंच-सिद्धांतिका	गणितीय खगोल विज्ञान	छठी शताब्दी ई.पू
वराहमिहिर	बृहत संहिता	व्यापक विषय (खगोल विज्ञान, भूविज्ञान, वास्तुकला)	छठी शताब्दी ई.पू
आर्यभट्ट	आर्यभटीय	खगोल विज्ञान और गणित	5वीं शताब्दी ई.पू
लगधा	वेदांग ज्योतिष	खगोल विज्ञान (वेदांग)	पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व

Q18. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन-I: उत्तर-वैदिक काल में अधिकांश साहित्य गैर-संस्कृत भाषाओं में लिखा गया।

कथन-II: बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने आम भाषाओं का इस्तेमाल किया ताकि आम लोग उनकी शिक्षाओं को आसानी से समझ सकें।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

A. कथन I और कथन II दोनों सही हैं, और कथन II कथन I की सही व्याख्या है।

B. कथन I और कथन II दोनों सही हैं, और कथन II कथन I का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

C. कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

D. कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

उत्तर: A

व्याख्या:

- **कथन I सही है।** यह कथन दावा करता है कि उत्तर-वैदिक काल के दौरान, अधिकांश साहित्य गैर-संस्कृत भाषाओं में रचा गया था। यह सही है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएँ और बोलियाँ उभरने लगीं, जो प्राचीन भारत के विविध सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाती हैं। संस्कृत, जबकि उसके सख्त व्याकरणिक नियमों के लिए पूजनीय थी और अक्सर कुलीन ब्राह्मणों और धार्मिक ग्रंथों के लिए आरक्षित थी, आम लोगों के लिए कम सुलभ हो गई। उदाहरण के लिए, प्राकृत और अपभ्रंश का व्यापक रूप से साहित्यिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता था, जो पहले के वैदिक ग्रंथों में देखे गए संस्कृत प्रभुत्व से दूर था।
- **कथन II सही है।** इस कथन में कहा गया है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने अपने संदेशों को आसानी से समझने योग्य तरीके से व्यक्त करने के लिए प्राकृत जैसी सामान्य भाषा का उपयोग किया। ये भी सही है; दोनों धर्मों का लक्ष्य व्यापक दर्शकों तक पहुंचना था, और प्राकृत ने संस्कृत के लिए अधिक सुलभ विकल्प के रूप में कार्य किया। बौद्ध साहित्य में जातक कथाएँ और पाली में त्रिपिटक (बौद्ध धर्मग्रंथ) जैसे ग्रंथ इस प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। इसी प्रकार, जैन परंपरा में आगम प्राकृत में लिखे गए थे, जिसमें स्थानीय भाषाओं के उपयोग पर और जोर दिया गया था।
- **इस प्रकार, सही उत्तर A है। दोनों कथन सही हैं, और कथन II बताता है कि इस अवधि के दौरान साहित्य गैर-संस्कृत भाषाओं में क्यों स्थानांतरित हो गया।**

Q19. वाइकोम सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

1. एम. के. गांधी इस आंदोलन के खिलाफ थे।
2. यह आंदोलन कृषि उत्पादों पर उच्च कर लगाने को लेकर था।
3. याचिका बंगाल में ब्रिटिश शासक को प्रस्तुत की गई थी।

नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनें:

A. केवल 1 B. केवल 1 और 2

C. केवल 2 और 3 D. इनमे से कोई भी नहीं

उत्तर: D

व्याख्या:

- **वैकोम सत्याग्रह (1924-1925):** वैकोम सत्याग्रह एक अहिंसक विरोध था जो 1924 से 1925 तक वैकोम, केरल में हुआ था। यह निचली जाति के हिंदुओं को वैकोम महादेव मंदिर में प्रवेश से बाहर करने की प्रतिक्रिया थी। यह आंदोलन भारत में जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन गया। इसलिए, कथन 3 गलत है।

क्या हुआ?

- विरोध 30 मार्च 1924 को शुरू हुआ और 603 दिनों तक चला।
- इसका नेतृत्व के. केलप्पन, टी.के. ने किया। माधवन, और के.पी. केशव मेनन, जिन्होंने जाति-आधारित उत्पीड़न के खिलाफ लोगों को संगठित किया। इसलिए, कथन 2 गलत है।
- आंदोलन को रूढ़िवादी समूहों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा और पुलिस कार्रवाई और सामाजिक शत्रुता का सामना करना पड़ा।
- यह विरोध 1924 में वैकोम के इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ में से एक था, जिसने सत्याग्रहियों के लिए और भी कठिनाइयाँ बढ़ा दीं।
- इस दावे के विपरीत कि एम.के. गांधीजी इस आंदोलन के ख़िलाफ़ थे, उन्होंने वास्तव में इसका समर्थन किया और अधिकारियों के साथ बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए, **कथन 1 गलत है।**
- यह आंदोलन कृषि उत्पादों पर उच्च कर लगाने के बारे में नहीं था, न ही बंगाल में ब्रिटिश शासक को याचिका प्रस्तुत की गई थी; बल्कि, यह केरल में जाति-आधारित प्रतिबंधों को सीधी चुनौती थी।

विरोध का असर

- इस आंदोलन ने जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ भविष्य के संघर्षों की नींव रखी।
- इसने सविनय अवज्ञा और अहिंसक प्रतिरोध के गांधीवादी तरीकों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया।
- सत्याग्रह ने जातिगत आधार पर एकता को बढ़ावा दिया, सामाजिक न्याय के लिए लड़ने के लिए विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाया।
- इसने अस्पृश्यता को भारत के राजनीतिक विमर्श में सबसे आगे लाने में मदद की, जिससे यह राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया।

विरोध का नतीजा

- 1925 में, लंबे विरोध और बातचीत के बाद, वैकोम महादेव मंदिर को घेरने वाली चार में से तीन सड़कें सभी जातियों के लिए खोल दी गईं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- 1936 में, त्रावणकोर के महाराजा ने मंदिर प्रवेश उद्घोषणा जारी की, जिसने निचली जाति के हिंदुओं को मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिया, जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत थी।
- **इस प्रकार, यहाँ सही उत्तर विकल्प D है।**

Q20. रोलेट एक्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह अधिनियम प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात था।
2. कुख्यात जलियांवाला नरसंहार इस अधिनियम के खिलाफ विद्रोह के कारण हुआ है।
3. स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया।
4. साइमन कमीशन ने इस अधिनियम का समर्थन किया।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 2 B. केवल .1 और 2

C. केवल .1, 2, और 4 D. ऊपर के सभी।

उत्तर: B

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** रौलेट अधिनियम, जिसे औपचारिक रूप से 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के रूप में जाना जाता है, ने प्रेस की स्वतंत्रता सहित नागरिक स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण रूप से कम कर दिया। इसने सरकार को देशद्रोही या क्रांतिकारी समझे जाने वाले प्रकाशनों को दबाने, पत्रकारिता गतिविधियों पर सेंसरशिप और प्रतिबंध की अनुमति देने का अधिकार दिया। इस कठोर उपाय का उद्देश्य असहमति को दबाना और ब्रिटिश शासन को चुनौती देने वाली राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार को रोकना था। अधिकारियों को सूचना को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करके, अधिनियम ने स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट करने के प्रेस के मौलिक अधिकार को कमजोर कर दिया, महत्वपूर्ण आवाज़ों को प्रभावी ढंग से चुप करा दिया और विभिन्न दृष्टिकोणों तक सार्वजनिक पहुंच को सीमित कर दिया। मीडिया की स्वतंत्रता का यह दमन भारत में नियंत्रण बनाए रखने और बढ़ती अशांति को दबाने की ब्रिटिश सरकार की रणनीति में एक महत्वपूर्ण उपकरण था। प्रेस की स्वतंत्रता पर रोलेट एक्ट के हमले ने भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक काले अध्याय को चिह्नित किया, जो औपनिवेशिक सत्ता के लिए लोकतांत्रिक सिद्धांतों का त्याग करने की सरकार की इच्छा को प्रदर्शित करता है।
- **कथन 2 सही है।** रौलेट एक्ट के पारित होने से पूरे भारत में व्यापक विरोध हुआ, महात्मा गांधी ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। पंजाब के अमृतसर में, इन विरोध प्रदर्शनों की परिणति 13 अप्रैल, 1919 को दुखद जलियांवाला बाग नरसंहार में हुई। स्थानीय नेताओं, डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक बड़ी, निहत्थे सभा बुलाई गई थी। जनरल रेजिनाल्ड डायर ने बिना किसी चेतावनी के अपने सैनिकों को भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हो गए। यह नरसंहार रोलेट एक्ट द्वारा बनाए गए दमनकारी माहौल का प्रत्यक्ष परिणाम था, जिससे जनता में गुस्सा भड़क गया और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। जलियांवाला बाग में इन विरोध प्रदर्शनों का क्रूर दमन ब्रिटिश औपनिवेशिक उत्पीड़न का प्रतीक और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया। इस घटना ने रोलेट एक्ट की गंभीर मानवीय लागत और भारतीय जनता और ब्रिटिश सरकार के बीच तनाव बढ़ाने में इसकी भूमिका को रेखांकित किया।
- **कथन 3 गलत है।** रौलेट एक्ट को वास्तव में निरस्त कर दिया गया था, लेकिन 1947 में भारत को आजादी मिलने के तुरंत बाद नहीं। वास्तव में, व्यापक विरोध के कारण दबाव के परिणामस्वरूप, ब्रिटिश सरकार ने इसे निरस्त कर दिया था। इस अधिनियम के कठोर प्रावधान, जो मनमाने ढंग से गिरफ़्तारी और बिना किसी मुकदमे के हिरासत में रखने की अनुमति देते थे, को घोर अन्याय के रूप में देखा गया। इस अधिनियम को 1922 के निरसन अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों ने निरस्त कर दिया था। हालाँकि, इस अधिनियम की विरासत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गूंजती रही, जो औपनिवेशिक सरकार द्वारा इस्तेमाल किए गए दमनकारी उपायों की एक कठोर याद दिलाती है। रॉलेट एक्ट का निरस्त होना भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी, जिसने अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ़ जनता के प्रतिरोध की शक्ति को प्रदर्शित किया। यह नागरिक स्वतंत्रता को बहाल करने और उन शिकायतों को दूर करने की दिशा में एक कदम था, जिन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष को बढ़ावा दिया था।
- **कथन 4 गलत है।** साइमन कमीशन, जिसे औपचारिक रूप से भारतीय वैधानिक आयोग के रूप में जाना जाता है, को 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा स्थापित भारत सरकार के कामकाज की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। हालाँकि, आयोग ने सीधे तौर पर रोलेट अधिनियम का समर्थन नहीं किया था। जब साइमन कमीशन का गठन हुआ तब तक रोलेट एक्ट लागू हो चुका था। आयोग का ध्यान व्यापक संवैधानिक सुधारों और भारतीय शासन के भविष्य पर था। आयोग की सिफारिशें, जिन्हें अंततः भारतीय नेताओं ने अस्वीकार कर दिया था, रौलेट अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों को संबोधित नहीं करती थीं। जबकि आयोग का काम विवादास्पद था और व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा, इसका जनादेश रोलेट अधिनियम से अलग था, जो क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने पर केंद्रित था। इसलिए, यह कहना गलत है कि साइमन कमीशन ने रोलेट एक्ट का समर्थन किया था।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

Q21. भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा/से क्रांतिकारी संगठन था/थे?

1. अभिनव भारत
2. अनुशीलन समिति
3. भारतीय देशभक्त संघ
4. सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3

C..केवल 1 और 4 D. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: A

व्याख्या:

- **अभिनव भारत :** अभिनव भारत (यंग इंडिया सोसाइटी) एक गुप्त सोसाइटी थी जिसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाइयों गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर ने 1904 में नासिक में की थी। यह "मित्र मेला" नामक एक पुराने संगठन से उभरा था। इस सोसाइटी का उद्देश्य क्रांतिकारी तरीकों से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, तथा पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करना था। इसके सदस्य क्रांतिकारी साहित्य का प्रसार करने और सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाने सहित विभिन्न गतिविधियों में शामिल थे। उल्लेखनीय सदस्यों में अनंत लक्ष्मण कन्हेरे शामिल थे, जिन्होंने 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट ए.एम.टी. जैक्सन की हत्या की थी। इस संगठन का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव की भावना और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने की इच्छा को प्रेरित करना था। अभिनव भारत की गतिविधियों को अंततः ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दबा दिया गया था, लेकिन एक कट्टरपंथी राष्ट्रवादी समूह के रूप में इसकी विरासत भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बनी रही। इसलिए यह एक क्रांतिकारी संगठन था।

- **अनुशीलन समिति :** अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था जो 20वीं सदी की शुरुआत में बंगाल में उभरा था। इसका गठन विभिन्न स्थानीय युवा समूहों के विलय के माध्यम से किया गया था, जिसमें सतीश चंद्र बसु और प्रमथनाथ मित्रा जैसे प्रमुख लोगों ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समिति का उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष और क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। इसने बंगाल और भारत के अन्य हिस्सों में शाखाएँ स्थापित कीं, युवा क्रांतिकारियों की भर्ती और प्रशिक्षण दिया। उल्लेखनीय सदस्यों में अरबिंदो घोष, बरिंद्र कुमार घोष और जतिंद्रनाथ मुखर्जी (बाघा जतिन) शामिल थे। संगठन ने अलीपुर बम कांड और विभिन्न हत्या के प्रयासों सहित अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध के कई कार्यों में भाग लिया था। अनुशीलन समिति ने अपने सदस्यों को औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण, नैतिक शिक्षा और क्रांतिकारी विचारधारा पर जोर दिया। इसकी गतिविधियों ने भारतीय युवाओं में प्रतिरोध और बलिदान की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए यह क्रांतिकारी संगठन था।

- **इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन :** इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद ने की थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति-संगठन के रूप में स्थापित किया गया था, जिसके बारे में सर सैयद का मानना था कि इसमें हिंदू बंगालियों का वर्चस्व था और यह मुस्लिम हितों के लिए हानिकारक था। एसोसिएशन का उद्देश्य भारतीयों, विशेष रूप से मुसलमानों के बीच ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी को बढ़ावा देना और बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन का मुकाबला करना था। इसने मुस्लिम समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करने और ब्रिटिश शासन के ढांचे के भीतर उनकी शैक्षिक और सामाजिक उन्नति की वकालत करने की मांग की। एसोसिएशन की गतिविधियों में अपने ब्रिटिश समर्थक रुख को बढ़ावा देने के लिए पर्चे प्रकाशित करना और बैठकें आयोजित करना शामिल था। इसने मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होने से रोकने और ब्रिटिश प्रशासन के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम किया। इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन ने उस समय की जटिल राजनीतिक गतिशीलता और विभिन्न भारतीय समुदायों के बीच ब्रिटिश शासन के प्रति विविध प्रतिक्रियाओं को प्रतिबिंबित किया। इसलिए यह एक क्रांतिकारी संगठन नहीं था।

- **सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन :** सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1877 में सैयद अमीर अली और कलकत्ता के अन्य प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने की थी। इसका उद्देश्य भारत में मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक हितों का प्रतिनिधित्व करना था। संघ ने मुसलमानों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देने और ब्रिटिश शासन के ढांचे के भीतर उनके अधिकारों की वकालत करने की मांग की। इसने ब्रिटिश सरकार के सामने मुस्लिम चिंताओं और मांगों को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संघ ने शैक्षिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया, मुस्लिम शिक्षा को आधुनिक बनाने और उच्च शिक्षा तक पहुँच को बढ़ावा देने की मांग की। इसने सामाजिक मुद्दों को भी संबोधित किया, भारतीय समाज में मुसलमानों की स्थिति को सुधारने के लिए सुधारों की वकालत की। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन भारत में संगठित मुस्लिम राजनीतिक गतिविधि का एक प्रारंभिक उदाहरण था, जिसने बाद के मुस्लिम राजनीतिक संगठनों के लिए आधार तैयार किया। इस प्रकार यह एक क्रांतिकारी संगठन नहीं था। इसलिए यहाँ सही उत्तर विकल्प A है।

Q22. किन घटनाओं ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कलह के बीज बोये?

1. मुस्लिम लीग का गठन (1906)
2. बंगाल का विभाजन (1905)

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. असहयोग आंदोलन (1920)

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3

उत्तर: A

व्याख्या:

- **मुस्लिम लीग का गठन (1906) :** मुस्लिम लीग के गठन ने भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ते विभाजन में योगदान दिया। प्रारंभ में, इसका उद्देश्य मुस्लिम हितों की रक्षा करना था, लेकिन बाद में इसने भारत के विभाजन और 1947 में पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **बंगाल का विभाजन (1905) :** बंगाल के विभाजन के ब्रिटिश निर्णय को मुख्य रूप से बंगाली भाषी आबादी को धार्मिक आधार पर (हिंदू और मुस्लिम) विभाजित करने के प्रयास के रूप में देखा गया, जिससे भारतीयों में कलह और नाराजगी की तीव्र भावना पैदा हुई। इसने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया और इसे समुदायों के बीच विभाजन पैदा करने का सीधा प्रयास माना गया।
- **असहयोग आंदोलन (1920) :** लाला लाजपत राय जैसे नेताओं द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन, कलह पैदा करने के बजाय भारतीय आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच एकता को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। इसने महत्वपूर्ण रूप से कलह नहीं फैलाई बल्कि स्वशासन के लिए राष्ट्रवादियों को एकजुट करने का प्रयास किया। इस प्रकार, विकल्प A सही है।

Q23. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: होमरूल आंदोलन भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के एक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक था।

कथन II: होम रूल आंदोलन ने ब्रिटिश डोमिनियन की तर्ज पर स्वशासन की वकालत की।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

A. कथन I और कथन II दोनों सही हैं, और कथन II कथन I की सही व्याख्या है

B. कथन I और कथन II दोनों सही हैं, और कथन II कथन I का सही स्पष्टीकरण नहीं है

C. कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है

D. कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

उत्तर: A

व्याख्या:

- **कथन I सही है।** होमरूल आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व किया। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जैसे प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में, इस आंदोलन ने जनता को राजनीतिक भागीदारी के लिए एकजुट करके भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण की शुरुआत की। इसने ध्यान को पूरी तरह से संवैधानिक तरीकों से हटाकर लोकप्रिय लामबंदी पर केंद्रित कर दिया, जिसने पूरे भारत में राष्ट्रीय चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आंदोलन स्वशासन (स्वराज) के विचार को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण था और इसने भविष्य के जन आंदोलनों की नींव रखी।
- **कथन II सही है।** क्योंकि होमरूल आंदोलन ने वास्तव में स्वशासन के लिए एक विस्तृत एजेंडा सामने रखा था। विचार केवल सुधारों की मांग करना नहीं था, बल्कि सीमित स्व-शासन की एक प्रणाली का प्रस्ताव करना था, जहां भारत को अपने मामलों पर अधिक स्वायत्तता होगी लेकिन फिर भी वह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहेगा। इस आंदोलन ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों के समान भारत के लिए एक स्वशासी निकाय की स्थापना की वकालत की। होम रूल लीग को स्पष्ट रूप से औपनिवेशिक संरचना को चुनौती देने और एक वैकल्पिक दृष्टिकोण पेश करने के लिए डिज़ाइन किया गया था जहां भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर खुद पर शासन कर सकते थे। इसलिए, यहां सही उत्तर विकल्प A है।

Q24. स्वदेशी आंदोलन की विशेषता थी_

1. समितियों का संगठन
2. श्रमिक हड़ताल
3. राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 B. केवल 2

C. केवल 2 और 3 D. 1, 2 और 3

उत्तर: D

व्याख्या:

- स्वदेशी आंदोलन (1905-1908) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसका उद्देश्य विशेष रूप से ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना और भारतीय निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना था। यह 1905 में बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया थी और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय गौरव, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना था।
- **समितियों का संगठन :** स्वदेशी आंदोलन ने पूरे भारत में कई स्वदेशी समितियों (समितियों) का गठन देखा, जहाँ लोगों ने

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

विरोध प्रदर्शन आयोजित किए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और राष्ट्रीय एकता के लिए काम किया। इन समितियों ने आंदोलन को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- **श्रमिक हड़ताल :** इस आंदोलन के कारण श्रमिक हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों में वृद्धि हुई, खासकर उन उद्योगों में जहाँ श्रमिक ब्रिटिश नियोक्ताओं द्वारा खराब कामकाजी परिस्थितियों और शोषण के खिलाफ़ विरोध कर रहे थे। ये हड़तालें ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के खिलाफ़ आंदोलन के विरोध का एक अनिवार्य हिस्सा थीं।
- **राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना :** स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना को प्रेरित किया। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और अरबिंदो घोष जैसे नेताओं ने अंग्रेजों द्वारा थोपी गई पश्चिमी शैली की शिक्षा प्रणाली का मुकाबला करने के लिए स्वदेशी मूल्यों पर जोर देते हुए राष्ट्रवादी तरीके से शिक्षा को बढ़ावा दिया। अत: विकल्प D सही है।

Q25. कांग्रेस के उदारवादियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मांगें की गईं

1. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
2. शस्त्र अधिनियमों को निरस्त करना
3. स्थायी बंदोबस्त का विस्तार
4. सेना में भारतीयों के लिए उच्च नौकरियां

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3

C. केवल 3 और 4 D. 2, 3 और 4

उत्तर: D

व्याख्या:

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के उदारवादी चरण की विशेषता सुधारों के प्रति सतर्क दृष्टिकोण और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के ढांचे के भीतर क्रमिक परिवर्तनों की मांग थी। कांग्रेस के उदारवादियों द्वारा रखी गई प्रमुख मांगें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर केंद्रित थीं, जिनका उद्देश्य ब्रिटिश व्यवस्था के भीतर काम करते हुए भारतीय लोगों को लाभ पहुंचाना था।
- **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार :** इस अवधि के दौरान उदारवादियों ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग नहीं की। सार्वभौमिक मताधिकार का विचार, जहाँ सभी वयस्क लिंग, धन या शिक्षा की परवाह किए बिना मतदान कर सकते थे, उनके मंच में काफी हद तक अनुपस्थित था। यह मांग बहुत बाद में आई, खासकर अधिक कट्टरपंथी तत्वों के उदय और गांधीवादी युग के प्रभाव के बाद। इस प्रकार, कथन 1 गलत है क्योंकि यह उदारवादियों की मांग नहीं थी।
- **शस्त्र अधिनियम को निरस्त करना :** उदारवादी चरण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण मांगों में से एक शस्त्र अधिनियम (1878) को निरस्त करना था, जिसे भेदभावपूर्ण और दमनकारी माना जाता था। इसने भारतीयों के हथियार रखने और ले जाने के अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया, जिससे उन्हें खुद का बचाव करने से रोका गया। उदारवादियों ने इस कानून को निरस्त करने की मांग की, इसे औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतीय आबादी को निरस्त्र करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पीड़न के उपकरण के रूप में देखा। कथन 2 सही है, क्योंकि इस चरण के दौरान शस्त्र अधिनियम को निरस्त करना एक प्रमुख मांग थी।
- **स्थायी बंदोबस्त का विस्तार :** स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, जिसे मूल रूप से 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू किया गया था, को कई लोगों ने जमींदारों (भूमि मालिकों) के लिए फायदेमंद माना था। उदारवादियों ने इस प्रणाली को भारत के अन्य हिस्सों में विस्तारित करने की वकालत की, उनका मानना था कि यह भूस्वामियों को सुरक्षित संपत्ति अधिकार प्रदान करके कृषि अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करेगा। सार्वभौमिक रूप से समर्थित नहीं होने के बावजूद, उदारवादियों ने इसे भारतीय भूस्वामियों को लाभ पहुंचाने और भारतीयों के हाथों में भूमि राजस्व संग्रह पर अधिक नियंत्रण लाने के तरीके के रूप में देखा। उस समय, अधिकांश उच्च सैन्य पदों पर ब्रिटिश अधिकारी थे, जबकि भारतीय बड़े पैमाने पर निचले रैंक तक ही सीमित थे। सेना में अधिक से अधिक भारतीयों की भागीदारी की मांग को भारतीयों को सशक्त बनाने और औपनिवेशिक प्रशासन के भीतर नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा गया। कथन 4 सही है, क्योंकि उदारवादियों ने सेना में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सुधारों की मांग की थी।

Q26. निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें:

क्र सं	स्वतंत्रता सेनानी	संबद्ध ब्रिटिश व्यक्तित्व	वर्ष
1.	मदन लाल ढींगरा	कर्जन वायली	1909
2.	उधम सिंह	माइकल ओ ड्वायर	1939
3.	लाला हरदयाल	जॉन सॉन्डर	1930

उपरोक्त पंक्तियों में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही से सुमेलित है?

A. केवल एक B. सिर्फ दो

C. तीनों D. इनमे से कोई भी नहीं।

उत्तर: B

व्याख्या:

- **युग्म 1 सही है।** एक प्रमुख क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई, 1909 को लंदन में कर्जन वायली की हत्या कर दी। कर्ज़न वायली भारत में औपनिवेशिक प्रशासन से जुड़े एक ब्रिटिश अधिकारी थे और ढींगरा उन्हें ब्रिटिश अत्याचार के प्रतिनिधि के रूप में देखते थे। ढींगरा के कृत्य को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए सीधी चुनौती माना गया और उनके कार्यों के लिए उन्हें 17 अगस्त, 1909 को फाँसी दे दी गई।

- **युग्म 2 सही है।** उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओ'डायर की हत्या कर दी। ओ'डायर 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिसके कारण सैकड़ों निहत्थे भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। उधम सिंह की हत्या बदले की कार्रवाई और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक बयान था। जबकि हत्या 1940 में हुई थी, 1939 को कभी-कभी ऐतिहासिक संदर्भों में उद्धृत किया जाता है, जिसमें हमले से पहले के व्यापक राजनीतिक माहौल का जिक्र होता है, क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले के महीनों में हुआ था।

- **युग्म 3 गलत है।** प्रखर बुद्धि और क्रांतिकारी उत्साह की छवि वाले लाला हर दयाल 1884 में दिल्ली के मध्य से उभरे, जिनका उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की नींव को चुनौती देना था। उनकी आरंभिक शैक्षणिक प्रतिभा, जिसकी परिणति ऑक्सफोर्ड में अध्ययन के रूप में हुई, ने भारत की स्वतंत्रता के प्रति प्रबल जुनून को नकार दिया। पारंपरिक रास्ते को छोड़कर, वह क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की तूफानी दुनिया में कूद पड़े और 1913 में गदर पार्टी के पीछे एक महत्वपूर्ण ताकत बन गए। संयुक्त राज्य अमेरिका की उपजाऊ जमीन से, उन्होंने पार्टी के प्रभावशाली समाचार पत्र, "गदर" के माध्यम से विद्रोह के बीज बोए, जिससे भारतीय प्रवासियों के बीच प्रतिरोध की ज्वाला भड़क उठी। एक विद्वान और लेखक, उन्होंने शब्दों की शक्ति को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, उनके तर्कवादी और मानवतावादी दर्शन ने स्वतंत्रता की उनकी निरंतर खोज को बढ़ावा दिया। हालाँकि उनके जीवन को निर्वासन और अथक वकालत से चिह्नित किया गया था, लेकिन उनका प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भीतर गहराई से प्रतिबिंबित हुआ, जिससे बौद्धिक विद्रोह और स्वतंत्रता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की विरासत छूट गई।

- 1928 में, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी. सॉन्डर्स को अधीक्षक जेम्स स्कॉट समझकर उनकी हत्या कर दी। यह कृत्य लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध था, जो एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में घायल हो गये थे। यह हत्या, लाहौर षडयंत्र मामले की एक प्रमुख घटना थी, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा दिया। अंततः, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्रांतिकारी प्रतिरोध के प्रतीक बनकर उनके कार्यों के लिए फाँसी दे दी गई। इसलिए, यहां सही उत्तर विकल्प B है।

Q27. निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

क्रम संख्या	संगठन	संबंधित व्यक्तित्व
1.	इंडियन लीग	शिशिर कुमार घोष
2.	इंडियन एसोसिएशन	आनंद मोहन बोस
3.	मद्रास मूलनिवासी संघ	गजुलु लक्ष्मीनरसु चेट्टी
4.	ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन	केशव चंद्र सेन

उपरोक्त पंक्तियों में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही ढंग से मेल खाती है?

A. केवल एक B. सिर्फ दो

C. केवल तीन D. चारों

उत्तर: C

व्याख्या:

- **युग्म 1 सही है।** इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। लीग ने प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश प्रशासन में भारतीयों के अधिक प्रतिनिधित्व की वकालत की। सिसिर कुमार घोष और सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीतिक अधिकारों की दिशा में काम करने के लिए शिक्षित भारतीयों को एकजुट करने की मांग की थी। इंडियन लीग की गतिविधियों ने बाद के वर्षों में और अधिक कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलनों के गठन में योगदान दिया।

- **युग्म 2 सही है।** आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ, 1876 में इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। इंडियन एसोसिएशन एक प्रमुख राजनीतिक संगठन था जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने ब्रिटिश व्यवस्था के भीतर भारतीय अधिकारों, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक सुधारों के मुद्दों को उठाने की मांग की। आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन के एक प्रमुख व्यक्ति होने के नाते, इसकी गतिविधियों में गहराई से शामिल थे, उन्होंने अलग-अलग समय पर इसके सचिव और अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इस एसोसिएशन ने भारत में राजनीतिक कार्रवाई के भविष्य की नींव रखी, खासकर जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) का विकास इसी से हुआ।

- **युग्म 3 सही है।** 1852 में स्थापित मद्रास नेटिव एसोसिएशन (एमएनए) ने मद्रास प्रेसीडेंसी के उभरते भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। गज़ुलु लक्ष्मीनारासु चेट्टी जैसी शख्सियतों द्वारा स्थापित, यह ब्रिटिश

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

शासन के तहत स्थानीय आबादी की शिकायतों को उठाने के लिए समर्पित एक अग्रणी संगठन के रूप में उभरा। एमएनए ने दमनकारी राजस्व नीतियों से लेकर शैक्षिक सुधारों और बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए सरकार से अथक याचिका दायर की। हालांकि इसका जीवन काल अपेक्षाकृत संक्षिप्त था, 1860 के दशक के अंत तक आंतरिक कलह और गति कम होने के कारण, इसका प्रभाव गहरा था। इसने भविष्य के राजनीतिक आंदोलनों के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार किया, सामूहिक आवाज की भावना पैदा की और संगठित वकालत की शक्ति का प्रदर्शन किया। एमएनए की विरासत एक उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका में है, जो राजनीतिक चेतना की चिंगारी को प्रज्वलित करती है और आने वाले अधिक संरचित और व्यापक राष्ट्रवादी आंदोलनों के लिए मंच तैयार करती है।

- **युग्म 4 गलत है।** ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन सीधे तौर पर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से जुड़े नहीं थे। 1851 में स्थापित ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन (बीआईए) एक प्रारंभिक राजनीतिक संगठन था जो ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारतीय हितों का प्रतिनिधित्व करता था। इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर और राजा राममोहन रॉय (अन्य लोगों के बीच) ने की थी, केशव चंद्र सेन ने नहीं। केशव चंद्र सेन एक सुधारवादी थे और उन्होंने ब्रह्म समाज में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सुधारों पर केंद्रित एक आंदोलन था। हालाँकि वह भारतीय अधिकारों और सुधारों की वकालत में सक्रिय थे, लेकिन उनका काम सीधे तौर पर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से जुड़ा नहीं था।

Q28. निम्नलिखित कथन पर विचार करें

1. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सदस्य थे।
2. राजेंद्र प्रसाद 1946 की अंतरिम सरकार में मंत्री थे।
3. राजेंद्र प्रसाद ने अधिक भोजन उगाओ नारे को लोकप्रिय बनाया।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3

उत्तर: D

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। उन्हें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान उनका नेतृत्व महत्वपूर्ण था, और भारतीय लोकतंत्र के प्रति उनकी बुद्धिमत्ता और समर्पण का व्यापक रूप से सम्मान किया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत के शासन ढांचे को आकार देने पर चर्चा में वह सबसे आगे थे, जो इस कथन को सटीक बनाता है।
- **कथन 2 सही है।** 1946 के कैबिनेट मिशन के बाद, जिसके कारण अंतरिम सरकार का गठन हुआ, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अंतरिम सरकार भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि इसका गठन स्वतंत्रता से पहले देश के मामलों का प्रबंधन करने के लिए किया गया था। अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद की भूमिका महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्होंने विभाजन और स्वतंत्रता की चुनौतियों से जूझ रहे देश में खाद्य सुरक्षा और कृषि सुधारों पर काम किया था। चुनौतीपूर्ण समय के दौरान खाद्य आपूर्ति के प्रबंधन में उनके योगदान ने सार्वजनिक सेवा में उनकी विरासत को और मजबूत किया, जिससे इस कथन की सच्चाई की पुष्टि हुई।
- **कथन 3 सही है।** भारत के राष्ट्रपति के रूप में, राजेंद्र प्रसाद ने कृषि विकास को बढ़ावा देने और स्वतंत्रता के बाद शुरुआती वर्षों में भारत द्वारा सामना की जाने वाली भोजन की कमी को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाई। "अधिक भोजन उगाओ" अभियान एक ऐसी पहल थी जिसका उन्होंने कृषि उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए पुरजोर समर्थन किया था। यह नारा यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया कि भारत भोजन में आत्मनिर्भरता हासिल कर सके। नारे को लोकप्रिय बनाने के उनके प्रयासों ने किसानों को खाद्य उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से उस भोजन की कमी को देखते हुए जो देश स्वतंत्रता और विभाजन के बाद अनुभव कर रहा था।

Q29. भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की पूर्व संध्या पर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. सरकारी कर्मचारियों से कांग्रेस के प्रति निष्ठा दिखाने को कहा।
2. सैनिकों से अपने ही लोगों पर गोली चलाने से इंकार करने को कहा गया।
3. रियासतों से अपने लोगों की संप्रभुता स्वीकार करने को कहा।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 B. केवल 2

C. केवल 1 और 3 D. 1,2 और 3

उत्तर: D

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

सभी भारतीयों से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उठने का आह्वान किया, और हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन मुख्य रूप से एक जन आंदोलन था, फिर भी सरकारी कर्मचारियों से ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने से इनकार करने और भारतीय हितों का समर्थन करने का आह्वान किया गया। कई सरकारी अधिकारियों को इस्तीफा देने या औपनिवेशिक प्रशासन के लिए काम जारी रखने से इनकार करने के लिए कहा गया।

- **कथन 2 सही है।** भारत छोड़ो आंदोलन में गांधीजी का आह्वान ब्रिटिश सेना के सैनिकों से था कि वे अपने ही लोगों पर गोली चलाने से इनकार करें। यह उनकी व्यापक अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा रणनीति का एक हिस्सा था। गांधीजी का मानना था कि यदि सैनिक अपने ब्रिटिश कमांडरों के बजाय भारत के लोगों के प्रति वफादार होंगे, तो औपनिवेशिक शासन ध्वस्त हो जाएगा। वह चाहते थे कि सैनिक राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को पहचानें और उन आदेशों का पालन न करें जिनका उद्देश्य अपने साथी भारतीयों पर अत्याचार करना था।

- **कथन 3 सही है।** भारत छोड़ो आंदोलन के हिस्से के रूप में, गांधी और कांग्रेस नेतृत्व ने रियासतों को भारतीय लोगों की संप्रभुता को पहचानने और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया। रियासतें अभी भी ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन थीं लेकिन उनके अपने शासक थे। कांग्रेस चाहती थी कि ये राज्य ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त हो जाएं और भारतीय लोगों की स्वशासन की मांग के साथ जुड़ जाएं।

Q30. उत्तर उत्तरमेरुर शिलालेख का सार निम्नलिखित में निहित है

A. चोल काल में स्थानीय स्वशासन का विवरण।

B. सेन साम्राज्य का गौरव।

C. विजयनगर साम्राज्य का इतिहास।

D. होयसल साम्राज्य का स्थापत्य गौरव।

उत्तर: A

व्याख्या:

- उत्तरमेरुर शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजों में से एक है जो चोल काल के दौरान स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर गहराई से नज़र डालता है। इसे वैकुंडा पेरुमल मंदिर की दीवारों पर उकेरा गया है और इसमें सभा या ग्राम सभा के कामकाज का विवरण है, जो स्थानीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार थी। शिलालेख में बताया गया है कि सभा के लिए सदस्यों का चयन कैसे किया जाता था, उनकी योग्यताएँ और उनकी भूमिकाएँ और जिम्मेदारियां क्या थीं। यह लॉटरी के माध्यम से प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया और पात्रता के लिए विशिष्ट मानदंडों को रेखांकित करता है, जिसमें भूमि स्वामित्व, आयु और वैदिक ग्रंथों का ज्ञान शामिल है। शिलालेख में सभा के भीतर विभिन्न विशेष समितियों पर भी प्रकाश डाला गया है, जैसे कि उद्यान समिति, टैंक समिति और वार्षिक समिति, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट कार्यों के लिए जिम्मेदार थी। इस प्रकार, विकल्प A सही है।

Q31. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन-I: नमक आंदोलन एम.के. गांधी द्वारा शुरू किया गया था।

कथन-II: एम.के. गांधी का उद्देश्य सभी गरीब लोगों को नमक मुफ्त उपलब्ध कराना था।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

A. कथन I और कथन II दोनों सही हैं, और कथन II कथन I की सही व्याख्या है।

B. कथन I और कथन II दोनों सही हैं, और कथन II कथन I का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

C. कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

D. कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

उत्तर: C

व्याख्या:

- **कथन I सही है।** नमक मार्च, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, वास्तव में 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। यह ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ एक प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान था। गांधी और उनके अनुयायी साबरमती आश्रम से 240 मील से अधिक पैदल चलकर तटीय गांव दांडी तक पहुंचे, जहां उन्होंने समुद्री जल को वाष्पित करके अपना नमक बनाया, ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन किया, जिन्होंने भारतीयों को अपना नमक बनाने से रोक दिया था। यह मार्च भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अहिंसक प्रतिरोध का प्रतीक था।

- **कथन II गलत है।** जबकि गांधी का विरोध नमक कर पर केंद्रित था, उनका प्राथमिक लक्ष्य गरीबों को मुफ्त में नमक उपलब्ध कराना नहीं था। इसके बजाय, यह अन्यायपूर्ण ब्रिटिश नमक कानूनों को चुनौती देने के लिए था, जिसने गरीबों को अंग्रेजों से ऊंची कीमतों पर नमक खरीदने के लिए मजबूर करके उन पर आर्थिक बोझ डाला। गांधी का उद्देश्य ऐसी बुनियादी आवश्यकता पर ब्रिटिश अधिकार की अवैधता को प्रदर्शित करना और भारतीय आबादी को अपना स्वयं का नमक बनाकर सविनय अवज्ञा में शामिल होने के लिए प्रेरित करना था, जिससे ब्रिटिश नियंत्रण को चुनौती दी जा सके। नमक उत्पादन का कार्य अंग्रेजों के साथ आत्मनिर्भरता और असहयोग का प्रतीक था, न कि गरीबों को सीधे नमक उपलब्ध कराने का था।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

Q32. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (सीएसपी) की स्थापना और विचारधारा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

1. सीएसपी की स्थापना 1934 में कांग्रेस सदस्यों द्वारा की गई थी, जिन्होंने गांधी के रहस्यवाद और कांग्रेस के प्रति भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांप्रदायिक रवैये दोनों को खारिज कर दिया था।
2. सीएसपी ने विशेष रूप से अपने समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में सशस्त्र संघर्ष की वकालत की।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: A

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (सीएसपी) की स्थापना 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक गुट के रूप में हुई थी। इसके संस्थापक वे सदस्य थे जो कांग्रेस के भीतर प्रचलित विचारधाराओं, विशेष रूप से गांधीवादी सिद्धांतों पर जोर से मोहभंग कर रहे थे, जिसे वे तर्कसंगत विरोधी और अत्यधिक रहस्यमय मानते थे। वे सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर अधिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण चाहते थे, जिसका उन्हें लगा कि गांधी के दर्शन में इसका अभाव है। इसके अतिरिक्त, सीएसपी कांग्रेस के प्रति भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांप्रदायिक और हठधर्मी दृष्टिकोण की आलोचना करती थी, जिसके बारे में उनका मानना था कि इसने व्यापक राष्ट्रवादी आंदोलन में संभावित सहयोगियों को अलग-थलग कर दिया है। सीएसपी का लक्ष्य एक अधिक समावेशी मंच तैयार करना है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समग्र लक्ष्यों के साथ जुड़े रहते हुए श्रमिक वर्ग की आकांक्षाओं को संबोधित करेगा।
- **कथन 2 गलत है।** सीएसपी में ऐसे सदस्य शामिल थे जो समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में सशस्त्र संघर्ष या तोड़फोड़ का समर्थन करते थे, लेकिन इसने विशेष रूप से इस दृष्टिकोण की वकालत नहीं की। पार्टी अपनी रणनीतियों में विविध थी और इसमें आचार्य नरेंद्र देव जैसे प्रमुख नेता शामिल थे जिन्होंने अहिंसक प्रतिरोध और लोकतांत्रिक समाजवाद पर जोर दिया था। सीएसपी का उद्देश्य अहिंसा और लोकतांत्रिक जुड़ाव के सिद्धांतों के साथ क्रांतिकारी कार्रवाई की आवश्यकता को संतुलित करते हुए विभिन्न युक्तियों को संयोजित करना था। उनकी विचारधारा मार्क्सवाद और फेबियनवाद दोनों से प्रभावित थी, जिसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई तरीकों की अनुमति दी, जिसमें राजनीतिक भागीदारी, जमीनी स्तर पर लामबंदी और सहकारी समितियों और ट्रेड यूनियनों की स्थापना शामिल थी। इस प्रकार, यह धारणा कि सीएसपी ने विशेष रूप से सशस्त्र संघर्ष की वकालत की है, इसकी विचारधारा और रणनीतियों की जटिलता का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

Q33. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सूबेदार खान लोदी ने पांडिचेरी में फ्रांसिस मार्टिन को भूमि हस्तांतरित कर दी।
2. औरेंग्जेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने के लिए फरमान जारी किया।
3. एंग्लो-मैसूर युद्ध के बाद मैसूर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 B. केवल 2
C. केवल 1 और 3 D. 1,2 और 3

उत्तर: D

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** बीजापुर के सुल्तान के अधीन वालिकंदपुरम के शासक शेर खान लोदी ने 1673 में फ्रांसीसियों को जमीन दी, जिसका उपयोग एक बस्ती स्थापित करने के लिए किया गया जो अंततः पांडिचेरी का फ्रांसीसी उपनिवेश बन गया। फ्रांसीसी भारत के पहले गवर्नर-जनरल फ्रांकोइस मार्टिन ने पांडिचेरी को एक संपन्न बंदरगाह शहर के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें अक्सर "पुडुचेरी के पिता" के रूप में जाना जाता है।
- **कथन 2 सही है।** औरंगजेब ने वास्तव में 1691 में एक फरमान (शाही फरमान) जारी किया था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कर या सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। जबकि बयान में "ब्रिटिश इंडिया कंपनी" का उल्लेख है, यह आम तौर पर समझा जाता है कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को संदर्भित करता है।
- **कथन 3 सही है।** चौथे आंग्ल-मैसूर युद्ध (1798-1799) के बाद, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान, सेरिंगपट्टम की घेराबंदी के दौरान मारे गए और अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने वाडियार परिवार को मैसूर के सिंहासन पर बहाल कर दिया, लेकिन प्रभावी रूप से राज्य पर नियंत्रण कर लिया और इसे ब्रिटिश संरक्षित राज्य में बदल दिया।

Q34. क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है/हैं?

1. क्रिप्स के मिशन में भारतीय समेत दस सदस्य शामिल थे।
2. क्रिप्स मिशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध को हल करने में विफल रहा।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. क्रिप्स के भारत मिशन की असफलता के बाद गांधीजी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3

C. 1, 2 और 3 D. केवल 1 और 3

उत्तर: B

व्याख्या:

- **कथन 1 गलत है।** क्रिप्स मिशन, जिसका नेतृत्व स्टैफ़ोर्ड क्रिप्स ने किया था, में केवल ब्रिटिश सदस्य शामिल थे। यह 1942 में चल रहे द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन के लिए भारतीय राजनीतिक नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए भारत भेजा गया एक ब्रिटिश मिशन था। मिशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था. क्रिप्स को भारत के लिए संवैधानिक सुधारों और युद्धोत्तर योजनाओं पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था, लेकिन मिशन में भारतीय प्रतिनिधियों को अपनी टीम में शामिल नहीं किया गया था।

- **कथन 2 सही है।** क्रिप्स मिशन का उद्देश्य युद्ध के बाद स्वशासन के वादों के बदले युद्ध प्रयासों में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करना था। हालाँकि, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की दूरी को पाटने में विफल रही। कांग्रेस ने प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने तत्काल स्व-शासन की मांग की और ब्रिटिश प्रस्ताव को अपर्याप्त पाया। इस बीच, जिन्ना की मुस्लिम लीग को भी लगा कि प्रस्ताव मुस्लिम मांगों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करते हैं, खासकर पाकिस्तान के निर्माण के संबंध में। परिणामस्वरूप, मिशन भारत में दो प्रमुख राजनीतिक समूहों के बीच गतिरोध को तोड़ने में विफल रहा।

- **कथन 3 सही है।** भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगों को संबोधित करने में क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद, गांधी और कांग्रेस नेतृत्व ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। आंदोलन ने भारत से ब्रिटिशों की तत्काल वापसी का आह्वान किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा तत्काल स्वतंत्रता की पेशकश करने से इनकार करने से गांधी बहुत निराश थे, उनका मानना था कि अब भारत के लिए अपनी स्वतंत्रता की मांग करने का समय आ गया है। भारत छोड़ो आंदोलन एक सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना था, हालांकि इसे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गंभीर दमन का सामना करना पड़ा था।

Q35. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत सरकार अधिनियम (1935) एक संघीय व्यवस्था का प्रावधान करता है।
2. अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना 1937 में हुई थी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों D. इनमे से कोई भी नहीं

उत्तर: A

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने भारत में संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी। इस अधिनियम ने संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा, जिसमें केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। इसने एक ऐसी प्रणाली बनाई जिसमें प्रांतों को कुछ शक्तियाँ दी गईं जबकि अन्य केंद्र सरकार के पास रहीं। हालाँकि, यह प्रणाली एक पूर्ण संघीय प्रणाली के बजाय एक केंद्रीकृत संघवाद की तरह थी, जिसमें अंग्रेजों ने भारतीय शासन पर महत्वपूर्ण नियंत्रण बनाए रखा।

- **कथन 2 गलत है।** 1935 के भारत सरकार अधिनियम में अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान था, लेकिन वास्तव में इसे कभी स्थापित नहीं किया गया। अधिनियम में प्रांतों और रियासतों से मिलकर अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रस्ताव था, लेकिन रियासतों के विरोध और राजनीतिक मुद्दों के कारण संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। अधिनियम में संघ का विचार तो रखा गया था, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया।

Q36. मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

A. वल्लभाचार्य ने पुष्टिमार्ग सम्प्रदाय की स्थापना की।

B. रामानंद ने भगवान राम को समर्पित रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की।

C. द्वैत दर्शन को माधवाचार्य ने बढ़ावा दिया, जो व्यक्तिगत आत्मा और ईश्वर के द्वैत पर जोर देता है।

D. वारकरी पंथ उत्तर प्रदेश में भगवान शिव को समर्पित एक भक्ति परंपरा है।

उत्तर: D

व्याख्या:

- **विकल्प A सही है।** पुष्टिमार्ग संप्रदाय, वल्लभाचार्य द्वारा 1500 ई. के आसपास स्थापित एक वैष्णव संप्रदाय है, जो शुद्ध, प्रेमपूर्ण भक्ति (भक्ति) के दर्शन के माध्यम से भगवान कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित है। अनुयायी एक ही ब्रह्म के रूप में परम सत्य में विश्वास करते हैं और कृष्ण की व्यक्तिगत मूर्ति के प्रति सेवा (निस्वार्थ सेवा) के माध्यम से अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। यह मार्ग देवता के साथ एक अंतरंग, व्यक्तिगत संबंध पर जोर देता है, जो बिना शर्त प्रेम और श्रद्धा पर आधारित है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **विकल्प B सही है।** अद्वैत विद्वान रामानंद की शिक्षाओं पर आधारित रामानंदी संप्रदाय हिंदू धर्म के भीतर सबसे बड़ा मठवासी समूह है। ये वैष्णव भिक्षु, जिन्हें रामानंदी, वैरागी या बैरागी के नाम से जाना जाता है, भगवान राम, विष्णु के अवतार की पूजा के लिए समर्पित हैं। अपने सख्त तपस्वी अभ्यास और ध्यान के लिए जाने जाने वाले, वे मुक्ति (मोक्ष) प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय कृपा के महत्व पर भी जोर देते हैं। मुख्य रूप से गंगा के मैदानों में स्थित, रामानंदी संप्रदाय के दो उपसमूह हैं: त्यागी, जो त्याग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और नागा, जो योद्धा तपस्वी हैं।

- **विकल्प C सही है।** 13वीं शताब्दी में दार्शनिक-संत माधवाचार्य द्वारा स्थापित ब्रह्म संप्रदाय एक वैष्णव परंपरा है जो भगवान विष्णु को सर्वोच्च प्राणी या परब्रह्म के रूप में पूजती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के ब्रह्मा देवता के विपरीत, यहाँ "ब्रह्मा" विष्णु को ब्रह्मांड के सार्वभौमिक निर्माता और पालनकर्ता के रूप में संदर्भित करता है। माधवाचार्य की शिक्षाओं ने द्वैत (द्वैतवाद) पर जोर दिया, एक ऐसा दर्शन जो पहले के स्कूलों द्वारा सिखाए गए अद्वैतवाद के विपरीत व्यक्तिगत आत्मा (जीव) और ईश्वर (ब्रह्म) के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करता है। अनुयायियों का मानना है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान की सेवा करना और उन्हें प्राप्त करना है, जिसे विष्णु के प्रति अटूट भक्ति (भक्ति) के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

- **विकल्प D गलत है।** वारकरी संप्रदाय या वारकरी पंथ महाराष्ट्र में भगवान विठोबा को समर्पित एक भक्ति परंपरा है, जो विष्णु का एक रूप है, जिसकी पूजा पंढरपुर में विठोबा के मंदिर के आसपास केंद्रित है। शराब और तम्बाकू से परहेज़ करने के लिए जाने जाने वाले वारकरी हर साल वारी नामक तीर्थयात्रा करते हैं, जहाँ भक्त विभिन्न समाधि स्थलों से पंढरपुर तक जुलूस (पालकी) में संतों की पादुकाएँ (पवित्र पदचिह्न) ले जाते हैं। इस तीर्थयात्रा के दौरान रिंगन और धव जैसे अनोखे आयोजन होते हैं; रिंगन में, एक पवित्र घोड़ा तीर्थयात्रियों की पंक्तियों के बीच से गुजरता है, जो उड़ी हुई धूल को आशीर्वाद के रूप में इकट्ठा करते हैं और लिखते हैं। इस परंपरा के प्रमुख संतों में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम शामिल हैं, जिन्होंने उनकी भक्ति और दार्शनिक शिक्षाओं में बहुत योगदान दिया।

Q37. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रथम आंग्ल-बर्मा युद्ध के बाद असम और मणिपुर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए।
2. 1816 में सुगौली की संधि के बाद कुमाऊं क्षेत्र ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया।
3. सिक्किम 1770 में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के तहत एक रियासत बन गया।
4. 1750 में सिंध पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2,3 और 4
C. केवल 1,2, और 3 D. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: A

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** प्रथम आंग्ल-बर्मा युद्ध (1824-1826) 1826 में यंडाबो की संधि के साथ समाप्त हुआ। संधि के हिस्से के रूप में, बर्मा (अब म्यांमार) को असम और मणिपुर पर अपने दावे छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, जिन्हें बाद में ब्रिटिश नियंत्रण में लाया गया था। इन क्षेत्रों को ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र बना दिया गया था, हालांकि इन्हें तुरंत शामिल नहीं किया गया था। इस संधि ने इन क्षेत्रों पर ब्रिटिश प्रभाव को मजबूत किया, जिससे ब्रिटिश भारत में उनके अंतिम विलय के लिए मंच तैयार हुआ।

- **कथन 2 सही है।** एंग्लो-नेपाली युद्ध (1814-1816) के बाद, 1816 में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। संधि के हिस्से के रूप में, नेपाल को कुमाऊं और गढ़वाल सहित बड़े क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। ये क्षेत्र, जो पहले नेपाल का हिस्सा थे, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सीधे नियंत्रित किए गए, इस प्रकार ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गए।

- **कथन 3 गलत है।** सिक्किम 1890 से पहले कुछ समय के लिए ब्रिटिश संरक्षित राज्य था, 1861 में टिटालिया की संधि के बाद ब्रिटिश प्रभाव बढ़ गया था। हालांकि, 1890 में सिक्किम को औपचारिक रूप से ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के भीतर एक रियासत के रूप में मान्यता दी गई थी। इसका मतलब यह था कि जहां इसने एक स्थानीय शासक को बनाए रखा, वहीं ब्रिटिश ने इसके विदेशी मामलों और रक्षा को नियंत्रित किया।

- **कथन 4 गलत है।** 1843 में, मिआनी की लड़ाई के बाद, अंग्रेजों ने वर्तमान पाकिस्तान के एक क्षेत्र सिंध पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने सिंध के नवाब नासिर खान की सेना को हरा दिया और परिणामस्वरूप, सिंध को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। सिंध पर कब्जा करने से भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण विस्तार हुआ।

Q38. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन-I: 1887 में भारत के सामाजिक सम्मेलन की स्थापना कुछ प्रमुख कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई थी।

कथन-II: प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

A. कथन I और कथन II दोनों सही हैं, और कथन II कथन I की सही व्याख्या है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

B. कथन I और कथन II दोनों सही हैं, और कथन II कथन I का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

C. कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

D. कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

उत्तर: B

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** भारतीय सामाजिक सम्मेलन (आईएससी) की स्थापना 1887 में एम.जी. जैसे प्रमुख सुधारकों द्वारा की गई थी। रानाडे और रघुनाथ राव। दोनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के प्रभावशाली सदस्य थे। हालाँकि, उन्होंने विशेष रूप से सामाजिक सुधारों के लिए समर्पित एक अलग मंच की आवश्यकता देखी, जो उन्हें लगा कि कांग्रेस के राजनीतिक फोकस में उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। इस प्रकार आईएससी की स्थापना जातिगत भेदभाव, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह और अन्य सामाजिक बुराइयों जैसे सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए की गई थी।

- **कथन 2 सही है।** जब 1885 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, तो इसका प्राथमिक ध्यान राजनीतिक सुधारों और भारत के लिए स्व-शासन की मांग पर था। सामाजिक मुद्दे, हालांकि कुछ सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण थे, उस समय कांग्रेस का केंद्रीय फोकस नहीं थे। कांग्रेस के प्रारंभिक नेतृत्व का मानना था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक एकता आवश्यक थी और उन्हें डर था कि विभाजनकारी सामाजिक मुद्दे इस एकता को नुकसान पहुँचा सकते हैं। परिणामस्वरूप, सामाजिक सुधार आंदोलनों को कांग्रेस के एजेंडे में शामिल नहीं किया गया, जिससे उन चिंताओं को दूर करने के लिए एक मंच के रूप में भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना हुई।

Q39. भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषताओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. ह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था।
2. यह पूर्णतः अहिंसक आन्दोलन था।
3. भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले बंबई में शुरू किया गया था।
4. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कर्नाटक पद्धति प्रसिद्ध थी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3

C. केवल 1, 3 और 4 D. केवल 1, 2 और 4

उत्तर: C

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** भारत छोड़ो आंदोलन काफी हद तक स्वतःस्फूर्त प्रकृति का था। हालांकि गांधी और कांग्रेस नेतृत्व ने आंदोलन का आह्वान किया, लेकिन इसने पूरे देश में तेजी से गति पकड़ ली क्योंकि विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों ने विरोध प्रदर्शन और सविनय अवज्ञा में भाग लिया। यह आंदोलन औपचारिक संगठन के बिना तेजी से फैल गया, खासकर गांधी के "करो या मरो" के आह्वान के बाद।

- **कथन 2 गलत है।** भारत छोड़ो आंदोलन एक अहिंसक संघर्ष के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन व्यवहार में यह पूरी तरह से अहिंसक नहीं था। ब्रिटिश प्रतिक्रिया कठोर थी और विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा की घटनाएं हुईं। कई प्रदर्शनकारियों की ब्रिटिश पुलिस से झड़प हुई और तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को नष्ट करने की खबरें आईं। इसलिए, हालाँकि गांधीजी ने अहिंसा की वकालत की, लेकिन आंदोलन में हिंसक तत्व भी थे।

- **कथन 3 सही है।** भारत छोड़ो आंदोलन औपचारिक रूप से गांधी द्वारा 8 अगस्त, 1942 को गोवालिया टैंक मैदान, बॉम्बे (अब मुंबई) में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में शुरू किया गया था। यह आंदोलन की आधिकारिक शुरुआत थी.

- **कथन 4 सही है।** कर्नाटक पद्धति संगठित, अनुशासित और अहिंसक विरोध प्रदर्शन को संदर्भित करती है जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कर्नाटक में प्रसिद्ध रूप से नियोजित थे। केंगल हनुमंथैया और अन्य स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में, कर्नाटक के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन, हड़ताल और विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। कर्नाटक पद्धति के प्रमुख तत्वों में से एक हड़ताल (हड़ताल) और बहिष्कार करने के लिए जन लामबंदी का उपयोग था। यह क्षेत्र सत्याग्रह (अहिंसक प्रतिरोध) का केंद्र बन गया, स्थानीय जनता सक्रिय रूप से विरोध प्रदर्शनों और सविनय अवज्ञा में भाग लेने लगी।

Q40. ब्रिटिश प्रशासन और शिक्षा नीतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा शिक्षा के लिए धन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था।
2. व्हिटली आयोग 1929 ने उच्च शिक्षा के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषण की सिफारिश की।
3. वुड्स डिस्पैच का उद्देश्य भारत में साक्षरता को बढ़ावा देना था।
4. एलफिंस्टन कॉलेज की स्थापना 1835 में दादाभाई नौरोजी के सहयोग से की गई थी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 3 B. केवल 1, 2 और 3

C. 1, 2, 3 और 4 D. केवल 2,3 और 4

उत्तर: B

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** 1813 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था। यह पहली बार हुआ कि भारत में ब्रिटिश सरकार ने विशेष रूप से शिक्षा के लिए धन आवंटित किया। अधिनियम ने भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार के प्राथमिक उद्देश्य के साथ, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ₹1 लाख के आवंटन की अनुमति दी। यह शिक्षा में राज्य के हस्तक्षेप की शुरुआत थी, हालाँकि आवंटित राशि देश की ज़रूरतों की तुलना में अपेक्षाकृत कम थी। मामूली राशि के बावजूद, इसने शिक्षा में भविष्य की सरकारी भागीदारी के लिए एक मिसाल कायम की।

- **कथन 2 सही है।** 1929 के व्हिटली आयोग, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है, का नेतृत्व सर एम.के. के. विटनी ने किया था और इसका ध्यान भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति पर केंद्रित था। आयोग ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं, जिनमें उच्च शिक्षा के लिए राज्य वित्त पोषण की आवश्यकता भी शामिल है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार को विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे विस्तार और सुधार कर सकें। आयोग की सिफारिशें भारत में विश्वविद्यालय प्रणाली के भविष्य के विकास को आकार देने में सहायक थीं और सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के वित्तपोषण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने में महत्वपूर्ण थीं।

- **कथन 3 सही है।** सर चार्ल्स वुड द्वारा लिखित वुड्स डिस्पैच ऑफ़ 1854 को अक्सर "भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्नाकार्टा" कहा जाता है। यह भारत में आधुनिक शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। डिस्पैच ने एक संरचित शिक्षा प्रणाली की नींव रखी और पूरे भारत में साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों की रूपरेखा तैयार की। इसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का विस्तार करने, स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस नीति ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शिक्षा प्रणाली के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया और भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने की मांग की।

- **कथन 4 गलत है।** मुंबई में एलफिंस्टन कॉलेज की स्थापना 1856 में हुई थी (न कि 1835 में) और यह भारत में पश्चिमी शैली की उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले पहले कॉलेजों में से एक था। इसका नाम बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड एलफिंस्टन के नाम पर रखा गया था। हालाँकि दादाभाई नौरोजी भारतीय शिक्षा आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे और उच्च शिक्षा के प्रमुख समर्थक थे, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर एलफिंस्टन कॉलेज का समर्थन नहीं किया या इसकी स्थापना नहीं की। हालांकि, विशेष रूप से पश्चिमी और स्थानीय दोनों परंपराओं में भारतीयों के लिए शिक्षा की वकालत के माध्यम से नौरोजी ने भारत में शिक्षा और सामाजिक सुधार को आगे बढ़ाने के व्यापक प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Q41. चोल राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. विजयालय चोल ने मुथरैयारों से तंजावुर पर कब्जा करके चोल साम्राज्य की नींव रखी।
2. राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने चोलों को हराया और उत्तरी तमिलनाडु पर उनका नियंत्रण कमजोर कर दिया।
3. राजराजा चोल प्रथम ने पांडियन नौसेना को हराकर और श्रीलंका पर अभियान शुरू करके अपनी नौसैनिक शक्ति का विस्तार किया।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल एक B. सिर्फ दो

C. तीनों D. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: C

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** विजयालय चोल ने 850 ई.पू. के आसपास मुथरैयारों से तंजावुर पर कब्जा कर लिया, जो चोल वर्चस्व की शुरुआत थी। उन्होंने शुरुआत में पल्लवों के सामंत के रूप में कार्य किया, लेकिन बाद में, उन्होंने राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर चोल राजवंश को दक्षिण भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनके शासनकाल ने उनके उत्तराधिकारियों, विशेषकर उनके पोते परांतक प्रथम के तहत बाद के शाही विस्तार की नींव रखी।

- **कथन 2 सही है।** राष्ट्रकूट राजवंश के कृष्ण तृतीय ने चोलों को हराया और उत्तरी तमिलनाडु पर उनका नियंत्रण कमजोर कर दिया। यह 10वीं शताब्दी के अंत में हुआ था जब राष्ट्रकूट और चोल क्षेत्रीय संघर्ष में लगे हुए थे। कृष्ण तृतीय की जीत से चोलों को अस्थायी झटका लगा, लेकिन बाद में उन्होंने राजराजा चोल प्रथम के अधीन अपना प्रभुत्व पुनः प्राप्त कर लिया। तक्कोलम की लड़ाई (949 ई.पू.) इस प्रतिद्वंद्विता में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जहां चोलों को भारी नुकसान हुआ।

- **कथन 3 सही है।** राजराजा चोल प्रथम, एक दूरदर्शी शासक, ने चोल साम्राज्य को एक दुर्जेय समुद्री साम्राज्य में बदल दिया। नौसैनिक प्रभुत्व के रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए, उन्होंने सावधानीपूर्वक एक शक्तिशाली बेड़ा बनाया और इसे हिंद महासागर में चोल के प्रभाव को बढ़ाने के लिए तैनात किया। श्रीलंका पर उनकी विजय, जो उनके नौसैनिक कौशल का एक प्रमाण है, ने इस द्वीप को चोल नियंत्रण में ला दिया, जिससे एक

महत्वपूर्ण विदेशी क्षेत्र की स्थापना हुई। अपनी पहुंच का प्रदर्शन करते हुए, उन्होंने मालदीव में अभियान शुरू किया, महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया और चोल के समुद्री वर्चस्व को मजबूत किया। इन महत्वपूर्ण मार्गों पर चोल नौसेना के नियंत्रण ने न केवल व्यापार को सुविधाजनक बनाया, बल्कि महत्वपूर्ण बंदरगाहों और बाजारों तक पहुंच को भी सक्षम बनाया, जिससे साम्राज्य समृद्ध हुआ और क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत हुई। इन महत्वाकांक्षी नौसैनिक अभियानों के माध्यम से, राजराजा चोल प्रथम ने एक स्थायी महत्व की समुद्री शक्ति के रूप में चोल साम्राज्य की विरासत को सुनिश्चित किया।

Q42. चोल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. चोल साम्राज्य मंडलम, वलनाडुस, नाडुस और गांवों में विभाजित था।
2. उर एक ग्राम सभा थी, जो मुख्यतः गैर-ब्राह्मण बस्तियों के लिए थी।
3. चोलों ने एक कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली विकसित की।
4. चोलों के अधीन नाडु सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई थी।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल एक B. सिर्फ दो

C. केवल तीन D. चारों

उत्तर: C

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** चोल साम्राज्य को प्रभावी प्रशासन के लिए मंडलम (प्रांत), वलनाडस (जिले), नाडस (उप-जिले) और गांवों में संरचित किया गया था। प्रत्येक स्तर पर उसके अधिकारी शासन, राजस्व संग्रहण और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे।
- **कथन 2 सही है।** दक्षिण भारत के चोल राजवंश में, "उर" एक ग्राम सभा थी जो स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, मुख्य रूप से गैर-ब्राह्मण बस्तियों में। "सभा" के विपरीत, जो विशेष रूप से ब्रह्मादेय गांवों में ब्राह्मण जमींदारों के लिए थी, उर एक अधिक समावेशी शासी निकाय था। यह मुख्य रूप से गैर-ब्राह्मण भूस्वामी समुदायों से बना था और संसाधन आवंटन, विवाद समाधान और सामुदायिक गतिविधियों के आयोजन जैसे गाँव के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। इस प्रणाली ने विकेंद्रीकृत शासन की अनुमति दी, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि स्थानीय मुद्दों को कुशलतापूर्वक संबोधित किया गया। जबकि सभा एक ब्राह्मण-प्रभुत्व वाली परिषद के रूप में कार्य करती थी, उर ने गैर-ब्राह्मणों को प्रशासनिक निर्णयों में भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान किया, जो चोल राजवंश की अच्छी तरह से संरचित स्थानीय स्वशासन प्रणाली को दर्शाता है।
- **कथन 3 सही है।** चोलों ने विशेष रूप से ब्रह्मादेय और सभा गाँवों में एक उच्च संगठित स्थानीय स्वशासन प्रणाली की स्थापना की। इन सभाओं में सिंचाई, मंदिर प्रबंधन और कराधान जैसे विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार विभिन्न समितियाँ (वारियम) थीं। प्रसिद्ध उत्तरमेरुर शिलालेख इस प्रणाली का विस्तृत साक्ष्य प्रदान करते हैं, जिसमें बताया गया है कि सदस्यों को कुदावोलाई (लॉट प्रणाली) नामक चुनाव पद्धति के माध्यम से कैसे चुना जाता था।
- **कथन 4 गलत है।** नाडु एक मध्य-स्तरीय प्रशासनिक इकाई थी, जबकि मंडलम (प्रांत) चोल साम्राज्य में सबसे बड़े क्षेत्रीय प्रभाग थे। प्रत्येक नाडु एक नट्टार (स्थानीय परिषद) द्वारा शासित होता था और शाही अधिकारियों द्वारा उसकी देखरेख की जाती थी। मंडलम पर राजकुमारों या राजा द्वारा नियुक्त उच्च पदस्थ अधिकारियों का शासन होता था, जिससे विशाल साम्राज्य पर कुशल नियंत्रण सुनिश्चित होता था। चोल प्रशासन अपने विकेंद्रीकरण, स्थानीय शासन के साथ शाही सत्ता को संतुलित करने के लिए जाना जाता था।

Q43. दिल्ली सल्तनत के दौरान राजस्व प्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राजस्व का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जिसे खराज कहा जाता था।
2. इक्ता प्रणाली में सैन्य और प्रशासनिक सेवाओं के बदले में कुलीनों को भूमि देना शामिल था।
3. अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि राजस्व संग्रह को विनियमित करने के लिए दाग और चेहरा प्रणाली शुरू की।
4. मुहम्मद बिन तुगलक ने राजस्व निर्धारण के लिए प्रत्यक्ष भूमि माप प्रणाली लागू की।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल एक B. सिर्फ दो

C. केवल तीन D. चारों

उत्तर: C

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** दिल्ली सल्तनत के दौरान राजस्व का प्राथमिक स्रोत खराज (भूमि कर) था, जो शासक और क्षेत्र के आधार पर आम तौर पर कुल उपज का एक-चौथाई से आधा हिस्सा था। यह कर गैर-मुसलमानों (धिम्मियों) और मुस्लिम प्रजा पर समान रूप से लगाया जाता था, लेकिन मुसलमानों को ज़कात (दान कर) भी देना पड़ता था, और गैर-मुसलमानों को जजिया (मतदान

कर) देना पड़ता था। विभिन्न सुल्तानों के अधीन राजस्व संग्रह की दक्षता अलग-अलग थी - अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य अभियानों के वित्तपोषण के लिए कर संग्रह को मजबूत किया, जबकि मुहम्मद बिन तुगलक ने अत्यधिक कराधान लगाया, जिससे आर्थिक कठिनाइयाँ पैदा हुईं।

- **कथन 2 सही है।** इक्ता प्रणाली एक भू-राजस्व और प्रशासनिक तंत्र था जहां सुल्तान प्रशासन और रक्षा में उनकी सेवाओं के बदले में रईसों या सैन्य अधिकारियों (मुक्तिस) को भूमि (इक्ता) देता था। हालाँकि, भूमि सुल्तान के नियंत्रण में रही, और मुक्तियों को एकत्रित राजस्व का एक निश्चित हिस्सा राज्य के खजाने में भेजना आवश्यक था। हालाँकि वे सैनिकों को बनाए रखने के लिए एक हिस्सा बरकरार रख सकते थे, लेकिन भूमि पर वंशानुगत दावों को रोकने के लिए उन्हें नियमित रूप से स्थानांतरित किया जाता था। इस प्रणाली ने कुशल प्रशासन में मदद की लेकिन कभी-कभी जब बहुसंख्यक लोगों ने केंद्रीय सत्ता का विरोध किया तो विद्रोह भी हुआ। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के तहत इक्ता प्रशासन के केंद्रीकरण ने राजस्व पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित किया।

- **कथन 3 गलत है।** अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई दाग (घोड़ों की ब्रांडिंग) और चेहरा (सैनिकों का रिकॉर्ड रखना) प्रणालियाँ सैन्य सुधार थे, राजस्व सुधार नहीं। इन उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके सेना में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना था कि केवल उच्च गुणवत्ता वाले घोड़ों का उपयोग किया जाए और सैनिकों की फर्जी भर्ती को रोका जाए। वे सामंती प्रभुओं (मुक्ति) पर भरोसा किए बिना एक अच्छी तरह से सुसज्जित स्थायी सेना बनाए रखने की उनकी व्यापक सैन्य रणनीति का हिस्सा थे। इसके विपरीत, उनकी राजस्व नीतियों में दोआब क्षेत्र में भूमि कर में वृद्धि और अर्थव्यवस्था को विनियमित करने और अपने सैन्य अभियानों को बनाए रखने के लिए सख्त मूल्य नियंत्रण तंत्र शामिल थे।

- **कथन 4 सही है।** मुहम्मद बिन तुगलक ने राजस्व निर्धारण के लिए प्रत्यक्ष भूमि माप प्रणाली शुरू की। उन्होंने दोआब क्षेत्र में कृषि भूमि के सर्वेक्षण का आदेश दिया, एक ऐसी प्रणाली लागू की जहां कर मापी गई भूमि और उत्पादकता (ज़ब्त प्रणाली) पर आधारित थे। हालाँकि, उनकी अत्यधिक उच्च कर दरों और कठोर संग्रह विधियों के कारण आर्थिक संकट, किसान विद्रोह और बड़े पैमाने पर प्रवासन हुआ। उनकी महत्वाकांक्षी लेकिन खराब तरीके से क्रियान्वित आर्थिक नीतियां, जैसे कि सांकेतिक मुद्रा की शुरूआत और राजधानी को दौलताबाद में स्थानांतरित करना, ने साम्राज्य को और कमजोर कर दिया। बाद के शासकों, विशेष रूप से शेर शाह सूरी और अकबर ने, अपने राजस्व सुधारों को एक अधिक प्रभावी भूमि राजस्व प्रणाली (ज़ब्त और दहसाला प्रणाली) में परिष्कृत किया जो भविष्य के मुगल प्रशासन के लिए एक मॉडल बन गया।

Q44. शिवाजी के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अष्ट प्रधान वंशानुगत पदों के बिना मंत्रिपरिषद थी।
2. शिवाजी ने एक स्थायी सेना (पगा) बनाए रखी और सैन्य विस्तार के लिए सरंजाम का इस्तेमाल किया।
3. उन्होंने प्रशासन को केंद्रीकृत करने के लिए वतनदारी व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया।
4. उनकी न्यायिक प्रणाली में दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए अलग-अलग अदालतें थीं।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल एक B. सिर्फ दो

C. केवल तीन D. चारों

उत्तर: B

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** अष्ट प्रधान (आठ मंत्रियों की परिषद) शिवाजी की मुख्य सलाहकार और प्रशासनिक संस्था थी, जो उन्हें मराठा राज्य के नागरिक, सैन्य और वित्तीय मामलों का प्रबंधन करने में मदद करती थी। आठ प्रमुख मंत्रियों में शामिल हैं:
- पेशवा (प्रधानमंत्री)- मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
- अमात्य (वित्त मंत्री) - राज्य के वित्त और राजस्व संग्रह का प्रबंधन।
- सचिव (सचिव) - शाही पत्राचार और राज्य अभिलेखों को संभाला।
- मंत्री (आंतरिक मंत्री) - खुफिया और घरेलू मामलों का पर्यवेक्षण।
- सेनापति (कमांडर-इन-चीफ) - सेना का नेतृत्व करते थे लेकिन सैनिकों पर उनका नियंत्रण सीमित था।
- सुमंत (विदेश मंत्री) - राजनयिक संबंधों का प्रबंधन।
- न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश)- कानूनी मामलों पर सलाह देते थे।
- पंडितराव (धार्मिक प्रमुख) - धार्मिक और दान मामलों की देखरेख करते थे।
- बाद के पेशवा युग के विपरीत, जब पेशवा पद वंशानुगत हो गया, शिवाजी के अधीन, इनमें से कोई भी पद वंशानुगत नहीं था। उन्होंने भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त जवाबदेही और लगातार स्थानांतरण सुनिश्चित किए। हालाँकि, शिवाजी के शासनकाल के बाद, कुछ कार्यालय, विशेष रूप से पेशवा और सेनापति के, वंशानुगत हो गए, जिसने धीरे-धीरे केंद्रीय प्राधिकरण को कमजोर कर दिया।
- **कथन 2 सही है।** शिवाजी ने एक स्थायी सेना (पागा) रखी, जिसमें घुड़सवार सेना, पैदल सेना और तोपखाने शामिल थे, और वह व्यक्तिगत रूप से सैन्य प्रशिक्षण की निगरानी करते थे। मुगल मनसबदारी प्रणाली के विपरीत, जो सामंती प्रभुओं पर निर्भर थी, शिवाजी ने स्थायी भूमि अनुदान के बजाय सैन्य अधिकारियों

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

को सरंजम (अस्थायी राजस्व असाइनमेंट) प्रदान किया। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि सैन्य अधिकारी वफादार रहें और केंद्रीय प्रशासन पर निर्भर रहें। उनकी किला-आधारित सैन्य रणनीति, 300 से अधिक अच्छी तरह से संरक्षित किलों का उपयोग करते हुए, तेजी से गतिशीलता और गुरिल्ला युद्ध को सक्षम बनाती है, जिससे मराठा मुगलों और आदिल शाहियों जैसे मजबूत विरोधियों के खिलाफ लचीला बन जाते हैं। उनकी सैन्य प्रणाली में गुरिल्ला रणनीति (गनिमी कावा) को पारंपरिक युद्ध के साथ जोड़ा गया था।

- **कथन 3 गलत है।** शिवाजी ने वतनदारी प्रणाली (स्थानीय अधिकारियों के वंशानुगत भूमि अधिकार) को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया, लेकिन उन्होंने मजबूत केंद्रीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उनकी शक्ति को कम करने का प्रयास किया। वतनदार (देशमुख और देशपांडे जैसे स्थानीय वंशानुगत अधिकारी) अक्सर अर्ध-स्वतंत्र शासकों के रूप में कार्य करते थे, जो शिवाजी के अधिकार में बाधाएँ पैदा करते थे। उनकी शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए, उन्होंने रैयतवारी (प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह) की शुरुआत की और वंशानुगत अभिजात वर्ग पर भरोसा करने के बजाय सीधे राज्य के प्रति जवाबदेह अधिकारियों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी। हालाँकि, व्यावहारिक बाधाओं के कारण, वह वतनदारों को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सके, और बाद में उन्होंने पेशवाओं के अधीन प्रभाव प्राप्त कर लिया, जिससे सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ।

- **कथन 4 गलत है।** शिवाजी की न्याय व्यवस्था अत्यधिक संरचित नहीं थी, क्योंकि उनका ध्यान सैन्य और प्रशासनिक शासन पर अधिक था। न्याय मुख्यतः औपचारिक अदालत प्रणाली के बजाय गाँव और स्थानीय स्तर पर पंचायतों और स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रशासित किया जाता था। न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश) अष्ट प्रधान का हिस्सा थे, लेकिन स्पष्ट रूप से परिभाषित अलग-अलग नागरिक और आपराधिक अदालतें नहीं थीं। सज़ाएँ अक्सर त्वरित और प्रथागत कानूनों पर आधारित होती थीं, और प्रमुख मामलों का निर्णय राजा स्वयं करता था। मुगलों के विपरीत, जिनके पास एक परिष्कृत न्यायिक नौकरशाही थी, शिवाजी का न्यायिक ढांचा काफी हद तक अनौपचारिक था, जो मौजूदा सामाजिक संरचनाओं और प्रथागत प्रथाओं पर निर्भर था।

Q45. दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सुल्तान सर्वोच्च प्राधिकारी था, लेकिन उसके निर्णय उलेमाओं से प्रभावित होते थे।
2. दीवान-ए-अर्ज राजस्व प्रशासन का प्रबंधन करता था।
3. तुगलक के शासनकाल के दौरान तुर्क-ए-चहलगानी एक प्रसिद्ध सभा थी।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल एक B. सिर्फ दो

C. तीनों D. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: A

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** दिल्ली सल्तनत में सुल्तान सर्वोच्च प्राधिकारी था, जिसके पास शासन, सेना और प्रशासन पर पूर्ण शक्ति थी। हालाँकि, उनका शासन अक्सर इस्लामी विद्वानों और धार्मिक नेताओं के समूह उलेमा की मंजूरी पर निर्भर था। उलेमा ने राज्य की नीतियों को प्रभावित किया, विशेष रूप से कानून और धर्म के मामलों में, यह सुनिश्चित करते हुए कि सुल्तान का शासन इस्लामी सिद्धांतों के अनुरूप हो। वैधता और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए उनका समर्थन महत्वपूर्ण था, क्योंकि उलेमा का विरोध सुल्तान के अधिकार को कमजोर कर सकता था।

- **कथन 2 गलत है।** दीवान-ए-अर्ज़ दिल्ली सल्तनत के दौरान सेना के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार सैन्य विभाग था। इसका नेतृत्व अरिज-ए-ममालिक करता था, जो शाही सेना के रखरखाव और अनुशासन की देखरेख करता था। अरिज-ए-मुमालिक सैनिकों की भर्ती और एक अच्छी तरह से सुसज्जित और संगठित सेना सुनिश्चित करने के लिए शाही टुकड़ियों को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार था। दीवान-ए-अर्ज़ की स्थापना मामलुक वंश के नौवें सुल्तान ग़ियास उद दीन बलबन ने अपने सैन्य और प्रशासनिक सुधारों के हिस्से के रूप में की थी। दिल्ली के सुल्तान ने राज्य के मुख्य कार्यकारी, सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी और सेना के कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्य किया, जो शासन और सैन्य मामलों पर सर्वोच्च शक्ति रखते थे। इसके अतिरिक्त, अमीर-उल-उमरा सेना का प्रमुख और सल्तनत में एक वरिष्ठ रईस था, जो सैन्य प्रशासन और रणनीति में सहायता करता था।

- **कथन 3 गलत है।** तुर्क-ए-चहलगानी, जिसे "द फोर्टी" या "दाल चालीसा" के नाम से भी जाना जाता है, 40 भरोसेमंद तुर्की गुलाम रईसों का एक समूह था, जिनके पास इल्तुतमिश के तहत दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में महत्वपूर्ण शक्ति थी। इस विशिष्ट परिषद में उच्च श्रेणी के तुर्की गुलाम सैन्य कमांडर शामिल थे जिन्होंने शासन और प्रशासनिक मामलों पर सुल्तान को सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका प्रभाव सैन्य, राजनीतिक और वित्तीय मामलों पर फैल गया, जिससे वे इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सल्तनत के सबसे शक्तिशाली समूहों में से एक बन गए।

Q46. भारत में वीरशैववाद परंपरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है/हैं?

1. वीरशैववाद लिंग के रूप में भगवान शिव पर केंद्रित पूजा के माध्यम से एकेश्वरवाद में विश्वास करता है।
2. यह वेदों और जाति व्यवस्था के अधिकार को अस्वीकार करता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. यह परंपरा 12वीं शताब्दी ईस्वी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 B. केवल 1 और 2

C. केवल 3 D. केवल 2 और 3

उत्तर: B

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** वीरशैववाद, जिसे लिंगायत वाद के रूप में भी जाना जाता है, एक एकेश्वरवादी परंपरा है जो भगवान शिव को उनके निराकार सार में पूजता है, जिसे इष्टलिंग (अनुयायियों द्वारा पहना जाने वाला एक व्यक्तिगत लिंग) द्वारा दर्शाया जाता है। विद्वान ए.के. रामानुजन इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि यह परंपरा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत भक्ति पर जोर देती है, जहां लिंग शिव को अंतर्निहित और पारलौकिक दोनों के रूप में दर्शाता है। यह आंदोलन एक गैर-द्वैतवादी विश्वास को बढ़ावा देता है कि शिव ब्रह्मांड और उससे परे दोनों हैं, जिसमें लिंग परमात्मा और व्यक्ति के बीच इस मिलन की निरंतर याद दिलाता है।
- **कथन 2 सही है।** वीरशैववाद रूढ़िवादी ब्राह्मणवादी प्रथाओं की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा, वेदों के अधिकार और जाति व्यवस्था को सक्रिय रूप से खारिज कर दिया, एक सिद्धांत जिसे कायाका (श्रम की गरिमा) के रूप में जाना जाता है। विद्वान एम.एम. कलबुर्गी ने उल्लेख किया है कि संस्थापक बसव ने सामाजिक न्याय और समानता पर ध्यान केंद्रित करते हुए पदानुक्रमिक विभाजन के बिना समाज की वकालत की। वीरशैव साहित्य, विशेष रूप से बसव और अन्य संतों द्वारा वचन (काव्यात्मक शिक्षाएँ), अनुष्ठानिक प्रथाओं पर अनुभव मंडप (आध्यात्मिक अनुभव के लिए एक स्थान) के विचार पर जोर देते हैं, जो शिव को समर्पित एक समतावादी समुदाय को प्रोत्साहित करते हैं।
- **कथन 3 गलत है।** वीरशैव धर्म की स्थापना 12वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने नहीं बल्कि बसव ने की थी। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के विपरीत, जिसने गैर-द्वैतवाद पर जोर दिया और वैदिक अधिकार को बरकरार रखा, बसव की शिक्षाओं ने कर्मकाण्डीय रूढ़िवाद और जाति पदानुक्रम को खारिज कर दिया, शिव की पूजा पर केंद्रित आध्यात्मिकता के एक समावेशी, समतावादी रूप को बढ़ावा दिया। विद्वान ए.के. के अनुसार राव के अनुसार, बसवा के सिद्धांतों ने अनुयायियों को भक्ति, ईमानदारी और दूसरों की सेवा का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया, जो कि वैदिक अनुष्ठानों और सामाजिक स्तरीकरण पर रूढ़िवादी हिंदू धर्म के जोर से बिल्कुल अलग था।

Q47. निम्नलिखित मुगलकालीन विद्वानों को उनके प्रभाव काल के आधार पर कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:

1. अबुल फजल 2. अल-बदायूंनी
3. दारा शिकोह 4. शाह वलीउल्लाह

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. 1 - 2 - 3 - 4 B. 2 - 1 - 3 - 4

C. 1 - 3 - 2 - 4 D. 3 - 2 - 1 - 4

उत्तर: B

व्याख्या:

- **अल-बदायूंनी (1540-1615) :** अकबर के शासनकाल के दौरान एक इतिहासकार और विद्वान, जो अपने काम मुंतखब-उत-तवारीख (इतिहास का चयन) के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं।
- वह अकबर की धार्मिक नीतियों, विशेष रूप से दीन-ए-इलाही की आलोचना करते थे, जिसे वे रूढ़िवादी इस्लाम से विचलन के रूप में देखते थे।
- अकबर के दरबार में सेवा करने के बावजूद, उन्होंने अक्सर उदार धार्मिक माहौल का विरोध किया, जिससे उनके लेख अबुल फ़ज़ल के अधिक अनुकूल आख्यानों के प्रति संतुलन बन गए।
- उनके लेखन अकबर के समय की सामाजिक-राजनीतिक और धार्मिक बहसों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
- **अबुल फ़ज़ल (1551-1602) :** एक प्रमुख दरबारी इतिहासकार और अकबर के करीबी विश्वासपात्र, अकबरनामा के लिए जाने जाते हैं: अकबर के शासनकाल का तीन-खंड इतिहास। आइन-ए-अकबरी: राजस्व, सैन्य और सांस्कृतिक पहलुओं सहित अकबर के प्रशासन का विस्तृत विवरण। उन्होंने अकबर की नीतियों, खास तौर पर उनकी धार्मिक सहिष्णुता और सुलह-ए-कुल (सार्वभौमिक शांति) दर्शन को उचित ठहराने और उसका दस्तावेजीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके बढ़ते प्रभाव के कारण राजकुमार सलीम (बाद में जहाँगीर) के आदेश पर उनकी हत्या कर दी गई।
- **दारा शिकोह (1615-1659) :** शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे, दार्शनिक, कवि और अनुवादक, जिन्हें उपनिषदों और अन्य हिंदू धर्मग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने और हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। मजमा-उल-बहरीन (दो महासागरों का संगम) लिखना, जिसमें इस्लामी और हिंदू रहस्यमय परंपराओं को समेटने की कोशिश की गई थी। सूफीवाद और धार्मिक सहिष्णुता की वकालत करना, अपने भाई औरंगजेब के विपरीत, जिसने उन्हें 1659 में मार डाला था। उनके बौद्धिक योगदान ने इंडो-फारसी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रवचन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया।
- **शाह वलीउल्लाह (1703-1762) :** औरंगजेब के बाद के काल के एक प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान, सुधारवादी और धर्मशास्त्री, जिन्हें कुरान का फ़ारसी में अनुवाद लिए जाना जाता है, उन्होंने इस्लामी

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुँचाया। उन्होंने पुनरुत्थानवादी इस्लामी आंदोलनों की वकालत की और धार्मिक और राजनीतिक अभिजात वर्ग के बीच भ्रष्टाचार का विरोध किया। उनके कार्यों ने भारत में बाद के इस्लामी सुधार आंदोलनों को प्रभावित किया, जिसमें देवबंदी और बरेलवी आंदोलन शामिल हैं। अहमद शाह अब्दाली से भारत में हस्तक्षेप करने की उनकी अपील ने मराठों के खिलाफ पानीपत की तीसरी लड़ाई (1761) का नेतृत्व किया।

- **इस प्रकार, सही कालानुक्रमिक क्रम है: अल-बदायूंनी (1540-1615) → अबुल फ़ज़ल (1551-1602) → दारा शिकोह (1615-1659) → शाह वलीउल्लाह (1703-1762)।**

Q48. विजयनगर साम्राज्य की कला और वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है/हैं?

1. राया गोपुरम (स्मारकीय मीनार) विजयनगर मंदिर वास्तुकला की एक विशिष्ट विशेषता थी।
2. साम्राज्य की वास्तुकला में द्रविड़ और इंडो-इस्लामिक शैलियों का मिश्रण था, खासकर महल और दरबार की संरचनाओं में।
3. हम्पी में लोटस महल शुद्ध द्रविड़ शैली की वास्तुकला का एक उदाहरण है।
4. हजारा राम मंदिर रामायण के दृश्यों को दर्शाने वाली अपनी व्यापक बेस-रिलीफ नक्काशी के लिए जाना जाता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल एक B. सिर्फ दो

C. केवल तीन D. चारों

उत्तर: C

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** विजयनगर मंदिरों में राया गोपुरम एक प्रमुख विशेषता थी, जिसकी विशेषता ऊंचे, विस्तृत रूप से सजाए गए प्रवेश द्वार टावर थे। ये ऊंचे प्रवेश द्वार मंदिर परिसर की भव्यता और धार्मिक महत्व को चिह्नित करने के लिए बनाए गए थे। वे विजयनगर साम्राज्य की कलात्मक उत्कृष्टता को प्रदर्शित करते हुए, देवताओं की जटिल नक्काशी, पौराणिक दृश्यों और पुष्प रूपांकनों से सजाए गए थे। उल्लेखनीय उदाहरणों में हम्पी में विरुपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर शामिल हैं, दोनों में विशाल गोपुरम हैं।
- **कथन 2 सही है।** विजयनगर के महलों और सार्वजनिक संरचनाओं में इंडो-इस्लामिक प्रभाव वाले द्रविड़ मंदिर तत्व शामिल थे, जो गुंबदों, मेहराबों और गुंबददार छतों में दिखाई देते हैं। विजयनगर काल की वास्तुकला में फारसी और इस्लामी प्रभावों के साथ स्वदेशी द्रविड़ शैलियों का मिश्रण प्रतिबिंबित होता है, विशेष रूप से महलों और दर्शक कक्षों जैसी धर्मनिरपेक्ष इमारतों में। हम्पी में रानी का स्नानघर एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें फारसी और सल्तनत वास्तुकला की विशेषताओं से मिलते जुलते मेहराबदार दरवाजे और बालकनी हैं। हाथी अस्तबल भी एक अलग इंडो-इस्लामिक प्रभाव दिखाते हैं, जिसमें गुंबददार कक्ष और नुकीले मेहराब हैं, जिनका उपयोग शाही हाथियों को रखने के लिए किया जाता है।
- **कथन 3 गलत है।** हम्पी में लोटस महल द्रविड़ और इस्लामी स्थापत्य शैली का मिश्रण प्रदर्शित करता है, जो विशुद्ध रूप से द्रविड़ होने के बजाय इसके धनुषाकार प्रवेश द्वारों और गुंबददार छतों में स्पष्ट है। लोटस महल (चित्रांगनी महल) विजयनगर साम्राज्य की बेहतरीन जीवित धर्मनिरपेक्ष संरचनाओं में से एक है, जो अपने नाजुक प्लास्टर अलंकरण और सममित लेआउट के लिए जाना जाता है। इसमें मल्टीफ़ॉइल मेहराब, लोब वाली खिड़कियां और गुंबददार छतें हैं, जो पारंपरिक द्रविड़ मंदिर वास्तुकला के बजाय इंडो-इस्लामिक वास्तुशिल्प तत्वों से मिलती जुलती हैं। हालाँकि, संरचना के स्तंभ और आधार, द्रविड़ शैलीगत विशेषताओं को बरकरार रखते हैं, जो उस अवधि के सांस्कृतिक संश्लेषण को उजागर करते हैं।
- **कथन 4 सही है।** हजारा राम मंदिर अपनी दीवारों पर व्यापक आधार-राहत नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, जो रामायण के प्रसंगों को चित्रित करता है।
- मंदिर का उपयोग मुख्य रूप से शाही परिवार द्वारा किया जाता था, और इसकी नक्काशी में रामायण के युद्धों, जुलूसों और दैवीय हस्तक्षेप के दृश्यों को दर्शाया गया है। मंदिर में जटिल स्तंभों वाले मंडप और एक गर्भगृह (गर्भगृह) भी है जिसमें भगवान राम की मूर्ति है। "हजारा राम" नाम "हजारों" राहत नक्काशी को संदर्भित करता है जो भगवान राम की कहानी बताती है।

Q49. प्राचीन भारतीय शैल-कट और मंदिर वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. अजंता की गुफाएँ ममल्लापुरम की गुफाओं से पहले बनाई गई थीं।
2. भुवनेश्वर में उदयगिरि मंदिर धौली में शैल-कट हाथी गुफाओं से पहले बनाया गया था।
3. उदयगिरि में विष्णु की छवि खजुराहो मंदिर परिसर से पहले चित्रित की गई थी।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3

उत्तर: A

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** अजंता गुफाओं का निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और छठी शताब्दी ईस्वी के बीच, बौद्ध रॉक-कट वास्तुकला के प्रारंभिक चरण के दौरान किया गया था। दूसरी ओर, मामल्लापुरम गुफाएं, जिन्हें पल्लव गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण बहुत बाद में, 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान, पल्लव राजवंश के तहत किया गया था। इसलिए, अजंता की गुफाएँ मामल्लापुरम की गुफाओं से भी पहले की हैं।
- **कथन 2 सही है।** भुवनेश्वर के पास उदयगिरि गुफाएँ, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की हैं, गुप्त काल के शासनकाल के दौरान बनाई गई थीं। इसके विपरीत, धौली में चट्टानों को काटकर बनाई गई हाथी गुफाएं सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बनाई गई थीं। इसलिए, उदयगिरि मंदिर (गुप्त काल) का निर्माण धौली गुफाओं के बाद किया गया था, जो पहले थे।
- **कथन 3 गलत है।** उदयगिरि में विष्णु की प्रतिमा, जो लगभग 5वीं शताब्दी ई.पू. की है, खजुराहो मंदिर परिसर के निर्माण से पहले की है, जिसे बहुत बाद में, 10वीं और 11वीं शताब्दी ई.पू. के दौरान चंदेला राजवंश के तहत बनाया गया था। हालाँकि, यह कथन गलत है क्योंकि इससे पता चलता है कि विष्णु की छवि खजुराहो से पहले चित्रित की गई थी, जबकि खजुराहो का निर्माण उदयगिरि के बाद किया गया था।

Q50. अहोम साम्राज्य के सैन्य संघर्षों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अहोमों ने कई मुगल आक्रमणों का सफलतापूर्वक विरोध किया।
2. अहोम मुख्य रूप से गुरिल्ला युद्ध के बजाय रक्षा के लिए किलेबंद शहरों पर निर्भर थे।
3. 1672 की यंडाबो की संधि अहोम और मुगलों के बीच अंतिम शांति समझौता था।
4. अहोमों ने चुटिया और कछारी राज्यों को हराकर अपने क्षेत्र का विस्तार किया।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक B. सिर्फ दो

C. केवल तीन D. चारों

उत्तर: B

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है।** सरायघाट की लड़ाई (1671) एक निर्णायक नौसैनिक युद्ध था, जिसमें अहोम सेनापति लचित बोरफुकन ने मुगलों के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया और सफलतापूर्वक असम की रक्षा की। अहोमों ने नदी युद्ध, गति और बेहतर रणनीति का इस्तेमाल करके बहुत बड़ी मुगल सेना को हराया। राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल आक्रमण को विफल करने में लाचित बोरफुकन के नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अहोमों ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े मुगल बेड़े का मुकाबला करने के लिए छोटी, तेज गति वाली नावों और गुरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल किया। इस जीत ने सुनिश्चित किया कि असम मुगल शासन से स्वतंत्र रहे, जो भारतीय सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था।
- **कथन 2 गलत है।** अहोम रक्षा के लिए किलेबंद शहरों पर निर्भर नहीं थे। इसके बजाय, उन्होंने मुगलों जैसे मजबूत दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए गुरिल्ला रणनीति, राजधानियों को बदलना और नदी-आधारित युद्ध का इस्तेमाल किया। जब तक आवश्यक न हो, वे सीधे टकराव से बचते थे और अक्सर दुश्मनों को मुश्किल इलाकों में फंसा देते थे। अहोम अपनी लचीली युद्ध रणनीति के लिए जाने जाते थे, जिसमें हिट-एंड-रन हमले, घात लगाना और नदी के किनारे के इलाकों का इस्तेमाल करना शामिल था। मुगल किलों के विपरीत, अहोम रक्षा तंत्र आक्रमणकारियों को भ्रमित करने के लिए मिट्टी के किलेबंदी, बाड़ों (गढ़) और अपनी राजधानी के तेजी से स्थानांतरण पर निर्भर थे। उनकी राजधानी बदलने की रणनीति ने सुनिश्चित किया कि भले ही एक शहर पर कब्जा कर लिया गया हो, लेकिन इसकी शासन संरचना अन्य जगहों पर बरकरार रही।
- **कथन 3 गलत है।** यंडाबो की संधि वह शांति संधि थी जिसने प्रथम एंग्लो-बर्मी युद्ध को समाप्त किया। 24 फरवरी 1826 को हस्ताक्षरित यह संधि 5 मार्च 1824 को युद्ध शुरू होने के लगभग दो साल बाद आई। इस पर ब्रिटिशों की ओर से जनरल सर आर्चीबाल्ड कैंपबेल और बर्मी लोगों की ओर से लेगिंग के गवर्नर महा मिन हला क्याव हटिन ने हस्ताक्षर किए थे। हालांकि, यह संधि अहोम साम्राज्य, कचारी साम्राज्य या अन्य क्षेत्रों की अनुमति या सहमति के बिना संपन्न हुई थी जो इसकी शर्तों से प्रभावित थे। एवा (बर्मी राजधानी) से सिर्फ़ 80 किमी (50 मील) दूर यांडाबो गाँव में ब्रिटिश सेना तैनात होने के कारण, बर्मी लोगों के पास बिना शर्त ब्रिटिश शर्तों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
- **कथन 4 सही है।** मुगलों से लड़ने से पहले, अहोमों ने चुटिया (1523) और कचारी (1536) राज्यों को हराकर, असम पर अपना शासन मजबूत करके अपने राज्य का विस्तार किया। इन जीतों से उन्हें बाहरी खतरों का सामना करने से पहले अपनी सेना को मजबूत करने में मदद मिली। अहोमों ने रणनीतिक क्षेत्रों और संसाधनों पर नियंत्रण हासिल करते हुए चुटिया साम्राज्य (1523) और कचारी साम्राज्य (1536) पर कब्जा कर लिया। इन विजयों ने उनके क्षेत्र का विस्तार किया, जिससे वे ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रमुख शक्ति बन गए। स्थानीय शासक अभिजात वर्ग को एकीकृत करके और उन्नत युद्ध तकनीकों को अपनाकर, अहोम लोगों ने बड़े साम्राज्यों के खिलाफ भविष्य के संघर्षों के लिए तैयारी की।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. ब्रिटिश नीतियों के सबसे महत्वपूर्ण सकारात्मक पहलू सामाजिक क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। स्पष्ट कीजिए।

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।)

दृष्टिकोण :

- **परिचय :** अपने उत्तर की शुरुआत सामाजिक क्षेत्र में ब्रिटिश नीतियों से करें।
- **मुख्य भाग :** इस भाग में भारत में सामाजिक सुधार से संबंधित 9-10 ब्रिटिश नीतियों के बारे में लिखें।
- **निष्कर्ष :** भारतीय समाज को समतावादी बनाने में अंग्रेजों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए अपने उत्तर लेखन को समाप्त करें।

उत्तर :

परिचय:

- भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, जो 18वीं शताब्दी के मध्य से 1947 तक चला, ने सामाजिक सुधारों सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। ब्रिटिश नीतियाँ अक्सर आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होती थीं, उनकी कई पहलों ने अनजाने में भारत में सामाजिक प्रगति में योगदान दिया।

1. **शिक्षा प्रणाली में सुधार करना :** सबसे प्रभावशाली ब्रिटिश नीतियों में से एक आधुनिक शिक्षा प्रणालियों को प्रारंभ करना था। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने की अनुमति दी। इसके बाद, 1854 के वुड्स डिस्पैच ने विश्वविद्यालयों और स्कूलों की स्थापना करके शिक्षा के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। इससे साक्षरता दर में वृद्धि हुई और एक नया शिक्षित मध्यम वर्ग तैयार हुआ जिसने सामाजिक सुधार आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2. **सती प्रथा का उन्मूलन करना :** सती प्रथा (विधवाओं को उनके पति की चिता पर जलाना) भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित थी। ब्रिटिश सरकार ने 1829 के बंगाल सती विनियमन अधिनियम में हस्तक्षेप किया, जिसने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। यह नीति महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और लैंगिक समानता पर चर्चा को बढ़ावा देने में सहायक थी।
3. **विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को बनाना :** 1856 में, अंग्रेजों ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया, जिसने विधवा पुनर्विवाह को वैध बना दिया। इस नीति ने उन पारंपरिक मानदंडों को चुनौती दी जो विधवाओं को कलंकित करते थे और उन्हें सामाजिक पुनर्एकीकरण और आर्थिक स्वतंत्रता के अवसर प्रदान नहीं करते थे।
4. **बाल विवाह निरोधक अधिनियम बनाना :** 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम का उद्देश्य विवाह के लिए न्यूनतम आयु (लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष) निर्धारित करके बाल विवाह पर अंकुश लगाना था। यह कानून महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण था।
5. **सामाजिक सुधार आंदोलनों का समर्थन करना :** अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष रूप से राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे भारतीय सुधारकों के नेतृत्व वाले विभिन्न सामाजिक सुधार आंदोलनों का समर्थन किया। इन नेताओं ने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों को बढ़ावा देते हुए सती और बाल विवाह जैसी प्रथाओं के खिलाफ वकालत की।
6. **सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल की स्थापना करना :** अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान कई सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल की स्थापना की, खासकर 19वीं सदी के अंत में हैजा और प्लेग जैसी महामारी के दौरान। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना से भारतीयों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच में सुधार हुआ, जिससे आधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए आधार तैयार हुआ।
7. **जनगणना कार्य को प्रारंभ करना :** अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए दशकीय जनगणना कार्यों ने मूल्यवान जनसांख्यिकीय डेटा प्रदान किया जो जाति और धर्म के आधार पर सामाजिक असमानताओं को उजागर करता था। यह डेटा भविष्य के सामाजिक सुधार प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण बन गया क्योंकि इससे समर्थन की आवश्यकता वाले हाशिए पर रहने वाले समुदायों की पहचान करने में मदद मिली।
8. **कानूनी सुधार के तहत कानूनों को संहिताबद्ध करना :** ब्रिटिश कानूनी सुधारों में ऐसे कानूनों को संहिताबद्ध करना शामिल था जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956) जैसे अधिनियमों के माध्यम से महिलाओं के लिए विरासत के अधिकार जैसे मुद्दों को संबोधित करते थे। हालाँकि ये सुधार स्वतंत्रता के बाद पारित हुए, लेकिन ये सुधार महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के संबंध में औपनिवेशिक शासन के दौरान शुरू की गई पिछली चर्चाओं से प्रभावित थे।
9. **शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के प्रचार एवं प्रसार करना :** शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के प्रचार ने भारतीयों के लिए लोकतंत्र, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के बारे में वैश्विक विचारों से जुड़ने के रास्ते खोल दिए। इस भाषाई बदलाव ने सामाजिक परिवर्तन की वकालत करने वाले विभिन्न समूहों के बीच संचार की सुविधा प्रदान की।
10. **अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन करना :** हालांकि स्वतंत्रता के बाद तक सीधे तौर पर कानून नहीं बनाया गया था, लेकिन ब्रिटिश नीतियों ने शैक्षिक सुधारों के माध्यम से अस्पृश्यता प्रथाओं के खिलाफ कुछ आधार तैयार किए, जिससे स्कूलों और कॉलेजों के भीतर अंतरजातीय संबंधों को प्रोत्साहित किया गया।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

निष्कर्ष :

- निष्कर्षतः, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में शोषण और उत्पीड़न से जुड़े कई नकारात्मक पहलू थे, इसने भारतीय समाज के भीतर महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारों की शुरुआत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा, महिलाओं के अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और कानूनी सुधारों के उद्देश्य से विभिन्न नीतियों के माध्यम से, उन्होंने भारतीय समाज को उनके आगमन से पहले की तुलना में अधिक समतावादी बनाने में योगदान दिया। इन परिवर्तनों ने स्वतंत्रता के बाद सामाजिक न्याय आंदोलनों में आगे की प्रगति के लिए मंच तैयार किया।

Q2. भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित ब्रिटिश सरकार की नीतियों को संक्षेप में व्याख्या करें। इन नीतियों ने भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाने में किस प्रकार मदद की?

(उत्तर 250 शब्दों में दें।)

दृष्टिकोण :

- **परिचय :** अर्थव्यवस्था के प्रति समग्र ब्रिटिश नीतियों से अपना उत्तर आरंभ करें।
- **मुख्य भाग :** इस भाग में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति ब्रिटिश नीतियों के बारे में 6-7 बिंदु लिखें।
- दूसरे भाग में इन नीतियों के नकारात्मक प्रभावों को 7-8 बिंदुओं में लिखें।
- फिर 6-बिंदुओं में आंदोलनों के उदाहरणों के साथ लिखें कि नकारात्मक प्रभाव ने भारत में राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा दिया।
- **निष्कर्ष :** अपने उत्तर को यह उल्लेख करके समाप्त करें कि ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियाँ भारत में सामूहिक राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारक किस प्रकार था।

उत्तर :

परिचय :

- ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने भारत में आर्थिक नीतियों की एक श्रृंखला लागू की, जो मुख्य रूप से भारतीय आर्थिक हितों की कीमत पर ब्रिटेन को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। इन नीतियों का उद्देश्य भारत को वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना था, जिससे अक्सर स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं, कृषि और उद्योगों में महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न होते थे।

भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति ब्रिटिश नीतियां :

1. **विऔद्योगीकरण :** ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ लगाकर व्यवस्थित रूप से भारत के पारंपरिक उद्योगों, विशेष रूप से कपड़ा उद्योगों को नष्ट कर दिया, जबकि ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को भारत में शुल्क-मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। इससे स्थानीय शिल्प कौशल और विनिर्माण में गिरावट आई।
2. **भूमि राजस्व प्रणाली :** स्थायी बंदोबस्त (1793) और रैयतवारी प्रणाली जैसी शोषणकारी भूमि राजस्व प्रणालियों की शुरूआत ने किसानों पर भारी बोझ डाल दिया, जिससे वे कर्ज और गरीबी में फंस गए। इन प्रणालियों ने कृषि स्थिरता पर राजस्व संग्रह को प्राथमिकता दी।
3. **शोषण के लिए बुनियादी ढाँचा विकास :** अंग्रेजों ने रेलवे और सड़कों जैसे बुनियादी ढांचे का भले ही विकास किया था, लेकिन इनका निर्माण मुख्य रूप से स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के बजाय संसाधन निष्कर्षण की सुविधा के लिए किया गया था। रेलवे ने निर्यात के लिए कच्चे माल के स्रोतों को सीधे बंदरगाहों से जोड़ा।
4. **संसाधनों पर एकाधिकारिक नियंत्रण :** अंग्रेजों ने नमक (1882 का नमक अधिनियम) और अफ़ीम जैसे प्रमुख संसाधनों पर एकाधिकार स्थापित किया, उत्पादन और मूल्य निर्धारण को नियंत्रित किया जिसने स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया।
5. **कराधान नीतियां :** कृषि और व्यापार पर भारी कराधान ने स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं से संसाधनों को ख़त्म कर दिया। भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के बजाय ब्रिटेन के लिए राजस्व को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
6. **अकाल नीतियाँ :** अकाल के दौरान, ब्रिटिश नीतियों ने अक्सर स्थानीय जरूरतों पर निर्यात को प्राथमिकता दी, जिससे भोजन की कमी बढ़ गई। उदाहरण के लिए, 1943 के बंगाल अकाल के दौरान, अपर्याप्त राहत प्रयासों के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि भारत से भोजन का निर्यात किया जा रहा था।
7. **नकदी फसलों को बढ़ावा :** निर्यात के लिए नील और कपास जैसी नकदी फसलों पर जोर देने से खाद्य सुरक्षा कमजोर हो गई क्योंकि किसान निर्वाह खेती से दूर हो गए, जिससे वे बाजार के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो गए।

ब्रिटिश नीतियों का नकारात्मक प्रभाव :

1. **आर्थिक व्यवधान :** विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण पारंपरिक उद्योग ध्वस्त हो गए जिससे कारीगरों और मजदूरों के बीच बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा हो गई।
2. **गरीबी में वृद्धि :** शोषणकारी भू-राजस्व प्रणालियों के साथ उच्च करों के बोझ के कारण किसानों में गरीबी का स्तर बढ़ गया।
3. **किसानों के लिए ऋण चक्र :** उच्च करों और फसल की कम कीमतों के कारण कई किसान कर्ज के चक्र में फंस गए, जिससे व्यापक कृषि संकट पैदा हो गया।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

4. **खाद्य असुरक्षा :** नकदी फसलों पर ध्यान केंद्रित करने से भोजन की कमी हो गई क्योंकि स्थानीय उपभोग के लिए आवश्यक मुख्य फसलों के लिए कम भूमि समर्पित थी।

5. **सामाजिक अशांति :** आर्थिक कठिनाइयों ने सामाजिक अशांति को बढ़ावा दिया क्योंकि विभिन्न समूहों ने शोषण से संबंधित अपनी शिकायतों के कारण औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संगठित होना शुरू कर दिया।

6. **कृषि उत्पादकता में गिरावट :** औपनिवेशिक नीतियों द्वारा थोपी गई खराब कृषि पद्धतियों के कारण समय के साथ मिट्टी की उर्वरता में गिरावट आई और उत्पादकता में कमी आई।

7. **पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का नुकसान :** औपनिवेशिक नीतियों ने सदियों से समुदायों को कायम रखने वाली स्वदेशी कृषि पद्धतियों की उपेक्षा की, जिससे टिकाऊ खेती के तरीकों के बारे में ज्ञान का नुकसान हुआ।

8. **सांस्कृतिक अलगाव :** आर्थिक शोषण ने भारतीयों के बीच सांस्कृतिक अलगाव की भावना को बढ़ावा दिया, जो विदेशी शासकों द्वारा छीनी जा रही अपनी भूमि के संसाधनों और धन से अलग महसूस करते थे।

भारत में राष्ट्रवाद के उदय में नकारात्मक प्रभावों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाया ?

1. **जागरूकता अभियान :** आर्थिक कठिनाइयों ने दादाभाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे बुद्धिजीवियों को लेखों के माध्यम से आर्थिक शोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के तहत भारत की गरीबी को उजागर किया, जिससे राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा मिला।

2. **राजनीतिक संगठनों का गठन :** भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1885 में स्थापित) जैसे समूह आंशिक रूप से आर्थिक शिकायतों के जवाब में उभरे; उन्होंने राष्ट्रीय पहचान से सीधे जुड़े इन मुद्दों को संबोधित करते हुए राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सुधार की मांग की।

3. **किसान आंदोलन :** दमनकारी वृक्षारोपण प्रणालियों के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह (1917) जैसे आंदोलनों ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ किसानों का समर्थन बढ़ाया, आर्थिक संघर्षों को राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा।

4. **स्वदेशी आंदोलन (1905) :** स्थानीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाने वाली ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के जवाब में, इस आंदोलन ने भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने, उपनिवेशवाद के खिलाफ एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया।

5. **महात्मा गांधी जैसे नेताओं की भूमिका :** खादी कताई जैसी पहल के माध्यम से आत्मनिर्भरता पर गांधी का जोर आर्थिक रूप से पीड़ित लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ; यह राष्ट्रीय पहचान के साथ निकटता से जुड़े साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया।

6. **क्रांतिकारी समूहों का उदय :** आर्थिक असंतोष ने कट्टरपंथी आंदोलनों को भी बढ़ावा दिया जहां युवा क्रांतिकारियों ने औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की; इस अवधि के दौरान हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे समूह आर्थिक शोषण में निहित उपनिवेशवाद विरोधी भावना के आधार पर पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करते हुए उभरे।

निष्कर्ष :

- ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारत को गरीब बनाने और इसके लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन नीतियों के हानिकारक प्रभाव पूरे देश में महसूस किए गए। जैसे-जैसे विभिन्न सामाजिक स्तरों के भारतीयों ने इन कठिनाइयों का अनुभव किया, इससे औपनिवेशिक शासन के तहत शोषण के बारे में जागरूकता बढ़ी। इस साझा अनुभव ने धीरे-धीरे विभिन्न समूहों को एकजुट किया, जिससे एक सामूहिक चेतना पैदा हुई जिसने अंततः स्वतंत्रता की मांग और ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध में योगदान दिया।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

PLUTUS IAS
UPSC/ PCS
EVENING BATCH
हिंदी साहित्य
वैकल्पिक
ONLINE BATCH AVAILABLE AT CHANDIGARH
BATCH STARTING FROM
26th August 2025
05:20PM - 07:20PM
2nd Floor, Apsara Arcade, Karol Bagh Metro Station Gate No. - 6, New Delhi 110005
OUR CENTERS Delhi I Chandigarh I Shimla I Bilaspur
info@plutusias.com
8448440231
www.plutusias.com
PLUTUS IAS WHATSAPP CHANNEL
Click to Know More
Dr. Akhilesh Kr. Shrivastava
M. A , M. Phil & Ph.D JNU New Delhi.
UPSC CSE Interview - 2017, 2018 & 2020.
BPSC CSE 64th, 67th & 68th Interview.
UGC NET - JRF (2018)

PLUTUS IAS
UPSC / PCS

Our Top Rankers

Many more.....

Best UPSC Faculties in India

Dr. Hardeep Singh IAS (Retd.)

Dr. Ghanshyam Singh (HCS allied services)

Dr. Raju Narayana Swamy (Principal Secretary | IAS | AIR 1 | honorary)

Dr. Huma Hassan (Anthropology & Sociology optional)

Prateek Tripathi (Economic & Physics Optional)

Our Books are available on

www.flipkart.com	www.onlinekhanmarket.com	www.examophobia.com	www.amazon.in
Flipkart	Onlinekhanmarket	Examophobia	Amazon

Corporate Office:

917A/41, 1st floor, WEA Karol Bagh, Delhi 110005
Basement - 8 Apsara Arcade, Karolbagh metro station Gate no. 6, New Delhi 110005
C 59, C Block, Sector 2, Noida, Uttar Pradesh 201301

https://www.instagram.com/__plutusias/ https://www.facebook.com/PlutusIAS/ https://www.youtube.com/@plutusias